



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2015/अग्रहायण 6, 1937

No. 315]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2015/AGRAHAYANA 6, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

अंतिम जांच परिणाम

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं, के आयातों से संबंधित मामले में सहायिकी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाने संबंधी जांच।

**संख्या 17/6/2013-डीजीएडी :** - यतः समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सहायिकी प्राप्त वस्तुओं का अभिज्ञान, मूल्यांकन और उन पर प्रतिकारीशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए ;

**क. मामले की पृष्ठ भूमि**

2. यतः मेसर्स लार्सन एंड ट्यूब्स लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात याचिकादाता कहा गया है) ने शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और शुल्क टैरिफ (सहायिकी प्राप्त वस्तुओं का अभिज्ञान, मूल्यांकन और उन पर प्रतिकारीशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने "चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित

रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं, की कास्टिंग्स" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं अथवा कास्टिंग्स कहा गया है) के आयातों से संबंधित मामले में सहायिकी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाने संबंधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त आवेदन पत्र में याचिकादाता ने यह आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात के आरोपित सहायिकीकरण और उससे घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति होती है तथा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के आयात पर सहायिकी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

3. और यतः प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या 17/6/2013-डीजीएडी के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी करके नियमावली के उप-नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की है ताकि आरोपित सहायिकी का निर्धारण, मात्रा और प्रभाव का पता लगाया जा सके और ऐसे सहायिकी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने में पर्याप्त होगा।

4. विद्यमान निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की गई शब्दावली/संक्षिप्तियों को नीचे स्पष्ट किया जाता है :-

क्रमांक	शब्दावली/संक्षिप्तिया	अभिप्राय
1.	प्राधिकारी	निर्दिष्ट प्राधिकारी
2.	याचिकादाता/घरेलू उद्योग	मेसर्स लार्सन एंड ट्यूबरो लिमिटेड
3.	जीओआई	भारत सरकार
4.	एमएनआरई	नई और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा मंत्रालय
5.	एकल प्रतिवादी निर्यातक	मेसर्स झेंझियांग जिआली विंड पावर टेक्नालॉजी कंपनी लिमिटेड
6.	सीवीडी	सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क
7.	एससीएम/करार	सहायिकी और प्रतिकारी उपायों पर करार
8.	अधिनियम	सीमा शुल्क अधिनियम, 1975
9.	नियमावली	सीमा शुल्क टैरिफ (सहायिकी प्राप्त वस्तुओं का अभिज्ञान, मूल्यांकन और उन पर प्रतिकारीशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995

#### ख. क्रिया-विधि

5. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच करने के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि को प्रयोग किया गया है :

(i) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के उप-नियम (7) के अनुसार मौजूदा जांच की कार्यवाही शुरू करने से पहले सहायिकी-रोधी संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में स्थित चीन के दूतावास को अधिसूचित किया है।

(ii) प्राधिकारी ने स्थिति को स्पष्ट करने और इसका निदान करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक सहमति से करने के प्रयोजन से अपने विचार व्यक्त करने के लिए चीन सरकार को आमंत्रित किया था। इस संबंध में दिनांक 5 मई, 2014 को नई दिल्ली में परामर्श किया गया था, जिसमें चीन सरकार के निम्नलिखित प्रतिनिधियों (जिन्हें आगे जीओसी कहा गया है) ने भाग लिया था :

- (1) झा झेंझियांग, द्वितीय सचिव, चीन दूतावास, दिल्ली।
- (2) यांग झिउक्विंग, तृतीय सचिव, चीन दूतावास, दिल्ली।
- (3) गु युआन, प्रथम सचिव, एमओएफसीओएम, चीन जनवादी गणराज्य।

- (4) लुओ किसन, उप आयुक्त ।
- (5) गू यू, प्रथम सचिव, एमओएफसीओएम, चीन जनवादी गणराज्य ।
- (6) वांग हेजुन, वाणिज्यिक परामर्शदाता ।
- (7) कसू यान गुआंग, उप निदेशक, एमओएफसीओएम, चीन जनवादी गणराज्य ।
- (8) वांग क्सीहुई, वाणिज्यिक आयुक्त ।

(iii) परामर्श के दौरान और बाद में उनके दिनांक 26 मई, 2014 के शाब्दिक टिप्पणी द्वारा जीओसी ने यह दावा किया है कि याचिका में उल्लिखित प्रमाण कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अपूर्ण है, आरोपित सहायिकी योजनाओं/कार्यक्रमों को पहले से ही रद्द कर दिया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी जांच शुरू करने के लिए याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए । उक्त शाब्दिक टिप्पणी द्वारा जीओसी ने परामर्श के बाद निम्नलिखित निवेदन किए हैं :-

- (क) याचिका विधिवत् रूप से प्रलेखित नहीं हैं ।
  - (ख) याचिका में उल्लिखित अधिकतर आरोपित कार्यक्रम समर्थित प्रमाण के बिना कथन मात्र हैं ।
  - (ग) सहायिकी-रोधी शिकायत करने के लिए याचिकादाता ने संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि जैसे विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के निष्कर्षों की विषय सामग्री की, इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि क्या ऐसी पुरानी सूचना अन्य उत्पादों और स्थितियों के लिए यथोचित है और क्या वे मौजूदा याचिका के लिए प्रासंगिक है, नकल मात्र ही की है ।
  - (घ) कुछ उद्योगों को प्रदत्त लाभ, ऐसे उद्योग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में लगे हुए हैं ।
  - (ङ) याचिकादाता द्वारा आरोपित निरस्त कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए ।
  - (च) विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक और अस्पष्ट है ।
  - (छ) यदि विचाराधीन उत्पाद को इतने व्यापक तरीके से वर्णित किया जाता है, तो सभी समान वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए ।
  - (ज) इसके अतिरिक्त वास्तविक अंतर और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के भीतर विभिन्न उत्पाद श्रृंखलाओं में प्रयोग की विविधता को ध्यान में रखते हुए याचिकादाता को विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना चाहिए तथा प्रतिस्पर्द्धा, कीमत के प्रभाव के साथ-साथ क्षति और कारणात्मक संबंध का पृथक रूप से विश्लेषण करना चाहिए ।
  - (झ) याचिका में अत्यंत गोपनीयता बनाई रखी गई है । आयात के आंकड़ों, लागत आदि से संबंधित कुछ मुख्य सूचना याचिका में नहीं दी गई है । पारदर्शिता की कमी याचिकादाता के आरोपों का खंडन करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों को दुर्बल कर सकती है ।
  - (ञ) चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के खिलाफ प्रतिकारी उपाय किए जाने से भारतीय विद्युत संयंत्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता दुर्बल होगी और इससे बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों का कल्याण क्षीण होगा ।
- (iv) प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ने जांच की शुरुआत करने से पूर्व किए गए परामर्श के दौरान कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए थे । इसके परिणाम स्वरूप प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के प्रतिकारी सहायिकी आयातों और ऐसे आयातों के कारणवश घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्रथम दृष्टया प्रमाणों से यह जांच शुरू कर दी थी । प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका और जीओसी के तर्कों पर विचार किया था और यह तय किया था कि यह पता लगाने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पादों के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकारी सहायिकी से लाभ प्राप्त हुआ था और क्या ऐसी सहायिकीकृत आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे और यदि हां, तो क्या चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क उपाय (जिसे आगे “सीवीडी” अथवा “सहायिकी

शुल्क" कहा गया है) लागू करने की सिफारिश करना यथोचित है और यदि हां, तो विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए जाने वाले ऐसी सीबीडी की मात्रा कितनी हो, प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की जांच की शुरुआत की थी।

- (v) प्राधिकारी ने दिनांक 29 मई, 2014 की जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, ज्ञात चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात भारत के आयातकों/प्रयोक्ताओं, संबद्ध वस्तुओं के अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को, याचिकादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके पत्रों पर प्रेषित की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से उसे अवगत करा दें।
- (vi) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति प्रदत्त की थी।
- (vii) भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार जांच की शुरुआत करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को परामर्श दे कि वे उनको भेजी गई प्रश्नावलियों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दे दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और उनके पत्रों के साथ भी भेजी गई थी।
- (viii) प्राधिकारी ने जीओसी को प्रश्नावली भी भेजी थी ताकि ऐसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में संबद्ध तथ्यों/सूचना को प्राप्त किया जा सके जिनमें जीओसी द्वारा प्रतिकारी लाभ दिए गए हों। जीओसी ने प्रश्नावली का उत्तर भेजा है, जिसे उस सीमा तक ध्यान में रखा गया है, जितना कि वह वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है और जिसे अपनाया जा सकता है।
- (ix) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 (4) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी थी :-
- (क) वेनझाऊ केचेंग फाउंडरी कंपनी लिमिटेड, बेजिंग
  - (ख) जिआंग्सू वेनहुई स्टील इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिआंग्सू
  - (ग) शांक्सी क्यूईनचुआन मशीनरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, शांक्सी
  - (घ) डिंगझाऊ डोंगफांग फाउंडरी कंपनी लिमिटेड, हेबेई
  - (ङ) बेजिंग बेईग फाउंडरी कंपनी लिमिटेड, बेजिंग
  - (च) झेझिआंग जिआली विंड पॉवर टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड, हेंगझोऊ
- (x) हालांकि जीओसी ने अपने उत्तर में चीन में कार्टिंग के 200 उत्पादकों को अभिज्ञात किया है, लेकिन चीन से केवल एक उत्पादक/निर्यातक नामतः मेसर्ज झेझिआंग जिआली विंड पॉवर टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड ने ही प्रश्नावली का उत्तर भेजा है। चीन के अन्य किसी उत्पादक/निर्यातक ने न तो कोई सीधा उत्तर भेजा है और न ही जीओसी ने चीन में इन उत्पादकों के बारे में कोई सूचना भेजी है।
- (xi) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/आयातकों को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं :-
- (क) मेसर्ज चिरंजीवी विंड एनर्जी लिमिटेड
  - (ख) मेसर्ज गेमेसा विंड टरबाइन प्राईवेट लिमिटेड
  - (ग) मेसर्ज जी.ई. इंडिया इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
  - (घ) मेसर्ज ग्लोबल विंड पावर लिमिटेड
  - (ङ) मेसर्ज इनोक्स विंड लिमिटेड

- (च) मेसर्ज लीटविंड श्रीराम मेन्युफेक्चरिंग लिमिटेड
- (छ) मेसर्ज पाईनीर विन्कोन प्राईवेट लिमिटेड
- (ज) मेसर्ज आरआरजी एनर्जी लिमिटेड
- (झ) मेसर्ज श्रीराम ईपीआसीआई लिमिटेड
- (ञ) मेसर्ज शिवा विंड टरबाईन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- (ट) मेसर्ज साउदर्न विंड फार्मस् लिमिटेड
- (ठ) मेसर्ज विंड वर्ल्ड (इंडिया) लिमिटेड
- (ड) मेसर्ज सूजिऑन एनर्जी लिमिटेड
- (ढ) मेसर्ज इंडियन टरबाईन मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन
- (xii) निम्नलिखित आयातकों ने निर्धारित प्रपत्र में आयातकों के प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं :-
- (1) मेसर्ज पाईनीर विन्कोन प्राईवेट लिमिटेड
- (2) मेसर्ज इनोक्स विंड लिमिटेड
- (3) मेसर्ज जी.ई. इंडिया इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
- (xiii) जांच शुरू करने के बाद जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने भी निवेदन किए थे जिनकी जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक हुआ है, उनका निदान मौजूदा अंतिम निर्णय में किया गया है।
- (xiv) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया गया है, जो कि हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुली रखी गई है।
- (xv) जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के आंकड़े प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। डीजीसीआईएंडएस से उक्त सूचना प्राप्त हो गई है। प्राधिकारी ने इस निर्णय के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (xvi) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और डीजीएडी में संगत क्रिया-विधियों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर गैर-क्षति कीमत का आकलन किया गया है।
- (xvii) प्राधिकारी द्वारा जितनी आवश्यक समझा गया था, याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की गई है। जहां कहीं भी लागू होता है, वहां आवश्यक आशोधन सहित केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही उसके द्वारा विश्वास किया गया है।
- (xviii) प्राधिकारी ने चीन सरकार से अनुरोध किया था कि वह अपनी इच्छा के बारे में सूचित करे अन्यथा चीन सरकार और चीन के प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों उत्तर/प्रमाणों की मौके पर जांच करे। तथापि, चीन सरकार से निरंतर अनुरोध करने के बाद भी चीन सरकार और चीन के केवल एक प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों/प्रमाणों और किए गए दावों की मौके पर जांच इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि चीन ने न ही ऐसी जांच किए जाने पर सहमति प्रकट की थी और न ही प्राधिकारी को चीन का दौरा करने की आवश्यक अनुमति दी थी ताकि वह वहां जा कर मौके पर जांच कर सकें। परिणामस्वरूप चीन के ऐसे असहयोग के कारण अधिकारी को नियमावली के अनुसार उपलब्ध उत्तम जानकारी पर ही विश्वास करना पड़ा है।
- (xix) जीओसी और चीन के अकेले उत्पादक/निर्यातक, मेसर्ज जिआली विंड के प्रश्नावली के उत्तर की विस्तृत जांच की गई थी। यह आवश्यक और उपयुक्त समझा गया था कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों और प्रस्तुत की गई सूचना के बारे में और स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी उपयुक्त समझा गया था कि जीओसी और प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को प्रश्नावली के उत्तरों में पाई गई कमियों को दूर करने का और अवसर प्रदान किया जाए। जीओसी और

प्रतिवादी निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा बाद में प्रेषित की गई प्रश्नावलियों के पूरक उत्तर भेजे थे। तथापि, यह नोट किया गया कि जीओसी और प्रतिवादी निर्यातक ने ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत नहीं की थी जिनके लिए प्राधिकारी ने उनसे अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त जीओसी और मेसर्स जिआली विंड द्वारा भेजी गई सूचना/आंकड़ों की सत्यता और संपुष्टि प्राधिकारी द्वारा जीओसी के असहयोगी रवैये के कारण मौके पर नहीं की जा सकी। प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की गई है। ऐसी सूचना जो कि प्राकृतिक रूप से गोपनीय है अथवा जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उनके अगोपनीय वृत्तान्त के साथ प्रस्तुत किया गया है, को गोपनीय माना गया है।

- (xx) जहां कहीं भी संभव हुआ है वहां पक्षकारों ने गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें और उसे प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुसार सार्वजनिक फाईल पर रखा गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जब कभी भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में रिकार्ड किया है।
- (xxi) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2012 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2013 (वार्षिकीकृत 15 महीनों के लिए) तक की है। तथापि, क्षति की जांच अवधि को 1 अप्रैल, 2009 से लेकर जांच अवधि की समाप्ति तक माना गया है, अर्थात् इसमें वर्ष 2010 – 11, 2011 – 12, 2012-13 और जांच अवधि (पीओआई) भी शामिल है।
- (xxii) नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 22 जुलाई, 2015 और अगस्त, 2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में अपने प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत करें।
- (xxiii) नियमावली के नियम 18 के अनुसार जांच के अत्यावश्यक तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 17 नवंबर, 2015 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट कर दिया गया है और जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के साथ उन पर प्रस्तुत की गई टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने जाने पर उनका निदान इस अंतिम निर्णय में कर दिया गया है।
- (xxiv) इस अंतिम निर्णय में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\*सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
- (xxv) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 15 मई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 354/84/2015-टीआरयू के अंतर्गत जांच को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है और इसका अंतिम जांच परिणाम 28 नवंबर, 2015 तक जारी करने को कहा है।
- (xxvi) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 58.05 रूपए है।

#### ग. चीन सरकार द्वारा सहयोग का स्तर

6. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार (जीओसी) को विभिन्न आरोपितसहायिकी योजनाओं, उनके अंतर्गत चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदत्त लाभों तथा सहायिकी करार की तुलना में उसके प्रति संतुलन क्षमता से संबंधित विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने कमियां निर्दिष्ट करने के पत्रों के माध्यम से और अन्यथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी चीन सरकार ने न तो पूरी सूचना प्रस्तुत की है और न ही प्राधिकारी द्वारा मौके पर जांच करने के अनुरोध पर सहमति प्रकट की है। चीन सरकार ने प्राधिकारी को चीन के अकेले प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना की मौके पर जांच करने के लिए चीन का दौरा करने की भी अनुमति नहीं दी है। यदि चीन सरकार ने सहयोग दिया होता और उनकी सूचना/आंकड़ों के रिकार्ड की तथा चीन के अकेले प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक की मौके पर जांच करने करने की अनुमति दी होती तो प्राधिकारी इस तथ्य की संपुष्टि करने की बेहतर स्थिति में होता कि क्या आरोपित कार्यक्रम विद्यमान है, क्या आरोपित कार्यक्रमों में लिफ्ट एसओई सरकारी निकाय है और क्या आरोपित कार्यक्रम नियमों के अंतर्गत प्रतिकारी हैं। चूंकि चीन सरकार ने अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी को अन्य उपलब्ध उत्तम सूचना को देखना और उस पर विश्वास करना पड़ा है।

**घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र****घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद, “वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं, की कास्टिंग्स” है। वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों की कास्टिंग्स को “विंडमिल” अथवा “विंड टरबाइन” के रूप में भी जाना जाता है।
- (2) “विंडमिल” में अनेक कास्टिंग पुर्जे शामिल होते हैं, जैसे कि -
  - (क) हब, रोटोहब, रोटार नोब,
  - (ख) मुख्य फ्रेम, बेस फ्रेम, मुख्य फाउण्डेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउण्डेशन,
  - (ग) बियरिंग हाउसिंग, बीयरिंग सपोर्ट,
  - (घ) होलो शैफ्ट
  - (ङ) मुख्य एक्सिल, रोटार शैफ्ट, मुख्य शैफ्ट, रोटार कपलिंग, एक्सिल पिन,
  - (च) लेटरल सस्पेंडर,
  - (छ) पिच स्टॉप, स्टेटर,
  - (ज) जेनरेटर कास्टिंग्स, जेनरेटर के पार्ट, रोटार,
  - (झ) टर्क्यू आर्म सपोर्ट, गियर बॉक्स।
- (3) उत्पाद के कार्य क्षेत्र में शामिल केवल विंड टरबाइन ही विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल है। यदि ऐसी कास्टिंग को उसके कच्चे/बिना तैयार की गई/तैयार की गई रूप में अथवा उपस्करों की सब-असेम्बली के भाग के रूप में आयात किया जाता है तो वह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्राधिकार के भीतर आती है। सब-असेम्बली के मामले में याचिकादाता ने समग्र सब-असेम्बली पर सहायिकी-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध नहीं किया है। याचिकादाता ने सब-असेम्बली के कास्टिंग भाग पर सीवीडी लगाने का अनुरोध किया है।
- (4) विंड टरबाइन में कास्टिंग का मुख्य कार्य, विंड मिल में अन्य गैर-कास्टिंग पुर्जों और संघटकों जैसे कि ब्लेड्स आदि का प्रयोग करना होता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत की उत्पत्ति होती है।
- (5) हालांकि विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क के उप-शीर्ष संख्या 8503 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, इनका आयात, अध्याय 84 और 85 में अन्य टैरिफ शीर्षों जैसे कि 84834000, 85030090, 85030010 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र ही है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- (6) याचिकादाता द्वारा निर्मित की जाने वाली और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। याचिकादाता द्वारा निर्मित की जाने वाली और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की उनके विशेष लक्षणों के कारण तुलनीय हैं, जैसे कि भौतिक और रसायनिक लक्षण, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण। नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जाने वाली और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं एक समान वस्तुएं हैं।
- (7) “वायु से संचालित विद्युत के जेनरेटर (डब्ल्यूआईईजी)” एक “विंड मिल” है और इसलिए “वायु से संचालित विद्युत के जेनरेटरों” के लिए कास्टिंग का तात्पर्य “विंड मिल” अथवा “विंड टरबाइन” की कास्टिंग से ही है।

- (8) अकेले प्रतिवादी निर्यातक मेसर्स जिआली विंड ने निवेदन किया है कि कंपनी द्वारा गृह बाजार में बेची जाने वाली और भारत को निर्यातित वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से एक समान हैं। मेसर्स जिआली विंड ने यह भी निवेदन किया है कि कंपनी द्वारा गृह बाजार में बेची जाने वाली और भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित वस्तुओं में उनके भौतिक और तकनीकी लक्षणों में कोई अंतर नहीं है।

#### घ. 2. चीन सरकार द्वारा किए गए निवेदन

8. जांच शुरू करने के बाद चीन सरकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया गया है

#### घ. 3. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

9. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
- (1) विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक व्यापक हैं और इन्हें गलत वर्णीत किया गया है। इसे सरल किए जाने और बिना किसी संदिग्धता के स्पष्ट वर्णीत किए जाने की आवश्यकता है। परिभाषा के अनुसार कास्टिंग का अभिप्राय सांचे द्वारा निर्मित की गई एकल वस्तु से है। कास्टिंग कभी भी उप-संग्रहित रूप में नहीं हो सकती है।
  - (2) जैसा कि प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत में वर्णीत किया गया है, विचाराधीन उत्पाद केवल वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए प्रयुक्त होने वाली कास्टिंग से ही है। इस प्रकार किसी अन्य प्रकार की कास्टिंग जिसका प्रयोग विद्युत जेनरेटरों के लिए नहीं किया जाता है, संबद्ध जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है।
  - (3) ऐसे उत्पाद जो कास्टिंग नहीं हैं और उत्पाद किस्म के हैं और जिनका आयात भारत में नहीं होता है अथवा जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं, उनको संबद्ध जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
  - (4) यह आवश्यक नहीं है कि उप-संग्रहित कलपुर्जों पर दिए जाने वाले लाभ को अंतिम उत्पाद में शामिल किया जाएगा। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि कास्टिंग्स के विनिर्माताओं द्वारा सहायिकी का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए किया गया है, ऐसे निचले स्तर के उत्पादों को सीवीडी की जांच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए प्राधिकारी को उप-संग्रहित रूप में कास्टिंग्स को, वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के एक उप-संग्रहित अथवा एक कलपुर्जे के रूप में संबद्ध जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए।

#### घ. 4. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद का तात्पर्य और उसके कार्य-क्षेत्र को जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“5. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद, “वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं, की कास्टिंग्स” है। किसी विंड मिल में अनेक कलपुर्जों की आवश्यकता होती है, जैसे कि - हब, रोटोहब, रोटर नोब, मुख्य फ्रेम, बेस फ्रेम, मुख्य फाउण्डेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउण्डेशन, बियरिंग हाउसिंग, बीयरिंग सपोर्ट, होलो शैफ्ट, मुख्य एक्सिल, रोटर शैफ्ट, मुख्य शैफ्ट, रोटर कपलिंग, एक्सिल पिन, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटर कास्टिंग्स, जेनरेटर के पार्ट, रोटर, टर्ब्यू आर्म सपोर्ट और गियर बॉक्स आदि। किसी विंड टरबाइन में कास्टिंग का मुख्य कार्य विंड मिल में कुछेक अन्यकल पुर्जों और संघटकों जैसे कि ब्लेड आदि के साथ उसकी प्रयुक्ति होती है जिसके फलस्वरूप विद्युत की उत्पत्ति होती है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क के उप-शीर्ष संख्या 8503 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का कोई कटिबद्ध सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। तथापि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र ही है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

11. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रेक्षण निम्नानुसार हैं :-

- (1) जैसा कि जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद, वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं, की कास्टिंग्स” है। विचाराधीन उत्पाद को संग्रहित रूप से वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों की कास्टिंग्स (डब्ल्यूओईजी) भी कहा गया है।



- (2) किसी विंड टरबाइन में कास्टिंग का मुख्य कार्य विंड मिल में कुछेक अन्य कल पुर्जों और संघटकों जैसे कि ब्लेड आदि के साथ उसकी प्रयुक्ति होती है जिसके फलस्वरूप विद्युत की उत्पत्ति होती है।
- (3) विचाराधीन उत्पाद, वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए कास्टिंग (डब्ल्यूओईजी) है, जिसे मुख्यतया विंड मिल के रूप में भी जाना जाता है। विंड मिल एक ऐसी मिल होती है जो कि वायु ऊर्जा को घूमने वाले ब्लेडों के माध्यम से यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करती है जो कि टरबाइन को इस तरह से चलाती है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। एक विंड मिल में अनेक प्रकार की कास्टिंग और गैर-कास्टिंग कलपुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फाईबर ग्लास से निर्मित ब्लेड्स, स्टील के ढांचों से निर्मित टॉवर आदि।
- (4) विंड मिल में कास्टिंग के अनेक कलपुर्जे प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जैसे कि - हब, रोटोहब, रोटर नोब, मुख्य फ्रेम, बेस फ्रेम, मुख्य फाउण्डेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउण्डेशन, बियरिंग हाउसिंग, बीयरिंग सपोर्ट, होलो शैफ्ट, मुख्य एक्सिल, रोटर शैफ्ट, मुख्य शैफ्ट, रोटर कपलिंग, एक्सिल पिन, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटर कास्टिंग्स, जेनरेटर के पार्ट, रोटर, टर्क्यू आर्म सपोर्ट और गियर बॉक्स आदि।
- (5) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत उप-शीर्ष 8503 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा सूचित किया गया है और डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आयात के विश्वसनीय आंकड़ों से परिलक्षित होता है, विचाराधीन उत्पाद का आयात, विभिन्न अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र ही है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र, विंड मिल में प्रयुक्त जेनरेटर में केवल कास्टिंग के संदर्भ में ही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में कम से कम तीन प्रोद्योगिकियां प्रचलन में हैं - (क) विंड मिल, (ख) विंड टरबाइन और (ग) वायु संचालित विद्युत जेनरेटर। ये समस्त नामावलियां एक ही हैं और इनका अभिप्राय वायु की गति से संचालित शक्ति से विद्युत उत्पन्न करने से है। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 21/2014 में इसे "वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों के विनिर्माण करने में प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जों और कच्चे माल" के रूप में संदर्भित किया गया है। इससे इस तथ्य की भी संपुष्टि होती है कि जब इसे "वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों" के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका वास्तविक तात्पर्य विंड मिल से होता है। इस प्रकार अधिकारी नोट करते हैं कि विंड मिल, विंड टरबाइन और वायु से संचालित विद्युत जेनरेटर (डब्ल्यूओईजी) का अभिप्राय एक ही उत्पाद से है और डब्ल्यूओईजी की कास्टिंग्स, विंड मिल के लिए कास्टिंग अथवा विंड टरबाइन के लिए कास्टिंग के सिवाए और कुछ नहीं है।
- (6) प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में निहित मुख्य उत्पादन की प्रक्रिया, कच्चे कास्टिंग का उत्पादन करने की है। जैसे ही कच्ची कास्टिंग बना ली जाती है, उसे बहुताधिक मशीनी प्रचालनों से गुजरना पड़ता है। ऐसे मशीनी प्रचालनों को उत्पादकों द्वारा स्वयं निष्पादित किया जाता है अथवा अकेली ऐसी पार्टियों द्वारा किया जाता है जो कि (चीन अथवा भारत में) विनिर्माण प्रचालनों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं अथवा अंत प्रयोक्ताओं द्वारा स्वयं निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विंड मिल में संग्रहीत रूप से अनेक कास्टिंग्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछेक कास्टिंग्स को उप-संग्रहण (सब-असेम्बली) तैयार करने के लिए अन्य उत्पादों के साथ संघटित किया जाता है। अंततः एक विंडमिल में ऐसे अनेक उप-संग्रहण शामिल होते हैं। इसलिए अंतिम उपभोक्ता के पास यह विकल्प होता है कि वह विचाराधीन उत्पाद की खरीदारी उसके उत्पादन के किसी भी चरण में अथवा एक उप-संग्रहण के भाग के रूप में कर सकता है।
- (7) विंड मिल में प्रयुक्त होने वाले कुछेक उप-संग्रहण में गियर बॉक्स, नेसिल्ले असेम्बली और हब पिच असेम्बली शामिल है। ऐसे उप-संग्रहणों में कास्टिंग्स और अन्य संघटक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए नेसिल्ले असेम्बली में बेस फ्रेम, प्लेनेट कैरियर निहित गियर बॉक्स, हाउसिंग्स, टर्क्यू आर्म और रोबर हब/हब युक्त हब असेम्बली और पिच प्रणाली शामिल होती है। इसलिए उपभोक्ता स्वतंत्र होता है कि वह कास्टिंग खरीदे अथवा अन्य समान कलपुर्जों को पृथक् रूप से खरीदे तथा उन्हें अपने निजी स्थान पर संघटित करे अथवा उसके बजाय उप-संग्रहित उत्पाद को खरीदे।

- (8) सब-असेम्बली को तैयार करने में निहित प्रचालनों में पेचकस (स्कू) से संचालित प्रोद्योगिकी शामिल होती है और इसके लिए समग्र प्रचालनों के अनुपात में तुच्छ प्रयास ही करते पड़ते हैं। इसलिए किसी अंत प्रयोक्ता के लिए यह नितांत संभव है कि वह कास्टिंग और अन्य उत्पादों को पृथक् रूप से खरीदने के बजाय उप-संग्रहीत उत्पादों को ही खरीदे। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र में उप-संग्रहण को शामिल नहीं किया जाता है, तो व्यापार की रक्षा करने के लिए किए जाने वाले किसी भी उपाय का प्रयोजन ही निरर्थक हो जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को महज इसलिए उप-संग्रहण तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि यह उपायों के कार्य-क्षेत्र के भीतर कास्टिंग्स को शामिल करता है। इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि जहां तक यदि कोई सीवीडी उपाय करने का क्षेत्र-अधिकार है तो विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर उप-संग्रहण पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा जो कि उप-संग्रहण के कास्टिंग्स भाग तक ही सीमित होगा।
- (9) सब-असेम्बली को शामिल करने के प्रयोजन से यह उपयुक्त होगा कि ऐसी कास्टिंग्स पर भी जिनका आयात विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर एक उपस्कर/संघटक के एक भाग के रूप में किया जाता है, तब तक विचार किया जाए जब तक कि उपायों का कार्य-क्षेत्र, विंड मिलों अथवा विंड टरबाईनों अथवा वायु संचालित विद्युत के जेनरेटरों के लिए इन उपस्करों में प्रयुक्त होने वाले कास्टिंग के भाग तक सीमित रहता है।
- (10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह समझते हैं कि जांच शुरूआत करने संबंधी नोटिस में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र उपयुक्त है तथा यह अंतिम निर्धारण के लिए विचारार्थ उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित करता है :-

“वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए कास्टिंग्स को विंड मिल अथवा विंड टरबाईन के लिए कास्टिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं।”

#### घ. 5. समान वस्तुएं

12. विश्व व्यापार संगठन के सहायिकी और प्रतिकारी उपायों संबंधी करार में समान उत्पाद का निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

“{ “समान उत्पाद” का तात्पर्य ऐसे उत्पाद से है जो कि विचाराधीन उत्पाद के सभी पहलुओं में समान दिखता हो अथवा ऐसा उत्पाद नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य उत्पाद से है जो कि उसके सभी पहलुओं के अनुरूप समान नहीं दिखता है, लेकिन उसमें वे सभी लक्षण समान रूप से विद्यमान हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद में निहित हैं। ”

13. प्राधिकारी द्वारा समान वस्तु के संबंध में किए गए प्रेक्षण निम्नानुसार हैं :-

- (1) मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद, वायु से संचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए कास्टिंग्स को विंड मिल अथवा विंड टरबाईन के लिए कास्टिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, चाहे वे मशीन के हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा अर्ध-निर्मित की स्थिति में हैं अथवा अर्ध-निर्मित रूप में हैं अथवा वायु संचालित विद्युत जेनरेटरों के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में हैं।
- (2) विंड मिल में कास्टिंग के अनेक कलपुर्जे प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जैसे कि - हब, रोटोहब, रोटार नोब, मुख्य फ्रेम, बेस फ्रेम, मुख्य फाउण्डेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउण्डेशन, बियरिंग हाउसिंग, बीयरिंग सपोर्ट, होलो शैफ्ट, मुख्य एक्सिल, रोटार शैफ्ट, मुख्य शैफ्ट, रोटार कपलिंग, एक्सिल पिन, लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप, स्टेटर, जेनरेटर कास्टिंग्स, जेनरेटर के पार्ट, रोटार, टर्क्यू आर्म सपोर्ट आदि।
- (3) मिलों के ऊपर विभिन्न स्थलों पर विंड मिल में विंड कास्टिंग्स के विभिन्न कलपुर्जों को प्रयुक्त किया जाता है। एक ही प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न कलपुर्जों का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए एक जैसे कच्चे माल का ही प्रयोग किया जाता है और ये आकार, रूप, डिजाइन और प्रयुक्त मशीनिंग में अनिवार्य रूप से भिन्न दिखाई देते हैं, जो कि ऐसे स्थान पर निर्भर करता है, जहां इनका अंततः प्रयोग किया जाना होता है। इसलिए कास्टिंग्स के विभिन्न कलपुर्जों, कास्टिंग्स की सामान्य श्रेणी में ही आते हैं। कास्टिंग बहुत व्यापक शब्दावली है और

विभिन्न प्रयोजनार्थ अनेक प्रकार की कास्टिंग्स का उत्पादन किया जाता है। तथापि, मौजूदा जांच केवल डब्ल्यूओईजी के निमित्त कास्टिंग तक ही सीमित है। चूंकि विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स का पारस्परिक रूप से परिवर्तनीय रूप में उत्पादन किया जाता है और ये आकार, रूप, डिजायन और प्रयुक्त मशीनिंग में अनिवार्य रूप से भिन्न दिखाई देती हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स को मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ एक समान वस्तु बनती है। तथापि, ऐसा माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स का उत्पादन, विभिन्न अंत अनुप्रयोग के लिए किया जाता है तथा ये कास्टिंग्स उनकी संबद्ध लागतों और कीमतों की दृष्टि से अत्यधिक भिन्न हो सकती हैं। इसलिए आयातित उत्पाद की कीमत की तुलना, विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स की भारित औसत के आधार पर घरेलू उद्योग/एनआईपी से करना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए प्राधिकारी ने एक आदर्श समान मानदंड बनाया है, ताकि घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि इसका आगे विस्तार से उल्लेख किया गया है।

- (4) प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को विंड मिल में विभिन्न अंत अनुप्रयोगों के लिए निर्मित विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स के अनुरूप व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए सभी संघटकों में से हब विंड टरबाइन का सबसे भारी संघटक है जिसका भार 2 मेगा वाट टरबाइन के लिए 8 से 10 टन तक होता है। हब को ऐसे निर्मित किया जाता है और उसका ऐसा डिजायन बनाया जाता है ताकि वह सख्त हो, लेकिन साथ ही उसमें उच्च स्तर की कंपन को सहने की शक्ति निहित हो। जबकि रोटार नेव ऐसा संघटक है, जो कि रोटार ब्लेडों की सहायता से विंड में ऊर्जा को रोटरी यांत्रिकी चलन में परिवर्तित करता है। इसके अतिरिक्त बेस फ्रेम का प्रयोग, ब्लेडों को आधार देने अथवा जिस पर ब्लेड लगाए गए हैं, उसको आधार देने के लिए किया जाता है। इस उद्योग में निर्मित और बेचे जाने वाली विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स की सूची उनकी अंत अनुप्रयोगों के साथ नीचे दी गई है :-

क्रमांक	कास्टिंग की किस्म	अनुप्रयोग
1.	क - हब, रोटोहब, रोटार नोब	ये तीनों ब्लेडों को जोड़ते हैं और गियर बॉक्स को चक्रीय गति प्रदान करते हैं। हब को भी मशीन की पिच यांत्रिकी के साथ जोड़ा जाता है।
2.	ख - मुख्य फ्रेम, बेस फ्रेम, मुख्य फाउण्डेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउण्डेशन	इसे टॉवर के ऊपर लगाया जाता है और यह हब, रोटार शैफ्ट, गियर बॉक्स, जेनरेटर, नेसिल्ले कवर और अन्य छोटे संघटकों को स्पोर्ट करता है। फ्रेमसिआ जॉस को भी मशीन की यांत्रिकी के साथ जोड़ा जाता है।
3.	ग - बियरिंग हाउसिंग फ्रंट और रियर बियरिंग सपोर्ट सहित और रहित	बियरिंग हाउसिंग में बियरिंग को स्थापित किया जाता और यह रोटार शैफ्ट को स्पोर्ट करता है जो कि बियरिंग हाउसिंग में घूमती है।
4.	घ - होलो शैफ्ट	होलो शैफ्ट में मुख्य एक्सिल अथवा रोटार शैफ्ट को स्थापित किया जाता है और इस डिजायन में शैफ्ट स्थिर रहती है तथा होलो शैफ्ट हब को जेनरेटर के साथ जोड़ती है।
5.	ड- मुख्य एक्सिल, रोटार शैफ्ट, रोटार कपलिंग, एक्सिल पिन और मुख्य शैफ्ट (जिसे बार-	मुख्य एक्सिल मुख्य फ्रेम के साथ लगाई जाती है और यह हब, अन्य स्थिर और घूमने वाले कल पुर्जों के वजन का वहन करती है।

	बार कुटित किया जा सकता है)	
6.	च - लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप	लेटरल सस्पेंडर मुख्य फ्रेम पर लंबित रहता है। पिच स्टॉप पिचिंग यांत्रिकी के लिए होता है।
7.	छ - स्टेटर, कास्टिंग्स, जेनरेटर के पार्ट और रोटर	स्टेटर और रोटोर्स जेनरेटर के भाग हैं।
8.	ज - टर्क्यू आर्म सपोर्ट और रियर फ्रेम	टर्क्यू आर्म और सपोर्ट गियर बॉक्स को उसके स्थान पर कायम रखने के निमित्त होते हैं।
9.	झ - अन्य	इन पर कहीं भी विचार नहीं किया गया है।

- (5) यह नोट किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की कास्टिंग्स, संबद्ध लागत और कीमत की दृष्टि से भिन्न होती हैं और इसलिए कास्टिंग्स की किस्म को तुलना के प्रयोजनार्थ एक प्राचल माना गया है। इसके अतिरिक्त उत्पाद को अपरिष्कृत रूप में अथवा मशीनी रूप में बेचा जा सकता है। उत्पाद के अपरिष्कृत अथवा मशीनी रूप में विशेष अंतर को ध्यान में रखते हुए इस कारक को उचित कीमत की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी ने उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिए निम्नोक्त आदर्श उपयुक्त मानदंड बनाया है :-

**पीसीएन शब्दावली – डब्ल्यूओईजी के लिए कास्टिंग्स**

क्षेत्रीय विवरण	एसएन	कास्टिंग की किस्म
उत्पाद की किस्म	जेड	क - हब, रोटोहब, रोटर नोब
		ख - मुख्य फ्रेम, बेस फ्रेम, मुख्य फाउण्डेशन, नेसिल्ले, नेसिल्ले फ्रेम, नेसिल्ले फाउण्डेशन
		ग - बियरिंग हाउसिंग फ्रंट और रियर बियरिंग सपोर्ट सहित और रहित
		घ - होलो शैफ्ट
		ङ- मुख्य एक्सिल, रोटर शैफ्ट, रोटर कपलिंग, एक्सिल पिन और मुख्य शैफ्ट (जिसे बार-बार कुटित किया जा सकता है)
		च - लेटरल सस्पेंडर, पिच स्टॉप

		छ - स्टेटर, कास्टिंग्स, जेनरेटर के पार्ट और रोटर
		ज - टर्क्यू आर्म सपोर्ट और रियर फ्रेम
		झ - अन्य
प्रसंस्करण	एक्स	एम = मेकेनिकल सी = कास्ट के रूप में
क्षमता	वाई	निम्नोक्त तालिका के अनुसार

क्षमता (किलोवाट में)		पीसीएन
100	299	क
300	499	ख
500	699	ग
700	899	घ
900	999	ङ
1000	1000	च
1001	1199	छ
1200	1399	ज
1400	1599	झ
1600	1799	ञ
1800	1999	ट
2000	2000	ठ
2001	2099	ड
2100	2100	ढ
2101	2299	रा
2300	2499	त

2500	2699	थ
2700	2899	द
2900	3099	ध
3100	3299	ण
3300 के अधिक		प

- (6) याचिकादाता ने दावा किया है कि वस्तुओं का उत्पादन, उपभोक्ता/क्रेता द्वारा की गई मांगों और दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार किया जाता है और इसलिए घरेलू उद्योग और चीन के आपूर्ति कर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं, ग्राहकों द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशनों के अनुरूप होती हैं। याचिकादाता के इस दावे का हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खंडन नहीं किया गया है।
- (7) उत्पाद की बिक्री मुख्यतया अद्वय/संख्याओं में की जाती है। उत्पाद की कीमत डिजायन, आकार, भार और विशेष प्रकार की कास्टिंग के लिए निहित प्रसंस्करण प्रक्रिया पर निर्भर करती है। दो भिन्न विंड मिलों की हब जैसी प्रकृति की दो कास्टिंग्स, संबद्ध भार, डिजायन, मशीनिंग और निहित प्रसंस्करण प्रक्रिया के कारण एक समान नहीं हो सकती हैं। इसलिए ऐसी दोनों किस्मों में लागत और कीमत की दृष्टि से अत्यधिक भिन्नता हो सकती है।
- (8) चीन के अकेले प्रतिवादी निर्यातक ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मदों के तुलनीय हो सकती हैं। तथापि, कुछेक उपभोक्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं, चीन से आयातित वस्तुओं से उनकी गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न हैं।
- (9) प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि गुणवत्ता में अंतर व्याप्त है, इसकी अवधारणा एक उपभोक्ता द्वारा की गई है। नियमावली स्वतः ऐसी स्थिति को मान्यता देती है, जहां घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं सभी तरह से समान नहीं हो सकती हैं और इससे प्राधिकारी को ऐसा मौका मिलता है जिससे वह किसी अन्य वस्तु पर उन परिस्थितियों में विचार करे, हालांकि ऐसी वस्तुएं विचाराधीन उत्पाद के सभी पहलुओं में एक समान नहीं हो सकती हैं और उनके लक्षण, विचाराधीन उत्पाद के लक्षणों की ही तरह होते हैं।
- (10) घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की स्वीकार्यता का खंडन करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस तथ्य की संतुष्टि होती हो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं, हालांकि सभी पहलुओं की दृष्टि से विचाराधीन उत्पाद के ही समान नहीं हो सकती हैं, फिर भी उनके लक्षण ऐसे होते हैं कि वे विचाराधीन उत्पाद के समान ही दिखती हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और आपूर्ति की गई वस्तुओं की स्वीकार्यता पर किए गए निवेदन एक दूसरे से अत्यधिक विपरीत हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उसने विगत अनेक वर्षों से भारत और विदेशों में घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रतिवाद करने वाले हितबद्ध पक्षकार सहित अनेक उपभोक्ताओं के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया है और आपूर्ति की है और ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को अस्वीकार किया गया हो। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उपभोक्ता ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दे को उठाया है जबकि वास्तविक मुद्दा उपभोक्ता को कम कीमत के आयात प्राप्त होना है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि तथ्य तो यह है कि एक उपभोक्ता की प्रवृत्ति आयातों की अपेक्षा घरेलू उद्योग के उत्पाद के प्रति अत्यधिक बड़ी है जो कि इस तथ्य की और संपुष्टि करता है कि घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद के प्रतिस्थापन करने योग्य हैं।
- (11) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग, विगत अनेक वर्षों से विचाराधीन उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और उसे भारत और विदेशों दोनों में बेच रहा है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ऐसा पता चलता हो कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं विफल रही हों। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकारी की ऐसी धारणा है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से चीन से आयातित की जा रही वस्तुओं से तुलनीय हैं। तकनीकी और वाणिज्यिकीय रूप से दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापन करने योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को पारस्परिक रूप से बदलने के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले कुछ

उपभोक्ताओं इनको घरेलू उद्योग से भी खरीदा है । इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई और चीन से आयातित वस्तुओं का समान प्रयोजन है और ये समान रूप से ही कार्य करती है ।

- (12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी की यह धारणा है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं नियमावली के अनुसार चीन से आयातित विचाराधीन उत्पाद के ही समान हैं ।
- (13) उत्पाद डिजायन और मॉडल विशिष्ट है जो कि विंड मिल उत्पादकों के डिजायन और क्षमता पर निर्भर करता है । तथापि, घरेलू उत्पादक और निर्यातक दोनों ही भारत में उसी विंड मिल को आपूर्ति करते हैं ।

## **इ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और उसकी अवस्थिति**

### **इ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

14. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी अवस्थिति के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) मौजूदा याचिका मेसर्स लार्सन एंड ट्यूब्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50 % से भी अधिक बनता है । मेसर्स पटेल एल्वॉयज स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है ।
- (2) याचिकादाता भारत में संबद्ध वस्तुओं का पात्र उत्पादक है । याचिकादाता का उत्पादन, भारतीय उत्पादन में प्रमुख अंश बनता है । इसलिए याचिकादाता घरेलू उद्योग बनता है और वह नियमावली के अंतर्गत अवस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

### **इ.2. चीन सरकार द्वारा किए गए निवेदन**

15. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी अवस्थिति के बारे में चीन सरकार द्वारा कोई प्रासंगिक निवेदन नहीं किया है ।

### **इ. 3. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

16. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी अवस्थिति के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिका के साथ मेसर्स पटेल एल्वॉयज स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का कोई समर्थन पत्र संलग्न नहीं किया गया है ।
- (2) याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में अनेक अन्य उत्पादक हैं । तथापि, न तो उनकी सही संख्या निर्दिष्ट की गई है और न ही उनकी संख्या का कोई अनुमान संलग्न किया गया है ।
- (3) याचिकादाता ने आंकड़ों के दो सेट प्रस्तुत किए हैं - एक मूल याचिका के साथ और दूसरा अद्यतन याचिका के साथ । याचिकादाता प्रस्तुत की गई मूल याचिका में अन्य उत्पादकों का उत्पादन, अक्टूबर, 2012 से सितंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान 2500 एमटी होने का अनुमान लगाया गया है । तथापि, अद्यतन और अक्टूबर, 2012 से दिसंबर, 2013 तक की संवर्धित अवधि के लिए याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए संलग्न अनुबंध में उत्पादन में अधिक वृद्धि होने के बजाय वास्तविक रूप से तेज गिरावट आई दर्शायी गई है । इससे यह समझ में नहीं आता है कि दीर्घ अवधि में जिसमें मूल याचिका में निर्दिष्ट की गई अवधि शामिल है, कैसे उत्पादन हुआ है ।

#### ड. 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्रतिकारी शुल्क नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“ (ख) घरेलू उद्योग ” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में लगे हुए हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सहायिकी वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाएगा ” ।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका मेसर्स लार्सन एंड टयूबरो लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसके बाद मेसर्स पटेल एल्वॉयज स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन पत्र की एक प्रति क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों से संबंधित सूचना के साथ प्रस्तुत की गई है। याचिकादाता का उत्पादन, संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का मुख्य भाग बनता है। याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का न तो कोई आयात किया है और न ही संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक के साथ उसका कोई संबंध है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता का मौजूदा याचिका प्रस्तुत करने की अवस्थिति में है और वह नियमावली की घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर एक घरेलू उद्योग बनता है।

#### च. गोपनीयता

##### च.1. घरेलू उद्योग के विचार

19. जांच के दौरान गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिकादाता ने केवल ऐसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है जिसकी नियमावली के अंतर्गत गोपनीयता की अनुमति दी गई है और प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली सुसंगत क्रिया-विधि के अनुसार है।
- (2) याचिकादाता ने आवेदन के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत किए हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार सूचना की ऐसी कोई विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं कर पाया है, जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है और जिसकी गोपनीयता, नियमावली के अंतर्गत यथोचित नहीं है।
- (3) चीन सरकार और संबद्ध देश के केवल एक निर्यातक ने ही उत्तर प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर अत्यधिक अपर्याप्त हैं। यहां तक कि जो सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है (जैसे कि कच्चे माल के नाम आदि), उसका भी प्रकटन नहीं किया गया है। अभिज्ञात की गई 24 स्कीमों में से चीन सरकार ने केवल 3 स्कीमों के बारे में ही उत्तर दिया है तथा निर्यातक ने केवल 2 स्कीमों के बारे में उत्तर दिया है।
- (4) निर्यात ने सूचीबद्ध सूचना भी प्रस्तुत नहीं की है।

##### च. 3. चीन सरकार/उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

20. गोपनीयता के संबंध में चीन सरकार/उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिकादाता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिका अपूर्ण है और वह सहायक प्रमाण के रूप में “पर्याप्तता और परिशुद्धता” के मानकों को पूरा नहीं करती है।
- (2) याचिकादाता ने एमएस-एक्सिल के प्रपत्र में आयात के आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति, प्रत्येक सहायिकी कार्यक्रम के विद्यमान होने के संबंध में प्रमाण, संबंधित लागू होने वाले सहायिकी कार्यक्रम के प्रमाण, इस विशेष उद्योग पर लागू होने वाले सहायिकी कार्यक्रम के प्रमाण तथा अन्य घरेलू उत्पादक के प्रमाण और उनके उत्पादन की मात्रा के स्रोत की सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
- (3) सीवीडी नियमावली के नियम 7 (7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह अधिदेश प्राप्त है कि वह एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए। याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में याचिकादाता द्वारा अत्यधिक सूचना नहीं दी गई है।



- (4) सीवीडी नियमावली के नियम 6 (2) में ऐसी अपेक्षा की गई है कि आवेदन पत्र के समर्थन में अन्य बातों के साथ-साथ सहायिकी के प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं और यदि संभव हो तो उसकी राशि भी निर्दिष्ट की जाए। याचिकादाता ने कहीं भी सहायिकी की राशि के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
- (5) इसके अतिरिक्त याचिकादाता द्वारा प्रत्येक सहायिकी कार्यक्रम के लिए कुछ मानक (बैंचमार्क) प्रयुक्त किए जाने चाहिए थे ताकि सहायिकीकरण के स्तर का पता लगाया जा सके। तथापि, याचिका में प्रयुक्त किए गए ऐसे बैंचमार्क के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. नियमावली, 1995 के नियम 8 में सूचना की गोपनीयता के बारे में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

*“8. गोपनीय सूचनाएं— (1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7) और नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) और नियम 19 के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”*

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है और जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वहां ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा ऐसी गोपनीय सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकार को प्रकट नहीं किया है।

22. जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना जो कि सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में उपलब्ध है, उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

23. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन के संबंध में कि याचिकादाता ने आयात के आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात के आंकड़ों का कारोबार-वार सार्वजनिक वृत्तान्त, सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध करा दिया गया है। तथापि, यह अधिदेश नहीं है कि घरेलू उद्योग अथवा प्राधिकारी को सार्वजनिक फाईल में ऐसे आयात के आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध करानी चाहिए जिस पर विश्वास किया गया है। प्राधिकारी ने चीन सरकार द्वारा चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को आरोपित सहायिकी कार्यक्रमों की प्रतिकारिता की प्रथम दृष्टया प्रमाणों की जांच करने और उनसे संतुष्ट होने पर ही मौजूदा जांच की शुरुआत की थी।

### छ. विविध निवेदन

#### छ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध निवेदन

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) चीन सरकार का यह तर्क कि याचिका में पर्याप्त और परिशुद्ध सूचना निहित नहीं है जिससे कि जांच की शुरुआत को यथोचित माना जा सके, निराधार है। याचिका में अन्य जांच कर्ता प्राधिकारियों के निर्णय के रूप में प्रमाण निहित हैं जिनसे ऐसा पता चलता है कि याचिकादाता द्वारा सामने प्रस्तुत की गई स्कीमों को अन्य प्राधिकारियों द्वारा भी वास्तव में प्रतिकारी प्रभाव वाला पाया गया है। इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकादाता ने कुछेक स्कीमों के विद्यमान होने के बारे में आरोप लगाया है और इन स्कीमों के प्रतिकारी प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों से इन स्कीमों के विद्यमान होने और उनके प्रतिकारी प्रभाव सिद्ध होते हैं।

- (2) याचिका में ऐसे पर्याप्त प्रमाण निहित हैं जिनसे जांच की शुरुआत करना यथोचित है। ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि निर्धारण करने के लिए आवश्यक सभी प्रमाण प्राधिकारी को प्रारंभिक चरण में ही स्वतः उपलब्ध करा दिए जाएं। विश्व व्यापार संगठन का यह सिद्ध विधिशास्त्र है कि जैसे जैसे जांच की प्रगति होती है, प्रमाण की गुणवत्ता और मात्रा में संवर्धन होता जाता है।
- (3) याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात की गई विभिन्न स्कीमों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है – (क) देश व्यापक कार्यक्रम, (ख) क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम और (ग) प्रांत विशिष्ट कार्यक्रम। यह सुविज्ञात प्रमाण है कि याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात किए गए चीन में कास्टिंग के उत्पादक, याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात की गई विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन/सहायिकी प्राप्त करने के हकदार हैं। वास्तव में याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि कास्टिंग के उत्पादक इन प्रतिकारी प्रभाव वाली सहायिकियों से लाभान्वित हुए हैं।
- (4) प्रतिवादी निर्यातक ने पूरा सहयोग नहीं दिया है - (क) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने के कार्य में लगी हुई सभी सत्वों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, (ख) निर्यातक ने विभिन्न प्रकार की स्कीमों के संबंध में केवल जांच अवधि के लिए ही सूचना को प्रतिबंधित किया है, जबकि उन स्कीमों के लिए परिसम्पतियों की उपयोगी अवधि के लिए सूचना प्रदान की जानी चाहिए थी जिनमें परिसम्पतियों की अवधि के लिए लाभ प्राप्त हो रहे हैं तथा (ग) निर्यातक ने मुख्य सूचना को प्राधिकारी से छिपा कर रखा है।
- (5) निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसकी वेबसाइट से ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी को आर्थिक सहायता (सहायिकी) प्राप्त हुई है। तथापि, निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में कहीं भी इन स्कीमों का उल्लेख नहीं किया है।
- (6) चीन सरकार ने इच्छापूर्वक कुछ स्कीमों तक ही अपने उत्तरों को सीमित रखा है और याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात की गई सभी स्कीमों के बारे में उत्तर नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त यह बताते हुए कि कुछ कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, चीन सरकार ने इसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही चीन सरकार ने यह बताया है कि इन कार्यक्रमों में कोई अवशिष्ट लाभ नहीं थे और न ही चीन सरकार ने यह बताया है कि इन कार्यक्रमों को रद्द करते समय किसी अन्य कार्यक्रम को शुरू किया गया है। चीन सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम ऐसे लाभ प्रदान करते हैं जो कि कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद भी जारी रहते हैं (जिन्हें सामान्यतया सहायिकी के अंतर्गत "अवशिष्ट लाभ" कहा जाता है)। इसके अतिरिक्त चीन सरकार ने कुछेक कार्यक्रम समाप्त किए हैं और कुछेक अन्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनके अतिरिक्त चीन सरकार ने यह भी बताया है कि इन कार्यक्रमों को वर्ष 2008 में समाप्त कर दिया गया था, जबकि अन्य जांच प्राधिकारियों ने इन कार्यक्रमों के विद्यमान होने की संपुष्टि की है तथा अन्य जांच प्राधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिकारी सहायिकी देने की संपुष्टि की है।
- (7) याचिकादाता ने ऐसे अनेक कार्यक्रमों को अभिज्ञात किया है जो कि चीन में व्यापक हैं और जो सभी उद्योगों पर लागू होते हैं। इसलिए इस सीमा तक यह आवश्यक नहीं है कि चीन में कास्टिंग के प्रत्येक उत्पादक द्वारा ऐसे लाभों से लाभान्वित होने की पुष्टि की जाए। वित्तीय अंशदान और प्रदत्त लाभों के संबंध में याचिकादाता ने विशेष रूप से संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है।
- (8) ऐसे विवरण का कोई आधार नहीं है कि अन्य न्यायिक क्षेत्र के निष्कर्ष अप्रमाणिक दावा है। अधिकतर कार्यक्रम उत्पाद से तटस्थ हैं और इसलिए ऐसा तथ्य मात्र कि ये स्कीमें विभिन्न उत्पादों से संबंधित हैं, तुच्छ है।
- (9) याचिका में इस आशय के विवरण को कि प्रमाण उपलब्ध नहीं है, "स्वतंत्र प्रमाण" के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। याचिका में पर्याप्त प्रमाण निहित हैं। इसके अतिरिक्त चीन सरकार को जांच की शुरुआत करने से पहले परामर्श करने का अवसर भी प्रदान किया गया था और इसलिए चीन सरकार के पास यह सिद्ध करने के पर्याप्त अवसर थे कि याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात की गई स्कीमें, मौजूदा मामले में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों पर लागू नहीं होती थीं।
- (10) आवेदन पत्र में निहित विषय सामग्री के संबंध में अपील निकास (एबी) के निर्णय (डब्ल्यूटी/डीएस 379/एबी/आर दिनांक 25.3.2011) का हवाला देना पूर्णतया निराकार है। एबी का निर्णय, निर्धारण करने के संबंध में है जो कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुआ था जहां जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रमाण की गुणवत्ता और मात्रा में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। एबी का संबद्ध आदेश का अनुशीलन किया जा सकता है जो कि स्पष्ट दर्शाता है कि उक्त मामले में प्राधिकारी ने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया था कि क्या यूएस डीओसी द्वारा किए गए विगत निर्धारण की तुलना में मौजूदा अवधि में वास्तविक स्थिति बनी रही थी।

- (12) विश्व व्यापार संगठन के एबी ने यह माना था कि विगत और मौजूदा निर्धारण के बीच वास्तविक स्थिति में वस्तुपरक अंतर हो सकते हैं। तथापि, मौजूदा मामले में आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए और निर्धारण के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अब उपलब्ध प्रमाणों की गुणवत्ता और मात्रा में विशेष सुधार हुआ है। याचिकादाता ने अब यह प्रदर्शित करने के काफी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि इन स्कीमों के संबंध में वास्तविक स्थिति यथावत् बनी हुई है। इसके अतिरिक्त चीन सरकार अथवा प्रतिवादी निर्यातक ने यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि वास्तविक स्थिति में वस्तुपरक परिवर्तन हुआ है (इस तर्क को छोड़ कर कि वर्ष 2008 में कुछ स्कीमों को रद्द कर दिया गया था, जो कि अन्य प्राधिकारियों द्वारा पाया गया गलत तर्क है)।
- (13) चीन सरकार ने इन कार्यक्रमों में अवशिष्ट लाभों के नहीं होने की संपुष्टि नहीं की है। इसके अतिरिक्त ऐसे दावे के बावजूद कि इन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, अन्य जांच प्राधिकारियों ने ऐसे प्रतिकारी प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के निरंतर जारी रहने की पुष्टि की है।
- (14) मौजूदा मामले में निर्यातक देश अथवा निर्यातकों पर प्रमाण का कोई अनुचित भार नहीं डाला जा रहा है। प्रथमतः यदि स्कीम को समाप्त कर दिया गया है, तो इस आशय की अधिसूचना होनी चाहिए और चीन सरकार के लिए ऐसी अधिसूचना की प्रति प्रदान करना कठिन नहीं होना चाहिए। द्वितीयक एक निर्यातक को छोड़ कर किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसलिए किसी निर्यातक पर अनुचित भार डाले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। सहयोगी निर्यातक के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अनुचित भार डाले जाने के संबंध में किसी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से चीन सरकार ने जांच प्राधिकारियों के निर्णय का हवाला, यह सिद्ध किए बिना दिया है कि मौजूदा मामले में यह तथ्यों पर कैसे लागू होता है।
- (14) यदि कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट है, तो सूचना और प्रमाण के विचाराधीन उत्पाद से सह-संबंधित होने की आवश्यकता है। यदि कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट नहीं है तो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना अथवा प्रमाण प्रदान करना विवेचनात्मक नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि “विशेष आर्थिक क्षेत्र में ( शंगाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़ कर) विदेशी निवेश से उद्यम की स्थापना (एफआईई) करने के लिए अधिमान्य कर नीतियों” संबंधी कार्यक्रम पुडोंग क्षेत्र को छोड़ कर एसईजेड क्षेत्र में स्थापित एफआईई को लाभ प्रदान करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी सूचना और प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं कि एसईजेड क्षेत्रों में अवस्थित विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक ने वास्तव में लाभ प्राप्त किए हैं। यह उपयुक्त होगा कि इस अवधारणा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए कि पुडोंग क्षेत्र को छोड़ कर किसी अन्य एसईजेड क्षेत्र में अवस्थित कंपनी लाभ की हकदार है और उसने कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त किया होगा। यह निर्यातक पर निर्भर करता है कि वह यह सिद्ध करे कि ऐसी पात्रता होने के बावजूद भी उसने ऐसा लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- (15) चीन की केवल एक कंपनी ने ही मौजूदा जांच में उत्तर प्रस्तुत किया है। याचिका द्वारा संग्रहीत सूचना से ऐसा पता चलता है कि चीन में ऐसे लगभग 50 निर्यातक विद्यमान हैं जो कि संबद्ध उत्पाद का निर्माण करते हैं। चीन सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर का अनुशीलन किया जा सकता है जिसमें एक प्रश्न चीन में विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न उत्पादकों के नामों और उनके पतों से संबंधित है। चीन सरकार द्वारा दी गई सूचना का सह-संबंध होना चाहिए जो कि यह दर्शाती है कि चीन में बड़ी संख्या में उत्पादक विद्यमान होने के बावजूद प्राधिकारी को केवल एक उत्पादक ने ही उत्तर भेजा है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता द्वारा याचिका में दी गई सूचना और प्रमाणों और उसके बाद जांच की प्रक्रिया के दौरान दी गई सूचना और प्रमाणों से ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक ने वास्तव में सहायिकी का लाभ प्राप्त किया है।
- (16) चीन सरकार का यह तर्क कि सहायिकी की जांच करने की शक्ति असीमित नहीं है और कानूनी आवश्यकता से बाहर कोई भी सूचना और प्रमाण, विश्व व्यापार संगठन के कानूनों की भावना के विपरीत होगा और इसलिए ऐसा विवरण निराधार है।
- (17) वायु संचालित विद्युत जेनरेटर (डब्ल्यूओईजी) की कास्टिंग्स के लिए आयातक इस समय चीन से सहायिकी प्राप्त कीमतों पर कास्टिंग्स का आयात कर रहे हैं, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा इसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है/किया जा सकता है। देश में ऊर्जा उद्योग का विकास करने के लिए कास्टिंग उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। अनुचित रूप से कम कीमतों के आयातों ने भारत में कास्टिंग उद्योग उद्योग को काफी क्षति पहुंचाई है और पहुंचा रहा है।
- (18) चीन के मूल की संबद्ध वस्तुओं को चीन सरकार के विभिन्न स्तरों पर दी जा रही सहायिकियों से लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसी स्कीमों को कनाडा, यूरोप, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य पाटन—रोधी प्राधिकारियों द्वारा प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली माना गया है।

- (19) पक्षकारों की विलंबित सहभागिता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इंडियन विंड टरबाईन मेन्युफेचरर्स एसोसिएशन ने एक पृष्ठ की भी सूचना प्रस्तुत किए बिना मौखिक सुनवाई में भाग लिया है। एसोसिएशन की ऐसी भागीदारी उत्तर दिए जाने की निर्धारित तारीख के एक वर्ष और 20 दिनों के बाद हुई है।
- (20) चीन सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर में अत्यधिक कमियां हैं। इसके अतिरिक्त चीन सरकार ने केवल प्रतिवादी निर्यातक के संबंध में ही उत्तर दिया है और चीन में बाकी निर्यातकों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

## छ. 2. चीन सरकार द्वारा किए गए विविध निवेदन

25. चीन सरकार द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिका में निहित प्रमाण अपर्याप्त हैं। सहायिकी और प्रतिकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन में पर्याप्त प्रमाण निहित होने चाहिए जैसे कि - (क) सहायिकी विद्यमान है और यदि संभव हो तो उसकी राशि, (ख) गॉट, 1994 के अनुच्छेद-IV में उल्लिखित परिभाषा के भीतर क्षति, जैसा कि करार में प्रतिपादित किया गया है तथा (ग) सहायिकी-प्राप्त आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध। ऐसे साधारण दावे को जो कि संबद्ध प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, एएससीएम में उल्लिखित इस प्रावधान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।
- (2) चीन-ग्रेन ओरिएन्टड फ्लेट-रोलड इलेक्ट्रिकल स्टील (यूएस) के पेनल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विद्यमान सहायिकी के प्रमाण में वित्तीय अंशदान और लाभ तथा सहायिकी की प्रकृति का प्रमाण, जिसमें यह शामिल हो कि क्या सहायिकी विशिष्ट है, निहित होना जरूरी है।
- (3) याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि कुल 44 सहायिकी कार्यक्रमों में सहायिकियों की 7 मुख्य श्रेणियां शामिल हैं। लेकिन याचिका यह अभिज्ञात करने में विफल रही है कि कौन सा सहायिकी विशिष्ट कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है और क्या ऐसे कार्यक्रम विद्यमान हैं और क्या ऐसे क्षेत्र में जिसके भीतर निर्यातक उत्पादक आते हैं, वित्तीय लाभ दिए गए हैं। याचिका में अन्य न्याय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए ऐसे निर्णयों को केवल संग्रहित अथवा संलग्न मात्र किया गया है, जिनमें अन्य औद्योगिकीय उत्पाद शामिल हैं ताकि यह परिकल्पना करते हुए कि ऐसे सभी 44 सहायिकी कार्यक्रम विद्यमान हैं, जिनसे वित्तीय अंशदान और लाभ प्राप्त होते हैं, असिद्ध दावा किया जा सके।
- (4) अन्य निर्णयों का हवाला देने मात्र की अनुमति नहीं दी जाती है। चीन से कुछ उत्पादों पर यूएस - डेफिनेटिव पाटन-रोधी और प्रतिकारी शुल्क लगाने के मामले में अपील निकाय यह बताता है कि अन्य जांच के निर्णय उचित कारण और पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं होते हैं। यह विशेषकर इस लिए होता है क्योंकि प्रत्येक एकल जांच, उसमें शामिल किए गए उत्पादों, संबंधित अवधि और लक्षित सत्वों जैसे वास्तविक मुद्दों में अन्य जांच से भिन्न होती है। मौजूदा याचिका में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्र के उद्योग के विभिन्न उत्पादों की जांच में लिए गए निर्णयों को, संबद्ध वस्तु के लिए विशेष रूप से सहायिकियों की प्रासंगिकता को अभिज्ञात किए बिना ही मात्र संग्रह के रूप में शामिल किया गया है।
- (5) कुछ सहायिकी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और इस प्रकार कोई लाभ नहीं दिए जाते हैं। रद्द किए गए कुछ कार्यक्रमों के पर्याप्त प्रमाण, प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जो कि रद्द किए गए इन कार्यक्रमों के संबंध में जांच को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
- (6) जांच प्राधिकारी को निर्यातकों पर प्रमाण का अनुचित भार नहीं डालना चाहिए। निर्यातकों को आयातक देश के किसी उद्योग द्वारा लगाए गए आरोपों को असिद्ध और खंडित करने के लिए सूचना और प्रमाण प्रस्तुत करने के अधिकार दिए जाने चाहिए।
- (7) जांच प्राधिकारी प्रस्तुत और संग्रहीत की गई समस्त सूचना और प्रमाणों का संग्रहण और विश्लेषण करने के लिए तटस्थता की स्थिति में होता है। पक्षकारों के और विचार जानने और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक और सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऐसी कोई भी सूचना अथवा प्रमाण जो कि आवश्यक नहीं है अथवा जिनका जांच किए जा रहे उत्पाद से कोई सीधा संबंध नहीं है, को देने का अनुरोध नहीं किया जाए क्योंकि ऐसी कार्रवाई न निर्यातक पर अत्यधिक भार डाल सकती है।
- (8) ऊर्जा उद्योग का विशेष कर हरित ऊर्जा उद्योग का विकास करना भारत सरकार का मुख्य कार्यक्रम है। इसलिए प्रतिकारी उपाय लागू करना देश में इस क्षेत्र के विकास के अनुकूल नहीं होगा।

**छ. 3. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध निवेदन**

26. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिका में कमी है क्योंकि इसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें निर्यातक देश में रह कर किए गए सहायिकी कार्यक्रम को भी निकाला नहीं गया है। याचिकादाता ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिससे ऐसा पता चलता हो कि भारत में आ रही संबद्ध वस्तुएं सहायिकी-प्राप्त हैं और प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली हैं। तदनुसार समग्र जांच को समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है।
- (2) याचिकादाता द्वारा याचिका में दी गई 44 स्कीमों की सूची को विधिवत् सिद्ध नहीं किया गया है। इस संबंध में याचिकादाता द्वारा किया गया निवेदन मोटे तौर पर अपर्याप्त है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- (3) प्रक्रियात्मक और स्थाई मुद्दों के कारण विश्व व्यापार संगठन के सहायिकियों और प्रतिकारी उपायों संबंधी करार - "एएससीएम" करार के अनुसार मौजूदा सहायिकी-रोधी जांच शुरू करना असंगत है।
- (4) नई सहायिकी के आरोपों को मौजूदा जांच में शामिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्राधिकारी द्वारा नई सहायिकी के आरोप को स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी ऐसे विलंबित चरण में उन नई सहायिकियों के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए।
- (5) एएससीएम करार के अनुच्छेद 1 के उप-पैराग्राफ 2 के अनुसार करार के भाग III अथवा V के अनुसार सहायिकी प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली और इस संबंध में ऐसा उल्लेख है कि -

*पैराग्राफ 1 में परिभाषित सहायिकी, भाग II में उल्लिखित प्रावधान के अध्यक्षीन होगी अथवा भाग III अथवा V के अध्यक्षीन होगी, यदि ऐसी सहायिकी अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट सहायिकी है।*

- (6) विचाराधीन उत्पाद के लिए विक्रेता का चयन करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और वैध प्रक्रिया के बाद ही विक्रेता का चयन किया जाता है। इसके फलस्वरूप यदि विक्रेता को एक बार चयनित कर लिया जाता है तो उसको बदलना बहुत आसान नहीं होता है। यह सुझाव देना पूर्णतया असंगत है कि क्रेता केवल कीमत के कारक के आधार पर ही घरेलू उत्पाद की अपेक्षा उत्पाद का आयात करना पसंद करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को मांग-पूर्ति की प्रवृत्तियों की जांच करते समय इस पहलु पर विचार करने की आवश्यकता है।
- (7) इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने याचिका के पृष्ठ 8 पर यह बताया है कि एक ही प्रकार की दो कास्टिंग्स, उनसे संबद्ध भार, डिजाइन, मशीनिंग और उनमें निहित प्रसंस्करण के कारण प्रकृति में एक समान नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार उपरोक्त निवेदनों के अनुसार ऐसा संभव है कि चीन में निर्मित एक समान आकार की कास्टिंग, भार के कारण भारतीय समान वस्तुओं की तुलना में भिन्न हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप किलोग्राम अथवा एमटी के रूप में मापन का यूनिट, घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करने के लिए सही साधन नहीं हो सकता है।
- (8) नियमावली के अनुसार मौजूदा जांच में आईडब्ल्यूटीएमए एक हितबद्ध पक्षकार है और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर उसके अधिकार को छीना नहीं किया जा सकता है। मात्र इस कारण से कि आईडब्ल्यूटीएमए ने मौखिक सुनवाई होने तक कोई निवेदन नहीं किया था, मौखिक सुनवाई के दौरान स्वयं को प्रस्तुत करने तथा मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के उसके अधिकार की छीना नहीं जा सकता है। जब प्राधिकारी ने जांच को पूरा करने के लिए स्वतः ही समय सीमा को बढ़ा दिया है और ऐसी बड़ी हुई अवधि के दौरान मौखिक सुनवाई की है, तो ऐसी स्थिति में हितबद्ध पक्षकारों के हितों को इस आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है कि जांच समय-बद्ध है,
- (9) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि और क्षति के विश्लेषण की अवधि के लिए केवल पंक्ति-वार-पंक्ति आयात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग को अपरिष्कृत आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे तथा आंकड़ों की छंटाई करने के लिए क्रिया-विधि अपनानी चाहिए थी। प्राधिकारी ने भी कारोबार-वार विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए जब तक कि कारोबार-वार आयात के आंकड़ों की जांच नहीं कर ली जाती है, तब तक आयात के सही स्तर का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- (10) वायु संचालित विद्युत जेनरेटर के लिए कास्टिंग गैर-परम्परागत, गैर-प्रदूषण युक्त और ऊर्जा का नवीकरण योग्य स्रोत है। कास्टिंग्स का प्रयोग ऐसी विंड टरबाईनों में किया जाता है, जिनका प्रयोग कुछ अन्य गैर-कास्टिंग कल

पुर्जों के साथ किया जाता है जो वायु की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करते हैं। यदि कास्टिंग पर शुल्क लगाया जाता है, तो यह विद्युत के नवीकरण योग्य और गैर-परम्परागत स्रोत को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के खिलाफ होगा। इसलिए मौजूदा जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और वायु संचालित विद्युत जेनरेटर के लिए कास्टिंग पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

- (11) अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आज देश में ऊर्जा पैदा करना उच्च प्राथमिकता है। अनेक वर्षों से भारत की कुल ऊर्जा खपत बढ़ रही है और इसे अधिकतर ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों से ही पूरा किया जाता है, जैसे कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ऊर्जा की सदैव बढ़ रही खपत से न केवल ऊर्जा पर हमारा कुल व्यय बढ़ रहा है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का हमारा शेयर भी बढ़ रहा है। इसलिए प्रतिकारी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा।

#### छ. 4. नव और गैर-नवीकरण योग्य ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा व्यक्त किए गए विचार

27. एमएनआरई द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं :-

- (1) एमएनआरई के दिशानिर्देश, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त परीक्षण और सत्यापन एजेंसियों अथवा राष्ट्रीय वायु ऊर्जा संस्थान से आईईसी और जीएल प्रणालियों की प्रमाणीकरण स्कीमों के अनुसार टाईप परीक्षित और टाईप सत्यापित विंड टरबाइन की अनुमति देते हैं। विंड टरबाइन के संघटकों को उपरोक्त परीक्षण और सत्यापन स्कीम के आवश्यक मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- (2) डब्ल्यूओईजी के कास्टिंग संघटकों की कुल मांग वर्ष 2022 तक 7,00,000 एमटी होगी जबकि उसकी तुलना में एलएंडटी और पटेल एलवाएज स्थानीय विनिर्माण क्षमता केवल 90,000 टन/वार्षिक है।
- (3) एमएनआरई ने वर्ष 2022 तक 60 गेगा वाट क्षमता की स्थापना करने का एक महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तदनुसार कास्टिंग संघटकों की मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी। तथापि, घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को अनुचित व्यापारिक पद्धतियों के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए और उनके व्यवसाय के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- (4) अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए घरेलू विनिर्माण कंपनियों के पास क्षमता है लेकिन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

#### छ. 5. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. मौजूदा जांच की शुरुआत करने के नोटिस में प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया था कि निम्नलिखित प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने योग्य सहायिकी कार्यक्रमों की जांच करने का प्रस्ताव है :-

क्रमांक	शीर्ष	कार्यक्रम संख्या	स्कीमें
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रोत्साहन और अन्य	कार्यक्रम संख्या – 1	विशेष आर्थिक क्षेत्र (शंगाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़ कर) में स्थापित विदेशी निवेश से स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
	निर्दिष्ट क्षेत्र	कार्यक्रम संख्या – 2	समुद्रतटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम संख्या – 3	शंगाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

		कार्यक्रम संख्या – 4	एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कॉर्पोरेट आय कर में छूट और/अथवा कटौती
		कार्यक्रम संख्या – 5	एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आय कर में छूट और/अथवा कटौती
		कार्यक्रम संख्या – 6	एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्री और उपस्करों पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर (वीएटी) की छूट
		कार्यक्रम संख्या – 7	कास्टिंग और फोर्जिंग प्रणाली के लिए अधिमान्य कर
2.	अनुदान	कार्यक्रम संख्या – 8	राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि
		कार्यक्रम संख्या – 9	स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन-रोधी और/अथवा स्थानीय प्रतिकारी कानूनी व्यय
		कार्यक्रम संख्या – 10	अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान
		कार्यक्रम संख्या – 11	नवीनतम प्रायोगिक उद्यम अनुदान
		कार्यक्रम संख्या – 12	सुपरस्टार उद्यम अनुदान
		कार्यक्रम संख्या – 13	ऐसे उद्यमियों को पुरस्कार जिनके उत्पाद “चीन के सुविख्यात ट्रेड्समार्क्स” अथवा “चीन के प्रसिद्ध ब्रांड” के लिए योग्य बनते हैं
		कार्यक्रम संख्या – 14	उच्च-प्रौद्योगिकी की उद्यम निवेश निधि
		कार्यक्रम संख्या – 15	मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान और विदेशी निवेश से क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना
		कार्यक्रम संख्या – 16	नवीनतम लघु और मध्यम उद्यम अनुदान
3.	ईक्रीटी कार्यक्रम	कार्यक्रम संख्या – 17	निजी स्वामित्वाधीन उद्यमों को अनुदान
		कार्यक्रम संख्या – 18	ईक्रीटी अनुप्रेरणा
4.	अधिमान्य ऋण	कार्यक्रम संख्या – 19	अदत्त लाभांश
		कार्यक्रम संख्या – 20	कास्टिंग उद्योग को अधिमान्य ऋण और व्याज दर
5.	अधिमान्य आय कर कार्यक्रम और कर प्रोत्साहन	कार्यक्रम संख्या – 21	10 वर्ष से कम अवधि के लिए प्रचालन करने के लिए निर्धारित लाभप्रद एफआईई के लिए कम की गई कर की दर

		कार्यक्रम संख्या – 22	विदेशी निवेश से निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम संख्या – 23	एफआईआई के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो कि प्रोद्योगिकी प्रोद्योगिकी प्रोत्साहन और ज्ञान प्रोत्साहन हैं ।
		कार्यक्रम संख्या – 24	एफआईआई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम संख्या – 25	एफआईआई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिनके संस्थान और अवस्थापनाएं चीन में हैं और जो देश में ही निर्मित उपस्करों की खरीद के व्यवसायिक प्रचालनों में लगे हुए हैं।
		कार्यक्रम संख्या – 26	प्रोद्योगिकी उन्नय के प्रयोजनार्थ देश में ही निर्मित उपस्करों की खरीद के व्यवसायिक प्रचालनों में लगे हुए घरेलू उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम संख्या – 27	विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईआई लाभ का पुनर्निवेश करने के लिए आय कर की वापसी ।
		कार्यक्रम संख्या – 28	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां
		कार्यक्रम संख्या – 29	केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
		कार्यक्रम संख्या – 30	देश में ही निर्मित उपस्करों की खरीद के लिए आय कर जमा
		कार्यक्रम संख्या – 31	ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो कि उच्च और नई प्रोद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं ।
		कार्यक्रम संख्या – 32	गहन स्रोत उपयोग (विशेष कच्चा माल) करने में लगे हुए उद्यमों के लिए आय कर में रियायतें ।
		कार्यक्रम संख्या – 33	विशेष उपस्कर खरीदने से संबंधित कर जमा ।
		कार्यक्रम संख्या – 34	पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीति
		कार्यक्रम संख्या – 35	योग्यता प्राप्त आवासीय उद्यमों के बीच लाभांश की छूट
6.	सामग्री और मशीनरी के लिए शुल्कों और करों की राहत	कार्यक्रम संख्या – 36	आयातित प्रोद्योगिकियों और उपस्कर के लिए टैरिफ और आयात वीएटी की छूट ।
		कार्यक्रम संख्या – 37	भूमि के उपयोग शुल्क में कटौती
7.	उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त वस्तुएं/सेवा	कार्यक्रम संख्या – 38	उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त इनपुट सामग्री हॉट रोलड स्टील
		कार्यक्रम संख्या – 39	उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त हॉट रोलड स्टील



	कार्यक्रम संख्या – 40	उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त विद्युत
	कार्यक्रम संख्या – 41	औद्योगिक अथवा अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित कंपनियों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि ।
	कार्यक्रम संख्या – 42	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर जल की व्यवस्था करने का कार्यक्रम
	कार्यक्रम संख्या – 43	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विभिन्न वस्तुओं की व्यवस्था करना ।
	कार्यक्रम संख्या – 44	पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद ।
	कार्यक्रम संख्या – 45	बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त इनपुट सामग्री (कच्चा माल) और उपयोगी वस्तुएं

29 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों का इस तर्क के संबंध में कि याचिका में कमी है और यह प्रमाण शून्य है और इसलिए जांच को समाप्त करने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जो कि उनको उचित रूप से उपलब्ध थी ताकि याचिका का समर्थन किया जा सके और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जो यह दर्शाते थे कि प्रतिकारी सहायिकियां, क्षति और कारणात्मक संबंध विद्यमान है और जिनसे एएससीएम और भारतीय अधिनियम और नियमावली के अनुसार जांच शुरू करना न्यायोचित बनता था। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि अंतिम निर्धारण के लिए आवश्यक होता है, जांच शुरू करने के चरण में याचिका में प्रमाण होना आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी को स्वतः संतुष्ट मात्र होना पड़ता है कि जांच शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाण विद्यमान हैं। जहां कहीं भी आपवश्यक हुआ है, वहां प्राधिकारी ने अतिरिक्त सूचना मंगाई है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी सूचना सत्यापित की है।

30. इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता ने याचिका में स्वतः यह बताया है कि प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि याचिका के लिखित भाग में यह बताया गया है कि प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, फिर भी याचिका में प्रत्येक स्कीम से संबंधित प्रमाण शामिल थे। यहां तक कि याचिका में इन स्कीमों के बारे में यह बताया गया था कि प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, फिर भी याचिकादाता ने अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्धारण के रूप में प्रमाण प्रस्तुत किए थे। जब कि प्राधिकारी यह समझते हैं कि अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण, निर्धारण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है, फिर भी वे जांच शुरू करने को न्यायोचित मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण बनते हैं। याचिका में पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण निहित हैं जो यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऐसी आरोपित स्कीमों को प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली स्कीमों माना गया है।

31. इस प्रकार यह नोट किया गया है कि कुछ स्थानों पर याचिकादाता ने ऐसा बताया है कि संबद्ध प्रमाण संलग्न नहीं किए गए हैं, वस्तु स्थिति यह है कि याचिका में अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्णयों के रूप में पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के चरण में प्राधिकारी के पास विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में प्रमाण नहीं हैं, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां चीन में कोई भी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क देते हुए कि याचिकादाता ने संबद्ध सूचना प्रस्तुत नहीं की है, ऐसा नहीं दर्शाया है कोई भी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकादाता द्वारा याचिका में दिए गए प्रमाण यह दर्शाते हैं कि कुछेक जांच प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया सीवीडी मार्जिन, दिए गए ऋणों के लिए 10.45 प्रतिशत तक अधिक था तथा आर एंड डी के लिए अधिमान्य कर की छूट 9.71 प्रतिशत तक थी। विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में एफआईडी के लिए अधिमान्य कर नीतियां संचयी थीं और जहां पात्रता निर्यात निष्पादन से संबद्ध है, वहां मार्जिन 53 प्रतिशत तक अधिक था। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अंतर्गत विकसित देशों के लिए न्यूनतम सीमा 1 प्रतिशत मात्र है और विकासशील देशों के लिए 2 प्रतिशत है और इसलिए ऐसी अकेली स्कीमों ही जांच की शुरुआत को न्यायोचित बनाती है।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी अनेक स्कीमों के बारे में तर्क देते समय जो कि विद्यमान ही नहीं हैं, जीओसी ने कोई भी ऐसा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे पता चलता हो कि स्कीम लागू नहीं है। प्राधिकारी का यह विचार है कि जब किसी समय किसी कार्यक्रम को जीओसी द्वारा शुरू किया गया था और बाद में उसे वापिस ले लिया गया था, तो ऐसी स्थिति में जीओसी के पास उससे संबद्ध दस्तावेज होने चाहिए जिससे ऐसे कार्यक्रम के शुरू किए जाने और वापस लिए जाने का पता चल सके। तथापि, यह नोट किया गया है कि यह तर्क देते समय कि आरोपित स्कीमें लागू नहीं हैं, जीओसी ने न तो ऐसे कार्यक्रम के शुरू होने का कोई दस्तावेज और न ही कार्यक्रम को वापस लेने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि कार्यक्रमों को वापस लेने के संबंध में जीओसी का तर्क संबद्ध दस्तावेजी प्रमाण साथ समर्थित नहीं है। चूंकि जीओसी ने इस जांच के दौरान उनके द्वारा किए गए दावों सहित उनके आंकड़ों/सूचना की मौके पर जांच करने के प्रति सहमति प्रकट नहीं की है, उनके इस तर्क की सत्यवादिता को कि पूर्ववर्ती सहायिकी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जांच प्राधिकारियों ने यह पाया है कि ये स्कीमें विद्यमान हैं और उनके निर्णयों में प्रतिकारी हैं।

33. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि जीओसी ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचनाओं संख्य जी/एससीएम/एन/220/सीएचएन, जी/एससीएम/एन/253/सीएन और जी/एससीएम/एन/284/सीएचएन द्वारा विश्व व्यापार संगठन की एससीएम करार के अंतर्गत अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों को अधिसूचित किया है, जिनमें अधिकतर ऐसी स्कीमें/कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिन्हें मौजूदा जांच में चुनौती दी गई है।

34. जांच की शुरुआत को यथोचित सिद्ध के लिए प्रमाणों की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी की संतुष्टि होने और प्रमाणों की परिशुद्धता और पर्याप्तता की जांच करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने अन्य जांच प्राधिकारियों के ऐसे मामलों में जिनमें आरोपित कार्यक्रम प्रतिकारी थे, लिए गए निर्णयों के रूप प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने अपने दावे के संबंध में अन्य संबद्ध प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय कमीशन ने “चीन जनवादी गणराज्य मूल के कुछ आर्गेनिक कोटिड स्टील उत्पादों के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाने” के मामले में सर्कुलर वेलिड कार्बन क्वालिटी स्टील लार्डन पाईप के मामले में यूएस के निर्णय ज्ञापन द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर ही कुछ स्कीमों के बारे में अंतिम निर्धारण किया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी का यह विचार है कि जांच शुरू करने के चरण में प्रमाणों की परिशुद्धता और पर्याप्तता तथा प्राधिकारी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, प्रश्न मात्र ही है। प्राधिकारी की यह धारणा है कि यह तर्क करना उपयुक्त नहीं है कि आवेदन पत्र में 19 कार्यक्रमों के लिए कोई प्रमाण नहीं था। प्राधिकारी मेक्सिको से पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में गुआटेमाला पाटन-रोधी जांच के मामले में विश्व व्यापार संगठन के ऐसे निर्णय को भी नोट करते हैं जिसमें यह माना गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकारी याचिकादाता द्वारा उसकी याचिका में प्रस्तुत किए गए प्रमाणों तक ही स्वयं को सीमित कर ले। प्राधिकारी याचिका में अन्यथा दिए गए प्रमाण पर भी विचार कर सकते हैं, भले ही याचिकादाता ने उस पर विश्वास नहीं किया हो।

35. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तुएं “हरित उद्योग” से संबंधित हैं और उनके आयातों के खिलाफ किसी भी प्रकार के प्रतिकारी उपाय करने से इस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदर्शित किया गया है, कास्टिंग्स रूप में लागत, बमुश्किल कुल परियोजना लागत की 3-4 प्रतिशत बनती है। इसलिए जैसा कि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है, यदि प्रतिकारी उपाय किए जाने का कोई प्रभाव पड़ता है, तो वह 100 प्रतिशत के स्तर पर भी उपभोक्ता की कीमत को बमुश्किल से 0.1 प्रतिशत की वृद्धि करेगा। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के इस दावे का खंडन नहीं किया है। ऐसी किसी भी स्थिति में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतया सहायिकी-रोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन वस्तुओं के सहायिकीकरण से घरेलू उद्योग के होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में होगी। सीवीडी उपाय करने से किसी भी तरीके से चीन से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता भी प्रभावित नहीं होगी। सीवीडी उपाय करने से आयातों को मिलने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे और उनसे घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा तथा ये उपभोक्ताओं को उनकी व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होंगे। फिर भी उपभोक्ता आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकेगा।

36. नई सहायिकी के आरोपों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि याचिकादाता ने प्रारंभ में यह अनुरोध किया था कि जांच के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाए ताकि उसमें ऐसी सहायिकियों को भी शामिल किया जा सके, बाद में याचिकादाता ने अपने इस तर्क में संशोधन कर लिया था और यह निवेदन किया था कि अन्य सहायिकी स्कीमों के बारे में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों पर यह निर्णय लेने के लिए विचार किया जाए कि जीओसी ने ऐसी सभी स्कीमों के बारे में खुलासा नहीं किया है, जो कि चीन में प्रचलन में हैं और जिनमें कास्टिंग उत्पादकों को प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली सहायिकियों से लाभ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता द्वारा अब अभिज्ञात की गई नई सहायिकी स्कीमों को भी जांच में शामिल किए जाने से हितबद्ध पक्षकारों उनके संबंध में संबद्ध सूचना मंगानी अपेक्षित होगी और उसके बाद इन स्कीमों के बारे में भी व्यापक जांच करनी पड़ेगी। इस प्रकार प्राधिकारी के विचार से यह उपयुक्त है कि याचिकादाता द्वारा जांच के रिकार्ड में लाई गई इन नई

स्कीमों को शामिल करने के लिए जांच के दायरे को आगे नहीं बढ़ाया जाए। तथापि, यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रश्नावली में विशेष रूप से चीन में प्रचलित सहायिकी स्कीमों के बारे में सूचना मांगे जाने के बावजूद भी जीओसी ने चीन में प्रचलित ऐसी सहायिकी स्कीमों के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी के विचार से यह उपयुक्त है कि जांच को पूरा किए जाने के लिए बचे समय को ध्यान में रखते हुए इस चरण में इन स्कीमों को शामिल करने के लिए जांच के दायरे को आगे नहीं बढ़ाया जाए।

37. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग कम होने और द्रुत मूल्यहास स्कीम, जेनरेशन आधारित प्रोत्साहन को वापस लिए जाने के कारण हो रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है, फिर भी यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उत्पादक के बाजार के अंशदान में कुल मिलाकर गिरावट आई थी जो कि 14,122 मी.टन से घट कर 6,888 मी. टन रह गया था। इस प्रकार घरेलू उद्योग मांग में गिरावट आने के कारण पहले से ही नुकसान उठा रहा था, सहायिकीकृत आयातों ने घरेलू उत्पादकों के गिरते बाजार से बढ़ते हुए अंशदान को ले लिया था।

38. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को अत्यावश्यक तथ्यों के प्रकटन के बाद दूसरी सुनवाई करनी थी। हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन-रोधी में कानूनी प्रावधान और सहायिकी-रोधी नियमों के बीच तुलना की है और यह तर्क दिया है कि सहायिकी-रोधी नियमों में "अपने हितों की रक्षा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने" के प्रावधान विद्यमान है और पाटन-रोधी नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं होने से स्पष्ट होता है कि प्राधिकारी को अत्यावश्यक तथ्यों के प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी नियमों में प्रकटन विवरण को जारी करने से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

**भारतीय पाटन-रोधी नियम : "16. सूचना का प्रकटन - निर्दिष्ट प्राधिकारी अपना अंतिम निर्णय देने से पहले विचाराधीन ऐसे अत्यावश्यक तथ्यों की सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को देगा जो कि उसके निर्णय का आधार बनते हैं।"**

**विश्व व्यापार संगठन करार के प्रावधान : "6.9 प्राधिकारी अंतिम निर्धारण करने से पहले विचाराधीन ऐसे अत्यावश्यक तथ्यों की सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को देगा जो कि उसके ऐसे निर्णय का आधार बनते हैं, कि क्या सुनिश्चित उपाय किए जाएं। ऐसे प्रकटन पर्याप्त समय रहते किए जाने चाहिए ताकि पक्षकार अपने हितों की रक्षा कर सकें।"**

**एससीएम के प्रावधान : "12.8 प्राधिकारी अंतिम निर्धारण करने से पहले विचाराधीन ऐसे अत्यावश्यक तथ्यों की सूचना सभी हितबद्ध सदस्यों और हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकारों को देगा जो कि उसके ऐसे निर्णय का आधार बनते हैं, कि क्या सुनिश्चित उपाय किए जाएं। ऐसे प्रकटन पर्याप्त समय रहते किए जाने चाहिए ताकि पक्षकार अपने हितों की रक्षा कर सकें।"**

39. सीवीडी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत मौखिक सुनवाई किए जाने का अवसर प्रदान करने के बारे में किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :-

**"7 निर्दिष्ट प्राधिकारी (6) किसी भी हितबद्ध देश अथवा हितबद्ध पक्षकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि को जांच से संबद्ध किसी भी सूचना को मौखिक रूप से भी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक सूचना पर तभी विचार किया जाएगा जबकि उसे बाद में लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।"**

40. उपरोक्त प्रावधानों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम के सीधे पाठन से ऐसा पता चलता है कि प्राधिकारी को जांच के अत्यावश्यक तथ्यों का प्रकटन हितबद्ध पक्षकारों को करना अपेक्षित है। वास्तव में करार में भी ऐसी प्रत्यक्ष व्यवस्था है कि प्राधिकारी को जांच के अत्यावश्यक तथ्यों का प्रकटन करना आवश्यक है ताकि हितबद्ध पक्षकार अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। इससे प्राधिकारी पर ऐसा कोई भार नहीं पड़ता है कि वह अत्यावश्यक तथ्यों के प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां व्यक्त करने की अनुमति दें। किसी भी मामले में प्राधिकारी प्रकटन विवरण जारी करने के बाद हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां व्यक्त करने के अवसर प्रदान करेंगे और अंतिम निर्णय के लिए उन्हें जितना प्रासंगिक समझा जाएगा, ऐसी टिप्पणियों का निदान करेंगे। यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों पर प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुचित भार नहीं डालना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी की ऐसी धारणा है कि ऐसा विवरण औचित्य पूर्ण नहीं है। प्राधिकारी ने ऐसी किसी भी प्रकार की सूचना अथवा प्रमाण की मांग नहीं की है जिससे किसी प्रकार का अनुचित भार पड़ता हो। यदि कुछ सहायिकी कार्यक्रम चीन में प्रचलन में हैं, तो निर्यातक अथवा जीओसी को ऐसे कार्यक्रमों को शुरू किए जाने अथवा वापस लिए जाने से संबद्ध सूचना प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि चीन में बड़ी संख्या में कार्यक्रमों को बनाए रखा जा रहा है और यदि चीन में ऐसे बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का संचालन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, तो याचिकादाता के लिए प्राधिकारी को ऐसी समस्त

सूचना देना वास्तव में भारी भरकम कार्य होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस संबंध में याचिकादाता के तर्क यह हैं कि चीन में इन स्कीमों के बारे में अधिकतर सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

41. प्राधिकारी जीओसी के इस तर्क को नोट करते हैं कि सहायिकी की जांच करने की शक्ति सीमित नहीं है और कानूनी आवश्यकता से बाहर किसी भी प्रकार की सूचना अथवा प्रमाण, विश्व व्यापार संगठन के नियमों की भावना के विपरीत होंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा कोई असीमित शक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में 44 कार्यक्रमों में से दो कार्यक्रमों को छोड़ कर बाकी कार्यक्रमों के बारे में जीओसी ने कोई ऐसा खंडन नहीं किया है कि याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात किए गए ये कार्यक्रम चीन में कभी भी विद्यमान नहीं थे। केवल दो स्कीमों के बारे में जीओसी ने निवेदन किया है कि चीन में ऐसा कोई कार्यक्रम प्रचलन में नहीं था। इन दो कार्यक्रमों के लिए भी याचिकादाता घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उनमें गलत नाम प्रयुक्त किया गया है और अन्यथा चीन में एक ऐसा कार्यक्रम विद्यमान है जो कि अभिज्ञात किए गए लाभ प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने केवल कार्यक्रम की प्रकृति, प्रशासनिक प्राधिकारी के व्यौरों, संबद्ध कानूनी विधान, पात्रता के मानदंड, स्कीमों को शुरू करने अथवा समाप्त करने संबंधी प्रमाण आदि के बारे में सूचना मांगी थी। प्राधिकारी का यह विचार है कि किसी भी मामले में प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना अत्यधिक नहीं थी। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि सीवीडी की जांच में सभी प्राधिकारी इसी प्रकार की सूचना मांगते हैं। इसलिए जीओसी का यह तर्क कि प्राधिकारी द्वारा असीमित शक्ति का प्रयोग किया गया है, निराधार है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह तर्क देते हुए कि कुछ कार्यक्रम अब प्रचलन में नहीं हैं, जीओसी ने कार्यक्रम को शुरू करने और कार्यक्रम को वापस लेने संबंधी दस्तावेज की प्रति नहीं देने का रुख अपनाया है।

42. एसओई को एक निकाय के रूप में माने जाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने प्रारंभ में 44 कार्यक्रमों को अभिज्ञात किया था जिनमें से 37 कार्यक्रमों का संचालन उन निकायों द्वारा किया जा रहा था जो कि राज्य की श्रेणी (जीओसी, प्रांतीय, म्युनिसिपल कार्पोरेशन, चीन में स्थानीय निकाय) के भीतर आते हैं। याचिकादाता ने केवल ऐसे 7 कार्यक्रमों को अभिज्ञात किया था जिनका संचालन एसओई द्वारा किया जा रहा था। यदि चीन सरकार मौके पर जांच करने की अनुमति दे देती तो ऐसे एसओई का वास्तविक दर्जा स्थापित हो सकता था।

43. याचिका में सूचना के प्रकटन के संबंध में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की विस्तार से जांच की है और उनके विचार निम्नानुसार हैं :-

- (क) सॉफ्ट कापी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका अनुरोध निर्धारित प्रपत्र से बाहर है। आवेदन पत्र के प्रपत्र में आवेदक का ऐसा दायित्व नहीं है कि वह सॉफ्ट कापी में सूचना आवेदन पत्र के एनसीवी वृत्तान्त में दे।
- (ख) प्रत्येक सहायिकी कार्यक्रम के विद्यमान होने के संबंध में प्रमाण की कमी होने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने उचित सीमा तक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और याचिका में अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्णय निहित हैं जिनमें इन कार्यक्रमों को प्रतिकारी माना गया है।
- (ग) इस संबंध में कि सहायिक कार्यक्रम संबंध उत्पाद पर लागू किया जा रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में अभिज्ञात किए गए 44 कार्यक्रमों में से 42 कार्यक्रम ऐसे थे, जिनके आरोपित लाभ उत्पाद से संबंधित है। ऐसे लाभ व्यवसायिक उद्यम की किस्म से अथवा ऐसे स्थान से संबंधित हैं, जहां व्यवसायिक उद्यम स्थापित था अथवा कार्यक्रम निर्यात के प्रासंगिक है। यदि कोई कार्यक्रम निर्यातों के प्रासंगिक होता है, इससे ऐसा पता चलता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सभी निर्यातकों को उपलब्ध होता है, इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि क्या वे विचाराधीन उत्पाद अथवा अन्य उत्पाद का विनिर्माण कर रहे हैं। वास्तव में मौजूदा जांच इस आधार पर यथोचित बनती है कि ऐसे अनेक कार्यक्रमों को अभिज्ञात किया गया है, जो कि निर्यातों के प्रासंगिक हैं और जिनमें सीवीडी के अत्यधिक मार्जिन को अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा सिद्ध किया गया है।
- (घ) मेसर्स पटेल एल्वॉयज से समर्थन के पत्र की प्रति, उक्त कंपनी द्वारा प्रदान कर दी गई है और मौखिक सुनवाई के बाद घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लिखित निवेदनों के साथ उसका पुनः उल्लेख किया गया है।
- (ङ) अन्य उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में याचिका में ऐसी पर्याप्त सूचना निहित है जिससे इसकी पुष्टि होती है कि याचिकादाता का उत्पादन, नियमावली के अंतर्गत निर्धारित की गई सीमा से अधिक था। वास्तव में यह नोट किया जाता है कि याचिकादाता का दर्जा जांच की शुरुआत करने के बाद भी विषय की दृष्टि से बदला नहीं है।

44. इस तर्क के संबंध में कि ऐसी अवधारणा नहीं हो सकती है और यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कार्टिंग्स के विनिर्माताओं द्वारा उठाए जाने वाले सहायिकी के लाभ, अन्य उत्पादों को भी अतिरिक्त कर दिए गए हैं, उनको सीवीडी की जांच में ऐसे निचले स्तर के उत्पादों में शामिल नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने निचले स्तर के उत्पादों को जांच के अधिकार-क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया है। याचिकादाता ने निचले स्तर के उत्पादों

के कास्टिंग भाग पर ही सीवीडी शुल्क लगाने की मांग की है। यहां तक अवधि का संबंध है, दर्ज सूचना से ऐसा पता नहीं चलता है कि संग्रहण और उप-संग्रहण के रूप में उत्पाद का कोई आयात किया गया है और इसलिए किसी भी स्थिति में मौजूदा निर्धारण में निचले स्तर के उत्पादों को शामिल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

45. इस तर्क के संबंध में कि आरोपित कार्यक्रम विशिष्ट भौगोलिकीय क्षेत्र अथवा शहरों से संबंधित हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई भी उत्पादक ऐसे भौगोलिकीय क्षेत्र में स्थित था/वहां से प्रचालन कर रहा था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीओसी ने चीन में 200 से अधिक कास्टिंग्स उत्पादकों की सूची प्रदान की है जिनमें उनकी अवस्थिति दर्शाई गई है। लेकिन इन उद्योगों के दर्जे और उनके द्वारा लाभ उठाई जाने वाली सहायिकियों से संबंधित और ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जीओसी ने उसके अकेले प्रतिवादी निर्यातक के आंकड़ों को प्राप्त करने अथवा उनकी प्राधिकारी द्वारा जांच किए जाने में कोई सहयोग नहीं दिया है।
46. कुछ हितवद्ध पक्षकारों ने एससी ऑटोमोटिव टायर मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम डीए {2011 (263) ई.एल.टी. 481 (एस.सी.)} के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है और यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं और प्राधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करना प्राधिकारी की सिफारिशों को अमान्य करेगा। प्राधिकारी की यह धारणा है कि मौजूदा मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है, जितने वे लागू होते हैं और प्रासंगिक हैं उनका उतना अनुसरण किया गया है। उदाहरण के लिए इस तथ्य के बावजूद कि आईडब्ल्यूटीएमएस एसोसिएशन ने मौखिक सुनवाई के स्तर पर ही स्वयं को उजागर किया था और जांच शुरूआत करने के समय और मौखिक सुनवाई किए जाने के चरण तक कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी, लेकिन फिर भी प्राधिकारी ने उक्त एसोसिएशन को अपने मौखिक निवेदन और बाद में लिखित निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन द्वारा किए गए सभी निवेदनों को प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, उनकी जांच की गई है और अंतिम निर्णय में उनका निदान किया गया है।
47. यह तर्क दिया गया है कि नियम 4 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए किसी भी वस्तु के आयात के संबंध में किसी भी सहायिकी की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव के बारे में जांच करना आवश्यक है। जब तक ऐसे उत्पाद को सही तरह से परिभाषित नहीं कर लिया जाता है तब तक सहायिकी के प्रभाव की सही तरह से जांच नहीं की जा सकती है। प्राधिकारी का यह मानना है कि मौजूदा जांच की प्रक्रियाओं में वस्तु को सही तरीके से परिभाषित कर लिया गया है। विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के संबंध में जीओसी अथवा प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा कोई संदिग्धता आरोपित नहीं की गई है।
48. हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता द्वारा यूएस के यूटीलिटीज स्केल विंड टरबाइन के जिस मामले का हवाला दिया गया है, वह मौजूदा मामले में लागू नहीं होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता का हवाला, इस उत्पाद में यूएस प्राधिकारियों द्वारा पाई गई प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली स्कीमों के संबंध में है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने यह तर्क दिया है कि इस मामले में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र, वस्तुतः बहुत व्यापक है जिसके बारे में याचिकादाता द्वारा मौजूदा मामले में विचार भर नहीं किया गया है।
49. इस तर्क के संबंध में कि अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण को प्राधिकारी द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा निर्धारण, अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण के तथ्यतः लागू होने के आधार पर किया गया है। याचिकादाता ने अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्णय का हवाला, प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली स्कीमों के विद्यमान होने को सिद्ध करने के मात्र ही दिया है। फिर भी प्राधिकारी ने मौजूदा मामले में प्रत्येक स्कीम के बारे में स्वतंत्र निर्धारण किया है।
50. इस तर्क के बारे में कि जांच शुरू करने के समय डीजीसीएडी द्वारा उपयुक्त रूप से कोई विचार नहीं किया गया था, प्राधिकारी ऐसे तर्क से सहमत नहीं है और उनकी यह धारणा है कि प्रमाण की उपयुक्तता, परिशुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही जांच शुरू की गई थी ताकि उसको यथोचित सिद्ध किया जा सके।

## ज. सहायिकी और सहायिकी मार्जिन

### ज. 1. भूमिका

51. याचिकादाता ने यह आरोप लगाया है कि जीओसी संबद्ध उत्पादों के अपने उत्पादकों/निर्यातकों को सहायिकी प्रदान कर रही है। याचिका में अनेक सहायिकी स्कीमों के लिए उचित पृथक् दृष्टया पर्याप्त प्रमाण निहित हैं, जो कि विधान और अनेक नीतिगत दस्तावेजों दोनों में शामिल हैं और उत्पाद को राज्य का समर्थन प्राप्त होने का आधार है। जांच शुरू करने पर चीन सरकार और चीन से एक उत्पादक/निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। याचिकादाता ने यह तर्क दिया है कि वस्तुओं की आपूर्ति चीन के एक से अधिक उत्पादों द्वारा की गई है और और प्रश्नावली का उत्तर चीन के केवल एक उत्पादक ने ही दिया है। इसलिए याचिकादाता

का यह तर्क है कि किसी भी स्थिति में चीन सरकार को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि कुछ सीमा तक ऐसे लाभ चीन के अन्य उत्पादकों द्वारा भी उठाए गए हैं।

52. प्राधिकारी ने विभिन्न आरोपित सहायिकी कार्यक्रमों के प्रतिकारी प्रभाव के बारे में याचिकादाता, चीन सरकार और चीन के एक मात्र प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद, चीन के केवल एक उत्पादक द्वारा ही निर्मित और निर्यातित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन सरकार ने प्रतिवादी निर्यातक के संबंध में ही प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किया है। चीन सरकार ने यह जानते हुए भी कि चीन में अनेक कास्टिंग उत्पादक/निर्यातक और ऐसी स्कीमें विद्यमान हैं जिनके लाभ ऐसे अनेक उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उठाए गए हो सकते हैं, चीन के ही अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

53. मौजूदा जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले और एससीएम के करार के अनुसार प्राधिकारी ने चीन सरकार को स्थिति स्पष्ट करने और करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक सहमति बनाने के प्रयोजन से परामर्श करने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा परामर्श 5 मई, 2014 को नई दिल्ली में किया गया था जिसमें चीन सरकार (जिसे जीओसी भी कहा गया है) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था :-

- (1) झा झिझियांग, द्वितीय सचिव, चीन दूतावास, दिल्ली।
- (2) यांग झिउक्किंग, तृतीय सचिव, चीन दूतावास, दिल्ली।
- (3) गु युआन, प्रथम सचिव, एमओएफसीओएम, चीन जनवादी गणराज्य।
- (4) लुओ किसन, उप आयुक्त।
- (5) गू यू, प्रथम सचिव, एमओएफसीओएम, चीन जनवादी गणराज्य।
- (6) वांग हेजुन, वाणिज्यिक परामर्शदाता।
- (7) क्सू यान गुआंग, उप निदेशक, एमओएफसीओएम, चीन जनवादी गणराज्य।
- (8) वांग क्सीहुई, वाणिज्यिक आयुक्त।

54. परामर्श के दौरान और बाद में दिनांक 26 जुलाई, 2014 के अपने पत्र द्वारा जीओसी ने यह दावा किया था कि याचिका में प्रस्तुत प्रमाण कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अपूर्ण थे और कुछ आरोपित स्कीमों/कार्यक्रमों को पहले से ही रद्द कर दिया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच शुरू करने के लिए याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। हालांकि जीओसी ने तर्क दिया था कि अधिकतर आरोपित स्कीमों/कार्यक्रम कभी भी विद्यमान नहीं थे अथवा विद्यमान थे, लेकिन उन्हें रद्द कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने अपने ऐसे तर्क के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण कभी भी प्रस्तुत नहीं किया था। यहां तक कि यदि जीओसी जांच करने के प्रति सहमत होती और प्राधिकारी को जीओसी के साथ-साथ मेसर्स जिआली विंड के आंकड़ों/सूचना को मौके पर जांच करने की अनुमति दे देती तो प्राधिकारी तथ्यों की संपुष्टि कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जीओसी ने न ही अपनी जांच के प्रति सहमति प्रकट की और न ही प्राधिकारी को चीन के एक मात्र प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक की जांच करने की अनुमति दी है।

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ने जांच शुरू करने से पूर्व आयोजित परामर्श के दौरान किए गए अपने दावों के समर्थन में कोई भी संपुष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के प्रतिकारी प्रभाव डालने वाले सहायिकी प्राप्त आयात होने और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर जांच शुरू करने की कार्रवाई की थी। प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत याचिका और जीओसी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया था और यह माना था कि प्रतिकारी शुल्क की जांच शुरू करना उपयुक्त है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों निर्यातकों को प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली सहायिकियों से लाभ हुआ है और क्या ऐसे सहायिकी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यदि हां, तो क्या यह उपयुक्त है कि चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क उपाय ( जिसे आगे “सीवीडी” अथवा “सहायिकी रोधी शुल्क” कहा गया है) लागू करने की सिफारिश की जाए ताकि ऐसी सीवीडी की मात्रा का निर्धारण किया जा सके, जो विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाया जा सके।

**ज.2. प्रतिकारी सहायिकियों के बारे में घरेलू उद्योग के विचार**

56. जीओसी द्वारा प्रदत्त प्रतिकारी सहायिकियों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) जीओसी संबद्ध वस्तुओं के अपने निर्यातकों/उत्पादकों को प्रतिकारी सहायिकी प्रदान कर रही है।
- (2) याचिका में अनेक सहायिकियों के विद्यमान होने, जो कि विधान और अनेक नीतिगत दस्तावेजों दोनों में शामिल हैं, के बारे में प्रथम दृष्टया प्रमाण निहित हैं जो उत्पाद को प्राप्त होने वाली राज्य सहायता के आधार हैं।
- (3) घरेलू उद्योग ने चीन में विद्यमान निम्नलिखित सहायिकी स्कीमों को अभिज्ञात किया है जो कि एएससीएम और भारतीय नियमों में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली स्कीमों हैं।

**विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रोत्साहन और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र**

- (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र (शंगाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़ कर) में स्थापित विदेशी निवेश से स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां।
- (ख) समुद्रतटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिकओर प्रोद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां।
- (ग) शंगाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां।
- (घ) एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्पोरेट आय कर में छूट और/अथवा कटौती।
- (ङ) एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आय कर में छूट और/अथवा कटौती।
- (च) एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्री और उपस्करों पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर (वीएटी) की छूट।
- (छ) कास्टिंग और फोर्जिंग प्रणाली के लिए अधिमान्य कर।

**क. अनुदान**

- (क) राज्य प्रमुख प्रोद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि।
- (ख) स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन-रोधी और/अथवा स्थानीय प्रतिकारी कानूनी व्यय
- (ग) अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान।
- (घ) नवीनतम प्रायोगिक उद्यम अनुदान।
- (ङ) सुपरस्टार उद्यम अनुदान।
- (च) ऐसे उद्यमियों को पुरस्कार जिनके उत्पाद "चीन के सुविख्यात ट्रेड्समार्क्स" अथवा "चीन के प्रसिद्ध ब्रांड" के लिए योग्य बनते हैं।
- (छ) उच्च-प्रोद्योगिकी की उद्यम निवेश निधि।
- (ज) मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान और विदेशी निवेश से क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना।
- (झ) नवीनतम लघु और मध्यम उद्यम अनुदान।
- (ञ) निजी स्वामित्वाधीन उद्यमों को अनुदान।

**ख. ईक्विटी कार्यक्रम**

- (क) ईक्विटी अनुप्रेरणा।
- (ख) अदत्त लाभांश।

**ग. अधिमान्य ऋण**

- (क) कास्टिंग उद्योग को अधिमान्य ऋण और व्याज दर।

**घ. अधिमान्य आय कर कार्यक्रम**

- (क) 10 वर्ष से कम अवधि के लिए प्रचालन करने के लिए निर्धारित लाभप्रद एफआईई के लिए कम की गई कर की दर ।
- (ख) विदेशी निवेश से निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- (ग) एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो कि प्रोद्योगिकी प्रोद्योगिकी प्रोत्साहन और ज्ञान प्रोत्साहन हैं ।
- (घ) एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- (ङ) एफआईई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिनके संस्थान और अवस्थापनाएं चीन में हैं और जो देश में ही निर्मित उपस्करों की खरीद के व्यवसायिक प्रचालनों में लगे हुए हैं ।
- (च) प्रोद्योगिकी उन्नय के प्रयोजनार्थ देश में ही निर्मित उपस्करों की खरीद के व्यवसायिक प्रचालनों में लगे हुए घरेलू उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- (छ) विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई लाभ का पुनर्निवेश करने के लिए आय कर की वापसी ।
- (ज) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां ।
- (झ) केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें ।
- (ञ) देश में ही निर्मित उपस्करों की खरीद के लिए आय कर जमा ।
- (ट) ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो कि उच्च और नई प्रोद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं ।
- (ठ) गहन स्रोत उपयोग (विशेष कच्चा माल) करने में लगे हुए उद्यमों के लिए आय कर में रियायतें ।
- (ड) विशेष उपस्कर खरीदने से संबंधित कर जमा ।
- (ढ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीति ।
- (रा) योग्यता प्राप्त आवासीय उद्यमों के बीच लाभांश की छूट ।

**ङ. सामग्री और मशीनरी पर शुल्कों और करों की राहत**

- (क) आयातित प्रोद्योगिकियों और उपस्कर के लिए टैरिफ और आयात वीएटी की छूट ।
- (ख) भूमि के उपयोग शुल्क में कटौती ।

**च. उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त वस्तुएं/सेवाएं**

- (क) उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त इनपुट सामग्री हॉट रोलड स्टील ।
- (ख) उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त हॉट रोलड स्टील ।
- (ग) उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त विद्युत ।
- (घ) औद्योगिक अथवा अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित कंपनियों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि ।
- (ङ) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर जल की व्यवस्था करने का कार्यक्रम ।
- (च) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विभिन्न वस्तुओं की व्यवस्था करना ।
- (छ) पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद ।
- (ज) बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त इनपुट सामग्री (कच्चा माल) और उपयोगी वस्तुएं ।

57. उपरोक्त आरोपित स्कीमें ऐसी प्रकृति की हैं, जिनसे अनुदान, ऋण, ईक्विटी अनुप्रेरणा अथवा त्यागे गए राजस्व जैसे कि प्रोत्साहन प्रदत्त किए जाते हैं । प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर प्राधिकारी ने उपरोक्त आरोपित स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में जांच शुरू की है ।



58. जीओसी ने अपने उत्तर में पांच सेटों में अपने उत्तर दिए हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

(क) चीन में ऐसा कोई कार्यक्रम विद्यमान नहीं है - जीओसी ने इसका उत्तर नहीं दिया है कि क्या ऐसी स्कीम को अन्य किसी नाम से प्रयुक्त किया गया है।

(ख) स्कीम अब प्रचलन में नहीं है - स्कीम को समाप्त कर दिए जाने के बारे में जीओसी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यहां तक कि यदि स्कीम को समाप्त भी कर दिया गया है, तब भी उसकी प्रकृति अनुदान, ऋण अथवा इक्विटी देने की है और उसके लाभ परिसम्पतियों को उनकी समस्त उपयोगी अवधि तक प्राप्त होते रहेंगे। दूसरे इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन में ऐसी स्कीम किसी भी समय विद्यमान थी। यदि ऐसी स्कीम विगत 15 वर्षों के दौरान विद्यमान थी तो उसके लाभ परिसम्पतियों को उनकी समस्त उपयोगी अवधि तक प्राप्त होते रहेंगे। तथापि, जीओसी ने इन कार्यक्रमों को वापस लिए जाने के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जीओसी के ऐसे दावों के बावजूद ऐसे कार्यक्रमों की अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा निरंतर जांच की जाती रही है और इन कार्यक्रमों में प्रतिकारी सहायिकियां होती हैं। इसलिए ऐसा कहना कि ये “स्कीमों अब प्रचलन में नहीं हैं”, का यह अभिप्राय कतई नहीं है कि इन स्कीमों के संबंध में जांच नहीं की जानी चाहिए।

(ग) याचिकादाता द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है - प्रथम दृष्टया याचिकादाता ने अन्य प्राधिकारियों के निर्णय प्रस्तुत किए हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि स्कीमों प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली हैं। इसके अतिरिक्त जीओसी ने कभी भी ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि ऐसी स्कीमों चीन में कभी भी विद्यमान नहीं थीं अथवा उत्पाद के उत्पादक ने उससे प्राप्त होने वाले लाभ नहीं उठाए हैं अथवा वह उससे लाभान्वित नहीं हो रहा है।

(घ) विचाराधीन उत्पाद पर लागू नहीं होता है - जीओसी ने उल्लेख किया है कि उत्पाद को स्टील स्क्रैप और पिग ऑयरन से विनिर्मित किया जाता है और न कि होट रोल्ड स्टील से। हालांकि याचिकादाता द्वारा बाद में किए गए निवेदन में ऐसा उल्लेख किया गया है कि टंकण में वृष्टि होने के कारण स्कीम का गलत ढंग से उल्लेख कर दिया गया था। स्कीम का मुख्य ध्येय पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर इनपुट प्रदान करना था। इस प्रकार उचित बाजार मूल्य के कम मूल्य पर इनपुट सामग्री को प्राप्त किए जाने के संबंध में याचिका में गलती से “होट रोल्ड स्टील” उल्लिखित कर दिया गया है। याचिका से यह प्रमाणित होता है कि याचिकादाता के हवाले का तात्पर्य ऐसी इनपुट से है, जिनका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के लिए किया जाता है, जैसे कि पिग ऑयरन, स्टील स्क्रैप (सीआरसीए), फेरो सिलिकोन, फेरो सिलिकोन एमजी, कोक, इनोक्यूलेट्स, सिलिका सैंड, रेसिन, केटेलिस्ट, एलपीजी, फर्नेस लाईनिंग सामग्री, डीजल, लेडल लाईनिंग सामग्री, सिरैमिक ट्यूब्स, स्लीव्स और रिफ्रेक्टरी कोटिंग। इस प्रकार याचिका में होट रोल्ड स्टील शब्दों को कृपया पिग ऑयरन, स्टील स्क्रैप (सीआरसीए), फेरो सिलिकोन, फेरो सिलिकोन एमजी, कोक, इनोक्यूलेट्स, सिलिका सैंड, रेसिन, केटेलिस्ट, एलपीजी, फर्नेस लाईनिंग सामग्री, डीजल, लेडल लाईनिंग सामग्री, सिरैमिक ट्यूब्स, स्लीव्स और रिफ्रेक्टरी कोटिंग के बतौर पढ़ा जाए। याचिकादाता होट रोल्ड स्टील के संदर्भ में खेद प्रकट करता है और उसका यह निवेदन है कि उसकी ऐसी वृष्टि स्वभाविक थी और इसलिए जीओसी और निर्यातक को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली इनपुट के आधार पर ही अपने उत्तर देने चाहिए थे।

(ङ) स्कीम अब प्रचलन में नहीं है - इस पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार निर्दिष्ट प्राधिकारी का है। यहां तक कि अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा भी उक्त स्कीमों को प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली बताया गया है। इसके अतिरिक्त जीओसी ने ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि ऐसी स्कीम कैसे अभियोग्य नहीं है।

59. चीन सरकार अथवा प्रतिवादी निर्यातक ने इसका खंडन नहीं किया है कि ये स्कीमों अनुदान प्रकृति की थीं। और न ही चीन सरकार अथवा प्रतिवादी निर्यातक ने इसका खंडन किया है कि प्रतिवादी निर्यातक ने विगत में ऐसी अनुदान स्कीमों के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त किया है। इस पर विचार करते हुए कि अनुदान स्कीमों के लाभ, परिसम्पतियों की समस्त उपयोगी अवधि तक बने रहते हैं, प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि इन स्कीमों के संबंध में जांच को जारी रखे जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जांच प्राधिकारियों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि ये अनुदान स्कीमों प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली हैं।

60. किसी भी स्थिति में यह सुस्थापित है कि याचिका में सभी स्कीमों के बारे में व्यापक उल्लेख नहीं किया गया है तथा निर्यातक और जीओसी को सत्यनिष्ठा से “ऐसी किसी भी अन्य स्कीम” के बारे में व्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो कि चीन के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों पर लागू होती थीं।

61. चीन सरकार ने दावा किया है कि प्रतिवादी निर्यातक, मेसर्स झेझियांग जिआली विंड पावर टेक्नालोजी, हेंगझाऊ ने ऐसी किसी भी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाला कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया है, जिसे याचिकादाता द्वारा प्रतिकारी आरोपित किया गया है। हालांकि एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक ने निम्नलिखित स्कीमों के लिए आवेदन किया है :-

(1) उच्च और नई प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां।

(2) योग्यता प्राप्त आवासी उद्यमों के बीच लाभांश की छूट।

62. इस प्रकार इससे यह पता चलता है कि उपरोक्त स्कीमों में चीन जनवादी गणराज्य में विद्यमान हैं और वे उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू होती हैं।

63. जीओसी यह स्पष्ट करने में विफल थी कि हाल ही के वर्षों में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा आरोपित स्कीमों/कार्यक्रमों को कैसे प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली सिद्ध किया है। चीन सरकार अथवा प्रतिवादी निर्यातक का यह तर्क नहीं है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम चीन सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है जिसके लाभ, याचिकादाता द्वारा बताए गए लाभों की प्रकृति जैसे ही हों। चीन सरकार का यह तर्क है कि याचिकादाता के पास प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

64. विभिन्न स्कीमों के विद्यमान होने और जीओसी द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय योगदान से संबंधित प्रमाण सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। चीन सरकार का यह तर्क नहीं है कि उसने ऐसी सभी प्रकार की सूचना को सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया है और न ही चीन सरकार का यह तर्क है कि कुछ सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और ऐसी सूचना याचिकादाता द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

65. यह संभव है कि याचिकादाता द्वारा विनिश्चित किए गए एक नाम के बजाय कार्यक्रमों को विभिन्न नामों से जाना जाता हो। वास्तव में ऐसा समझा जाता है कि चीन की कंपनियों के नाम भी चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा में भिन्न हो सकते हैं। क्या प्रासंगिक है, वह स्वतः "नाम" नहीं, बल्कि ऐसे "लाभ" हैं, जो कि चीन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इस तथ्य मात्र से कि लाभ किसी अन्य नाम से दिए जा रहे हैं और याचिकादाता ने किसी अन्य नाम को प्रयुक्त किया है, लाभ के प्रतिकारी प्रभाव के संबंध में कानूनी स्थिति बदल नहीं जाती है। याचिकादाता ने नाम का उल्लेख केवल चीन सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ विशेष स्कीमों के लाभ से जोड़ने के लिए ही किया है।

66. जीओसी ने कभी भी इस जांच की प्रक्रिया के दौरान याचिकादाता द्वारा अन्य प्राधिकारियों के निर्णय, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट, व्यापारिक नीतियों की पुनरीक्षा, पुनरीक्षा, प्राइवेट अनुसंधान रिपोर्टें आदि जैसे प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रमाण का खंडन दस्तावेजी समर्थन के साथ नहीं किया है।

67. वास्तव में जीओसी ने प्रश्नावली में निर्धारित "अन्य सहायिकियों" के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। जांच की प्रक्रिया के अनुसार याचिकादाता ने यह पाया कि जीओसी ने वास्तव में चीन में प्रचलित अनेक स्कीमों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। प्रश्नावली में निम्नानुसार निर्धारित है :-

"2. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, भले ही उनमें से कुछ कार्यक्रम, याचिकादाता द्वारा सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं, आपको उनके प्रश्नों के बारे में पूरे उत्तर देने चाहिए, भले ही संबद्ध सरकार का यह विश्वास हो कि ऐसे कार्यक्रम प्रतिकारी नहीं हैं।

5. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर, मानक प्रश्नावली के अनुबंध और इस प्रश्नावली के साथ संलग्न अन्य सभी अनुबंधों में से, जैसे भी लागू हों, में दिए जाएं जो कि संबंधित कार्यक्रम के प्रासंगिक हों।

7. विभाग से यह अपेक्षित है कि वह इस जांच के दौरान पता लगे किसी भी ऐसे कार्यक्रम की जांच करेगा जो कि संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन अथवा निर्यात पर प्रतिकारी सहायिकी प्रदान करता है। इसलिए आपको ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है, कि क्या किसी उद्यमी द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाला कोई लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं।"

68. इसलिए प्रश्नावली का प्रयोजन, ऐसी सभी स्कीमों का निदान करना है, जो कि चीन में प्रचलित हो सकती हैं, लेकिन जिनकी जांच करने के लिए याचिकादाता ने अनुरोध नहीं किया है। जीओसी इस उत्तर को महज इसलिए प्रतिबंधित नहीं कर सकती है कि ऐसी स्कीमों को याचिकादाता द्वारा अभिज्ञात किया गया है। जीओसी को चाहिए कि वह चीन में उपलब्ध प्रत्येक स्कीम और उसके लागू होने के संबंध में सूचना प्रदान करे। तथापि, ऐसा प्रमाण है कि जीओसी ने प्राधिकारी को ऐसी स्कीमों के विद्यमान होने के बारे में नहीं बताया है।

69. इस प्रकार याचिकादाता ने चीन में निम्नलिखित स्कीमों के रिकॉर्ड में विद्यमान होने के बारे में सूचित किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह यह तय करे कि ये स्कीमों प्रतिकारी प्रभाव डालने वाली स्कीमों बनती हैं और जीओसी ने इन

स्कीमों के बारे में उत्तर देना उचित नहीं समझा है। जीओसी की प्रश्नावली इस प्रसंग में अधूरी है। इसके अतिरिक्त जीओसी ने जान बूझ कर निम्नलिखित स्कीमों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

#### **अनुदान**

- (1) निर्यात सहायता अनुदान।
- (2) विदेशी व्यापार के संपोषण स्थाई विकास के लिए अनुदान – विशेष निधि।
- (3) शिजिआङ्ग सरकार का शहरी निर्यात पुरस्कार (हेबेल प्रांत)।
- (4) शेयरो को सूचीबद्ध करने के लिए अनुदान।
- (5) हेबेल प्रांत और जिआंगसू प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान।
- (6) हेंगझाऊ प्रीफेक्चर तथा फुआंग सिटी (झेजिआंग प्रांत) और (अनहुल प्रांत) से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) अनुदान।
- (7) म्युनिस्पल सरकार – निर्यात अनुदान।
- (8) ऐसे उद्यमियों के लिए फुआंग शहर की सरकार का अनुदान जो प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास केन्द्र चला रहे हैं (अनहुल प्रांत)।
- (9) ऐसे उद्यमियों के लिए फुआंग शहर की सरकार का अनुदान जो कर के रूप में 100 मिलियन आरएमबी से भी अधिक का भुगतान कर रहे हैं।
- (10) उप-संविदा सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत फुआंग शहर की सरकार का अनुदान।
- (11) प्रांतीय सरकार – उपस्कर अनुदान।
- (12) विदेश कार्य सेवा व्यय की प्रतिपूर्ति।
- (13) व्यापार मेले में भाग लेने के लिए सरकार से प्रत्यर्पण।
- (14) ऊर्जा बचाओ प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि।
- (15) प्रमुख उद्योगों को बढावा देने और नवीकरण प्रौद्योगिकी के लिए राज्य की विशेष निधि।
- (16) टिआन्जिन बिन्हाई के नए क्षेत्र और टिआन्जिन आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र में सहायिकियां प्रदान कर रहे हैं।

#### **कर कार्यक्रम**

- (1) एफआईई के लिए दो निशुल्क, तीन अर्धशुल्क कार्यक्रम।
- (2) टिआन्जिन पोर्ट फ्री ट्रेड जोन के उद्यमी आय कर दर में कटौती।
- (3) विशेष उपस्कर खरीदने से संबंधित कर जमा।
- (4) विभिन्न स्थानीय कर में छूट (शान्दोंग प्रांत, चोंगिंग शहर, गुआंग्सी क्षेत्र झुआंग, केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों का विकास करने के लिए कर का विशेष लाभ)।
- (5) केन्द्रीय क्षेत्र में अचल परिसम्पत्तियों पर वैट (वीएटी) की कटौती।
- (6) केन्द्रीय क्षेत्र में वैट (वीएटी) की छूट।
- (7) घरेलू निर्मित उपस्कर पर वैट (वीएटी) की छूट।
- (8) चीन में निर्मित उपस्कर की एफआईई की खरीद पर वैट (वीएटी) की छूट।

#### **निर्यात सहायिकी**

- (1) निर्यात विक्रेता के ऋण
- (2) निर्यात क्रेता के ऋण

#### **अधिमान्य ऋण और उधार**

- (1) चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमान्य निर्यात वित्त पोषण।
- (2) राजकोपीय बॉण्ड ऋण अथवा अनुदान।
- (3) नवीकरण योग्य ऊर्जा उद्योग के लिए नीतिगत सहायता।

**वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रावधान**

- (1) औद्योगिकीय क्षेत्रों और एसईजेड में स्थित कंपनियों के लिए प्रशानिक प्रभारों में छूट।
- (2) उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदत्त कच्चा माल।

70. याचिकादाता ने इस चरण में पाई गई विशिष्ट सहायिकी स्कीमों को सीवीडी जांच में शामिल करने के लिए उसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने का अनुरोध नहीं किया है। याचिकादाता ने चीन में विद्यमान इन सहायिकियों का उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए किया है कि निर्यातक और जीओसी ने जानबूझ कर ऐसी बृहत् सूचना छिपाई है और कम सूचना प्रस्तुत की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रश्नावली में विचाराधीन उत्पाद पर लागू होने वाली “किन्हीं अन्य स्कीमों” से संबंधित सूचना शामिल है, जिनके बारे में चीन के उत्पादकों और जीओसी को उत्तर देना बहुत जरूरी था। तथापि, इन कंपनियों और जीओसी ने ऐसी कोई भी सूचना नहीं देने का रवैया अपनाया है। अब याचिकादाता द्वारा दिए गए प्रमाण से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि तथ्यों को छिपाया गया है और साथ ही तथ्यों को दबा कर रखा गया है।

71. याचिकादाता ने निवेदन किया है कि जीओसी एक तरफ तो यह बताती है कि ऐसा कोई कार्यक्रम विद्यमान है, जबकि दूसरी तरफ ऐसी स्कीमों/कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी के नामों और पतों का उल्लेख करती है।

72. केवल मेसर्स जेजिआंग जिलाली विंड पावर टेक्नोलोजी ने ही प्रश्नावली का उत्तर दिया है। हालांकि प्राप्त किए गए लाभ केवल प्रतिवादी निर्यातक तक ही प्रतिबंधित/सीमित नहीं होते हैं। तथापि, यही कंपनी चीन में विचाराधीन उत्पाद की एक मात्र उत्पादक नहीं है। आयात के आंकड़ों से यह स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध अवधि के दौरान अनेक अन्य निर्यातक कंपनियों ने संबद्ध उत्पाद के निर्यात किए हैं। इसलिए चीन सरकार द्वारा दिए गए प्रश्नावली के उत्तर को अधूरा/कमी युक्त माना जाना चाहिए क्योंकि उसने यह माना है कि केवल प्रतिवादी निर्यातक ने ही लाभ प्राप्त किया है।

73. अनुदानों, अधिमान्य ऋणों और ब्याज दरों, आय कर कार्यक्रमों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), प्रोत्साहन और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित अधिकतर कार्यक्रमों के संबंध में निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि उसने किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया है। फिर भी यह नोट करना आवश्यक है कि निर्यातक की प्रश्नावली में निर्यातक ने जो उत्तर दिए हैं, उसके विपरीत निर्यातक की वेबसाइट में दर्शाई गई सूचना उसका खंडन करती है।

74. निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि उसने “अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्यय की कटौती संबंधी कर नीतियों” और “ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो कि उच्च और नई प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं” के लिए आवेदन किया है, फिर भी उसने ऐसा दावा किया है कि कंपनी को घाटे होने के कारण निर्यातक ने कभी भी ऐसे लाभ प्राप्त नहीं किए थे।

75. घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत आरोपित स्कीमों के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

**1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रोत्साहन और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र -**

- (1) कार्यक्रम संख्या - 1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र (शंगाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़ कर) में स्थापित विदेशी निवेश से स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां : इनमें प्रतिकारी सहायिकियां शामिल हैं, जैसा कि यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राज्य के कर निर्धारण प्रशासन (एसएटी), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम), जो कि सरकारी निकाय है, द्वारा संचालित होता है। यह कार्यक्रम एफआईई को 15% की दर से आय कर की कटौती के रूप में लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित केवल एफआईई तक ही सीमित हैं। इस कार्यक्रम के विद्यमान होने की संपुष्टि जिन दस्तावेजों से हुई है वे इस प्रकार हैं : चीन जनवादी गणराज्य के कर नियम के अनुच्छेद 19 द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी उद्यम, 1991, राज्य परिषद की वर्ष 2007 की गुओ फा संख्या 39, चीन जनवादी गणराज्य के उद्यमी आय कर नियम, 2008, डब्ल्यूटीओ के दस्तावेज जी/एससीएमएन123/सीएचएन दिनांक 13 अप्रैल, 2006, डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/300, कुछ गाल्वेनाईज्ड स्टील वायर के बारे में कनाडा के अंतिम निर्णय, कुछ स्टेनलैस स्टील सिंक्स के बारे में कनाडा के अंतिम निर्णय। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे कि हाइड्रा ग्रीनी हाईड्रोलिक्स इक्विपमेंट एक्जेजारी (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड और एंटीक ब्रेकिंग सिस्टम्स (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड इसके पात्र हैं क्योंकि ये इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में अवस्थित हैं और ये एफआईई हैं।

- (2) कार्यक्रम संख्या - 2 : समुद्रतटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिकओर प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां : इनमें प्रतिकारी सहायिकियां शामिल हैं, जैसा कि यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय (एमओएफ),

राज्य का कर निर्धारण प्रशासन (एसएटी), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम), जो कि सरकारी निकाय है, द्वारा संचालित होता है। यह कार्यक्रम एफआईई को 15% की दर से और शहरों के पुराने शहरी जिलों में 24 % की दर से आय कर की कटौती के रूप में लाभ प्रदान करता है। इसकी स्थापना, समुद्री तटवर्तीय आर्थिक खुले क्षेत्रों तथा आर्थिक और प्रोद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में की गई है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ, समुद्री तटवर्तीय आर्थिक खुले क्षेत्रों तथा आर्थिक और प्रोद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थित केवल एफआईई तक ही सीमित हैं। इस कार्यक्रम के विद्यमान होने की संपुष्टि जिन दस्तावेजों से हुई है, वे इस प्रकार हैं : चीन जनवादी गणराज्य के आय कर द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी उद्यम (कर नियम), चीन जनवादी गणराज्य के आय कर द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी उद्यमों के आय कर नियम के क्रियान्वयन के लिए नियमावली के साथ चीन जनवादी गणराज्य के उद्यमी आय कर नियम, 2008, डब्ल्यूटीओ का दस्तावेज जी/एससीएम/एन/123/सीएचएन दिनांक 13 अप्रैल, 2006। जीओसी द्वारा स्थापित किए गए समुद्री तटवर्तीय आर्थिक खुले क्षेत्र इस प्रकार हैं : डलियान, क्निहुआनगडाओ, टिआन्जिन, वाईन्टाल, क्निगडाओ, लिआनयुआंगंग, नान्टोंग, शंघाई, निन्गबो, वेंझाऊ, फ्यूझाऊ, गुआंगझोऊ, झांजियांग, बेईहाई। कुछ गाल्वेनार्ड स्टील वायर के बारे में कनाडा के अंतिम निर्णय। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे कि गेक्सप्रो इंडस्ट्रीज सप्लाय शंघाई कंपनी लिमिटेड, हाइड्रा ग्रीनी हार्डटोलिक्स इक्विपमेंट एक्जेजारी (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड, सिनोवेल विंड ग्रुप कंपनी लिमिटेड और एंटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड इसकी पात्र कंपनियां हैं क्योंकि ये समुद्री तटवर्तीय आर्थिक खुले क्षेत्रों तथा आर्थिक और प्रोद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में अवस्थित हैं और ये एफआईई हैं।

- (3) **कार्यक्रम संख्या - 3 : शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां :** इनमें प्रतिकारी सहायिकियां शामिल हैं, जैसा कि यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राज्य का कर निर्धारण प्रशासन (एसएटी), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम), जो कि सरकारी निकाय है, द्वारा संचालित होता है। यह कार्यक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में अवस्थित एफआईई को आय कर की कटौती के रूप में अनुदान के लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ, निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित केवल एफआईई तक ही सीमित हैं। इस कार्यक्रम के विद्यमान होने की संपुष्टि निम्नोक्त दस्तावेजों द्वारा की गई है, नामतः राज्य परिषद की डिक्री (1991) संख्या 85 (30 जून, 1991), चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश (1991) संख्या 45 (9 अप्रैल, 1991), राज्य परिषद के परिपत्र गुओ की 2000 की फा संख्या 37, उद्यमी के आय कर से संबंधित पारगमन अधिमान्य नीतियों का अनुपालन करने के लिए राज्य परिषद की अधिसूचना, गुओ की 2007 की फा संख्या 39 और डब्ल्यूटी/टीपीआर/300, कुछ गाल्वेनार्ड स्टील वायर के बारे में कनाडा के अंतिम निर्णय। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे कि गेक्सप्रो इंडस्ट्रीज सप्लाय शंघाई कंपनी लिमिटेड और शंघाई झोंग झू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसकी पात्र कंपनियां हैं क्योंकि ये पुडोंग क्षेत्र में अवस्थित एफआईई हैं।

- (4) **कार्यक्रम संख्या - 4 : एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कापरेट आय कर में छूट और/अथवा कटौती :** इनमें प्रतिकारी सहायिकियां शामिल हैं, जैसा कि यह कार्यक्रम राज्य के कर निर्धारण प्रशासन (एसएटी) विभाग द्वारा संचालित होता है, जो कि एक सरकारी निकाय है। यह कार्यक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित उद्यमों को लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ, विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित कुछ उद्यमों तक ही सीमित हैं। इस कार्यक्रम के विद्यमान होने की संपुष्टि निम्नोक्त दस्तावेजों द्वारा की गई है, नामतः चीन जनवादी गणराज्य के कर नियम, 2008 के अनुच्छेद 28.2, चीन जनवादी गणराज्य के उद्यमी आय कर नियम के क्रियान्वयन संबंधी विनियम के अनुच्छेद 93, परिषद द्वारा, "वित्त मंत्रालय, कर निर्धारण का राज्य प्रशासन, संसाधनों के गहन उपयोग संबंधी राज्य विकास और सुधार आयोग द्वारा घोषित कापरेट आय कर केटालॉग (2008 संस्करण) नोटिस" {काल शुई (2008) संख्या 117} (2008), विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए चीन जनवादी गणराज्य के उद्यम आय कर नियम, राज्य परिषद द्वारा जारी परिपत्र गुओफा (2014) संख्या 14 (2014), राज्य परिषद का नोटिस 40, कापरेट आय कर का अनुच्छेद 57, चीन जनवादी गणराज्य के अध्यक्ष की डिक्री संख्या 63, 2007, चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद की डिक्री संख्या 516, 2007, डब्ल्यूटीओ की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट - जी जी/एससीएम/एन/एन/274/सीएचएन-2014, डब्ल्यूटीओ का दस्तावेज डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/300, डब्ल्यूटीओ का दस्तावेज जी/एससीएम/एन/एन/123/सीएचएन दिनांक 13 अप्रैल, 2006 और कुछ गाल्वेनार्ड स्टील वायर के बारे में कनाडा के अंतिम निर्णय। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे कि जिआंग्सू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड, एंटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड, डालियान हुआरूई हेवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, गेमेसा विंड (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड, गेक्सप्रो

इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कंपनी लिमिटेड, हाईड्रा ग्रेने हाईड्रोलिक्स ईक्विपमेंट एक्सेसरी (टिआंजिन) कंपनी लिमिटेड, जिआंगियन फेंगडियान फलेंज फलेंज मेन्युफेक्चरर कंपनी लिमिटेड, जिआंगियन हेंगरून रिंग फोरजिंग कंपनी लिमिटेड, क्वाईगडो अनुहा न्यू एनर्जी ईक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड, क्वाईगडो रिचुआन प्रीसिजनमशीनरी कंपनी लिमिटेड इसकी पात्र कंपनियां हैं क्योंकि ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित हैं।

- v. **कार्यक्रम सं. 5 : एस ई जैड तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में (एफ आई ई के लिए) स्थानीय आयकर से छूट और/ अथवा कमी** – इसमें प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एक लोक निकाय वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), राज्य कर प्रशासन (एस ए टी), वाणिज्य मंत्रालय, (एम ओ एफ सी ओ एम) द्वारा किया जाता है, कार्यक्रम में कम आयकर के रूप में ऐसे एफ आई ई को लाभ प्रदान किया गया है जो विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) और अन्य निर्दिष्ट जोनों में स्थित होते हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट जोनों में स्थित होते हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ विशिष्ट एस ई जैड और निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित कुछ एफ आई ई के लिए ही सीमित है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी विदेशी निवेश और विदेशी उद्यमों के साथ उद्यमों के लिए चीन जन. गण. के आयकर कानून (कर कानून); अनुच्छेद 5, विदेशी निवेश और विदेशी उद्यमों के साथ उद्यमों के लिए चीन जन. गण. के आयकर कानून के संबंध में विनियमन; ग्वांगडोंग प्रांत में विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में विनियमन (1980-08-26); हैनन द्वीप को विकसित करने में निवेश को प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य परिषद के प्रावधान (1988-0-04); विश्व व्यापार संगठन का दिनांक 13 अप्रैल, 2006 का दस्तावेज सं. जी/एस सी एम/एन/123/सी एच एन द्वारा प्रमाणित की गई है। कतिपय गाल्वेनाइज्ड स्टील तार के संबंध में कनाडा के अंतिम जांच परिणाम; कतिपय स्टेनलैस स्टील सिंक के संबंध में कनाडा के अंतिम जांच परिणाम; चीन के कास्टिंग विनिर्माता, जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक इक्विपमेंट एक्सेसरी (तियांजिन) कं. लि., गेक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि. पात्र हैं क्योंकि इन्हें विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जैड) तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।

- vi. **कार्यक्रम सं. 6 : विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जैड) और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में (एफ आई ई के लिए) आयातित सामग्रियों और उपस्कर के संबंध में टैरिफ और मूल्यवर्धित कर (वैट) की छूट** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एक लोक निकाय, वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), राज्य कर प्रशासन (एस ए टी), वाणिज्य मंत्रालय (एम ओ एफ सी ओ एम) द्वारा किया जाता है, कार्यक्रम में विदेशी निवेश के मार्गनिर्देशन के लिए उद्योगों की सूची में “प्रोत्साहित” अथवा “प्रतिबंधित” निर्णयों में आने वाले एस ई जैड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित एफ आई ई को लाभ प्रदान किया गया है और उपस्करों के टैरिफ तथा आयात में वैट से छूट प्रदान की जाएगी। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल विशिष्ट एस ई जैड और निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित कतिपय एफ आई ई के लिए ही सीमित है। कार्यक्रम की मौजूदगी, आयातित उपस्करों के लिए कराधान नीतियों के समायोजन से संबंधित राज्य परिषद के नोटिस के अनुच्छेद 1 और 2 (गुओ फा (1997) सं. 37) तथा विदेशी निवेश के मार्गनिर्देशन के लिए उद्योगों की सूची (2004) (30 नवंबर, 2007 तक) अथवा विदेशी निवेश के मार्गनिर्देशन के लिए उद्योगों की सूची (2007) (1 दिसंबर, 2007 के बाद); राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) की घोषणा सं. 2014 की 49; राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) की घोषणा सं. 2014 की 49; राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) की घोषणा सं. 2014 की 51; विश्व व्यापार संगठन अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट कनाडा, दस्तावेज सं. जी/एस सी एम/एन 274/सी ए एन, दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा प्रमाणित की गई है। चीन के कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील सिंक के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम और कतिपय स्टेनलैस स्टील के सिंक के संबंध में कनाडा के अंतिम जांच परिणाम, चीन के कास्टिंग विनिर्माता गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि., हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक इक्विपमेंट एक्सेसरी (तियांजिन) कं. लि., साइनवेल विंड ग्रुप कं. लि. तथा एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि. पात्र हैं क्योंकि वे कथित एस ई जैड और निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं।

- vii. **कार्यक्रम सं. 7 : कास्टिंग और फोर्जिंग प्रणाली के लिए अधिमानी कर** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) और राज्य कर प्रशासन (एस ए टी), द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है, और अधिमानी कर व्यवस्था अर्थात् कर बचत के रूप में चीन जन. गण. में कास्टिंग विनिर्माताओं को लाभ प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे विशिष्ट उद्यमों तक ही सीमित है जो परिपत्र के साथ संलग्न सूची में दिए गए उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री कर रहे हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे वास्तविक रूप से संकलित वैट का 35 प्रतिशत वापस करने के लिए पात्र होंगे। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे उद्यमों तक ही सीमित है जो कास्टिंग जैसे उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, जो उक्त लाभ के पात्र हैं। कार्यक्रम का अस्तित्व वित्त मंत्रालय के परिपत्र काई शुई सं 2003 का 96 और चीन के नवीकरणीय ऊर्जा कानून के अनुच्छेद 24, 25 और 26 द्वारा प्रमाणित किया गया है। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अंतिम जांच परिणाम में भी योजना को प्रतिसंतुलनकारी माना गया है। कतिपय सीमलैस कार्बन और अलॉय स्टील स्टेन्डर्ड, पी आर सी से लाइन और प्रैसर पाइप के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम में भी योजना को प्रतिसंतुलनकारी माना है।

## II. अनुदान

- viii. **कार्यक्रम सं. 8 : राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एक लोक निकाय, वाणिज्य मंत्रालय (एम ओ एफ सी ओ एम) द्वारा किया जाता है, कार्यक्रम में ऐसे बड़े आकार के एस ओ ई को लाभ प्रदान किया गया है जो उद्यम के लिए या तो सीधे सरकार के अंशदान से या कम व्याज के ऋण का प्रावधान

करके 512 प्रमुख उद्योगों के बीच हाई क्रेडिट रैंक बनाए हुए हैं, जहां पर कि सरकार ने उद्यम के ऋणों के लिए ब्याज का भुगतान किया है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे एस ओ ई तक ही सीमित है, जिनकी 512 प्रमुख उद्योगों के बीच हाई क्रेडिट रैंक बनी हुई है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण विशेष निधि के प्रशासन के लिए उपाय ; "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपायों " तथा "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना के लिए ट्रेजरी बांड विशेष निधि के प्रशासन के लिए उपायों " के प्रख्यापन और प्रचालन के संबंध में नोटिस (गुओ जिंग माओ तोऊ जी (1999) सं. 886 (नोटिस); "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के प्रशासन के लिए उपाय " के संशोधनों के नोटिस और "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकीय नवीकरण परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी-बांड विशेष निधि के प्रशासन के लिए उपाय" (गुओजिंग माओ तोऊ जी {2000} सं. 822), गुओजिंग माओ तोऊ जी सं. 1999 की 122 ; राज्य आर्थिक और व्यापार आयोग से "राष्ट्रीय प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और प्रशासन के लिए उपाय " के प्रख्यापन और परिचालन के संबंध में नोटिस (ट्रेल क्रियान्वयन के लिए) (गुओ जिंग माओ तोऊ जी (1999) सं. 1038; विश्व व्यापार संगठन दस्तावेज जी/एस सी एम/क्यू2/सी एच एन/28; डब्ल्यू टी ओ -जी/एस सी एम/क्यू 2/सी एच एन/42 - 2011)। चीन से कतिपय नॉन ओरियटेंड इलैक्ट्रिक स्टील के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम; कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील के संबंध में यूरोपीय संघ के अंतिम जांच परिणाम; कतिपय गालवेनाइज्ड स्टील की तार के संबंध में कनाडा के अंतिम जांच परिणाम ; कनाडा से कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक ; चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जैसे सियाली विंड पावर तथा निंगबो जिंगलॉग टेक्नोलॉजी कं. पात्र हैं क्योंकि वे एस ओ ई हैं।

- ix. **कार्यक्रम सं. 9 : स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी और/ अथवा प्रतिसंतुलनकारी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण वाणिज्य मंत्रालय और प्रादेशिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, जो कि लोक निकाय हैं और ऐसी कंपनियों को लाभ प्रदान करते हैं, जो पाटनरोधी जांचों में शामिल हैं और वाणिज्य मंत्रालय तथा प्रादेशिक प्राधिकरणों के अनुदेशों का पालन करते हैं, वे पाटनरोधी जांचों में भाग लेने के उपरांत 40 प्रतिशत तक की कानूनी फीस लेने के लिए पात्र हैं। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे संबंधित उद्यमों तक ही सीमित हैं, जो ए डी डी अथवा सी वी डी जांचों में शामिल हैं। इस कार्यक्रम की मौजूदगी पाटनरोधी ,सब्सिडी रोधी और सुरक्षा जांच के लिए सहायक नीति कार्यान्वित करने के लिए नियम हैं। चीन से कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रॉड के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम, यूरोपीय संघ - कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील; कनाडा - कतिपय गालवेनाइज्ड स्टील वायर ; कनाडा - कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक।
- x. **कार्यक्रम सं. 10 : अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण स्थानीय एवं नगरपालिका शासन जैसे बीजिंग म्युनिसिपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिशन तथा वुक्सिंग जिले की सरकार और वुक्सिंग जिला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो (एस टी बी) द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय हैं। यह आर्थिक विकास पद्धति तथा आर्थिक पुनर्गठन के निर्माण में तेजी लाने, जिले के आत्मनिर्भरता नवोन्मेष की क्षमता में वृद्धि करने ; "नवोन्मेषी नगरीय जिले " पर रणनीति को कार्यान्वित करने और मजबूत और तीव्र आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहने हेतु लाभ प्रदान करते हैं। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे संबंधित उद्यमों के लिए ही सीमित है, जिनके पास अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सुविधाएं हैं और जो पात्रता के मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यक्रम का अस्तित्व विदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह के उद्यमों का अर्जन करने और शेनियांग आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र के प्रशासन की विदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास टीम की नियुक्ति करने ; वुक्सिंग जिले के तीन प्रकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व्ययों पर प्रबंधकीय उपायों के प्रकाशन और निगमन के संबंध में वुक्सिंग जिले के लोक शासन कार्यालय को नोटिस जारी करने के संबंध में है। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय स्टेनलेस स्टील के लिंक के संबंध में कनाडा के अंतिम जांच परिणाम और कनाडा - कतिपय गालवेनाइज्ड स्टील वायर, चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. तथा झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कं. लि.।
- xi. **कार्यक्रम सं. 11 : नवोन्मेषी प्रायोगिक उद्यम अनुदान** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इसके विभिन्न प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय हैं, जैसे कि झेजियांग प्रांत। योजना के तहत लाभ छोटे तथा मझोले आकार में उद्यमों के लिए है, जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ केवल ऐसे विशिष्ट प्रांतों और छोटे तथा मझोले उद्यमों (एस एम ई) के लिए ही सीमित है, जो पात्रता के मानदंडों के अन्तर्गत आते हैं। कार्यक्रम का अस्तित्व छोटे तथा मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के संबंध में पी आर सी कानून के अनुच्छेद 10 और 11, छोटे तथा मझोले उद्यमों (एस एम ई)

के विकास के लिए विशेष निकायों के प्रशासन के संबंध में उपाय जारी करने पर उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के नोटिस (वित्त मंत्रालय की क्रमांक 96 (2012), छोटे तथा मझोले उद्यमों (एस एम ई) के विकास के लिए विशेष निधि अन्तरिक उपाय जारी करने के संबंध में उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के नोटिस (काई क्यूई (2014) सं. 38) , " छोटे तथा मझोले उद्यमों (एस एम ई) के विकास के लिए विशेष निधि के प्रबंधन के संबंध में अन्तरिम उपाय जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के नोटिस (काई जियान (2015) सं. 458) से प्रमाणित है। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे झेजियांग प्रांत के जियाली विंड पावर और निंगबो जिनलोंग टेक्नोलॉजी कं. लि. जैसे कुछ निर्यातक ऐसे अनुदान के लिए पात्र हैं। संदर्भ अलॉय और कार्बन स्टील वायर रोड के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम।

- xii. **कार्यक्रम सं. 12 : सुपरस्टार उद्यम अनुदान** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन जन.गण. सरकार द्वारा प्रांतीय प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, जो एक लोक निकाय है। मात्र उद्यम के पास 'आउटपुट बिक्री होना चाहिए जो अनुदान की पात्रता में आता है' यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल कुछ विशिष्ट उद्यमों तक ही सीमित हैं जिनके पास अपेक्षित आउटपुट बिक्री है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व सुपरस्टार उद्यमों तथा उत्कृष्ट उद्यमों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए उपाय, सुपरस्टार उद्यमों, उत्कृष्ट उद्यमों और मुख्य उद्यमों के लिए मानदंडों की घोषणा के संबंध में हुआ सरकार कार्यालय का नोटिस है। चीन के कास्टिंग उत्पादक जियांगसू एफ ए डब्ल्यू फाउंड्री कं. लि., डेकिंग जुफेंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कं. लि. तथा जियाली विंड पावर जैसे कुछ निर्यातक ऐसे अनुदान के लिए पात्र हैं।
- xiii. **कार्यक्रम सं. 13 : ऐसे उद्यमों को पुरस्कृत करना, जिनके उत्पाद "चीन के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क" अथवा "चीन के प्रसिद्ध ब्रांड" की अपेक्षा पूरी करते हैं**, इनमें प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन की सरकार द्वारा राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन स्तरों पर किया जाता है, यह एक लोक निकाय है। पात्र उद्यम केवल ऐसे प्रमुख उद्यमों तक ही सीमित हैं, जिनके उत्पाद 'चीन के विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड' की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, वे इस लाभ के लिए पात्र ही यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे उद्यमों तक ही सीमित है, जिनके उत्पाद 'चीन के विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड' और/ अथवा 'प्रसिद्ध ट्रेडमार्क (चीन के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। कार्यक्रम का अस्तित्व आदेश सं. 124 - चीन के प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के प्रशासन के लिए उपाय - दिसम्बर, 2009 चीन के प्रसिद्ध ब्रांड-उत्पादों के प्रशासन के लिए उपाय - दिसम्बर, 2006, व्यापार नीति समीक्षा डब्ल्यू टी /टी पी आर/ एस/300, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) रिपोर्ट जी /एस सी एम /क्यू 2/सी एच एन/ 42) चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन तथा ताइवान से नॉन-ओरिएंटेड इलैक्ट्रिक स्टीम के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम, चीन से कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड के संबंध में यू एस के अंतिम जांच परिणाम तथा चीन जन. गण. के मूल के सोलर ग्लास के संबंध में यूरोपीय संघ के अंतिम जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादक जियाली विंड पावर, डालियन हुआरूई हैवी इंडस्ट्री स्टील कास्टिंग कं. लि. तथा जियांगसू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि. कुछ ऐसे निर्यातक हैं, जो इस अनुदान के लिए पात्र हैं।
- xiv. **कार्यक्रम सं. 14 : हाई टैक उद्योग की उद्यम निवेश निधि** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम की अनुरक्षण चीन की सरकार के एन डी आर सी और राष्ट्रीय, प्रांतीय/ नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, जो कि लोक निकाय हैं, पात्र उद्यमों को एन डी आर सी के संगत स्थानीय भागीदार के साथ दर्ज होना चाहिए। ये निदेश कंपनियां हाई टैक उद्यमों के रूप में मान्य होनी चाहिए और जो छोटे और मझोले आकार के होंगे, उन्हें लाभान्वित किया जाता है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम ने अन्तर्गत लाभ केवल ऐसे उद्यमों तक ही सीमित है, जिनके हाई-टैक कार्यक्रम हैं और हाई टैक जोन अथवा शहर में अथवा बीजिंग, शंघाई, तियांजिन, चोंगकिंग जैसे प्रांतों में स्थित हाई टैक पार्क में स्थित हैं। कार्यक्रम का अस्तित्व अस्थायी प्रशासन उपाय - 2005 के रूप में चोंगकिंग सरकार के कार्यालय के परिपत्र, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के दस्तावेज जी /एस सी एम /एन/267/सी ए एन तथा चाइना मार्केट रेगुलेटरी ओवरव्यू - 2013 में वेब रिसर्च उद्यमीय पूंजी निवेश से प्रमाणित है। पी आर सी से कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक के संबंध में कनाडा के अंतिम जांच परिणाम, गालवेनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम एक्सट्रेक्ट्स स्टील और एल्यूमिनियम जिंक कोटेड स्टील के संबंध में आस्ट्रेलिया अंतिम जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादक गेमेसा विंड (ट्राइजिन) कं.लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (ट्राइजिन) कं. लि., हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट एससरी (ट्राइजिन) कं. लि. शंकाई एस एस आई सी ई एण्ड ए इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.; साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि., जो बीजिंग, शंघाई, ट्राइजिन तथा चोंगकिंग में स्थित हैं।



- xv. **कार्यक्रम सं. 15 : विदेशी निवेश से मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना करने को बढ़ावा देने के लिए अनुदान** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण प्रांतों के स्थानीय वाणिज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, जो कि लोक निकाय हैं। कार्यक्रम में गुआंगजोऊ जैसे प्रांतों में स्थित एफ आई ई को लाभ प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व "मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के संबंध में गुआंगजोऊ को प्रोत्साहित करने के संबंध में गुआंगजोऊ नगरपालिका सरकार के सामान्य कार्यालय के नोटिस' (सं. 34 (2006) जो बाद में "मुख्यालय की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रेषित विचारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए गुआंगजोऊ नगरपालिका की सरकार (सुई (2012) 2" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के संबंध में गुआंगजोऊ नगरपालिका का प्रावधान ; चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि. जो गुआंगजोऊ नगरपालिका में स्थित है।
- xvi **कार्यक्रम सं. 16 : नवोन्मेमी छोटे तथा मझोले उद्यमों के अनुदानों** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन की सरकार द्वारा राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार के स्तर पर किया जाता है, जैसे गुआंगडोंग प्रांत की सरकार इस कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जो एक लोक निकाय हैं। कार्यक्रम में प्रमुख परियोजनाओं के लिए आर एंड डी द्वारा मान्यता प्राप्त छोटी फर्मों के लिए शुरूआती पूंजी में छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों (एस एम ई) को लाभ प्रदान किया गया है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों (एस एम ई) को बढ़ावा देने के लिए पी आर सी कानून के अनुच्छेद 12, 13, 36 द्वारा स्थापित किया गया है। छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों की अन्तर्राष्ट्रीय विपणन विकास निधियों के प्रशासन के लिए उपाय, छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों की अन्तर्राष्ट्रीय विपणन विकास निधियों के प्रशासन के लिए उपायों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियमों (1 जुलाई, 2001), छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विपणन विकास निधियों के प्रशासन के उपायों से संबंधित परिपत्र (2010), विदेश व्यापार विकास कोष और प्रबंधन संकल्पना, कार्डी क्यूई (2014), "छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों (एस एम ई) के विकास के लिए विशेष निधियों के प्रशासन के लिए उपाय" वित्त मंत्रालय का नोटिस (सं. 96 (2012) ; वित्त मंत्रालय तथा उद्यो एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोटिस (कार्डी क्यूई (2014) सं. 38) और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी " 'छोटे तथा मझोले आकार के उद्यमों (एस एम ई) के विकास के लिए विशेष निधियों के प्रबंधन पर अंतरिम उपाय" (कार्डी जियन (2015) सं. 458) चीन के कास्टिंग उत्पादक जियाली विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि. इस अनुदान की पात्र हैं ।
- xvii **कार्यक्रम सं. 17 : निजी स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों को अनुदान** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण युनान प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है । कार्यक्रम में युनान प्रांत में स्थित गैर - एस ओ ई को लाभ प्रदान किया गया है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह विशिष्ट प्रांत में स्थित गैर- एस ओ ई के लिए ही सीमित है । इस कार्यक्रम का अस्तित्व गैर - राज्य स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के संबंध में जारी नोटिस से प्रमाणित है , जिसमें कि उद्यमों की पात्रता उल्लिखित है।
- III. **इक्रीटी कार्यक्रम**
- xviii **कार्यक्रम सं. 18 : इक्रीटी प्रदान करना** जिसमें एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि इस कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन की सरकार द्वारा राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों, के सी आई सी सी और एस ए एस ए सी के स्तर पर किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। इसमें ऐसी कंपनियों को लाभ प्रदान किया गया है, जहां पर कि सरकार अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिकार के अर्जन के बिना प्रमुख शेयरधारक है। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में अंतिम जांच परिणाम भी योजना को प्रति संतुलनकारी बनाते हैं। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह सीमित संख्या में ऐसे चुनिन्दा संस्थानों तक ही सीमित है जिनमें कि सरकार ने भाग लिया है।
- xix. **कार्यक्रम सं. 19 : भुगतान न किए गए लाभांश** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार के स्तर पर किया जाता है, जो कि एक लोक प्राधिकरण हैं। इसमें सीमित संख्या में ऐसी चुनिन्दा संस्थाओं को लाभ प्रदान किया जाता है, जिनमें कि सरकार सहभागी है और इसीलिए यह विशिष्ट है। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अंतिम जांच परिणाम में भी योजना को प्रतिसंतुलनकारी पाया गया है।

#### IV. अधिमान्य ऋण

xx. कार्यक्रम सं. 20 : कास्टिंग उद्योग के लिए अधिमान्य ऋण और ब्याज की दरें - इसमें एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार, सी आई सी सी तथा एस ए एस ए सी के स्तर पर किया जाता है जो कि एक लोक निकाय है। यह उद्योग के विस्तार में सहायता और विकास करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों से कम (सब्सिडी प्राप्त) ब्याज पर ऋण प्रदान करके कास्टिंग उत्पादकों को लाभ प्रदान कर रहा है। चीन सरकार चीन में स्थापित कई प्रमुख बैंकों में प्रमुख शेयरधारक है इसलिए बैंकों तक उसकी पहुंच है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह सीमित संख्या में ऐसी चुनिन्दा संस्थाओं तक ही सीमित है जिनमें कि सरकार की भागीदारी होती है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व यिनफा (2003) सं. 250 और यिनफा (2004) सं. 251; चीन के बैंकों की कार्मिक रिपोर्ट; विदेशी निवेश उद्योगों के मार्ग निर्देशन के लिए सूचिका (कैटलॉग) (2011 में संशोधित); वाणिज्यिक बैंकिंग कानून (2003) का अनुच्छेद 34 और 38 ; एन डी आर सी आदेश सं. 35 - आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के विकास के लिए नीतियां, आदेश सं. 40 तथा वाणिज्यिक बैंकों संबंधी कानून अधिनियम की धारा 24 25, 34, जो सरकार की औद्योगिक नीतियों की पूर्ति के संबंध में हैं ; चीन के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में 2006 डच बैंक रिसर्च ; दस्तावेज डब्ल्यू टी /टी पी आर /एस / 230, पृष्ठ 79, अप्रैल 2010; दस्तावेज डब्ल्यू टी /टी पी आर /एस/264 पृष्ठ 122, जुलाई 2012; यह सूचना चीन के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में 2006 डच बैंक रिसर्च, पृष्ठ 3-4 से ली गई है; यह सूचना चीन की आर्थिक रिपोर्ट क्वार्टर टू, 2010; मोनेटरी पॉलिसी एनालिसिस ग्रुप आफ पीपल बैंक ऑफ चाइना, दिनांक 5 अगस्त, 2010, पृष्ठ 10 से ली गई है। आई एम एफ वर्किंग पेपर, "चीन के बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में प्रगति" क्या बैंक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ ?", डब्ल्यू पी/06/71, मार्च, 2006 (पृष्ठ 3-4, 13, 18-20 देखें); आई एम एफ वर्किंग पेपर, " चीन में ब्याज दर को उदार बनाना", डब्ल्यू पी /09/171, अगस्त, 2009, (देखें पृष्ठ 3-4, 21-23); आई एम एफ कंट्री रिपोर्ट, पी आर सी : 2010 आर्टिकल IV कंसल्टेशन, सं. 10/ 238, जुलाई, 2010 (देखें पृष्ठ 22, 24 तथा 26 - 29); ओ ई सी डी 2010 , चीन का आर्थिक सर्वेक्षण, फरवरी, 2010, (देखें अध्याय 3, पृष्ठ 71, 73-81, 97) ओई सी डी, चीन के वित्तीय क्षेत्र के सुधार, इकॉनॉमिक डिपार्टमेंट वर्किंग पेपर सं. 747, ई सी ओ /डब्ल्यू के पी (2010) 3, 01 फरवरी, 2010 (देखें पृष्ठ 2, 8 - 15, 36) ; स्टील इंडस्ट्री के लिए समायोजन और पुनरुद्धार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत नियम (2009) में - "प्रमुख महत्वपूर्ण उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि" के लिए प्रावधान किए गए हैं। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अंतिम जांच परिणामों में भी योजना को प्रतिसंतुलनकारी पाया गया है।

#### V. अधिमान्य आयकर कार्यक्रम

xxi. कार्यक्रम सं. 21 : उत्पादनकारी एफ आई ई के लिए कम की गई कर दरें, जो न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालित करने हेतु अनुसूचित हैं- इसमें एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि इस कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), वाणिज्य मंत्रालय (एफ ओ एफ सी ओ एम), राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) तथा स्थानीय कर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह ऐसे एफ आई ई को लाभ प्रदान करता है, जो लाभ कमाने के लिए शुरू किया गया है। उन्हें पहले और दूसरे वर्षों में आयकर से पूरी छूट और तीसरे, चौथे तथा पांचवें वर्षों में आयकर से 50% की छूट मिल सकती है। आयकर पर सामान्य छूट के संबंध में, चाहे इस आय (लाभ) से जो भी क्रियाकलाप सृजित हो, यह माना गया है कि इस कार्यक्रम के तहत प्राप्तकर्ता उद्यम को सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाएगा। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह ऐसे एफ आई ई तक ही सीमित है, जो लाभ कमा रहे हैं। इस कार्यक्रम का अस्तित्व एफ आई ई आयकर कानून के अनुच्छेद 8, डिक्री [1991] सं. 85, राज्य परिषद [30 जून, 1991], चीन जन. गण. के राष्ट्रपति का आदेश [1991] सं. 45 [9 अप्रैल, 91], राज्य परिषद परिपत्र गुआ फा सं. 39 (2007) ; विश्व व्यापार संगठन दस्तावेज जी/एस सी एम/ एन/ 123/सी एफ एन , दिनांक 13 अप्रैल, 2006 ; उद्यम आय कर कानून, 2008 द्वारा प्रमाणित है। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक के संबंध में कनाडा के अन्तिम जांच परिणाम, चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणामों में भी योजना को प्रतिसंतुलनकारी माना गया है। चीन के कास्टिंग उत्पाद जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि. तथा गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि. तथा साइनोबेल विंड ग्रुप कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।

- xxii. **कार्यक्रम सं. 22 : विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियों में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है** क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) , वाणिज्य मंत्रालय (एम ओ एफ सी ओ एम) , राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) तथा इसके स्थानीय कर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह निवेश किए गए ऐसे निर्यातोन्मुखी उद्यमों को लाभ प्रदान करता है, जो विदेशी कारोबार द्वारा संचालित है, जिसके लिए किसी भी वर्ष में उस वर्ष के लिए उद्यमों के उत्पादों के आऊटपुट मूल्य के 70% अथवा अधिक तक की सभी निर्यात उत्पाद राशि को आऊटपुट मूल्य के लिए कर कानून में विनिर्दिष्ट कर की दर पर उद्यम आयकर में आधा प्रतिशत तक की कमी की जाती है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह ऐसे एफ आई ई तक सीमित है, जहां निर्यात में कंपनी की 70 % बिक्री शामिल है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व उद्यम आयकर अधिमान्य नीतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) और राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) के परिपत्र आई शुई [2009] सं. 69 ; चीन के उद्यम आय कर ; एस ए टी परिपत्र गुओ शुई फा सं. 1/2013; परिपत्र 115 – अक्टूबर, 2009; एस ए टी परिपत्र गुओ शुई फा सं. 139/1995; परिपत्र आई शुई (2014) सं. 59 और 65; चीन का औद्योगिक सब्सिडी अध्ययन (2007); डब्ल्यू टी/टी पी आर/एस/300; जी/एस सी एम/एन/123/सी एच एन; जी/एस सी एम/क्यू2/ सी एच एन/25; जी/एस सी एम/ क्यू2/सी एच एन/29; जी/एस सी एम/एन/274/सी ए एन; जी/एस सी एम/क्यू2/सी एच एन/ 48; जी/एस सी एम/एन/155/सी एच एन; जी/एस सी एम/एन/186/सी एच एन; जी/एस सी एम /एन/235/सी एन ; - 2012 – के तहत प्रमाणित है। चीन जन. गण. कतिपय थर्मोइलैक्ट्रिक कूलर तथा वार्मर; यूएस – कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड ; यू एस- सोडियम नाइट्रेट चीन जन. गण. में जांच सूची का प्रारंभ ; चीन जन. गण. से कतिपय ऑयल कन्ट्री ट्यूबलर वस्तुएं ; चीन जन. गण. से कतिपय सीमलेस कास्टिंग ; यूरोपीय संघ - कतिपय आर्गेनिक स्टील उत्पाद – 2013; यूरोपीय संघ – कोटेड फाइन पेपर – 2011, चीन से कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड के संबंध में यू एस के अन्तिम जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे हाइड्रा ग्रेने – हाइड्रोलिक इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि. तथा गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (तियांजिन) कं. लि. तथा साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।
- xxiii. **कार्यक्रम सं. 23 : गहन प्रौद्योगिकी और गहन ज्ञान वाले एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियों में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है,** क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), वाणिज्य मंत्रालय (एम ओ एफ सी ओ एम), राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) तथा इसके स्थानीय कर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। इसमें विदेशी निवेश वाले ऐसे उद्यमों को लाभ प्रदान किया गया है जो गहन प्रौद्योगिकी और गहन ज्ञान वाले हैं, और जिनके प्रमुख उत्पादों को, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित “चीन के उच्च और नए प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची” में सूचीबद्ध किया गया है और इन उत्पादों का उस वर्ष का बिक्री राजस्व, उस उद्यम के कुल वार्षिक बिक्री राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक है, उन पर 15 प्रतिशत की दर पर कर कम किया गया उद्यम आय कर लगाया जाएगा। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह “उच्च” अथवा “नए” प्रौद्योगिकी उद्यमों अथवा “उच्च” अथवा “नए” प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास जोनों में स्थापित किए गए एफ आई ई तक ही सीमित है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व एस ए टी परिपत्र गुओ शुई फा सं. 139/1995; एस ए परिपत्र गुओ शुई फा सं. 135/2003; जी/एस सी एम/एन/123/सी एच एन ; जी/एस सी एम/क्यू2/सी एच एन/25; जी/एस सी एम/ एन/267/सी ए एन द्वारा स्थापित है। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि. तथा गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (तियांजिन) कं. लि. तथा साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।
- xxiv. **कार्यक्रम सं. 24 : एफ आई ई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां-** इसमें एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण (एस ए टी) और इसके स्थानीय कर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह आर एंड डी क्रियाकलापों को करने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यमों को विदेशी निवेश का लाभ प्रदान करता है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह आर एंड डी क्रियाकलापों को करने वाले एफ आई ई तक ही सीमित है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व प्रख्यापन और परिचालन से संबंधित नोटिस है और विदेशी निवेश उद्यमों के साथ प्रौद्योगिकी विकास शुल्क के संबंध में आफसेट करयोग्य आय से संबंधित मामलों पर राज्य कर प्रशासन के परिपत्र में एफ आई ई के लिए इस कार्यक्रम के तहत आय कर आफसेट प्रदान किया गया है (गुओ शुई फा [1999] सं. 173) (एफ आई ई- आर एंड डी कर आफसेट), तकनीकी, नवोन्मेषी उद्यमों के संबंध में उद्यम आयकर के लिए अधिमान्य नीतियों पर राज्य करप्रधान प्रशासन और वित्त मंत्रालय के परिपत्र में सभी उद्यमों के लिए इस कार्यक्रम के तहत आय कर आफसेट प्रदान किया गया है। (आई शुई जी [2006] सं. 8) (उद्यम आर एंड डी कर आफसेट) ; विदेशी निवेश वाले अनुसंधान व विकास केन्द्रों को प्रदत्त छूट और कर

वापसी के लिए उपायों के संबंध में परिपत्र ; चीन जन. गण. के अध्यक्ष की डिक्री - 63 - उद्यम आय कर के अनुच्छेद 30, 95 ; डब्ल्यू टी/टी आर एस/300 ; जी/एस सी एम/क्यू2 / सी एच एन / 49 - अक्टूबर, 2013 ; जी/एस सी एम/एन/267/सी ए एन - अर्धवार्षिक रिपोर्ट ; जी/एस सी एम/एन/123/ सी एच एन ; जी/एस सी एम/क्यू2/सी एच एन/25 ; कोटेड फाइन पेपर के संबंध में यूरोपिय संघ के अन्तिम जांच परिणाम (2011); कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड के संबंध यू एस अन्तिम जांच परिणाम ; चीन के कार्स्टिंग उत्पादक जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रो लिक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि. तथा साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।

xxv. **कार्यक्रम सं. 25 :** एफ आई ई और ऐसे विदेशी उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जिनके पास चीन में संस्थापनाएं अथवा स्थान हैं तथा जो उत्पादन अथवा कारोबारी प्रचालनों में शामिल हैं और घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद कर रहे हैं- इसमें एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि इस कार्यक्रम का अनुरक्षण (एस ए टी) और इसके स्थानीय कर व्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। इसमें ऐसे एफ आई ई को लाभ प्रदान किया गया है जो चीन निर्मित उपस्करों में निवेश करते हैं और जिनकी परियोजनाएं विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक मार्ग निर्देश की सूचिका की प्रोत्साहित अथवा प्रतिबंधित वी श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह एफ आई ई तक ही सीमित है और यह आयातित वस्तुओं की अपेक्षा घरेलू उपयोग करने के संबंध में प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व आयात की गैर - शुल्क छूट योग्य वस्तुओं की सूचिका (2012 समायोजित) ; घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद के संबंध में एफ आई ई के लिए आय कर क्रेडिट ; कर के प्रशासन के लिए अन्तरिम उपाय प्रदान करने के संबंध में राज्य कर प्रशासन का परिपत्र ; विदेशी निवेश उद्यमों के मार्गनिर्देशन के लिए सूचिका (2011 में संशोधित) ; आयातित उपस्करों की कर नीतियों के समायोजन के संबंध में राज्य परिषद का परिपत्र (गुओ फा [1997] सं. 37) ; प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपस्करों एवं मशीनरी के संबंध में आयात स्तरीय कर नीतियों के समायोजन के संबंध में नोटिस (काई गुआनशुई [2014] सं. 2); जी/एस सी एम/एन/ 123 - सी एच एन दस्तावेज ; जी/एस सी एम/ एन/155/सी एच एन - दस्तावेज ; और जी/ एस सी एम/एन/86/सी एच एन दस्तावेज ; जी/एस सी एम/एन/267/सी ए एन - कनाडा - चीन जन. गण. के कार्स्टिंग उत्पादकों जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रो लिक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि. और गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि. से कतिपय गाल्वेनाइज्ड स्टील वायर ; एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि. और साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।

xxvi. **कार्यक्रम सं. 26 :** प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयोजन के लिए घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद करने वाले घरेलू उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियों में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय और राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह घरेलू उद्यमों को लाभ प्रदान करता है, जिन्हें प्रौद्योगिकीय उन्नयन परियोजनाओं के लिए घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद के लिए अधिमान्य कर व्यवहार प्रदान किया जाता है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह ऐसे घरेलू उद्यमों तक सीमित है, जो घरेलू उत्पादित उपस्करों के लिए घरेलू उपस्करों की खरीद करते हैं। यह इस कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहनों के लिए पात्र है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व टैरिफ अधिनियम, 1930 की धारा 771 (5) ; वित्त मंत्रालय परिपत्र काई शुई सं. 290/1999 ; जी/एस सी एम/एन/123/सी एच एन ; जी/एस सी एम/क्यू2/सी एच एन/25 ; यू एस बोल्टलेस स्टील शेल्विंग द्वारा प्रमाणित है। चीन के कार्स्टिंग उत्पादक जैसे गेमेसा विंड (तियांजिन) कं. लि. ; डालियन हुवारूई हैकी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं. लि.; जियांग्सू फा फाउंड्री कं.लि.; जियांग्सू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कं. लि. ; जियांजिन फेगंडियन, फ्लैज मैनुफैक्चर कं. लि. ; जियांजिन हेंगुन रिंग फोर्जिन कं. लि. ; किंगडाओ अन्हुआ न्यू एनर्जी इक्विपमेंट कं. लि. ; किंगदाओ रिचुअन प्रेसिजन मशीनरी कं. लि. ; सतारेम चाइना लि. ; शांडोंग लइवू जिनलेई विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि. ; शंघाई सीक ई एंड एंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. ; झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि.; झुझोऊ टाइम्स न्यू मैटीरियल टेक्नोलोजी कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।

xxvii. **कार्यक्रम सं.27 :** विदेशी निवेशकों द्वारा एफ आई ई लाभों का पुनः निवेश करने के लिए आय कर वापसी में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि यह कार्यक्रम एस ए टी और इसके स्थानीय कर व्यूरो द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह एक ऐसे एफ आई ई में विदेशी निवेशकों को लाभ प्रदान करता है, जो पुनः निवेश की गई राशि पर भुगतान किए गए आय कर के संबंध में 40 प्रतिशत (यदि लाभ का पुनः निवेश किया गया है) अथवा 100 प्रतिशत (यदि लाभ को एक निर्यातानुमुखी अथवा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत उद्यम में निवेश किया गया है) वापस प्राप्त करने योग्य हैं।

निवेशक का लाभ, कर वापसी की राशि में प्रदान किया जाता है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह चीन में उद्यमों में पुनः निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व उद्यम आय कर अधिमान्य नीतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय और राज्य कर प्रशासन के परिपत्र – कार्ड शुई [2009] सं 69 ; उद्यम आय कर अधिमान्य नीतियां – 2015 के संबंध में वित्त मंत्रालय और राज्य प्रशासन की सूचिका – परिपत्र ; विदेशी निवेश वाले उद्यम और विदेशी उद्यम आय कर कानून 1991 का अनुच्छेद 10 (एफ आई ई आयकर कानून) ; विदेशी निवेश उद्यम और विदेशी उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन नियमों का अनुच्छेद 80 (एफ आई ई कर विनियम) ; जी/एस सी एम/एन/235/सी ए एन – 2012 – चीन जन. गण. से कतिपय थर्मो इलैक्ट्रिक कूलर और वार्मर ; चीन जन. गण. से कतिपय ऑयल कंट्री ट्यूबलर वस्तुएं ; चीन जन. गण. से कतिपय सीमलेस कास्टिंग ; यू एस कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड ; चीन जन. गण. से सोडियम नाइट्रेट की यू एस जांच सूची; विदेशी निवेश वाले उद्यमों के विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए पुनः निवेश के लिए कर प्रतिपूर्ति के संबंध में कुछ मामलों पर राज्य कर प्रशासन का परिपत्र (गुओ शुई फा [1993] सं. 9) द्वारा प्रमाणित है। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि. और गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि. ; साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. ; एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि. ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।

xxviii **कार्यक्रम सं. 28 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्ययों की कटौती के लिए कर नीतियों में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी** शामिल है, क्योंकि इस कार्यक्रम का अनुरक्षण स्थानीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम कारपोरेट आय में 50 प्रतिशत तक की कटौती करने के लिए ऐसे उद्यमों को लाभ प्रदान करता है, जहां पर कि ऐसी कंपनियां राज्य से प्राथमिक सहायता प्राप्त कर रही है और उनकी परियोजनाएं हार्ड टेक औद्योगिकीकरण को मार्गनिर्देश प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध की गई है, वे इस लाभ के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम का अस्तित्व पी आर सी के उद्यम आय कर कानून के कार्यान्वयन के संबंध में विनियमों के अनुच्छेद 95, कारपोरेट आय कर कानून के अनुच्छेद 30 (1) से ही प्रमुख क्षेत्रों के लिए मार्गनिर्देशन (अधिसूचना सं. 6, 2007) ; चीन के राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) द्वारा जारी गुओ शुई फा [2008] सं. 116 (परिपत्र 116), प्रमुख कटौती के लिए पात्र आर एंड डी व्यय के क्षेत्र का उल्लेख, जो व्यवहारिक तौर पर कुछ ऐसी आर एंड डी संबंधी व्ययों को अलग पाए जिनका सुपर कटौती के प्रयोजन के लिए पात्र आर एंड डी व्यय के रूप में परिपत्र 116 में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था ; दिनांक 29 सितंबर, 2013 को चीन के वित्त मंत्रालय तथा एस ए टी ने कार्ड शुई [2013] 70 (परिपत्र 70) प्रकाशित किया, जिसमें परिपत्र 116 से उल्लिखित आर एंड डी व्यय की मूल श्रेणियों में परिवर्धन तथा स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। परिपत्र सं. 70 दिनांक 1 जनवरी, 2013 को अथवा उसके बाद किए गए आर एंड डी व्यय के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है। चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, तथा ताइवान से नान – ओरिएंटेड इलैक्ट्रिक स्टील के संबंध में यू एस अन्तिम जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे गेमेसा विंड (तियांजिन) कं. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि., डालियन हुआरूई हेवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं. लि., गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि., जियांग्सू फा फाउंडरी कं. लि., जियांग्सू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलोजी कं. लि., जियांगिन फेंगडियन फ्लेज मैनुफैक्चर कं. लि., जियांगिन हेगुन रिंग फोर्जिंग कं. लि., किंगडाओ एन्हुआ न्यू एनर्जी इक्विपमेंट कं. लि., किंग डाओ रिचुअन प्रेसिजन मशीनरी कं. लि., सतारेम चाइना लि., शेनजेंग लईवू जिनलेई विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि., शंघाई सिक ई एंड ए इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. तथा झुझोऊ टाइम्स न्ये मैटीरियल टेक्नोलोजी कं. लि.

xxix. **कार्यक्रम सं. 29 : केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतों में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी** शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार द्वारा प्रांतीय स्तर पर किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों में कम किए गए आय कर के रूप में स्थापित उद्यमों को लाभ प्रदान करता है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित उद्यमों के लिए ही सीमित है। कार्यक्रम का अस्तित्व पश्चिमी क्षेत्र विकास के लिए अनुकूल कर नीतियों के संबंध में नोटिस से है (वित्त मंत्रालय, सामान्य कर ब्यूरो तथा सामान्य सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा जारी, 1 जनवरी, 2001 से प्रभावी) ; पश्चिमी विकास रणनीति के गहन कार्यान्वयन के लिए संगत कर नीतियों से संबंधित मामलों पर परिपत्र (कार्ड शुई [2011] सं. 58) ; पश्चिमी चीन विकास रणनीति के आगे कार्यान्वयन से संबंधित उद्यम आयकर नीतियों के मामलों के संबंध में घोषणा (6 फरवरी, 2013) ; राज्य कर प्रशासन की घोषणा सं. 14 [2015] – पश्चिमी क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित उद्योगों की सूचिका के कार्यान्वयन में उद्यम आय कर से संबंधित मामलों पर घोषणा (2015 – 03- 10) , 12 वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र का विकास ; राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने 20 फरवरी को यह घोषणा की कि राज्य परिषद ने औपचारिक रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के

दौरान पश्चिमी विकास योजना अनुमोदित की है ; विदेशी – निवेश दिशानिर्देश जारी किए गए ( 10 जून, 2013 से प्रभावी) ; पश्चिमी क्षेत्र विकास रणनीति में वृद्धि करने के संबंध में उद्यम आयकर से संबंधित मामलों पर राज्य कर प्रशासन की घोषणा (घोषणा सं. 12) ; चीन के व्यापक पश्चिमी क्षेत्र का विकास करने के लिए अनेक नीतियों के संबंध में राज्य परिषद का परिपत्र (गुओ फा (2000) सं. 33) । केन्द्रीय क्षेत्र में हेनन, हुबेई तथा हुनान प्रांत शामिल हैं और पश्चिमी क्षेत्र में चोंग किंग, सिचुआन, गुईजोऊ, युन्नान, तिब्बत शांक्सी, गान्सू, कुइंगई, निंगशिया तथा जिन्जियांग शामिल हैं। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय यूनियन के अन्तिम जांच परिणाम चीन के कास्टिंग उत्पादक शी जिया जुआंग डांजुओ ट्रेड कं. लि., जुझोऊ जिया बैंग फोटो इलैक्ट्रिक मैटीरियल कं. लि. तथा झुझोऊ टाइम्स न्यू मैटीरियल टेक्नोलोजी कं. लि. इस निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित हैं ।

xxx. **कार्यक्रम सं. 30 : घरेलू तौर पर निर्मित उत्पादन उपस्कर की खरीद के लिए आय कर ऋण** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एस ए टी तथा चीन के स्थानीय कर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है । कार्यक्रम में उद्यमों को कर लाभ (अर्थात् एक कर ऋण) के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है, जो किसी वर्ष विशेष में अर्जित हुआ है और उसका उपयोग किसी अलग वर्ष में किया गया है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल प्रोत्साहित श्रेणी और सीमित 'बी' श्रेणी के तहत उपस्कर का उपयोग करने वाले उद्यम के लिए ही सीमित है । कार्यक्रम का अस्तित्व दिनांक 1 जुलाई, 1999 की प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों में निवेश के लिए उद्यम आय कर ऋण के संबंध में अन्तिम उपायों तथा होम मेड उपस्करों की खरीद में एक उद्यम के निवेशों के कार्यान्वयन को रोकने पर राज्य कर प्रशासन के दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी नोटिस सं. 52 [2008] से है । चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम ।

xxxii. **कार्यक्रम सं. 31 : उच्च और नई प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप मान्य की गई कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियों में** प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ एस टी) द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है । कार्यक्रम में ऐसे उद्यमों को कर बचत के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है, जिन्होंने उच्च और नई प्रौद्योगिकी के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है । यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल ऐसे उद्यमों के लिए ही सीमित है जिनके पास उच्च और नए प्रौद्योगिकी उद्यम का दर्जा है अथवा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है । इस कार्यक्रम का अस्तित्व उद्यम आयकर संबंधी पी आर सी कानून के अनुच्छेद 28 (सं. 63 जो दिनांक 16 मार्च, 2007 को प्रख्यापित हुआ), एस ए टी परिपत्र गुओ शुई फा सं. 135/2003 ; परिपत्र कार्डी शुई (2014) सं. 59 और 65; डब्ल्यू टी/टी पी आर/एस/300; जी/एस सी एम/ क्यू2/ सी एच एन/ 29 ; चीन का औद्योगिक सब्सिडी अध्ययन - 2007 , यूरोपीय यूनियन – कतिपय आर्गेनिक स्टील उत्पाद - 2013 चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पाद । चीन के कास्टिंग उत्पादकों में झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि. इत्यादि है ।

xxxiii. **कार्यक्रम सं. 32 : व्यापक संसाधन के उपयोग में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायतें (विशेष कच्चे माल)** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार तथा राज्य परिषद द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है । यह कार्यक्रम कर बचतों के रूप में उद्यमों को लाभ प्रदान करता है । यह विशिष्ट कार्यक्रम है, जो केवल ऐसे उद्यमों के लिए ही सीमित है, जिनकी कंपनियां इस तरह से उसी सूचिका में सूचीबद्ध उत्पादों का निर्माण कर रही है ताकि चीन सरकार की सूचिका से बाहर किए प्राथमिक कच्चे माल का उपयोग करके संगत राष्ट्रीय और औद्योगिक मानकों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम का अस्तित्व उद्यम आयकर संबंधी पी आर सी कानून के अनुच्छेद 28 और 33 ; राज्य परिषद द्वारा उद्यम आयकर संबंधी पी आर सी कानून के कार्यान्वयन के संबंध में विनियमों का अनुच्छेद 99 ; यूरोपीय संघ – कोटेड फाइन पेपर – 2011 से है । चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में अंतिम जांच परिणाम ; चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन तथा ताइवान से नॉन ओरियंटेड इलैक्ट्रिक स्टील के संबंध में यू एस के अन्तिम जांच परिणाम ।

xxxiiii. **कार्यक्रम सं. 33 विशेष उपस्करों की खरीद के संबंध में कर ऋण** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार और राज्य परिषद द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है । कार्यक्रम में उद्यमों को आय कर में कमी के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है जिससे कर की बचत होती है । यह ऐसे उद्यमों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है जो पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा और पानी की बचत तथा उत्पादन बचत के प्रयोग के लिए उपस्करों की खरीद करते हैं । इस कार्यक्रम का अस्तित्व उद्यम आयकर संबंधी पी आर सी कानून के अनुच्छेद 34, राज्य

परिषद द्वारा उद्यम आय कर संबंधी पी आर सी कानून के कार्यान्वयन के संबंध में विनियमों के अनुच्छेद 100 से है। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम।

xxxiv. **कार्यक्रम सं. 34 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमाम्य आय कर नीति** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार, वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) तथा राज्य कर प्रशासन (एस ए टी) द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम मूल्यह्रास वृद्धि तथा नियत परिसंपत्ति की खरीद से जुड़े परिशोधन व्यय में कमी लाकर पात्र कंपनियों के लिए सृजित कर बचतों के रूप में लाभ प्रदान करता है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र (लायोंनिंग, जिलिन तथा हिलोंगजियांग प्रांतों और डालियन नगर पालिका) में स्थित उद्यमों तक ही सीमित है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व पूर्वोत्तर में पुराने औद्योगिक आधार वाली कंपनियों के पुनरुत्थान के लिए उद्यम आय कर (काई शुई सं. 153, 20 सितंबर, 2004), वित्त मंत्रालय और राज्य कर प्रशासन द्वारा परिसम्पत्तियों के ह्रास तथा पूर्वोत्तर के पुराने औद्योगिक आधार में परिशोधन नीति के कार्यान्वयन की क्षमता के संबंध में नोटिस (काई शुई, सं. 17, 2 फरवरी, 2005) से है। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में अन्तिम यूरोपीय संघ के जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादकों में डालियन हुआरूई हैवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं. लि. इत्यादि है।

xxxv. **कार्यक्रम सं. : 35 पात्र निवासी उद्यमों के बीच लाभांश की छूट** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। कार्यक्रम में लाभांश, बोनस तथा अन्य इक्विटी निवेशों के संबंध में चीन के निवासी उद्यमों के लिए कर छूट प्रदान करके लाभ प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह चीन में निवासी उद्यमों के लिए ही है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व पी आर सी के उद्यम आय कर कानून के अनुच्छेद 26 के तहत और पी आर सी के उद्यम आय कर कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियमों के अनुच्छेद 83, 6 दिसंबर, 2007 को प्रख्यापित राज्य परिषद की डिक्री सं. 512 ; चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के जांच परिणाम।

## VI. सामग्रियों और मशीनों पर शुल्कों एवं करों से राहत

xxxvi. **कार्यक्रम सं. 36 : आयातित प्रौद्योगिकियों तथा उपस्करों के लिए टैरिफ और आयात वेट की छूट** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एन डी आर सी, एस ए टी तथा इसके स्थानीय कर व्यूरों द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। कार्यक्रम में ऐसे एफ आई ई को लाभ प्रदान किया जाता है जो “प्रोत्साहित” अथवा “सीमित” की श्रेणियों में आते हैं और अथवा ऐसे डी आई ई को लाभ प्रदान किया जाता है जो डी आई ई सूचिका (कैटेलाॅग) के अन्तर्गत आते हैं और वे ऐसे उपस्करों का आयात करते हैं, जिन्हें टैरिफ और अथवा वेट से छूट प्रदान की गई है, जो उद्यम के अपने उपयोग के लिए होने चाहिए। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह ऐसे एफ आई ई अथवा डी आई ई के लिए ही सीमित है, जो सूचिका (कैटेलाॅग) में आते हैं। इस कार्यक्रम का अस्तित्व आयातित उपस्करों के लिए कराधान नीतियों के समयोजन से संबंधित राज्य परिषद के नोटिस के अनुच्छेद 1 और 2 (गुआ फा [1997] सं. 37), डब्ल्यू टी ओ दस्तावेज जी/एस सी एम/एन/123/सी एच एन, दिनांक 13 अप्रैल, 2006, विदेशी निवेश के मार्गनिर्देशन के लिए उद्योगों की सूचिका है। वर्तमान में राज्य द्वारा समर्थित उद्योग, उत्पाद और प्रौद्योगिकी की सूचिका (2004) ; राज्य परिषद के आयात की वस्तुएं, जो विदेशी निवेश परियोजनाओं की सूचिका के लिए कर से छूट प्राप्त नहीं है। चीन जन. गण. के मूल के सोलर ग्लास के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम। चीन के कास्टिंग उत्पादक जैसे गेमेसा विंड (तियांजिन) कं. लि. ; एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांजिन) कं. लि. ; डालियन हुआरूई हैवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं. लि. ; गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि. ; जियांगसू फा फाउन्ड्री कं. लि. ; जियांगसू जिक्सिन विंड एनर्जीटेक्नोलोजी कं. लि. ; जियन्जिन फेंगाडियन फ्लेज मैनुफैक्चर कं. लि. ; जियांजिन हेंगरू रिंग फोर्जिंग कं. लि. ; किंग डाओ अंहुआ न्यू एनर्जी इक्विपमेंट कं. लि. ; किंग डाओ रिचुअन प्रेसिजन मशीनरी कं. लि. ; सतारेम चाइना लि. ; शानडोंग लइवू जिनलेई विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि. ; शंघाई सीक ई एंड ए इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. ; साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. ; झुझोऊ टाइम्स न्यू मैटीरियल टेक्नोलोजी कं. लि. ; ऐसे लाभ के लिए पात्र हैं।

xxxvii. **कार्यक्रम सं. 37 : भू उपयोग शुल्क में कमी** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि इस कार्यक्रम का अनुरक्षण एस ए टी द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रांतीय और स्थानीय भू उपयोग प्रबंधन प्राधिकरण भू उपयोग शुल्क के संकलन के लिए जिम्मेदार थे, जो कि एक लोक निकाय है। इस कार्यक्रम में ऐसे एफ आई ई को लाभ प्रदान किया जाता है, जिन्होंने भू उपयोग अधिकारों को अन्तरण करके अर्जित किया है और इस योजना के लिए पात्र है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है, क्योंकि यह एफ आई ई

के लिए ही सीमित है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व है – राज्य परिषद का आदेश [2006] सं. 484); गुओ बान फा का अनुच्छेद iv. 5 [1999] सं. 73) (कस्टम दस्तावेज 18) भू उपयोग शुल्क और अधिमान्य कटौती के पुनः समायोजन और शेजेन विशेष आर्थिक जोन में भू उपयोग शुल्कों से छूट के संबंध में उपाय। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक के संबंध में कनाडा की अंतिम जांच परिणाम ; चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम ; चीन से कार्बन और कतिपय अलाय स्टील वायर रोड के संबंध में यू एस के अन्तिम जांच परिणाम, चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन तथा ताइवान से नॉन ओरिंटेड इलैक्ट्रिक स्टील के संबंध में यू एस का अन्तिम जांच परिणाम ; चीन जन. गण. के मूल के सोलर ग्लास के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम।

#### **VII. उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं/सेवाएं**

xxxviii. **कार्यक्रम सं. 38 : उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदान की गई इनपुट मैटीरियल होट रोल्ड स्टील एवं**

xxxix **कार्यक्रम सं. 39 : उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सरकार द्वारा प्रदान किया गया और होट रोल्ड स्टील**

कार्यक्रम सं. 38 एवं 39 को टंकण संबंधी अशुद्धियों के कारण दाखिल याचिका में शामिल कर लिया गया है। याचिकाकर्ता को यह पूरी जानकारी है कि होट रोल्ड स्टील को कास्टिंग के निर्माण कार्य में कच्चे माल के रूप में नहीं किया गया है।

xi. **कार्यक्रम सं. 40 : सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रदान की गई बिजली** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एन डी आर सी द्वारा किया जाता है और ट्रांस प्रोविंसियल और प्रोविन्सियल ग्रिड का प्रचालन राज्य के स्वामित्व वाले दो आपूर्तिकर्ताओं अर्थात् चीन के स्टेट ग्रिड कारपोरेशन तथा चीन साउदर्न पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा किया जाता है, जो कि लोक निकाय है। कार्यक्रम में ऐसे को लाभ प्रदान किया जाता है जो उद्यमों को चीन जन. गण. में अन्य बड़े औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए सामान्यतः लागू दर से कम दर पर विद्युत प्रदान कर रहे हैं और ऐसे निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित हैं, जहां निर्यात करने वाले उत्पादक स्थित हैं। अधिमानित उद्यमों और उद्योगों के एक सीमित समूह के लिए छूट प्राप्त करें लागू करने की छूट है, विशेषकर प्राथमिकता वाले उद्योगों जैसे कास्टिंग उद्योग के लिए संगत एन डी आर सी नोटिस में कम विद्युत दरें निर्धारित की गई हैं और स्थानीय कीमत ब्यूरो द्वारा जारी नोटिस में शामिल की गई है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व प्रमाणित है और उससे चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम प्रतिसंतुलनकारी हुए हैं; चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन और ताइवान से नाना – आरिंटेड इलैक्ट्रिक स्टील के संबंध में यू एस के अन्तिम जांच परिणाम चीन जन. गण. के मूल के सोलर ग्लास के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम।

xli. **कार्यक्रम सं. 41 : औद्योगिक अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोनों में स्थित कंपनियों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम के लिए भूमि** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण भूमि एवं संसाधन मंत्रालय, चीन सरकार द्वारा एस ओ ई के माध्यम से किया जाता है, जो इस कार्यक्रम का अनुरक्षण करते हैं और जो एक लोक निकाय है। कार्यक्रम में चीन की सरकार द्वारा छूट की दर पर अथवा शुल्क आधार पर उद्यमों को लाभ प्रदान किया जाता है। भू उपयोग नीतियां एक विशिष्ट आधार पर संचालित की जाती हैं; विशेषकर चीन की स्थानीय सरकारें केवल ऐसे कतिपय हाइ टेक उद्यमों के लिए ही छूट प्राप्त भूमि सुलभ कराती है, जो विशिष्ट प्रकृति के हों। इस कार्यक्रम का अस्तित्व भूमि प्रशासन कानून के अनुच्छेद 2 द्वारा स्थापित है और इसे प्रतिसंतुलनकारी बनाया गया है; चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम ; चीन, जर्मनी, कोरिया, स्वीडन, तथा ताइवान से नॉन ओरिंटेड इलैक्ट्रिक स्टील के संबंध में यू एस के अन्तिम जांच परिणाम, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय स्टेनलेस स्टील के सिंक के संबंध में कनाडा के अन्तिम जांच परिणाम।

xlii. **कार्यक्रम सं. 42 : पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम जल के प्रावधान वाल कार्यक्रम** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण एन डी आर सी, जल संसाधन मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। कार्यक्रम में ऐसे निर्यातकों को लाभ प्रदान किया जाता है, जहां पर कि वे “सीवेज उपचार शुल्क” के रूप में विशेष रूप से लागू परित्यक्त राजस्व के रूप में सामान्य जल आपूर्ति से कम भुगतान करते हैं। इससे पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम पानी प्रदान किया गया है। निर्यातकों ने जिस श्रेणीसे वे संबंधित हैं, उस श्रेणी के उपयोक्ताओं के लिए सामान्यतः लागू जल आपूर्ति की पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया है क्योंकि पानी की कीमत के “सीवेज उपचार शुल्क” घटक का भुगतान नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम का अस्तित्व चीन के कार्बन और कतिपय अलाय स्टील वायर रोड के यू एस अन्तिम जांच परिणाम द्वारा स्थापित और प्रतिसंतुलित है।



- xliii **कार्यक्रम सं. 43 : पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रावधान** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। यह कार्यक्रम ऐसे एस ओ ई को सीधी निधि अन्तरित करके पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम के रूप में लाभ प्रदान करता है क्योंकि कास्टिंग उत्पादकों द्वारा तैयार कच्चे माल में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल कच्चे माल के इनपुट जैसे पिग आयरन, स्टील स्क्रेप (सी आर सी ए) फैरोसिलिकोन, फैरो सिलिकोन एम जी, कोक, इनोकुलेंट, सिलिका सेंड, रेसिन, केटलिस्ट, एलपीजी, फर्नेस लाइनिंग मैटीरियल, डीजल, लेडल लाइनिंग मैटीरियल, सेरमिक ट्यूब, स्लीव्ज और रेफ्रेक्ट्री कोटिंग शामिल है और चीन जन. गण. के सरकारी प्राधिकरणों से आपूर्ति की जाती है। कार्यक्रम का अस्तित्व निम्नलिखित से अनुरक्षित और प्रतिसंतुलित है ; यू एस – गालवेनाइज्ड स्टील वायर चीन और मैक्सिको से ; यू एस – कतिपय सीमलेस कार्बन और अलॉय स्टील स्टैंडर्ड, लाइन और प्रैसर पाइप (सीमलेस पाइप) चीन जन. गण. से ; तथा यू एस – कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड, चीन से।
- xliv. **कार्यक्रम सं. 44 : पर्याप्त क्षतिपूर्ति से अधिक के लिए सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद** में एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार द्वारा एस ओ ई के माध्यम से किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। कार्यक्रम में चुनिन्दा उद्यमों के लिए वस्तुओं की खरीद के लिए धनराशि के सीधे अन्तरण के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह ऐसे कतिपय पात्र उद्यमों के लिए ही सीमित है जो प्राधिकरणों द्वारा चुने जाते हैं। चीन जन. गण. के मूल के कतिपय आर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में यूरोपीय संघ के अन्तिम जांच परिणाम तथा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय गालवेनाइज्ड स्टील वायर के संबंध में कनाडा के अन्तिम जांच परिणाम।
- xliv. **कार्यक्रम सं. 45 : सरकार द्वारा बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रदान की गई इनपुट सामग्रियों (कच्चे माल) तथा उपयोगी वस्तुओं** में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है, क्योंकि कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन जन. गण. सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि एक लोक निकाय है। कार्यक्रम में एस ओ ई द्वारा कास्टिंग उत्पादकों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम इनपुट सामग्रियों (कच्चे माल) और उपयोगी वस्तुओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया जाता है और इसलिए इसमें प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ कास्टिंग निर्यातकों तक ही सीमित है और इनपुट सामग्री (कच्चा माल तथा उपयोगी वस्तुएं) पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम कीमत पर दी जाती है। बाजार कीमत पर नहीं दी जाती है। इनपुट सामग्री में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शामिल है जैसे पिग आयरन, स्टील स्क्रेप (सी आर सी ए) फैरोसिलिकोन, फैरो सिलिकोन एम जी, कोक, इनोकुलेंट, सिलिका सेंड, रेसिन, केटलिस्ट, एल पी जी, फर्नेस लाइनिंग मैटीरियल, डीजल, लेडल लाइनिंग मैटीरियल, सेरमिक ट्यूब, स्लीव्ज और रेफ्रेक्ट्री कोटिंग शामिल है और चीन जन. गण. के सरकारी प्राधिकरणों से आपूर्ति की जाती है। कार्यक्रम का अस्तित्व निम्नलिखित से अनुरक्षित और प्रतिसंतुलित है ; यू एस – गालवेनाइज्ड स्टील वायर चीन और मैक्सिको से ; यू एस – कतिपय सीमलेस कार्बन और अलॉय स्टील स्टैंडर्ड, लाइन और प्रैसर पाइप (सीमलेस पाइप) चीन जन. गण. से ; तथा यू एस – कार्बन और कतिपय अलॉय स्टील वायर रोड, चीन से।

### ज. 3 चीन सरकार/उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा अनुरोध

76. कथित सब्सिडी स्कीमों के संबंध में, प्रतिवादी इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिए हैं :-
- वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर 44 सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सीवीडी जांच आरंभ की है। यद्यपि जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, प्राधिकारी किसी नए सब्सिडी कार्यक्रम पर इस अवस्था में विचार न करे। इस बात का ध्यान रखे बिना यदि प्राधिकारी किसी नई सब्सिडी पर विचार करता है तो ऐसी परिस्थितियों में एक पृथक जांच आरंभ करनी होगी।
  - याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका में, चीन जन. गण. के 5 निर्यातकों को नाम दिए गए हैं। तथापि, याचिका में कही भी ऐसा आरोप नहीं है जिससे की 44 योजनाएं, जो सूचीबद्ध हैं, उनमें से सभी कार्यक्रम योजनाएं किसी निर्यातक के लिए लागू हैं। सची में दी गई किसी भी योजना का संबंध भौगोलिक क्षेत्र अथवा किसी खास उद्योग से नहीं है, जिनसे कि निर्यातक संबंधित ही इसके अभाव में कथित कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी नहीं हो सकते।
  - इसके अलावा, प्रत्येक 44 सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच समाप्त किए जाने की जरूरत है क्योंकि सी वी डी नियमों और एस सी एम करार के आलोक में प्रत्येक सब्सिडी प्रतिसंतुलनकारी नहीं होती। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित सब्सिडी कार्यक्रमों में निम्नलिखित कमियां/समस्याएं मौजूद है :-  
क. निर्यातक देश में सब्सिडी कार्यक्रम निरस्त किए गए है।

ख. (क) वित्तीय योगदान (ख) प्रदान किए जा रहे लाभ और (ग) विशेष उल्लेख के संबंध में कोई भी आरोप नहीं है।

ग. कार्यक्रम के नाम के अलावा कोई भी सूचना नहीं है

घ. यह स्वीकार्य है कि कथित सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

ङ. कथित कार्यक्रमों के संबंध में कनाडा, आस्ट्रेलिया, यू एस और यूरोपीय संघ के प्राधिकरणों के कतिपय जांच परिणाम के अलावा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। इन मामलों में भी उनमें से किसी भी अन्तिम जांच परिणाम का संबंध संगत उत्पादक अथवा किसी भी ज्ञात उत्पादक अथवा याचिका में सूचीबद्ध निर्यातक से नहीं है। कतिपय विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों अथवा शहरों से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में याचिका में कोई भी प्रमाण नहीं है कि कोई भी संबंधित उत्पाद का उत्पादक संगत भौगोलिक क्षेत्र अथवा शहर में प्रचालन कर रहा था अथवा स्थित था।

च. ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को लोक निकाय क्यों माना गया।

iv. अन्य देशों से जांच परिणामों के रूप में प्रस्तुत सभी साक्ष्य (बिना स्वीकार किए अनुमानों के आधार पर है कि उन्हें साक्ष्य माना जाए) अपील निकाय के डी एस 379 और डी एस 436 में जांच परिणाम निर्णय से संबंधित नहीं है कि संबंधित संस्था सरकारी प्राधिकरण है जिससे कि वह सरकारी कार्य कर सके और केवल व्यापार अथवा अन्य वाणिज्यिक कार्यों के लिए नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत किए गए सभी जांच परिणामों में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एस ओ ई) को केवल इस कारण से सरकारी निकाय माना गया था कि वे राज्य के स्वामित्वाधीन थे। तदनुसार, याचिका में अथवा परवर्ती पत्रों में उल्लिखित अन्य सरकारों के कोई भी जांच परिणाम अपील निकाय के निर्णयों के अनुरूप नहीं थे।

v. याचिकाकर्ता ने कथित सब्सिडी के बारे में विशेष उल्लेख और लाभ संबंधी अप्रमाणित दावों के साथ केवल आरोप लगाए हैं। यह स्थापित करने के बीच कि एक कार्यक्रम का अस्तित्व है (कानून और प्रशासन प्राधिकार के संबंध में पर्याप्त सूचना, के साथ) और यह स्थापित करने के बीच कि कार्यक्रम में एक कार्रवाई योग्य अथवा निषिद्ध सब्सिडी है, अन्तर होता है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने कुछ कथित कार्यक्रमों के बारे में सूचना दाखिल की है लेकिन कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि क्यों भारत द्वारा डब्ल्यू टी ओ का सदस्य होने के नाते इन कार्यक्रमों के प्रतिसंतुलन के लिए शुल्क लगाना न्यायोचित है। याचिकाकर्ता को सामने लाए सब्सिडी के आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

77. कथित सब्सिडी योजनाओं के संबंध में चीन सरकार ने यह तर्क दिए हैं :-

क) चीन सरकार ने यह दावा किया है कि कथित निम्नलिखित योजनाएं मौजूद नहीं हैं :-

I. उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं / सेवाएं।

i. सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई गई।

ii. औद्योगिक अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोनों में स्थित कंपनियों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम पर भूमि

iii. पर्याप्त क्षतिपूर्ति से कम पर पानी उपलब्ध कराने के प्रावधान वाले कार्यक्रम

II. अधिमान्य ऋण

i. कास्टिंग उद्योग को अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें

ख) चीन सरकार ने यह दावा किया है कि कास्टिंग उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निम्नलिखित कथित योजनाएं लागू नहीं होती क्योंकि जांच के अधीन उत्पादकों के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री हॉट रोलड स्टील और कोल्ड रोलड स्टील है नहीं बल्कि स्टील स्क्रैप है।

I. उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुएं/सेवाएं :

i. उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा इनपुट सामग्रियां हॉट रोलड स्टील उपलब्ध कराई गई।

ii. उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा हॉट रोलड स्टील उपलब्ध कराई गई।

ग) चीन सरकार ने यह दावा किया कि निम्नलिखित कथित योजनाएं “अब से” लागू नहीं है।

I. विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) प्रोत्साहन और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र :-

i. विशेष आर्थिक जोनों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र के अलावा) में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों (एफ आई ई) के लिए अधिमान्य कर नीतियां

- ii. तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों में और आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास जोनों में स्थापित किए गए एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- iii. शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- iv. कारपोरेट आय कर छूट और / अथवा एस ई जैड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कमी
- v. स्थानीय आयकर छूट और / अथवा एस ई जैड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कमी
- vi. एस ई जैड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपस्कर पर टेरिफ और मूल वर्धित कर (वेट) से छूट
- vii. कास्टिंग और फोर्जिंग प्रणालियों के लिए अधिमान्य कर

## II अनुदान

- i. राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि
- ii. ऐसे उद्यमों को पुरस्कृत करना, जिनके उत्पाद “चीन के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क ” अथवा “ चीन के प्रसिद्ध ब्रांड ” के लिए चुने गए हैं।

## III अधिमान्य आय कर कार्यक्रम

- i. न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादनकारी एफ आई ई के लिए कम कर की दरें ।
- ii. विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- iii. गहन प्रौद्योगिकी और गहन ज्ञान वाले एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- iv. एफ आई ई के अनुसंधान और विकास अधिमान्य कर नीतियां
- v. ऐसे एफ आई ई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जिनकी चीन में संस्थापनाएं अथवा स्थान हैं और कारोबारी प्रचालनों अथवा उत्पादन, घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद में लगे हैं ।
- vi. प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयोजन के लिए घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद करने वाले घरेलू उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां ।
- vii. विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई लाभों के पुनः निवेश के लिए आय कर की वापसी

## IV. सामग्रियों और मशीनों पर शुल्कों और करों से राहत

- i. आयातित प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के लिए टैरिफ और आयात वेट से छूट

## V. सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रदान की गई वस्तुएं /सेवाएं

- i. घरेलू तौर पर निर्मित उत्पादन उपस्कर की खरीद के लिए आयकर ऋण

घ) चीन सरकार ने यह दावा किया है कि आवेदन में निम्नलिखित योजनाओं के लिए कथित सब्सिडी के वास्तविक अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य शामिल नहीं हैं :-

## I. अनुदान

- i. स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी और/ अथवा प्रतिसंतुलनकारी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति
- ii. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
- iii. नवोन्मेषी प्रायोगिक उद्यम अनुदान
- iv. सुपरस्टार उद्यम अनुदान
- v. हाई टेक उद्योग की उद्यम निवेश निधि

- vi. विदेशी निवेश से मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु अनुदान
- vii. नवोन्मेषी छोटे तथा मझोले उद्यम अनुदान
- viii. निजी स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों को अनुदान
- II. सामग्रियों और मशीनों पर शुल्कों एवं करों से राहत
  - i. भू उपयोग शुल्कों में कमी।
- III. सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रदान की गई वस्तुएं/सेवाएं
  - i. केन्द्रीय और पश्चिम क्षेत्रों के लिए कर रियायत
  - ii. व्यापक संसाधनों के उपयोग (विशेष कच्ची सामग्री) में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायतें।
  - iii. विशेष उपस्करों की खरीद के संबंध में कर ऋण
  - iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
  - v. सरकार द्वारा पर्याप्त क्षतिपूर्ति से अधिक की वस्तुओं की खरीद
- IV. इक्विटी कार्यक्रम
  - i. इक्विटी प्रदान करना
  - ii. भुगतान न किए गए लाभांश
- V. अधिमान्य ऋण
  - i. कास्टिंग उद्योग के लिए अधिमान्य ऋण और ब्याज की दरें
- ड.) चीन सरकार ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित कथित योजनाएं वहां लागू हैं, जहां लाभ किसी इनपुट, संबद्ध उत्पाद के किसी निर्यात अथवा आयात से संबंधित नहीं है, जिनमें कर लाभ पाने के लिए राज्य से महत्वपूर्ण सहायता की जरूरत होती है :-
  - i. ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मानी गई हो।
- च) चीन सरकार ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित कथित योजनाएं सब्सिडी नहीं है बल्कि बिना लाभ के दोहरे कराधान से बचने के लिए एक छूट है :
  - i. पात्र रिहायशी उद्यमों के बीच लाभांश की छूट
- छ) नए सब्सिडी अभिकथन (एन एस ए) को विलंब से किए गए अभिकथन में शामिल नहीं किया जा सकता। एन एस ए को उचित समय अवधि (जांच आरंभ होने के 2 माह बाद) के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और फिर भी यदि प्राधिकारी को एन एस ए पर विचार करना ही है तो इसके लिए अलग से एक जांच आरंभ करनी चाहिए और निर्यातक देश के साथ पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए।
- ज) केवल प्रतिवादी निर्यातक, झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी हेंगझोऊ ने यह दावा किया है कि निर्यातक कंपनी ने कभी भी इन कार्यक्रमों का उपयोग अथवा लाभ पाने के लिए आवेदन नहीं किया है। साथ ही, जियाली न तो एक विदेशी निवेश वाला उद्यम है और न ही एस ई जैड अथवा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में निर्यातक कंपनी ने कभी भी इनपुट सामग्री के रूप में होट रोलड स्टील का उपयोग नहीं किया है। कंपनी ने बिजली, पानी, भूमि और विभिन्न वस्तुएं जांच की अवधि के दौरान खरीदी है और इस कार्यक्रम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया।
- झ) केवल एक सहयोगी निर्यातक/ उत्पादक ने यह कहा है कि उसने “ अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यय में कमी के लिए कर नीतियों ” और “उच्च और नई प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के रूप में मान्यता वाली कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियों ” के लिए आवेदन किया है और स्थानीय कर ब्यूरो से अनुमोदन प्राप्त किया है। ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुए हैं। तथापि, इस कार्यक्रम की प्रकृति कम आय कर की दर की है लेकिन ऐसे लाभ केवल तभी फायदेमंद माने जा सकते हैं जबकि उद्यम को लाभ

हुआ हो। निर्यातक कंपनी ने वर्ष 2012 में भारी नुकसान के चलते उपरोक्त योजनाओं से कोई लाभ नहीं लिया था। साथ ही, यह कर रियायतें न तो प्रत्यक्ष और न हो अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं के अर्जन से संबद्ध है।

- ज) निर्यातक झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी, हेंगजोऊ ने यह दावा किया है कि यह एक निजी स्वामित्व वाली सीमित देयता कंपनी है। अतः उन्होंने इक्विटी कार्यक्रमों यथा इक्विटी प्राप्ति और भुगतान न किए गए लाभांश में से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- ट) याचिकाकर्ता ने 5 निर्यातकों का नाम लिया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहीं भी आरोप नहीं लगाया है कि किस निर्यातक से सभी कार्यक्रम लागू हैं। सूची में उल्लिखित कोई भी योजना संबंधित निर्यातकों, जिनका नाम उल्लिखित है, के भौगोलिक क्षेत्र अथवा विशिष्ट उद्योगों से संबंधित नहीं है।
- ठ) इच्छुक पक्षकारों ने सब्सिडी के आरोपों के लिए याचिकाकर्ता के आरोपों के पर्याप्त होने के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। याचिका में कानूनी मानकों और अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है। याचिका में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। आई डब्ल्यू टी एम ए ने यह कहा है कि कार्यक्रम के लिए यह अपेक्षा पूरी होनी चाहिए कि क्या कार्यक्रम ए एस सी एम के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में 'सब्सिडी' के लिए पात्र हैं।
- ड) चीन सरकार ने यह उल्लेख किया है कि चीन के निर्यातक उत्पादक ने सहयोग किया जिसमें विस्तृत सूचना और साक्ष्य इस आशा से प्रदान किए गए कि प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए मतों और तथ्यों को ध्यान में रखेगा।
- ढ) याचिकाकर्ता को (क) एक सब्सिडी और यदि संभव हो उसी राशि (ख) क्षति और (ग) कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य शामिल करने चाहिए। बिना संगत साक्ष्य के केवल अनुमान के आधार पर इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
- ण) याचिकाकर्ता यह पहचानने में असमर्थ रहा कि कौन सा विशेष कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है और क्या उसमें कोई वित्तीय योगदान और क्षेत्र में कोई लाभ मौजूद है।
- त) प्रत्येक 44 कार्यक्रमों के लिए जांच को समाप्त किया जाए क्योंकि ये प्रतिसंतुलनकारी नहीं हैं। कथित सब्सिडी कार्यक्रमों में कमियां/ समस्याएं मौजूद हैं जैसे :-

क. निर्यातक देश में सब्सिडी कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं।

ख. (क) वित्तीय योगदान (ख) प्रदान किए जा रहे लाभ और (ग) विशेष उल्लेख के संबंध में कोई भी आरोप नहीं है।

ग. कार्यक्रम के नाम के अलावा कोई भी सूचना नहीं है।

घ. यह स्वीकार्य है कि कथित सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

ड. कथित कार्यक्रमों के संबंध में कनाडा, आस्ट्रेलिया यू एस और यूरोपीय संघ के प्राधिकरणों के कतिपय जांच परिणामों के अलावा कोई भी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।

i. उनमें से कोई जांच परिणाम विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) अथवा किसी भी ज्ञात ऐसे उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है जो याचिका में सूचीबद्ध है।

ii. कार्यक्रम विशेष भौगोलिक क्षेत्रों अथवा शहरों से संबंधित है, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि कोई उत्पादक भौगोलिक क्षेत्र में प्रचालन कर रहा है/स्थित है।

iii. इस बात के संबंध में कोई भी यह प्रमाण नहीं है कि एस ओ ई को क्यो लोक निकाय माना जाए।

थ) याचिकाकर्ता इन तीन तत्वों की मौजूदगी को प्रमाणित नहीं कर पाया जिनमें कि प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है नामतः (i) सरकार और लोक निकाय का वित्तीय योगदान ; (ii) लाभ ; और (iii) विशिष्टता। यदि उपरोक्त तीन पूर्वापेक्षाओं में से एक या अधिक अपेक्षा पूरी नहीं होती तो ऐसे मामले में ऐसे कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त हो जाती है।

द) भारत सरकार यह स्पष्ट करें : (i) क्या उसने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सब्सिडी संबंधी साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता का आकलन किया ; और (ii) किस आधार पर यह माना गया कि याचिका में प्रत्येक सब्सिडी योजना के संबंध में पर्याप्त और सटीक सूचना की गई है। जहां तक संबंधित उत्पाद के निर्यातक उत्पादक का संबंध है , याचिका पर एस जी एम करार के अनुच्छेद 11.3 के तहत यथा अपेक्षित जांच प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार प्रदान करने पर ही विचार किया जाना चाहिए।

- ध) सभी सूचना एवं तथ्य संबंधित पी यू सी से पूर्ण रूप से संबंधित होने चाहिए। पी यू सी से प्रत्यक्ष संगतता का अनुरोध न होना चाहिए। यह अनावश्यक भार डालने के समान हुआ कि कोई निर्यातक उसे पूरा नहीं कर पाए। विशेष रूप से सभी सब्सिडी संबंधी सूचना और साक्ष्य (1) संबद्ध व्यापारी (2) सहयोगी कंपनी से संबंधित होने चाहिए।
- न) कार्यक्रम को संचालित करने वाले राज्य अथवा एस ओ ई होने से लोक निकाय की अपेक्षा पूरी हो जाती है – यह अधूरी और गलत स्थिति है। किसी संस्था में राज्य का स्वामित्व भर होने से यह नहीं माना जा सकता कि वह संस्था ए एस सी एम के अनुच्छेद 1.1 अथवा सीमा शुल्क टैरिक अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रयोजन से लोक निकाय है। संस्था के कानूनी, संगठनात्मक अथवा वित्तीय संरचना जैसे अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए।
- प) याचिकाकर्ता ने डी एस 379 और डी एस 436 में ए बी के निर्णय पर विचार नहीं किया है। याचिकाकर्ता को पहले यह देखना चाहिए कि संबंधित संस्था सरकारी कार्यों को करने के लिए सरकारी प्राधिकार रखती है और केवल व्यापार अथवा अन्य वाणिज्यिक कार्यों को ही देखना चाहिए। सभी जांच निष्कर्षों में एस ओ ई को लोक निकाय केवल इस कारण से माना था कि वे राज्य के स्वामित्व की थी। किसी भी जांच परिणाम में ए बी के निर्णय के अनुरूप उल्लेख नहीं किया गया।
- फ) नियम 7 (7) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा काफी सूचना साझा नहीं की गई है। याचिका अधूरी है और सहायक साक्ष्य के रूप में पर्याप्तता और सटीकता के मानदंडों को पूरा नहीं करती।

क) प्रत्येक सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी के संबंध में साक्ष्य।

ख) संबंधित उत्पाद के लिए लागू सब्सिडी कार्यक्रम के साक्ष्य।

ग) इस विशेष उद्योग के लिए लागू सब्सिडी कार्यक्रम के साक्ष्य।

घ) अन्य घरेलू उत्पादक और उनकी उत्पादन गुणवत्ता के स्रोत के साक्ष्य।

- ब) याचिका में कुल 18 कार्यक्रम, जिन्हें कार्यक्रम संख्या प्रदान की गई है, को किसी न किसी रूप में घूट अथवा आय कर की अधिमान्य दर प्रदान किए जाने के रूप में आरोपित किए गए हैं। यह सोचने की बात है कि एक खास उद्यम को उसी समय सभी 18 कार्यक्रमों के लिए कर की अधिमान्य दर से लाभान्वित किया जाएगा। यह मानकर भी ऐसे कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप (i) वित्तीय योगदान है (ii) लाभ प्रदान किए गए और (iii) और साथ ही विशिष्ट भी है, लाभ को किसी एक कार्यक्रम अथवा नीतियों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी किया जा सकता है न कि सभी कार्यक्रमों के लिए।
- भ) याचिका में कुल 7 कार्यक्रमों जिन्हें कार्यक्रम संख्या से 14 से 18, 37 और 42 प्रदान की गई है, को उस क्षेत्र में स्थित उद्यमों को सब्सिडी प्रदान करने के रूप में आरोपित किया गया है। यह मानकर भी कि ऐसे कार्यक्रम के परिणामस्वरूप (i) वित्तीय योगदान है, (ii) लाभ प्रदान किए गए हैं और (iii) और साथ ही विशिष्ट भी है, लाभ केवल एक कार्यक्रम अथवा नीतियों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी होगा न कि सभी कार्यक्रमों के लिए। तथापि, यह मानने की बात है कि एक खास उद्यम को विभिन्न सब्सिडियों से लाभान्वित किया जाएगा क्योंकि यह ऐसे सभी विभिन्न प्रांतों में स्थित नहीं हो सकता। किसी भी रूप में एस सी एम करार के अनुच्छेद 8 के तहत इन कार्यक्रमों में वंचित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए सब्सिडी शामिल है।
- म) प्राधिकारी ने कथित कार्यक्रमों के लिए जांच आरंभ करके सी बी डी नियमावली के नियम 6, एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 3 का उल्लंघन किया है क्योंकि यह कार्यक्रम 2008 में बंद कर दिया गया है। यह ए एस सी एम के तात्पर्य से कार्रवाई योग्य नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए जांच याचिका में प्रदान किए गए साक्ष्य का अभाव होने पर एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.9 के तहत समाप्त की जानी चाहिए।

#### ज. 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

78. कथित सब्सिडी योजनाओं के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न विवादों और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विवादों की जांच की गई है और इस प्रकार समाधान किया गया है:
- i. नए सब्सिडी अभिकथन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में जांच के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि इन नई सब्सिडी को शामिल किया जा सके, लेकिन याचिकाकर्ता ने बाद में अपने मत को बदला और यह अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अन्य सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी के संबंध में लाए गए साक्ष्य यह मानने के लिए स्वीकार किए जाए कि चीन सरकार ने सभी योजनाओं को प्रकट नहीं किया है जो चीन में लोकप्रिय है और जहां कास्टिंग उत्पादक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी से लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा बाद में पहचानी गई अतिरिक्त योजनाओं तक जांच का विस्तार वर्तमान जांच पूरी होने के लिए उपलब्ध समय को

देखते हुए, उपयुक्त नहीं हो सकती। तथापि, भाषा के परिवर्तन को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि चीन सरकार ने चीन में प्रचलित अतिरिक्त कथित सब्सिडी योजनाओं के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यद्यपि प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली में विशेष रूप से चीन में प्रचलित किसी भी अन्य योजना के संबंध में सूचना मांगी थी।

- ii. इस विवाद के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने सब्सिडी कार्यक्रम और चीन जन. गण. से अभिज्ञान 5 निर्यातकों का, भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में अथवा विशिष्ट उद्योगों, जिनसे ये निर्यातक संबंधित हैं, के साथ सह संबंध स्थापित नहीं किया, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान उसके पास उपलब्ध समुचित साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन चीन में 200 से अधिक कास्टिंग उत्पादकों की सूची प्रस्तुत करते समय चीन सरकार ने उक्त सूचना भी उपलब्ध करा दी। इसके अलावा, यदि चीन सरकार ने सहयोग किया होता और प्राधिकारी को सरकारी निकायों के साथ – साथ एकमात्र प्रतिवादी चीन के उत्पाद / निर्यातक के डाटा / सूचना की स्थल पर ही पुष्टि करने की अनुमति प्रदान की होती तो प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों / साक्ष्यों की जांच और समाधान करने की बेहतर स्थिति में होता है।
- iii. जहां तक इस विवाद का संबंध है कि डी एस 379 और डी एस 436 में अपील निकाय के निर्णय के परिणामों के संदर्भ में, किसी भी जांच प्राधिकारी को सबसे पहले यह स्थापित करना होता है कि संबंधित संस्था के पास सरकारी कार्य निष्पादन के लिए सरकारी प्राधिकार हो न कि केवल व्यापार अथवा अन्य वाणिज्यिक कार्यों को करने से लोक निकाय माना जाए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कथित सब्सिडी में शामिल एजेंसियां लोक निकाय नहीं हैं, न ही उन्होंने सहयोग किया और न ही प्राधिकारी को पुष्टि की अनुमति दी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में 44 कार्यक्रमों की पहचान की थी, जिनमें से 37 कार्यक्रम राज्य की श्रेणी (चीन सरकार, प्रांतीय, नगर पालिका निगम, चीन के स्थानीय निकाय) के भीतर आने वाले उन निकायों द्वारा संचालित किए जाते हैं। केवल 7 कार्यक्रम याचिकाकर्ता द्वारा अभिज्ञात किए गए थे, जो एस ओ ई द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जहां तक इन कार्यक्रमों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए कि ये प्रशासन प्राधिकरण कानून के तात्पर्य से लोक निकाय में शामिल हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना पर भरोसा करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में वर्तमान जांच में कथित सब्सिडी में शामिल सभी एजेंसियों के पास सरकारी कार्यों को करने के लिए सरकारी प्राधिकार है और इसीलिए लोक निकाय है।
- iv. इस विवाद के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने विशिष्टता और लाभ के संबंध में अप्रमाणित दावों के साथ प्रश्नगत सब्सिडी के बारे में केवल अप्रमाणित आरोप प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने विशिष्टता और लाभ के संबंध में सूचना प्रदान की है, जो उनके पास उपयुक्त रूप से उपलब्ध थी, जो जांच की अवधि के दौरान उनके मामले के समर्थन में, प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी का अस्तित्व दर्शाते हुए प्रदान की गई। यदि चीन सरकार ने यह सिद्ध करना होता तो वे सहयोग करते और प्राधिकारी को चीन के निर्यातक व एक मात्र प्रतिवादी के डाटा और उनके डाटा को स्थल पर पुष्टि करने की अनुमति प्रदान की होती।
- v. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह दावा करते हुए कि अनेक योजनाएं अब लागू नहीं हैं, चीन सरकार ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जिनसे यह पता चल सके कि ये योजनाएं अब लागू नहीं हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यदि चीन सरकार द्वारा किसी समय कोई कार्यक्रम शुरू किया गया था और बाद में वापस ले लिया गया, तो चीन सरकार इस स्थिति में होनी चाहिए कि वह कार्यक्रम की शुरुआत और उसे वापस लेने के संबंध में संगत दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि यह दावा करते हुए कि कथित कुछ योजनाएं अब लागू नहीं हैं, चीन सरकार ने न तो कार्यक्रम को शुरू करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदान किया और न ही कार्यक्रमों को वापस लेने में संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कार्यक्रमों के नाम बदल दिए गए हों अथवा पुराने कार्यक्रम को बदलकर अलग नाम से कोई कार्यक्रम उसी लाभ के साथ और उसी समूह को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। यदि चीन सरकार ने सहयोग किया होता और प्राधिकारी को सरकार के डाटा / सूचना के साथ – साथ चीन के एकमात्र प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक के डाटा / सूचना की पुष्टि करने की अनुमति प्रदान कर दी होती, तो सच्चाई एक बेहतर तरीके से सामने आती। लेकिन चूंकि चीन सरकार ने उनके डाटा / सूचना तथा इस जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए दावों की स्थल पर पुष्टि करने के लिए सहमति नहीं दी थी इसलिए उनके तर्क – वितर्क की सच्चाई कि कई पूर्ववर्ती सब्सिडी कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं, स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा, अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों ने इन योजनाओं की मौजूदगी और उनके जांच परिणामों में प्रति संतुलन पाया है।

79. घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 10 नवंबर, 2015 के पत्र के तहत एक विवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें इस जांच की अवधि के दौरान पहले उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का समेकित सन्दर्भ और साक्ष्यों की प्रति (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) का उल्लेख किया है। प्राधिकारी ने वह पत्र तथा उसके संलग्नक सार्वजनिक फाइल में इच्छुक पक्षकारों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए हैं।

। घरेलू उद्योग द्वारा सब्सिडी मार्जिन की गणना की गई है जो नीचे संबंधित योजनाओं के लिए उनके सामने दर्शाई गई है :-

क्र. सं.	योजना	जियाली	अन्य
1	निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान (कार्यक्रम 8 से 17)	5.89 प्रतिशत	5.89 प्रतिशत
2	राज्य की प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि		
3	स्थानीय सरकार द्वारा पाटनरोधी एवं / अथवा प्रतिसंतुलनकारी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति		
4	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान		
5	नवोन्मेषी प्रायोगिक उद्यम अनुदान		
6	सुपरस्टार उद्यम अनुदान		
7	ऐसे उद्यमों को पुरस्कृत करना, जो “चीन के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क” अथवा “चीन के प्रसिद्ध ब्रांड ” के उत्पादों के लिए पात्र हों।		
8	हार्ड टेक उद्योग की उद्यम निवेश निधि		
9	विदेशी निवेश से मुख्यालयों और क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान		
10	नवोन्मेषी छोटे एवं मझोले उद्यम अनुदान		
11	निजी स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों का अनुदान		
12	एसईजैड तथा अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आय कर छूट और / अथवा कमी (कार्यक्रम 6 )	0.00 प्रतिशत	0.25 प्रतिशत
13	एस ई जैड और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित और उपस्करों पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर (वैट) की छूट (कार्यक्रम – 6)	2.17 प्रतिशत	2.17 प्रतिशत
14	इक्विटी कार्यक्रम		
15	इक्विटी प्रदान करना (कार्यक्रम – 18)	5.18 प्रतिशत	5.18 प्रतिशत
16	भुगतान न किए गए लाभांश (कार्यक्रम – 19)	0.26 प्रतिशत	0.26 प्रतिशत
17	कास्टिंग उद्योग को अधिमान्य ऋण एवं ब्याज दरें (कार्यक्रम – 20)	0.59 प्रतिशत	2.46 प्रतिशत
18	ऐसे एफ आई ई और विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जिनके पास चीन में संस्थापना और स्थान हैं तथा जो घरेलू तौर पर उत्पादित उपस्करों की खरीद करने वाले उत्पादन अथवा कारोबारी प्रचालनों में लगे हैं (कार्यक्रम – 25)	0.76 प्रतिशत	0.76 प्रतिशत
19	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय में कमी करनेके लिए कर नीतियां (कार्यक्रम – 28)	0.32 प्रतिशत	0.32 प्रतिशत



20	ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्य की गई है (कार्यक्रम - 31)	1.56 प्रतिशत	1.74 प्रतिशत
21	विशेष उपस्करों की खरीद के संबंध में कर ऋण (कार्यक्रम - 18)	0.19 प्रतिशत	0.19 प्रतिशत
22	भू - उपयोग शुल्क पर शुल्कों और करों से राहत	1.69 प्रतिशत	1.69 प्रतिशत
23	आयातित प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के लिए टैरिफ और आयात वेट की छूट (कार्यक्रम - 26)		
24	भू उपयोग शुल्कों में कमी (कार्यक्रम - 37)		
25	कच्ची सामग्री - विद्युत (कार्यक्रम - 40)	2.17 प्रतिशत	2.17 प्रतिशत
26	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम राशि के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रावधान (कार्यक्रम - 43)		
क	कच्ची सामग्री - पिंग आयरन	0.32 प्रतिशत	0.32 प्रतिशत
ख	कच्ची सामग्री - सी आर सी ए स्क्रैप	7.62 प्रतिशत	7.62 प्रतिशत
	कुल सी वी डी मार्जिन	28.71 प्रतिशत	31.00 प्रतिशत

80. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दिनांक 12 नवंबर, 2015 के पत्र के तहत (प्रति सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करा दी गई है) दो विवरण प्रस्तुत किए हैं अर्थात् विवरण क - ऐसी योजनाओं की सूची, जिनके लिए जांच बंद की जाए और विवरण - ख ऐसी योजनाएं, जिनके लिए जांच जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि नीचे दिए गए विवरण - क के कार्यक्रमों के लिए याचिकाकर्ता के पास लाभों की मात्रा के संबंधों में अन्य कोई साक्ष्य नहीं है, जो कि उन लाभों के अलावा हो, जिनकी याचिकाकर्ता द्वारा नीचे दी गई विवरण - ख की सूची की योजनाओं में पहचान की गई है और प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि नीचे विवरण - क में सूचीबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में जांच समाप्त की जाए।

**विवरण - क -** ऐसी योजनाएं, जिनके लिए जांच वापस ली जानी है :

क्र. सं.	शीर्ष	कार्यक्रम सं.	योजनाएं
1	विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र प्रोत्साहन	कार्यक्रम सं. 1	विशेष आर्थिक जोनों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर) में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों (एफ आई ई) के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 2	तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक व प्रौद्योगिकीय विकास जोनों में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 3	शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 4	एस ई जैड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कारपोरेट आय कर छूट और
		कार्यक्रम सं. 7	कास्टिंग और फोर्जिंग प्रणाली के लिए अधिमान्य कर

2	अधिमान्य आय कर कार्यक्रम और कर प्रोत्साहन	कार्यक्रम सं. 21	न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादनकारी एफ आई ई के लिए कम कर दरें
		कार्यक्रम सं. 22	विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 23	गहन प्रौद्योगिकी और गहन ज्ञान वाले एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 24	एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 26	प्रौद्योगिकी उन्नय के प्रयोजन के लिए एफ आई ई लाभों का पुनः निवेश करने के लिए आय कर की वापसी
		कार्यक्रम सं. 27	विदेशी निवेशकों द्वारा एफ आई ई लाभों का पुनः निवेश करने के लिए आय कर की वापसी
		कार्यक्रम सं. 29	केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
		कार्यक्रम सं. 30	घरेलू तौर पर निर्मित उत्पादन उपस्करों की खरीद के लिए आयकर ऋण
		कार्यक्रम सं. 32	व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्ची सामग्री) (एफ आई ई के लिए) में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायत
		कार्यक्रम सं. 34	पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिमान्य आय कर नीति
		कार्यक्रम सं. 35	पात्र रिहायशी उद्यमों के बीच लाभांश छूट
3	सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर वस्तुएं / सेवाएं प्रदान करना	कार्यक्रम सं. 38	सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर इनपुट सामग्रियां होट रोल्ड स्टील प्रदान की गईं
		कार्यक्रम सं. 39	सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर होट रोल स्टील प्रदान की गईं
		कार्यक्रम सं. 41	औद्योगिक अथवा अन्य विशेष अर्थिक जोनों में स्थित कंपनियों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक से कम राशि के लिए भूमि
		कार्यक्रम सं. 42	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम राशि के लिए पानी के प्रावधान सहित कार्यक्रम
		कार्यक्रम सं. 44	पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक राशि के लिए सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद
		कार्यक्रम सं. 45	सरकार द्वारा बाजार मूल्य के कम कीमत पर इनपुट सामग्रियां (कच्ची सामग्री) तथा उपयोगी सेवाएं प्रदान करना

विवरण – ख – ऐसी योजनाएं जिनके लिए जांच जारी रखी जानी है :

क्र. सं.	शीर्ष	कार्यक्रम	योजनाएं
1	विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जैड) तथा	कार्यक्रम सं. 5	एस ई जैड और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट तथा / अथवा कमी

	अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रोत्साहन	कार्यक्रम सं. 6	एस ई जैड और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपस्करों पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर (वैट) की छूट
2	अनुदान	कार्यक्रम सं. 8	राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि
		कार्यक्रम सं. 9	स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी और/ अथवा प्रतिसंतुलनकारी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति
		कार्यक्रम सं. 10	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
		कार्यक्रम सं. 11	नवोन्मेषी प्रायोगिक उद्यम अनुदान
		कार्यक्रम सं. 12	सुपरस्टार उद्यम अनुदान
		कार्यक्रम सं. 13	ऐसे उद्यमों को प्ररस्कृत करना, जिनके उत्पाद “चीन के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क” अथवा “चीन के प्रसिद्ध ब्रांड” के लिए पात्र हो
		कार्यक्रम सं. 14	हाई – ट्रेक उद्योग की उद्यम निवेश निधि
		कार्यक्रम सं. 15	विदेशी निवेश से मुख्यालयों और क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान
		कार्यक्रम सं. 16	नवोन्मेषी छोटे तथा मझोले उद्यम अनुदान
		कार्यक्रम सं. 17	निजी स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों को अनुदान
3	इक्विटी कार्यक्रम	कार्यक्रम सं. 18	इक्विटी प्रदान करना
		कार्यक्रम सं. 19	भुगतान न किए गए लाभांश
4	अधिमान्य ऋण	कार्यक्रम सं. 20	कास्टिंग उद्योग के लिए अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें।
5	अधिमान्य आय कर कार्यक्रम और कर प्रोत्साहन	कार्यक्रम सं. 25	ऐसे एफ आई ई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां/ जिनके पास चीन में संस्थापन अथवा स्थान हो और घरेलू उत्पादित उपस्करों की खरीद करने वाले उत्पादन अथवा कारोबारी प्रचालनों में लगे हैं।
		कार्यक्रम सं. 28	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय की कमी के लिए कर नीतियां
		कार्यक्रम सं. 31	ऐसी कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां, जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्य की गई है।
		कार्यक्रम सं. 33	विशेष उपस्करों की खरीद से संबंधित कर ऋण
5	सागग्रियों और मशीनों पर शुल्कों और करों से राहत	कार्यक्रम सं. 36	आयातित प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के लिए टैरिफ और आयात वैट से छूट
		कार्यक्रम सं. 37	भू उपयोग शुल्कों में कमी
		कार्यक्रम सं. 40	सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर विद्युत प्रदान करना
		कार्यक्रम सं. 43	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम राशि के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रावधान

81. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोधों तथा उपरोक्त विवरण – क में उल्लिखित योजनाओं / कार्यक्रमों के संबंध में जांच को वापस लेने के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने उपरोक्त अनुसूची – क में सूचीबद्ध योजनाओं / कार्यक्रमों की आगे जांच नहीं की और केवल उपरोक्त विवरण – ख में सूचीबद्ध योजनाओं / कार्यक्रमों के प्रतिसंतुलनकारी होने की ही जांच करने तक स्वयं को सीमित रखा तथा घरेलू उद्योग को रियायत / क्षति की मात्रा तय की।

**विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) प्रोत्साहन और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्र**

82. कार्यक्रम सं. 5 : विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों (एफ आई ई के लिए) स्थानीय आय कर छूट और अथवा कमी।

क) **कार्यक्रम का संक्षिप्त व्यौरा** – घरेलू उपयोग ने यह आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में एसईजैड और अन्य निर्दिष्ट जोनों में स्थित एफ आई ई को कम आय कर के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है, जहां पर कि उत्पादक अथवा कारोबारी प्रचालनों में लगे और चीन में अपनी संस्थापना अथवा स्थान रखने वाले एफ आई ई को उनकी आय कर पर भुगतान किए गए स्थानीय कर की गणना कर योग्य आय पर 25 प्रतिशत की दर से की जाएगी ; स्थानीय आय कर की गणना कर योग्य आय पर 3 प्रतिशत की दर से की जाएगी। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र विदेशी निवेश वाले उद्यम शून्य दर पर स्थानीय आयकर की भुगतान करने के लिए पात्र होंगे अन्यथा यह चीन सरकार को 3 प्रतिशत की दर पर देना होता।

ख) **इच्छुक पक्षकारों के विचार** – चीन सरकार ने यह कहा है कि कार्यक्रम को उस समय बंद कर दिया गया था जब नए कारपोरेट आय कर कानून प्रभावी हुए थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी अनुग्रह अवधि नहीं थी। बाद में प्रकटीकरण के उपरांत की अवस्था में चीन सरकार ने प्राधिकारी का ध्यान लॉ आफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आन इंटरप्राइजेज इंकम टैक्स (दिनांक 16 मार्च, 2007 को 10वें राष्ट्रीय पीपल कांग्रेस के पांचवे सत्र में अंगीकार किया गया) की ओर आकर्षित करते हुए यह दोहराया है कि इस योजना कार्यक्रम को दिनांक 1.1.2008 से बंद कर दिया गया है।

चीन के प्रतिवादी कास्टिंग उत्पादक झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलोजी कं. लि. ने यह कहा है कि उसे इस कार्यक्रम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि वह न तो एफ आई ई है और न ही विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) में स्थित है।

आई डब्ल्यू टी एम ए ने यह तर्क दिया कि कार्यक्रम को आयात उपस्कर संबंधी कर नीतियों के समायोजन के संबंध में राज्य परिषद के परिपत्र (जी यू ओ एफ ए – 1997) सं. 37 के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2008 से बंद कर दिया गया था। यह कार्यक्रम निवेशों के प्रोत्साहन के लिए राज्य परिषद के हैनन द्वीप प्रांत के लिए उपलब्ध था। यह कार्यक्रम निर्यातक देश के क्षेत्र के भीतर वंचित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अतः यह कार्यक्रम एस सी एम करार के अनुच्छेद 8 के तहत गैर – कार्रवाई योग्य सब्सिडी की श्रेणी में आएगा। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए जांच को ए एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.9 के तहत बंद कर दिया जाए।

ग) **प्रशासन प्रधिकरण** – इस कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), राज्य कर प्रशासन (एस ए टी), वाणिज्य मंत्रालय (एम ओ एफ सी ओ एम) द्वारा किया जाता है जो कि ए एस सी एम और अधिनियम तथा नियमों के तात्पर्य से एक लोक निकाय है।

घ) **कार्यक्रम के तहत लाभ** – कार्यक्रम में ऐसे एफ आई ई को कर बचत के रूप में विदेशी निवेश उद्यमों के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) अथवा अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं। चीन सरकार ने यह दावा किया कि कथित योजनाएं 2008 में बंद कर दी गई हैं और प्रतिवादी निर्यातक ने योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि कथित योजना अभी भी चीन में अस्तित्व में है और यू एस तथा कनाडा जैसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलनकारी पाया गया है।

ड) **कार्यक्रम की विशिष्टता** – यह कार्यक्रम उद्यम विशिष्टता और क्षेत्र विशिष्टता दोनों वाला है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित एफ आई ई तक की सीमित है। चूंकि कार्यक्रम के तहत लाभ एक विशेष प्रकृति वाले और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे हैनन द्वीप, ग्वांग डोंग प्रांत तक ही सीमित है इसलिए नियमों के तात्पर्य से कार्यक्रम विशिष्टता में आता है।

च) **कार्यक्रम का प्रतिसंतुलनकारी होना** – जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है, कार्यक्रम का अस्तित्व विदेशी निवेश वाले उद्यमों तथा विदेशी उद्यमों के लिए चीन जन. गण. के आय कर कानून (कर कानून) ; अनुच्छेद 5 और 9 , विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए चीन जन. गण. के आय कर कानून के कार्यान्वयन का विनियमन ; ग्वांग डोंग प्रांत में

विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में विनियमन (1980-08-26); हैनन द्वीप के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य परिषद के प्रावधान (1988-05-04) से प्रमाणित है।

जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है, चीन सरकार ने भी डब्ल्यू टी ओ में इस योजना के अस्तित्व के बारे में सूचित किया है, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के दस्तावेज जी/एस सी एम/एन/123/सी एच एन, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 में उल्लेख किया गया है। कनाडा प्राधिकारी द्वारा भी पी आर सी से कतिपय गालवेनाइज्ड स्टील वायर तथा पीआरसी से कतिपय स्टेनलेस स्टील सिंक के अन्तिम जांच परिणाम में योजना को प्रतिसंतुलनकारी माना गया है।

**छ) अन्तिम जांच परिणाम और निष्कर्ष** – कार्यक्रम में नियमों के तात्पर्य से चीन सरकार द्वारा परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान किया है। कार्यक्रम के तहत लाभ विशेष क्षेत्र में स्थित विशेष प्रकार के कारोबारी उद्यमों तक ही सीमित हैं; इस प्रकार यह कार्यक्रम नियमों के तात्पर्य से विशिष्ट है। इस कार्यक्रम में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है। बाद के अनुरोधों में जांच के दौरान, याचिकाकर्ता ने चीन में कास्टिंग उत्पादकों/ निर्यातकों जैसे हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियांजिन) कं. लि., गैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कं. लि., साइनोवेल विंड ग्रुप कं. लि. तथा एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (तियांजिन) कं. लि. की सूची प्रस्तुत की, जो एस ई जैड और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा लाभ के लिए पात्र एफ आई ई की प्रकृति के हैं। चीन सरकार के प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने योजना की प्रतिसंतुलनकारिता के निर्धारण के लिए आगे कार्यवाही नहीं की है।

**83. कार्यक्रम संख्या 6 : एसईजेड तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों (एफआईई एवं डीआईई दोनों के लिए) में आयातित सामग्री और उपकरण पर प्रशुल्क एवं मूल्य-वर्धित कर (वैट) छूट**

**क. कार्यक्रम का सार** – घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम उन उद्यमों जो एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं और "मार्गदर्शी विदेशी निवेश और क्रय उपकरणों के लिए उद्योगों की सूची में 'प्रोत्साहित' अथवा प्रतिबंधित श्रेणियों में आती हैं, को लाभ देता है। इस प्रकार के उद्यमों को प्रशुल्क एवं आयात वैट से छूट दी जाएगी। यह कार्यक्रम उनके उत्पादन में उपयोग होने वाले मुख्य उपकरण के आयात के लिए एफआईई और घरेलू उद्यमों दोनों के पक्ष में वैट एवं आयात प्रशुल्क से छूट उपलब्ध कराता है।

**ख. हितबद्ध पक्षों के विचार** – जीओसी ने अपने प्रतिक्रिया में उल्लेख किया है कि यह कार्यक्रम कतिपय विदेशी निवेश परियोजनाओं और कतिपय घरेलू निवेश परियोजनाओं दोनों के लिए लागू है और घरेलू निवास परियोजना के आयात की गैर शुल्क छूट योग्य वस्तु की सूची में सूचीबद्ध श्रेणियों में नहीं आने की अवधि तक अपने स्वयं के प्रयोग के लिए आयातित उपकरण की खरीद पर आयात प्रशुल्क और वैट का भुगतान करने से अर्हता प्राप्त करने वाले उद्यमों की छूट में परिणत हो सकता है। यह कार्यक्रम आयातित उपकरण संबंधी समायोजन कर नीतियों से संबंधित राज्य परिषद के परिपत्र के अनुसरण में 29 दिसंबर, 1997 को स्थापित किया गया था (जीयूओएफए(1997) सं. 37)। नीति का उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और विकसित विदेशी प्रौद्योगिकी उपकरण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपग्रेड्स शुरू करना है। 25 दिसंबर, 2008 को वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क और राज्य प्रशासन कराधान के सामान्य प्रशासन ने आयात शुल्क के लिए कतिपय तरजीही नीतियों के समानरूपी समायोजन से संबंधित संगत मुद्दों के संबंध में एक घोषणा की थी। उक्त घोषणा (सं. 43[2008]) में यह उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार घरेलू निवेश परियोजनाओं और विदेशी निवेश परियोजनाओं द्वारा आयातित स्वयं के प्रयोग के लिए उपकरण, विदेशी सरकारों से आयातित उपकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के ऋणों, विदेशी प्रसंस्करण व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए गैर-मूल्यांकित आयातित उपकरण तथा संविदाओं के अनुसार उपर्युक्त उपकरण सहित आयातित प्रौद्योगिकियों और अनुरूपी पीसीज तथा स्पेयर पार्ट्स एवं जो राज्य परिषद (जीयूओएफए(1997) सं. 37) के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र राज्य द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, आयात मूल्य वर्धित कर पुनः लगाया जाएगा परंतु मूल रूप से निर्धारित सीमा के भीतर आयात शुल्क में छूट जारी रहेगी। बाद में प्रकटीकरण के उपरांत की अवस्था में चीन सरकार ने कतिपय अधिमार्ग आयात शुल्क के संबंध में प्राधिकारी का ध्यान वित्त मंत्रालय, सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन और राज्य कराधान प्रशासन के नोटिस की ओर आकर्षित करते हुए यह दोहराया है कि आयातमूल्य वर्धित कर का एकत्रण पुनः शुरू किया जाएगा जबकि टैरिफ की छूट लागू रहेगी।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह एसईजेड में स्थित नहीं है।

आईडब्ल्यूटीएम ने निश्चयपूर्वक कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन एफआईई को उपलब्ध कराया गया है जो प्रोत्साहित अथवा प्रतिबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम उन आदानों जो अंतिम उत्पाद के

उत्पादन के प्रयोग किया जाते हैं, पर लगाए गए पूर्व चरण संचयी प्रत्यक्ष कर की छूट अथवा माफी के लिए भी अनुमति देता है। याचिका ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराती कि निर्यातक एफआईई है। यह दावा किया गया है कि एसईजेड में स्थित उद्यम प्रशुल्क उपकरणों के लिए प्रशुल्क और आयात वैट से छूट प्राप्त हैं। एसईजेड में स्थित उद्यम आयातित सामानों और उपकरणों जो विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और आयात वस्तुओं पर प्रशुल्क और वैट छूट के लिए पात्र हैं, तथापि याचिका यह नहीं दर्शाती कि छूट जो कि दी गई है, उनसे अधिक जो एससीएम करार की पादटिप्पणी 1 के तहत अपेक्षानुसार प्रोद्भूत हो गई है। इसके अतिरिक्त, पादटिप्पणी 1 के साथ पठित एससीएम करार के अनुबंध -II का पैरा 1 भी आर्थिक सहायता के रूप में इस प्रकार के पूर्व चरण संचयी अप्रत्यक्ष कर से छूट देता है। यह कि, सरकारी राजस्व जो कि अन्यथा पूर्व निश्चित अथवा एकत्र नहीं किया गया, वित्तीय अंशदान केवल तभी माना जा सकता है जबकि निर्यातित सामान पर कर जो प्रोद्भूत हो गया है, से अधिक है, से छूट प्राप्त है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य पर्याप्त और उचित नहीं हैं।

**ग. प्रशासी प्राधिकारी** – यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राज्य कराधान प्रशासन (एसएटी), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) जो एससीएम तथा अधिनियम एवं नियमावली के प्रयोजन से एक सार्वजनिक निकाय के अंतर्गत आता है, द्वारा चलाया जाता है। एनडीआरसी और स्थानीय विकास एवं सुधार प्रशासन जैसे प्रभारी प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करें, कि निवेश परियोजना अपेक्षाओं/मानदंडों के अनुसार है अथवा नहीं।

**घ. कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ** – यह कार्यक्रम उन एफआईई अथवा डीआईई जो एसईजेड अथवा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं और 'प्रोत्साहित' अथवा 'प्रतिबंधित' श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, को पूर्व निश्चित राजस्व के रूप में उद्यमों को लाभ प्रदान करती है।

**ङ. कार्यक्रम की विशेषता** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा निश्चयपूर्वक कहा गया है कि यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ केवल इस प्रकार की एफआईई और डीआईई जो एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं और प्रोत्साहित अथवा प्रतिबंधित श्रेणियों के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, तक सीमित हैं। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि जीओसी ने इस कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदण्ड 'घरेलू निवेश परियोजना' और 'विदेशी निवेश परियोजना' और आयातित किए जा रहे उपकरण की किस्म पर आधारित इस कार्यक्रम के लिए तैयार किए हैं।

**च. कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम का अस्तित्व आयातित उपकरण के लिए कराधान नीतियों के समायोजन से संबंधित राज्य परिषद (जीयूओ एफए(1997) सं. 37) के नोटिस के अनुच्छेद 1 और 2 तथा विदेशी निवेश दिशानिर्देशित करने के लिए उद्योगों की सूची (2004) (30 नवंबर, 2007 तक) अथवा विदेशी निवेश दिशानिर्देशित करने के लिए उद्योगों की सूची (2007) (1 दिसंबर, 2007 के पश्चात 2014 की एसएटी घोषणा सं0 49, 2014 की एसएटी घोषणा सं. 51 द्वारा स्थापित किया गया है। कनाडा की डब्ल्यूटीओ अर्धवार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग द्वारा आगे अनुरोध किया गया है कि निर्दिष्ट योजना जी/एससीएम/एन274/सीएएन दिनांक 29 अगस्त, 2014 में सूचित की गई है। यह योजना चीन के विरुद्ध उनके विकर्ष परिणामों में अन्य प्राधिकारियों द्वारा काउंटरवेलेबल रखी गई है।

**छ. जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा पूर्वनिश्चित राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ विशेष क्षेत्र में स्थित कारबार उद्यमों की कुछ किस्मों तक सीमित हैं। इस प्रकार कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के तहत विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता से बना है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि लागत उत्पादक/निर्यातक जो एसईजेड में या एफआईई में स्थित हैं अथवा घरेलू उद्योग हैं, इस प्रकार के लाभ के लिए पात्र हैं। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता से बना है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने चीन में कास्टिंग उत्पादकों/निर्यातकों जैसे हाइड्रा ग्रेन हाइड्रोलेक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियानजीन) का. लि., जेक्सप्रो इंडस्ट्री स्प्लाई शंघाई का.लि., सिनोवेल विंड ग्रुप का. लि. और एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (तियानजीन) का.लि. जो एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित हैं और लाभ के लिए एफआईई पात्रता के स्वरूप की हैं, की सूची प्रस्तुत की है। चीन सरकार के प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने आयातित उपकरणों पर टैरिफ की छूट के संदर्भ में योजना के तहत निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों की गणना के संबंध में कार्यवाही की है।

**ज. आर्थिक सहायता राशि की गणना** – प्रतिसंतुलनकारी आर्थिक सहायता की राशि की गणना, जांच की अवधि (पी ओ आई) के दौरान मौजूद पाए गए प्राप्तकर्ताओं पर प्रदत्त लाभों की दृष्टि से की गई है। प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ सामान्य प्रशुल्क दर और कार्यक्रम के अंतर्गत देय घटी हुई प्रशुल्क दर मानते हुए प्रशुल्क और बचाई गई वैट की राशि मानी गई है। चूंकि लाभ कंपनी द्वारा

निर्यात का ध्यान रखे बिना उपलब्ध है इसलिए सी वी डी मार्जिन कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। प्रतिवादी निर्यातक, मैसर्स जिआली विंड ने यह दावा किया है कि उसे कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ है क्योंकि वह एस विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) में स्थित नहीं है।

यह नोट किया गया है कि यह आर्थिक सहायता उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का ध्यान रखे बिना पात्र उद्यमों के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ उनके उत्पादन में प्रयोग किए गए मुख्य उपकरणों के अयातों पर कुल वैट और आयात प्रशुल्क छूट पर उपलब्ध है। जब कंपनी यह दावा करने योग्य होती है कि वह इस कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए पात्र है तो कंपनी की कुल बिक्री पर उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा प्राप्त टैरिफ छूट के संबंध में कोई भी संगत ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं। याचिकाकर्ताओं अथवा इच्छुक पक्षकारों से संगत सूचना उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी ने कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता के संबंध में कोई भी मात्रा प्रदान की है।

#### अनुदान

84. उनके दिनांक 12 नवंबर, 2015 के पत्र के तहत घरेलू उद्योग ने केवल निम्नलिखित अनुदान संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में जांच को जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अनुदान	कार्यक्रम सं. 8	द स्टेट की टेक्नोलॉजी रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स फंड
	कार्यक्रम सं. 9	
	कार्यक्रम सं. 10	
	कार्यक्रम सं. 11	
	कार्यक्रम सं. 12	
	कार्यक्रम सं. 13	
	कार्यक्रम सं. 14	
	कार्यक्रम सं. 15	
	कार्यक्रम सं. 16	
	कार्यक्रम सं. 17	

#### 85. कार्यक्रम सं. 8 : द स्टेट की टेक्नोलॉजी रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स फंड

क. **कार्यक्रम का सार** – घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि कार्यक्रम की अनुदान बड़े आकार की एसओई को लाभ पहुंचाती है। ये उद्यमी 512 मुख्य उद्योगों में उच्च क्रेडिट रैंक रखते हैं। ये उद्यमी उद्यमों के लिए सीधे सरकारी योगदान अथवा कम व्याज ऋणों जहां उद्यमी द्वारा स्थापित ऋणों के लिए व्याज भुगतान सरकार देती है, के प्रावधान के जरिए प्राप्त करते हैं। चूंकि यह विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन एसओई जो 512 महत्वपूर्ण उद्योगों में उच्च क्रेडिट रैंक रखते हैं, तक सीमित है।

ट. **हितबद्ध पक्षों के विचार** – चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि यह कार्यक्रम 22 फरवरी, 2008 को रद्द कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिस्थापन अवधि और रियायत अवधि नहीं दी गई थी। इसलिए कोई कास्टिंग उत्पादक/निर्यातक जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकते अथवा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। याचिका के अनुसार इस कार्यक्रम का मूलभूत कानून राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए उपायों के प्रचार और परिचालन से संबंधित सूचना और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी बांड स्पेशल फंड के प्रशासन के लिए उपाय (जीओयूजेआईएनजीएमएओटीओयूजेडआई [1999] 886) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय पुनरुद्धार परियोजना के पर्यवेक्षण और प्रशासन के लिए उपाय के प्रचार और परिचालन से संबंधित सूचना (परीक्षण कार्यान्वयन के लिए) (जीओयूजेआईएनजीएमएओटीओयूजेडआई [1999] 11038) है। जैसाकि जीओसी द्वारा दावा किया गया है कि ये दोनों विनियम एनडीआरसी के आदेश संख्या-59 के तहत रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने आगे दावा किया है कि इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं

हुआ। बाद में प्रकटीकरण के उपरांत की अवस्था में चीन सरकार ने प्राधिकारी का ध्यान राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग की डिक्री सं. 59 की ओर आकर्षित करते हुए यह दोहराया है कि कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ। उन्होंने आगे दावा किया है कि मूल कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान वर्तमान जांच का हिस्सा नहीं है।

आईडब्ल्यूटीएमए ने निश्चयपूर्वक कहा है कि राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग डिक्री सं. 59 के अनुसार यह कार्यक्रम 22 जनवरी, 2008 को रद्द कर दिया गया था। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि निर्यातक उद्यमों ने निधि के लिए आवेदन किया है और निर्यातक उद्यम सक्षम नेतृत्व, सुदृढ़ प्रशासन और 512 महत्वपूर्ण उद्यमों में उच्च क्रेडिट रैंक, 120 पायलट उद्यम समूह तथा उद्योगों के अग्रणी उद्यम वाले राज्य स्वामित्व के बड़े आकार के उद्यम हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए जांच एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार समाप्त की जानी चाहिए।

**ख. प्रशासी प्राधिकारी -** यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय (एमओएफ) तथा वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) जो एससीएम तथा अधिनियम एवं नियमावली के प्रयोजन से एक सार्वजनिक निकाय के अंतर्गत आता है, द्वारा चलाया जाता है। यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इसके स्थानीय शाखा कार्यालय अथवा ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जाता है।

**ग. कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ-** जैसा कि घरेलू उपयोग द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रौद्योगिकी पुनरुद्धार, उद्यमों और उत्पादों, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुगम बनाने, उत्पाद ढांचे के सुधार, क्वालिटी में सुधार, आपूर्ति की वृद्धि, घरेलू उद्योग के विस्तार, राज्य अर्थव्यवस्था के सतत एवं सुदृढ़ विकास को बढ़ावा देने के लिए 512 प्रमुख उद्यमों में सूचीबद्ध पात्र उद्यमों को सीजीओ द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इस कार्यक्रम में आर्थिक सहायता इसका भाग है क्योंकि यह अनुदान के रूप में अथवा अचल परिसंपत्तियों की अधिग्रहण के लिए निधि के सीधे हस्तांतरण जो प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदत्त करता है। चूंकि अचल परिसंपत्तियां आर्थिक सहायता से संबद्ध है और अवधि में आबंटित की जाती है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि निर्यातक द्वारा 1998 से 2013 तक अनुदान प्राप्त की गई है तब भी पीओआई के दौरान लाभ जारी रहेंगे।

**घ. कार्यक्रम की विशिष्टता -** यह आर्थिक सहायता विशिष्ट है क्योंकि सहायता कतिपय बड़े आकार के राज्य स्वामित्व और 512 महत्वपूर्ण उद्यमों और 12 पायलट उद्यम समूहों से उद्यमों राज्य धारक उद्यमों तक सीमित है। अब तक परियोजना पूर्वोत्तर, केंद्रीय और पश्चिम क्षेत्रों में पुराने औद्योगिक आधार के विशेष रूप से निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती थी। यह नियमावली के प्रयोजन में भी विशिष्ट है।

**ड. कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता -** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम का अस्तित्व राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण विशेष निधि के प्रशासन के लिए उपाय, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए उपायों के प्रचार और परिचालन से संबंधित सूचना तथा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी-बांड विशेष निधि के प्रशासन के लिए उपाय () राज्य अर्थशास्त्र और व्यापार आयोग से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय पुनरुद्धार परियोजनाओं (परीक्षण कार्यान्वयन हेतु) के पर्यवेक्षण और परिचालन से संबंधित सूचना (), राष्ट्रीय उपाय तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए ट्रेजरी-बांड विशेष निधि के प्रशासन के लिए उपायों के संशोधन की सूचना () है।

**झ. जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम -** जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया था कि जीओसी ने चीनी जनवादी गणराज्य से ऑर्गेनिक कोटेड स्टील के आयात की सीवीडी जांच के मामले में यूरोपीय आयोग को अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह कार्यक्रम 2003 में समाप्त कर दिया गया है। जबकि वर्तमान जांच में की गई प्रतिक्रिया में जीओसी ने उल्लेख किया है कि यह योजना 2008 में रद्द की गई थी।

यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान की व्यवस्था करता है। कार्यक्रम के तहत लाभ कारबार उद्यमों की कतिपय किस्मों तक सीमित हैं। इसलिए यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबिलिटी आर्थिक सहायता से बना है। घरेलू उद्योग में जांच के दौरान आगे दावा किया कि कुछ चाइनीज उद्योगों की वेबसाइट सूचना दर्शाती है कि उन्हें इस प्रकार का अनुदान प्राप्त हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह दावा भी किया है कि प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ही पात्र हैं और इस कार्यक्रम के तहत अनुदान प्राप्त की है।



प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल एसओई इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं चूंकि जियाली एक एसओई नहीं है इसलिए प्राधिकारी का मत है कि यह इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने की पात्र नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दलियान हौरई हेवी इंडस्ट्री स्टील कास्टिंग का.लि., लाओनिंग, दलियान इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र एसओई में से एक है। अन्य सभी प्रतिक्रिया नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे और समाप्त कर दिए गए हैं। उत्तर न देने वाले अन्य सभी निर्यातकों के लिए चीन सरकार ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई अथवा व्यक्तिगत निर्यातक ने स्वयं ही इन कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त करने के बारे में सूचना नहीं दी। चीन सरकार के प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने योजना की प्रतिसंतुलनकारिता का निर्धारण करने के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की है।

#### 86. कार्यक्रम सं0 9 : स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी और/अथवा काउंटरवेलिंग कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति

**क. कार्यक्रम का सार :** याचिकाकर्ता ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम पाटन रोधी जांच में शामिल और वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) के अनुदेशों का पालन करने वाली उन कंपनियों के लिए लाभ प्रदान करता है जो एडीडी/सीवीडी जांच में भाग लेने पर 40% तक कानूनी फीस कटौती के लिए पात्र हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट हैं क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ केवल उन संबंधित उद्यमों तक सीमित हैं जो एडीडी अथवा सीवीडी जांच में शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय वित्तीय ब्यूरो पाटन-रोधी कार्यवाही में भाग लेने वाली किसी कंपनी के लिए 40% कानूनी फीस वापस करता है।

**ख. हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की सरकारी अनुदान प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुई।

आईडब्ल्यूटीएमए ने निश्चयपूर्वक कहा है कि संबद्ध उत्पाद के संबंध में भारत द्वारा संबद्ध उत्पाद संबंधी किसी पाटन रोधी अथवा किसी अन्य व्यापार उपचार उपाय जांच कभी भी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने यह भी नहीं दर्शाया है कि निर्यातक कभी पाटनरोधी जांच में शामिल थे और इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त किया है। उक्त कार्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई विशेषता सिद्ध नहीं की गई है। कार्यक्रम के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। याचिका में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अभाव में एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

**ग. प्रशासी प्राधिकारी -** यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय (एमओएफ) तथा वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) जो एससीएम तथा नियमावली के प्रयोजन से एक सार्वजनिक निकाय के अंतर्गत आता है, द्वारा चलाया जाता है। यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इसके स्थानीय वित्तीय शाखा कार्यालयों अथवा ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जाता है।

**घ. कार्यक्रम के तहत लाभ -** यह कार्यक्रम आर्थिक सहायता का हिस्सा है क्योंकि यह पाटनरोधी अथवा काउंटरवेलिंग शुल्क जांच कार्यवाही में कानूनी फीस को कवर करने के लिए अनुदान के रूप में अथवा निधि के सीधे अंतरण से वित्तीय योगदान के रूप में उपलब्ध कराता है और नियमावली के प्रयोजन के भीतर लाभ प्रदत्त करता है।

**ङ. कार्यक्रम की विशिष्टता -** यह आर्थिक सहायता नियमावली के तहत विशिष्ट है क्योंकि यह उन कतिपय उद्यमों जो विदेशी पाटन-रोधी कार्यवाहियों के अध्यक्षीन है, तक सीमित है।

**च. कार्यक्रम की काउंटरवेलिबिलिटी -** उक्त कार्यक्रम का अस्तित्व पाटन-रोधी, पाटन-आर्थिक सहायता और सुरक्षोपाय जांच के लिए सहायता नीति के कार्यान्वयन के लिए नियमावली है। यह योजना चीन के विरुद्ध उनके विकर्ष निष्कर्षों में भी अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा काउंटरवेलिबल रखा गया है।

**छ. जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम -** यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान की व्यवस्था करता है। कार्यक्रम के तहत लाभ कारबार उद्यमों की कतिपय किस्मों तक सीमित हैं। इसलिए यह

कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबिलिटी आर्थिक सहायता से बना है। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। तथापि, जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई सिवाय पुनः यह कहने के कि प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने निर्दिष्ट योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने कहा है कि इसने इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं लिया है और उनके लेखा परीक्षित लेखे भी यह नहीं दर्शाते कि उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि इस स्कीम के अंतर्गत लाभ जियाली अथवा संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने अन्य प्रतिक्रिया नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए इस योजना के तहत जीओसी द्वारा प्रदत्त लाभ की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया है।

#### 87. कार्यक्रम सं. 10 : अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान

क. **कार्यक्रम का सार :** घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम आर्थिक विकास पद्धति और आर्थिक पुनर्संरचना के अंतरण को त्वरित करने, आत्मनिर्भर अभिनव की क्षमता बढ़ाने, 'अभिनव शहरी जिला' संबंधी कार्यनीति कार्यान्वित करने, सुदृढ़ और तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने के लिए प्रयास करने के लिए पात्र उद्यमों को लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन संबंधित उद्यमों तक सीमित है जिनके पास आरएंडडी सुविधाएं हैं और पात्रता मानदण्डों के अंतर्गत आते हैं। बीजिंग सरकार और वूक्सिंग जिला तथा बीजिंग और वूक्सिंग जिले के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो इस कार्यक्रम के प्रशासन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। यह माना गया है कि विभिन्न जीओसी क्षेत्रीय निकायों द्वारा कई क्षेत्रों में यह कार्यक्रम प्रशासित किया जाता है।

ख. **हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस प्रकार का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। फिर भी यह नोट किया गया है कि सहयोग करने वाले निर्यातक उत्पादक वुक्सी शहर में स्थित नहीं हैं। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने निश्चयपूर्वक कहा है कि एससीएम करार के अनुच्छेद 8 के अनुसार यह कार्यक्रम गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें अनुसंधान एवं विकास के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता के लिए इसी प्रकार का प्रावधान सीवीडी नियमावली के नियम 11 के साथ पठित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(3) में मौजूद है और लागू है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम जिंगहो न्यू डिस्ट्रिक्ट में पंजीकृत और प्रचालन कर रही कंपनियों के संबंध में है। याचिकाकर्ता ने यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि संबद्ध उत्पाद के निर्यातक जिंगहो न्यू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसलिए यह कार्यक्रम एक गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता है और एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 और सीवीडी नियमावली के नियम 11 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी -** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी) तथा इसकी स्थानीय और नगर पालिका सरकार जैसे बीजिंग नगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक आयोग और वूक्सिंग जिला सरकार वूक्सिंग जिला प्रौद्योगिकी ब्यूरो (एसटीबी) जो एससीएम तथा अधिनियम एवं नियमावली के प्रयोजन से एक सार्वजनिक निकाय के अंतर्गत आता है, द्वारा चलाया जाता है। यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी), स्थानीय और नगर सरकारों तथा स्थानीय शाखा कार्यालयों अथवा ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जाता है।

घ. **कार्यक्रम के तहत लाभ -** इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए अनुदान जीओसी द्वारा वित्तीय योगदान है जिसमें चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमों को जीओसी द्वारा निधियों का सीधे अंतरण शामिल है। अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्राप्तकर्ता उद्यम की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में वित्तीय योगदान किया जाएगा।

- ड. कार्यक्रम की विशिष्टता** – केवल वे उद्यम जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान करते हैं, आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं। चूंकि मानदण्ड और शर्तें चीन में अन्य उद्यमों की तुलना में विशिष्ट उद्यमों को आर्थिक सहायता के लिए पहुंच उपलब्ध कराने का समर्थन करते हैं। इसलिए कार्यक्रम विशिष्ट माना गया है।
- च. कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी** – घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उक्त कार्यक्रम का अस्तित्व शियांग आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किए गए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय किस्म के उद्यमों के अधिग्रहण की सहायता हेतु कार्यान्वयन उपाय और विदेशी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास दल का रोजगार, वूक्सिंग जिले के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय व्ययों की तीन किस्मों संबंधी प्रबंधन उपाय प्रकाशित और जारी करने से संबंधित वूक्सिंग जिले की राष्ट्र सरकार के कार्यालय की सूचना प्रमाणित करती है। यह योजना चीन के विरुद्ध अपने विकर्ष परिणामों में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा काउंटरवेलेबल रखे गए हैं।
- छ. जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने उन संबद्ध देशों के कास्टिंग उत्पादकों/निर्यातकों की सूची प्रस्तुत की है जो इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। सिनोवल विंड ग्रुप का. लि. और झिजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का. लि. कुछ चाइनीज कास्टिंग उत्पादक हैं जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। जीओसी ने सहयोग किया होता ओर स्पॉट जांच की अनुमति दी होती हो प्राधिकारी द्वारा इस पहलू का पता लगाया जा सकता था।

चूंकि झिजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का. लि. पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करती इसलिए इस योजना के तहत उन्हें कोई लाभ प्रोदभूत नहीं हुआ है। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई सिवाय पुनः यह कहने के कि प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने निर्दिष्ट योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

#### 88. कार्यक्रम सं. 11 : अभिनव प्रयोगात्मक उद्यम अनुदान

- क. कार्यक्रम का सार :** घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को लाभ उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन संबंधित एसएमई तक सीमित हैं जो पात्रता मानदण्डों के अंतर्गत आती हैं।
- ख. हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस प्रकार का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झिजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने निश्चयपूर्वक कहा है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उल्लेख किया है कि इस कार्यक्रम के तहत जो उपक्रम लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं, को अनुसंधान एवं विकास कार्य करने चाहिए। परिणामतः एससीएम करार के अनुच्छेद 8 के अनुसार यह कार्यक्रम गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें अनुसंधान एवं विकास के लिए आर्थिक सहायता शामिल है। गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता के लिए इसी प्रकार का प्रावधान सीवीडी नियमावली के नियम 11 में मौजूद है और लागू है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम झिजियांग प्रांत में पंजीकृत और प्रचालन कर रही कंपनियों के संबंध में है। याचिकाकर्ता ने यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि संबद्ध उत्पाद के निर्यातक झिजियांग प्रांत में स्थित है। इसलिए यह कार्यक्रम एक गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता है और एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी** - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी) तथा इसके विभिन्न प्रान्तों के प्रशासनिक कार्यालय जो झिजियांग प्रान्त के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो के प्रशासनिक कार्यालय जो सार्वजनिक निकाय है तथा जो एससीएम तथा अधिनियम एवं नियमावली के प्रयोजन से एक सार्वजनिक निकाय के अंतर्गत आता है, द्वारा चलाया जाता है। यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी) और विभिन्न प्रान्तों में इसके प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

घ. **कार्यक्रम के तहत लाभ** - इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया अनुदान जीओसी द्वारा किया गया वित्तीय योगदान है जिसमें जीओसी द्वारा चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमियों के लिए निधियों का सीधा अंतरण शामिल है। अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्राप्तकर्ता उन उद्यमियों जो एसएमई की श्रेणी में आते हैं और अभिनव के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलाप करते हैं, की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में वित्तीय योगदान किया जाएगा।

ङ. **कार्यक्रम की विशिष्टता** - केवल वे उद्यम जो लघु और मध्यम उद्यम हैं और अभिनव अनुसंधान करते हैं, आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं। चूंकि मानदण्ड अथवा शर्तें आर्थिक सहायता के लिए पहुंच उपलब्ध कराने हेतु चीन में अन्य उद्यमियों की तुलना में आर्थिक सहायता हेतु विशेष रूप से समर्थन करती है, इसलिए इस कार्यक्रम को विशिष्ट माना गया है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि निंगबो गिलोंग टैक्नोलॉजीज का. लि., निंगबो साइक्स मशीनरी का. लि., झिजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजीज का. लि. जो झिजियांग प्रान्त में स्थित हैं और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ब्लज झिजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजीज का. लि. ने कहा है कि इसने इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है जबकि दूसरी कंपनियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। विशिष्टता की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है।

च. **कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी** - जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम का अस्तित्व एसएमई के संवर्धन संबंधी पीआरसी के कानून के अनुच्छेद 10 और 11 एसएमई के विकास के लिए विशेष निधियों के प्रशासन संबंधी उपाय जारी करने से संबंधित वित्त मंत्रालय और उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय [वित्त मंत्रालय की सं. 96 (2012)], एसएमई के विकास के लिए विशेष निधि अंतरिम उपाय जारी करने से संबंधित सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय [सीएआई क्यूआई (2014) सं. 38], एसएमई के विकास के लिए विशेष निधियों के प्रबंधन से संबंधित अंतरिम उपाय जारी करने से संबंधित वित्त मंत्रालय [सीएआई जिआन (2015) सं. 458] की सूचना द्वारा प्रमाणित है। अभिनव उद्यम स्थापित करने संबंधी झिजियांग प्रान्त की कार्य कार्यान्वयन योजना झिजियांग प्रान्त के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा प्रशासित की गई। यह योजना भी चीन के विरुद्ध अपने विकर्ष परिणामों में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा काउंटरवेलेबल रखा गया है।

छ. **जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** - यह कार्यक्रम एससीएम तथा नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने उन संबद्ध देशों के कास्टिंग उत्पादकों/निर्यातकों की सूची प्रस्तुत की है। चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जैसे जियाली विंड पावर तथा निंगबो जिलोंग टैक्नोलॉजीज का. लि. इस प्रकार के अनुदान के लिए झिजियांग प्रान्त में कुछ निर्यातक हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली के एक गैर-एसएमई होने के कारण इस योजना के तहत लाभ के मानदण्डों को पूरा नहीं करता। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई सिवाय पुनः यह कहने के कि प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने निर्दिष्ट योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

## 89. कार्यक्रम सं. 12 : सुपरस्टार उद्यम अनुदान

क. **कार्यक्रम का सार** : घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि 'आउटपुट स्केल' रखने वाले पात्र उद्यम इस अनुदान के लिए पात्र हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट होने के कारण इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ केवल उन विशिष्ट उद्यमों तक सीमित हैं जिनके पास अपेक्षित आउटपुट बिक्री है। प्राधिकारी ने यह अवार्ड इसकी बिक्री के कुल मूल्य के आधार दिया है। वह कंपनी जो वर्ष के लिए संगत बिक्री श्रेसहोल्ड को पूरा करती है, अगले वर्ष में यह अवार्ड प्राप्त करती है।

**ख. हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस प्रकार का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। फिर भी यह नोट किया गया है कि सहयोग करने वाले निर्यातक उत्पादक हुजोउ शहर में स्थित नहीं हैं। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने निश्चयपूर्वक कहा है कि इस कार्यक्रम के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदण्ड 2006-08 की अवधि से संबंधित हैं और न कि बाद की अवधि के लिए। यह सुझाव देने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि यह कार्यक्रम बाद की अवधि के लिए उपलब्ध है। यह कार्यक्रम हुजोउ आर्थिक समिति द्वारा चलाया जाता है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि एससीएम करार के अनुच्छेद 1(1)(i) के अनुसार अनुदान सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा सीधे उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इस कार्यक्रम को वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराने वाला नहीं माना जा सकता। यह आर्थिक सहायता कार्यक्रम केवल हुजोउ नगर में स्थित उपक्रमों के लिए उपलब्ध है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि निर्यातक हुजोउ शहर में स्थित है। याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

**ग. प्रशासी प्राधिकारी -** यह कार्यक्रम चीन जनवादी गणराज्य सरकार द्वारा प्रान्तीय प्राधिकारी जो सार्वजनिक निकाय है, के जरिए चलाया जाता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम हुजोउ आर्थिक समिति द्वारा प्रशासित है।

**घ. कार्यक्रम के तहत लाभ -** इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया अनुदान जीओसी द्वारा किया गया वित्तीय योगदान है जिसमें जीओसी द्वारा चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमियों के लिए निधियों का सीधा अंतरण शामिल है। अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्राप्तकर्ता उन उद्यमियों की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में वित्तीय योगदान किया जाएगा।

**ङ. कार्यक्रम की विशिष्टता -** हमने आगे निर्धारित किया है कि कतिपय उद्यमों अर्थात् वे उद्यम जो किसी वर्ष के दौरान कतिपय विक्रय मूल्य बढ़ जाता है, के लिए कानून की दृष्टि से इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान सीमित है। अतः आर्थिक सहायता विशिष्ट है।

**च. कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी -** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम का अस्तित्व सुपर स्टार उद्यमों और उत्कृष्ट उद्यमों के निर्धारण और प्रोत्साहन के लिए उपाय सुपरस्टार उद्यमों, उत्कृष्ट उद्यमों तथा आधारभूत उद्यमों के लिए मानदण्डों की घोषणा से संबंधित हुजोउ सरकार कार्यालय की सूचना है। चीन के विरुद्ध अपने विकर्ष परिणामों में अन्य प्राधिकारियों द्वारा इस योजना को भी काउंटरवेलेबल रखा गया है।

**छ. जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम -** यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जियांगसू एफएडब्ल्यू फाउंड्री का. लि., डेकिंग जुफेंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग का. लि. आदि इस प्रकार के अनुदान के लिए कुछ पात्र निर्यातक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली ने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था जो यह प्रमाणित कर सके कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई सिवाय पुनः यह कहने के कि प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने निर्दिष्ट योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

## 90. कार्यक्रम सं. 13 : 'चीन के सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्कों' अथवा 'चीन के प्रसिद्ध ब्रांडों' के लिए क्वालिटी उत्पादों वाले उद्यमों को अवार्ड

**क. कार्यक्रम का सार :** घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह योजना निर्यातक ब्रांडों को बढ़ावा देने और प्रसिद्ध ब्रांडों के बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए कंपनियों को अनुदान उपलब्ध कराती है। पात्र उद्यम उन महत्वपूर्ण उद्यमों जिनके उत्पाद चीन

के विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड के लिए अर्हक होते हैं और उक्त लाभ के लिए पदत हैं, के आधार पर विशेष रूप से चुने गए हैं। चूंकि यह कार्यक्रम विशिष्ट है इसलिए इस कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन उद्यमों जिनके उत्पाद चीन विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड और/अन्यथा प्रसिद्ध ट्रेडमार्क (चीन प्रसिद्ध ट्रेडमार्क) शीर्षक के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तक सीमित है।

- ख. हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि चीन के प्रसिद्ध ब्रांड केवल ऐतिहासिक संस्थान के हैं जो 2008 के बाद प्रयोग नहीं किए गए हैं। इस प्रकार किसी कास्टिंग उत्पाद/निर्यातक पीओआई के दौरान इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता अथवा आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई राशि जब यह अस्तित्व में थी, सदैव बहुत कम थी और अचल परिसंपत्तियों से संबंधित नहीं थी। इसलिए वर्ष 2008 से पहले प्राप्त की गई कोई अनुदान उसी वर्ष खर्च की गई थी और यह मानते हुए प्राप्त की गई थी कि चालू जांच के दौरान आईपी के लिए कोई लाभ विद्यमान नहीं था अथवा दिया गया था। फिर भी यह नोट किया गया है कि सहयोग करने वाले निर्याक उत्पादक गोंगडोंग और शेनडांग प्रान्त में स्थित नहीं है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया करने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने याचिका में स्वयं निश्चयपूर्वक कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए अर्हक उत्पादों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह साक्ष्य भी नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं का कोई भी निर्यातक इस कार्यक्रम के लिए अर्हक नहीं है। यह कार्यक्रम केवल गोंगडोंग प्रान्त में स्थित निर्यातकों के लिए उपलब्ध है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि निर्यातक गोंगडोंग प्रान्त में स्थित है। याचिकाकर्ता द्वारा चीन सरकार से निधियों का सीधे कोई अंतरण प्रमाणित नहीं किया गया है और इसलिए आर्थिक सहायता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते। इस कार्यक्रम के संबंध में याचिका में कोई विशिष्ट सिद्ध नहीं की गई है। इस कार्यक्रम के लिए जांच शुरू करके प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 6, एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

- ग. प्रशासी प्राधिकारी -** यह कार्यक्रम जीओसी द्वारा राष्ट्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय सरकार स्तरों, जो कि सार्वजनिक निकाय है, द्वारा चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर गोंगडोंग प्रान्त की सरकार इस कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

- घ. कार्यक्रम के तहत लाभ -** इस कार्यक्रम में पात्र उद्यमों को निधि के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपेक्षा है। यह योजना ब्रांड निर्यात को बढ़ाने और प्रसिद्ध ब्रांडों के बाजार हिस्से में वृद्धि करने के लिए है।

- ङ. कार्यक्रम की विशिष्टता -** यह आर्थिक सहायता योजना कतिपय उद्यमों अर्थात् प्रसिद्ध निर्यातक ब्रांड उद्यमों के लिए पहुँच के रूप में नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। पात्रता मानदंडों संबंधी इस प्रकार की कोई कानूनी अथवा प्रशासनिक सूचना नहीं है। तथापि, पात्रता पूर्णतः निर्यात किए जा रहे उत्पाद के सुज्ञात पहलू पर आधारित है।

- च. कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी -** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम आदेश सं. 124-चाइनीज प्रसिद्ध-ब्रांड उत्पादों-दिसंबर, 2009 के प्रशासन के लिए उपाय, चाइनीज प्रसिद्ध-ब्रांड उत्पाद-दिसंबर, 2006 के प्रशासन के लिए उपाय, "चीन विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांड" चीन प्रसिद्ध ब्रांड अथवा चीन सुप्रसिद्ध ब्रांड के शीर्षक के लिए गोंगडोंग प्रान्त के उन उद्यमों जिनके उत्पाद अर्हता प्राप्त करते हैं, को अवार्ड देने के आदेश/अथवा संबंधी निर्णय का अस्तित्व प्रमाणित करते हैं। स्वयं निर्यातक ब्रांड के विकास के लिए 2008 में विशेष अवार्ड निधि बजट से संबंधित सेंडोंग प्रान्त को सूचना (लूकाइकिझी) (2008) (संख्या - 75) घरेलू उद्योग द्वारा आगे अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम व्यापार नीति समीक्षा - डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/300, डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट जी/एससीएम/क्यू2/सीएचएन/42 में रिपोर्ट किया गया है। चीन के विरुद्ध अपने विकर्ष परिणामों अन्य प्राधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम को काउंटरवेलेबल रखा गया है।

**जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम -** यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने उन कास्टिंग उत्पादक/निर्यातक, जो जीओसी के प्रसिद्ध ब्रांड अवार्ड से युक्त हैं, की सूची प्रस्तुत की है। चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जैसे जियाली विंड पावर तथा निंगबों गिंगलॉंग टैक्नोलॉजी कंपनी, उनकी वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार इस प्रकार के अनुदानों के लिए पात्र हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली ने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सकें कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

#### 91. कार्यक्रम संख्या 14 : हाइटेक उद्योग की उद्यम निवेश निधि

क. **कार्यक्रम का सार :** घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम उन पात्र उद्यमों जिनके पास संयुक्त पूंजी है और एनडीआरसी के संबंधित स्थानीय काउंटरपार्ट के साथ सूचना रिकार्ड कराई है, को निधि का सीधे अंतरण करता है। उक्त उद्यम निवेश कंपनियों को हाइटेक उद्यमों के रूप में अनिवार्यतः मान्यता दी जाए और लघु से मध्यम आकार में होने चाहिए, लाभान्वित होते हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि इसके अंतर्गत लाभ केवल शहर अथवा प्रान्तों जैसे बीजिंग, संचाई, तियांजिन, चोंगकिंग में मौजूद हाइटेक जोन अथवा हाइटेक पार्क में स्थित हाइटेक कार्यक्रम वाले उद्यमों तक सीमित है।

ख. **हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की सरकारी अनुदान प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने याचिका में स्वयं निश्चयपूर्वक कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए अर्हक उत्पादों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह साक्ष्य भी नहीं है कि एससीएम करार के अनुच्छेद 1(1)(i) के अनुसार आर्थिक सहायता के लिए अर्हता प्राप्त की है। यह कार्यक्रम केवल न्यू नॉर्दर्न जिले में स्थित उद्यमों के लिए उपलब्ध है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक न्यू नॉर्दर्न जिले में स्थित हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में याचिका में कोई विशिष्ट सिद्ध नहीं की गई है। इस कार्यक्रम के लिए जांच शुरू करके प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 6, एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी -** यह कार्यक्रम एनडीआरसी, जीओसी, जो सार्वजनिक निकाय हैं, ने राष्ट्रीय, प्रान्तीय और नगर प्राधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

घ. **कार्यक्रम के तहत लाभ -** इन कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध कराया गया अनुदान जीओसी द्वारा वित्तीय योगदान है जिसमें चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमियों को जीओसी द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है। प्रत्येक अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय योगदान प्राप्तकर्ता उद्यमी (कास्टिंग सहित) की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय योगदान को जीओसी से निधियों की प्राप्ति के कारण कास्टिंग के प्राप्तकर्ता विनिर्माताओं को लाभ प्रदत्त करने के लिए माना गया है।

ङ. **कार्यक्रम की विशिष्टता -** उद्यम निवेश अनुदान उन विशिष्ट उद्यमों को उपलब्ध कराई जाती है जिनके पास हाइटेक दर्जा है और उद्यम के अल्प अथवा मध्यम किस्म के स्वरूप में है। इस प्रकार के उद्यम भी किसी निर्दिष्ट हाइटेक जोन में स्थित है। इस प्रकार यह योजना भारतीय नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है।

च. **कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी -** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि अस्थायी प्रशासन उपाय-2005 में चोंगकिंग पीपल्स गवर्नमेंट ऑफिस तथा चीन बाजार विनियामक परिदृश्य-2013 में वेब अनुसंधान-उद्यम पूंजी निवेश के परिपत्र द्वारा कार्यक्रम का अस्तित्व है। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि यह योजना डब्ल्यूटीओ दस्तावेज जी/एससीएम/एन/267/सीएएन रिकार्ड किए अनुसार डब्ल्यूटीओ में अस्तित्व में सूचित किया गया है। यह योजना भी चीन के विरुद्ध अपने विकर्ष परिणामों में अन्य प्राधिकारियों द्वारा काउंटरवेलेबल रखी गयी है।

छ. **जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम -** यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में निधि के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय

किस्मों तक सीमित होने के कारण इस प्रकार प्राधिकारी पाते हैं कि यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने उन कास्टिंग उत्पादक/निर्यातक, जो उक्त लाभ के लिए पात्र हैं, की सूची प्रस्तुत की है। चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जैसे गमेसा विंड (तियानजिन) कं. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (तियानजिन) कं. लि., जेक्प्रो इंडस्ट्री सप्लाय संघाई कं. लि., हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट एसेसरी (तियानजिन) कं. लि., सातारेम चाइना लि., संघाई एसआईआईसी ईएंडए इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., स्त्रोवेल विंड ग्रुप कं. लि. जो बीजिंग, संघाई, तियानजिन और चोंगकिंग में स्थित हैं, अनुदान के लिए पात्र हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली ने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए वे संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सकें कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है सिवाय पुनः यह कहने के कि निर्दिष्ट योजना से प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

## 92. कार्यक्रम सं. 15 : विदेश निवेश सहित मुख्यालयों और क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान

क. **कार्यक्रम का सार :** घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम गोंगलू जैसे चीन के कतिपय प्रान्तों में स्थित एफआईई को लाभ प्रदान करने के लिए है। यह कार्यक्रम उन एफआईई के लिए विशिष्ट है जो गोंगलू में स्थित हैं। जीओसी ने विदेशी उद्यमों को चीन की भूमि में अपना मस्तिष्क लगाने के लिए आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम उन विदेशी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए उपलब्ध है जिनके मुख्यालय कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित हैं। मुख्यालय के रूप में अर्हक होने के लिए सभी प्रचालनों के अनिवार्यतः नियंत्रण की सुविधा होनी चाहिए और किसी उद्यम के प्रबंधन जिसने चीन और अंतर्राष्ट्रीय रूप में दोनों में निवेश किया है। क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में अर्हक होने के लिए सभी प्रचालनों के अनिवार्यतः नियंत्रण की सुविधा होनी चाहिए और चीन के किसी निश्चित क्षेत्र में किसी अथवा सभी उद्यमों द्वारा निवेश किया हुआ होना चाहिए। मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय निवेश कंपनियां, प्रबंधन कंपनियां, अनुसंधान और विकास केंद्र तथा उत्पादन उद्यम हो सकते हैं।

ख. **हितबद्ध पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की सरकारी अनुदान प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि तथाकथित अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। फिर भी यह नोट किया गया है कि सहयोग करने वाले निर्यातक उत्पादक गोंगलू शहर में स्थित नहीं है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया करने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएम ने याचिका में स्वयं निश्चयपूर्वक कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए अर्हक उत्पादों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। याचिका में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्यक्रम संबद्ध उत्पाद के निर्यातकों से संबंधित है। यह कार्यक्रम केवल गोंगलू जिले में स्थित उद्यमों के लिए उपलब्ध है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक गोंगलू जिले में स्थित हैं। इसलिए याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी -** यह कार्यक्रम प्रांतों के स्थानीय वाणिज्य प्राधिकारी, जो सार्वजनिक निकाय हैं, द्वारा चलाया जाता है और गोंगलू के स्थानीय वाणिज्य प्राधिकारी द्वारा प्रशासित है।

घ. **कार्यक्रम के तहत लाभ -** इन कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध कराया गया अनुदान जीओसी द्वारा वित्तीय योगदान है जिसमें चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमियों को जीओसी द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है। प्रत्येक अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय योगदान प्राप्तकर्ता उद्यमी (कास्टिंग सहित) की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय योगदान को जीओसी से निधियों की प्राप्ति के कारण कास्टिंग के प्राप्तकर्ता विनिर्माताओं को लाभ प्रदत्त करना माना गया है।

ङ. **कार्यक्रम की विशिष्टता -** निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुदान इन उद्यमों, जो विशिष्ट क्षेत्र में स्थित हैं और एफआईई स्वरूप के हैं, तक सीमित है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम निर्धारित एएससीएम और नियमावली की शर्तों के भीतर भी विशिष्ट है तथा इस कार्यक्रम के संबंधित प्रान्तीय कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा शासित निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में पंजीकृत कतिपय उद्यमों तक सीमित है।



च. **कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम का अस्तित्व मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने संबंधी गोंगछू नगर के प्रावधान जारी करने के बारे में गोंगछू नगर पीपल्स सरकार के सामान्य कार्यक्रम की सूचना (सं. 34 (2006) जो बाद में मुख्यालय अर्थव्यवस्था के विकास के नोटिस के लिए भेजे गए विचारों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए गोंगछू नगर पीपल्स सरकार से प्रतिस्थापित किया गया था (एसयूआई (2010) 2) तथा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने संबंधी गोंगछू के प्रावधान द्वारा स्थापित है।

छ. **जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में निधि के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण इस प्रकार प्राधिकारी पाते हैं कि यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जैसे जेक्प्रो इंडस्ट्री सप्लाय संघाई कं. लि. जो गोंगछू नगरपालिका में स्थित एक एफआईई है, अनुदान के लिए पात्र हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली ने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि यह एफआईई नहीं है।

अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए कोई भी संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सकें कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है सिवाय पुनः यह कहने के कि निर्दिष्ट योजना में से प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

### 93. कार्यक्रम सं. 16 : नवाचार लघु और मध्यम उद्यम अनुदान

क. **कार्यक्रम का सार** : घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आर एंड डी द्वारा मान्यता प्राप्त लघु फर्मों के लिए स्टार्ट-अप पूंजी में एसएमई को लाभ प्रदान करती है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह एसएमई तक सीमित है।

ख. **हितबद्ध पक्षों के विचार** - चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की सरकारी अनुदान प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। फिर भी यह नोट किया गया है कि सहयोग करने वाले निर्यातक उत्पादक गोंगछू शहर में स्थित नहीं है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इससे लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने याचिका में स्वयं निश्चयपूर्वक कहा है कि इस कार्यक्रम के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह कार्यक्रम केवल गोंगडोंग प्रान्त में स्थित उद्यमों के लिए उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि संबद्ध वस्तुओं की निर्यातक इकायां गोंगडोंग प्रान्त में स्थित हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में विशिष्टता प्रमाणित नहीं हुई है। याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी** – यह कार्यक्रम राष्ट्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय सरकार स्तरों पर चीन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रकार गोंगडोंग प्रान्त और निंगबो झिंहाई विकास एवं सुधार ब्यूरो जो एक सरकार निकाय है, इस कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

घ. **कार्यक्रम के तहत लाभ** – इन कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध कराया गया अनुदान जीओसी द्वारा वित्तीय योगदान है जिसमें चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमियों को जीओसी द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है। प्रत्येक अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय योगदान प्राप्तकर्ता उद्यमी (कास्टिंग सहित) की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय योगदान को जीओसी से निधियों की प्राप्ति के कारण कास्टिंग के प्राप्तकर्ता विनिर्माताओं को लाभ प्रदत्त करने के लिए माना गया है।

ङ. **कार्यक्रम की विशिष्टता** – निर्दिष्ट कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उन कतिपय उद्यमों तक सीमित है जो मुख्य रूप से लघु और मध्यम उद्यम हैं और उनके पास अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आर एंड डी केंद्र है।

च. **कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम का एसएमई संवर्धन संबंधी पीआरसी के कानून के अनुच्छेद 12, 13, 36, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकासशील निधि के प्रशासन के लिए उपाय, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकासशील निधि के प्रशासन के लिए उपायों के कार्यन्वयन हेतु विस्तृत नियम (01 जुलाई, 2001) लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकासशील निधियों के प्रशासन के लिए उपाय जारी करते हुए परिपत्र सहयोग (2010), विदेश व्यापार विकास निधि और प्रबंधन पहुँच, सीएआई क्यूआई (2014), एसएमई के विकास के लिए विशेष निधियों के प्रशासन संबंधी उपाय जारी करने संबंधी मंत्रालय और उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोटिस (वित्त मंत्रालय का संख्या 96(2012); एसएमई के विकास के लिए विशेष निधियां अंतरिम उपाय जारी करने संबंधी तथा उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (सीएआई क्यूआई (2014) सं. 38) तथा एसएमई के विकास के लिए विशेष निधियों के प्रबंधन संबंधी अंतरिम उपाय जारी करने संबंधी वित्त मंत्रालय (सीएआई जियान (2015) संख्या 458 द्वारा प्रमाणित है।

छ. **जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में निधि के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों में याचिकाकर्ता ने उन कास्टिंग उत्पादक/निर्यातक की सूची प्रस्तुत की है, जो उपरोक्त अनुदान के लिए पात्र है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का लिमिटेड इस प्रकार की अनुदान के लिए पात्र हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली ने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। अन्य सभी सहयोग नहीं करने वाले निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए कोई भी संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सकें कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है सिवाय पुनः यह कहने के कि निर्दिष्ट योजना में से प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

#### 94. **कार्यक्रम सं. 17 : निजी स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों के लिए अनुदान**

क. **कार्यक्रम का सार** : घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम यून्नान प्रान्त में स्थित गैर-एसओई को लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है इसलिए विशिष्ट प्रान्त में स्थित गैर-एसओई तक सीमित है। यह कार्यक्रम आयातित प्रौद्योगिकियों अथवा उपकरणों की निवेश लागत में कमी करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है।

ख. **हितबद्ध पक्षों के विचार** – चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की सरकारी अनुदान प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया करने वाली कंपनी इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएम ने याचिका में स्वयं निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम यून्नान प्रान्त में स्थित गैर-एसओई के लिए उपलब्ध है। तथापि, यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक यून्नान प्रान्त के हैं। इस कार्यक्रम के लिए जांच शुरू करके प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली के नियम 6, एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी** – यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का भाग है इसलिए यह कार्यक्रम एक सरकारी निकाय यून्नान प्रान्तीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

घ. **कार्यक्रम के तहत लाभ** – इन कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध कराया गया अनुदान जीओसी द्वारा वित्तीय योगदान है जिसमें चीन में प्राप्तकर्ता उद्यमियों को जीओसी द्वारा निधियों का सीधे अंतरण शामिल है। प्रत्येक अनुदान के स्वरूप के कारण यह माना गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय योगदान प्राप्तकर्ता उद्यमी (कास्टिंग सहित) की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा

निर्यात के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय योगदान को जीओसी से निधियों की प्राप्ति के कारण कास्टिंग के प्राप्तकर्ता विनिर्माताओं को लाभ प्रदत्त करने के लिए माना गया है।

- ड. **कार्यक्रम की विशिष्टता** – उक्त अनुदान विशिष्ट है। इसलिए यह उन कतिपय उद्यमों जो निजी स्वामित्व वाली हैं और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों (निर्यातानुमुखी) तक सीमित है।
- च. **कार्यक्रम की काउंटरवेलेबिलिटी** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम का अस्तित्व गैर-राज्य-स्वामित्व अर्थव्यवस्था, जो पात्र उद्यमियों की सूची बनाती है, के विकास को त्वरित करने संबंधी नोटिस द्वारा प्रमाणित है।
- छ. **जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन के भीतर जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में निधि के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमियों की कतिपय किस्मों तक सीमित होने के कारण इस प्रकार प्राधिकारी पाते हैं कि यह कार्यक्रम नियमावली के प्रयोजन से विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है। जांच के दौरान बाद के अनुरोधों ने उन कास्टिंग उत्पादक/निर्यातक की सूची भेजी है, जो उपरोक्त अनुदान के लिए पात्र है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली ने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि यह यूप्रान प्रान्त में स्थित नहीं है। किसी कास्टिंग विनिर्माता के अस्तित्व के बारे में घरेलू उद्योग सूचना चीन सरकार अथवा किसी अन्य हितबद्ध पत्र द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जीओसी को कानूनों, विनियमों अथवा नीति के लिए कोई भी संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जो यह प्रमाणित कर सकें कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं थे। जीओसी ने आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

#### अनुदान के लिए आर्थिक सहायता मार्जिन की गणना

95. क्रम सं. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 पर जांच की गई उपरोक्त अनुदानों के संबंध में आर्थिक सहायता की राशि की गणना संबंधित कंपनी द्वारा प्राप्त लाभों के आधार पर की जानी अपेक्षित है। प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने दावा किया है कि इसे सरकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कंपनी की वेबसाइट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कंपनी को अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान "प्रसिद्ध ब्रांड अवार्ड" "उत्कृष्ट नवाचार उद्यम" तथा "मानक नवाचार उद्यम" प्रमाण-पत्र के रूप में अनुदान और अवार्ड प्रदान किया गया था। प्रतिक्रिया करने वाली एकमात्र कंपनी को वेबसाइट और उनके द्वारा दायर प्रतिक्रिया में विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। तथापि, जियाली ने अपनी स्थिति दोहराई और वेबसाइट पर दिखाए गए प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। इसके अतिरिक्त, जीओसी ने उनकी सूचना और प्रतिक्रिया करने वाले निर्यात की सूचना की स्पॉट जांच करने के लिए प्राधिकारी को अनुमति नहीं दी। कंपनी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभों के संबंध में प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक को प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपूर्णता पत्र में कंपनी ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"झीजियांग जियाली टैक्नोलॉजी कं. लि. और झीजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजी कं. लि. अलग-अलग कंपनियां हैं, झीजियांग जियाली टैक्नोलॉजी कं. लि., झीजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजी कं. लि. की मूल कंपनी है और यह निर्माणाधीन उत्पाद की कच्ची सामग्री के उत्पादन, बिक्री अथवा अधिप्राप्ति में शामिल है।

झीजियांग जियाली टैक्नोलॉजी कं. लि. के कार्य जियाली विंड में निवेश है। जियाली विंड अपना कारोबार स्वयं प्रचालित करती है और स्वतंत्र रूप में निर्णय लेती है तथा मूल कंपनी जियाली विंड के कारोबार प्रचालनों में कोई नियंत्रण नहीं करती।

हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहेंगे कि उपरोक्त सम्मान मूल कंपनी झीजियांग जियाली टैक्नोलॉजी कं. लि., जो इस जांच के अध्यधीन नहीं है, को दिया गया है।"

(क) झीजियांग प्रान्त के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो, झीजियांग प्रान्त के वित्त ब्यूरो, झीजियांग प्रान्त के राज्य कराधान ब्यूरो और झीजियांग प्रान्त के स्थानीय कराधान ब्यूरो द्वारा दिसंबर, 2008 में जियाली विंड को एक महत्वपूर्ण हाइटेक उद्यम के रूप में मान्यता दी गई थी, मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे कोई लाभ नहीं दिया गया था।

(ख) पेट्रोलियम स्पेशल पम्प, पेट्रोलियम कैमिकल उपकरण के उत्पाद पर झीजियांग जियाली टैक्नोलॉजी कं. लि. के प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई थी, मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे कोई लाभ नहीं दिया गया था।

(ग) जियाली विंड की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एसोसिएशन तथा झीजियांग विज्ञान प्रेस द्वारा सितंबर, 2008 में झीजियांग प्रान्त के उत्कृष्ट नवाचार उद्यम के रूप में मान्यता दी गई थी, मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे कोई लाभ नहीं दिया गया था।

- (घ) झीजियांग जियाली टैकनोलॉजी कं. लि. को झीजियांग प्रान्त के गुणता एवं तकनीकी ब्यूरो द्वारा दिसंबर, 2012 में "मानक नवाचार उद्यम" के रूप में मान्यता दी गई थी, मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे कोई लाभ नहीं दिया गया था।
- (ङ) झीजियांग जियाली टैकनोलॉजी कं. लि. को निम्नलिखित सरकारी कंपनियों द्वारा नवंबर, 2008 में "झीजियांग प्रान्त नवाचार पायलट उद्यम" के रूप में मान्यता दी गई थी: झीजियांग प्रान्त का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो, झीजियांग आर्थिक एवं व्यापार समिति, झीजियांग प्रान्त वित्त ब्यूरो, झीजियांग प्रान्त राज्य स्वामित्व परिसंपत्ति पर्यवेक्षण तथा प्रशासन आयोग, झीजियांग प्रान्त की सरकार का कार्यसमूह कार्यालय, झीजियांग प्रान्त गुणता एवं तकनीकी ब्यूरो, झीजियांग प्रान्त ट्रेड यूनियन; मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे कोई लाभ नहीं दिया गया था।

प्रकटीकरण के उपरांत जियाली ने यह अनुरोध किया है कि xxx की दो बार गणना की गई है और इस प्रकार से कुल xxx की राशि सही नहीं है। आर एम बी xzxx की राशि की "सरकारी सब्सिडी" ऐसी कुल राशि थी जिसमें वस्तु सं. 18 के माध्यम से वस्तु सं. 2 से सूचीबद्ध सभी वस्तुएं शामिल हैं जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मूल कंपनी को प्राप्त लाभ जियाली विंड के लिए लागू नहीं होंगे क्योंकि वे दो अलग अलग कंपनियां हैं और मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं है। मूल कंपनी को प्राप्त कोई भी आर्थिक सहायता विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है इसलिए यह जियाली विंड को प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि जियाली विंड ने अनुरोध किया है, यहां तक कि यदि प्राधिकारी कार्यक्रम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 के लाभों की गणना करना चाहता है तो इसमें कार्यक्रम 8 से 17 के पैकेज के लिए 5.89 % की गणना करने की बजाय वह कथित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए लाभ की गणना करें।

मूल कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल कंपनी को सरकार से विभिन्न शीर्षों के तहत अनुदान के रूप में विभिन्न वित्तीय लाभ प्राप्त हुए हैं। मूल कंपनी द्वारा प्राप्त कुल राशि \*\*\*आरएमबी है। इस प्रकार जियाली विंड द्वारा प्राप्त लाभ संबद्ध वस्तुओं के आबंटन योग्य \*\*\* आरएमबी है। चूंकि विभिन्न अनुदानों के तहत लाभ विशिष्ट बाजार तक सीमित नहीं हैं और उद्यम की किस्म तक सीमित हैं प्राप्त आर्थिक सहायता की राशि को सभी बाजारों में कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री से विभाजित किया गया है। तदनुसार, उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता की राशि जियाली के लिए 1.99% निर्धारित की गई है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत सूचना उपलब्ध नहीं होने और चीन के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक द्वारा वर्तमान जांच में प्राधिकारी को कोई सहयोग नहीं किए जाने के कारण प्राधिकारी इसे संभवतः यह मानते हैं कि असहयोगी निर्यातक इन कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं, इन कार्यक्रमों की पहुंच है और इसलिए इन कार्यक्रमों के तहत वित्तीय योगदान प्राप्त किया।

जीओसी ने चीन में कास्टिंग के 200 से अधिक उत्पादक चिन्हित किए हैं। याचिकाकर्ता ने यह साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि अन्य कास्टिंग उत्पादकों में से कुछ इस लाभ के लिए पात्र थे। चीन में कास्टिंग के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से किसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने 1.99% की दर पर अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सीवीडी मार्जिन निर्धारित किया है जो प्रतिक्रिया करने वाले एकमात्र निर्यातक के लिए निर्धारित है।

## इक्विटी कार्यक्रम

### 96. कार्यक्रम संख्या 18 : इक्विटी प्रदान करना

**क. कार्यक्रम का सार –** जीओसी ने साम्या अंतः प्रवाह के जरिए उद्यमों को नकदी की पर्याप्त राशि पिछले वर्षों में उपलब्ध कराई है। जीओसी ने (विभिन्न राज्य स्वामित्व कंपनियों के जरिए) अतिरिक्त शेयरधारक आधार प्राप्त किए बगैर उन कंपनियों में शेयर अधिगृहीत किए हैं जिनमें यह पहले से ही प्रमुख शेयरधारक था। जीओसी को मूल एवं अनुपूरक प्रश्नावलियों में इन कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था परंतु जीओसी द्वारा कोई संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इन साम्या अंतः प्रवाहों को नियमावली के प्रयोजन के भीतर प्राप्तकर्ता कंपनियों को लाभ प्रदत्त करने के लिए विचार किया गया है। इस प्रकार के अंतः प्रवाह निजी निवेशकों की निवेश प्रक्रियाओं के लिए असाधारण माने गए हैं। एसओई ने नए शेयर के अपने हिस्से के अधिक मूल्य की कीमत का भुगतान किया है जो निष्पक्ष बाजार परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है और इसने जुटाए गए धन का प्रयोग राज्य स्वामित्व परिसंपत्तियां और सामान्य निवेश बाजार से कम कीमतों पर खरीदने के लिए किया था। इसके शेयर कम मूल्य के होने के बावजूद जीओसी ने अन्य निवेशकों को उसी कीमत पर भुगतान किया क्योंकि अन्य शेयरधारकों को शेयर बेचने के अलावा उन्हें विभिन्न अधिकार और संभावना थी।

**ख. हितबद्ध पक्षों के विचार –** चीन सरकार ने प्रतिक्रिया की है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की सरकारी अनुदान प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कास्टिंग उत्पादकों को इस तरह की अनुदान से लाभ हुआ है। इस प्रकार एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसरण में अन्यो के लिए उस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है कि निर्दिष्ट अनुदान का अस्तित्व, राशि और स्वरूप विधिवत रूप से

प्रमाणित नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी का.लि. ने कहा है कि इसने कभी भी आवेदन, उपयोग नहीं किया अथवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हुआ।

आईडब्ल्यूटीएमए ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यह सुझाव देने के लिए याचिका में कोई साक्ष्य नहीं है कि सीआईसीसी और एसएसएससी एक सार्वजनिक निकाय हैं और चीन सरकार की ओर से काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल इस्पात उत्पादकों से संबंधित है और यह सुझाव देने के लिए याचिका में कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्यक्रम सामान्यतः और विशेष रूप से कास्टिंग उत्पादकों के लिए लागू है। 'पास थ्रू' लाभ प्रमाणित नहीं होने के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि लाभ साम्या अंतःप्रवाह के जरिए कास्टिंग उत्पादकों के लिए प्रोद्भूत हुए हैं। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए जांच शुरू करके सीवीडी नियमावली के नियम 6 और एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अभाव में एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

**ग. प्रशासी प्राधिकारी** – साम्या अंतःप्रवाह एक एसओई से संबंधित है, जहां चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कारपोरेशन लिमिटेड (सीआईसीसी) ने शेयर जारी करने के एक प्रमुख अंडरराइटर और प्रबंधक के रूप में काम किया है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि सीआईसीसी 51% राज्य स्वामित्व है और यह अंततः स्टेट आन्ड एस्सेट्स सुपरविजन एंड एडमिनिश्ट्रेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल (एस ए एस ए सी) द्वारा नियंत्रित है और एसओसी को नियंत्रित करने वाली जीओसी कंपनी के रूप में भी काम किया है। एस ए एस ए सी एक निवेशक के रूप में राज्य के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है और अपने सुपरविजन में राज्य स्वामित्व की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। राज्य काउंसिल द्वारा प्राधिकृत एस ए एस ए सी पर्यवेक्षित उद्यमों के उच्च कार्यपालकों की नियुक्ति करता है और हटाता है तथा कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए उनके निष्पादन का मूल्यांकन करता है। यह निर्देशक सिद्धांत और नीतियों के लिए उपक्रमों का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है और इस पर उद्यमियों की राज्य स्वामित्व की परिसंपत्तियों के मूलभूत प्रबंधन का दायित्व भी है तथा कानून के अनुसार स्थानीय राज्य स्वामित्व की परिसंपत्तियों के प्रबंधन कार्य के संबंध में निर्देश देता है और पर्यवेक्षण करता है। एस ए एस ए सी एसओई के प्रबंधकों के पारिश्रमिक और मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह एसओई प्रबंधकों की नियुक्ति करता है तथा पुरस्कृत करने और दंड देने के संबंध में निर्णय लेता है। एसओई प्रबंधकों का कैरियर एस ए एस ए सी पर निर्भर करता है। ये परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि एस ए एस ए सी के पास स्पष्ट रूप से सरकारी प्राधिकारी की शक्तियां हैं। एसओई के बोर्ड का गठन एसओई के जीओसी द्वारा नियंत्रण के उच्च स्तर को भी दर्शाता है। निदेशक मंडल के कई सदस्य और सुपरवाइजरों बोर्ड में विगत सरकारों और/अथवा पार्टी कार्यों में रखे गए थे अथवा हैं और उनका चयन एस ए एस ए सी अथवा कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीसीपी) जैसे सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रभावित होता है इसलिए ये कारोबार नियमावली तथा संगत डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र के प्रयोजन के भीतर सार्वजनिक निकायों के जरिए जीओसी द्वारा किए गए थे।

**घ. कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ** – साम्या अंतःप्रवाह नियमावली के प्रयोजन के भीतर निधियों के सीधे अंतरण का हिस्सा है। ये वित्तीय योगदान चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कारपोरेशन लिमिटेड (सीआईसीसी) तथा एस ए एस ए सी सहित इन कारोबारों में शामिल सार्वजनिक निकायों के जरिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

**ड. कार्यक्रम की विशेषता** – ये आर्थिक सहायता विशिष्ट है क्योंकि ये सीमित संख्या में चयनित उन कंपनियों को उपलब्ध कराए गए थे जिनमें सरकार भागीदार थी। इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह कार्यक्रम संबंधित उत्पाद के निर्यात करने वाले उत्पादकों के लिए काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है।

**च. क्या यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल है** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि जीओसी उद्यमों में शेयरधारक है और उतनी ही कीमत का भुगतान किया है जितनी अन्य निवेशकों को की गई थी। सरकारी निधि के सीधे अंतरण के लिए यह राशि कतिपय उद्यमों के लिए है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

**छ. जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – प्राधिकारी मानते हैं कि योजना काउंटरवेलेबल है क्योंकि साम्या प्रवाह के रूप में उन कतिपय उद्यमों को लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां सीआईसीसी है और शेयर जारी करने का प्रबंध करता है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि सीआईसीसी 51% राज्य स्वामित्व है और अंततः एस ए एस ए सी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो एससीएम तथा नियमावली के प्रयोजन के भीतर एक सार्वजनिक निकाय है।

**ज. आर्थिक सहायता की राशि की गणना:** सूचना नहीं होने के कारण प्रतिसंतुलनकारी आर्थिक सहायता की राशि की गणना प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ की दृष्टि से नहीं की जा सकती। प्रतिक्रिया करने वाले एकमात्र निर्यातक द्वारा भेजी गई जानकारी यह नहीं दर्शाती कि उन्होंने इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता तथा साथ ही इच्छुक पक्षकारों द्वारा कोई अन्य सूचना प्रदान न करने के कारण प्राधिकारी ने अन्य गैर प्रतिवादी निर्यातकों को प्राप्त लाभों की मात्रा नहीं दी है। .

## 97. कार्यक्रम 19 : अप्रदत्त लाभांश

**क. कार्यक्रम संबंधी सार :** चीन सरकार की नीति के अनुसार सरकारी उद्यमों को सरकार को तब भी उनके स्वामी के रूप में लाभांश नहीं देना होता है जब वे लाभ कमाएं। फलस्वरूप सरकारी उद्यम इस कार्यक्रम के अनुसार लाभांश के रूप में वितरित न किए गए लाभ को रखकर भारी निवेश वित्तपोषित कर पाते हैं।

**ख. इच्छुक पक्षकारों के विचार :** चीन सरकार ने उत्तर दिया है कि यह दर्शाने वाली याचिका में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि चीनी ढलाई उत्पादकों ने ऐसा कोई सरकारी अनुदान प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता ये दर्शाते हुए कोई साक्ष्य नहीं दे पाया कि ढलाई उत्पादकों को इन अनुदानों से लाभ मिला है। इस प्रकार एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार अन्य के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वे इस सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर दें कि कथित अनुदानों की मौजूदगी, धनराशि और प्रकृति को विधिवत रूप से महत्व नहीं दिया गया है। किसी भी स्थिति में उत्तरदायी कंपनी ने इस जांच में सहयोग किया है और इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं उठाया है।

उत्तरदायी चीन ढलाई उत्पादक जेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कं. लि. ने कहा है कि जियाली विंड एक निजी स्वामित्व वाली लिमिटेड उत्तरदायी कंपनी है। जियाली विंड ने इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं लिया।

आई डब्ल्यू टी एम ए ने विरोध जताया कि यह दर्शाने के लिए याचिका में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि यह कार्यक्रम ढलाई उत्पादकों पर लागू है। यह बताने के लिए भी याचिका में कोई साक्ष्य नहीं है कि सी आई सी सी और एस ए एस ए सी सरकारी निकाय है तथा चीन सरकार की ओर से काम कर रहे हैं। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए जांच शुरू करके एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3, सी वी डी नियमावली के नियम 6 का उल्लंघन किया है। इस कार्यक्रम के लिए जांच, याचिका में दिए गए साक्ष्य के अभाव में एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार समाप्त की जानी चाहिए।

**ग. प्रशासक प्राधिकारी :** चीन ने एस ए एस ए सी के रूप में ज्ञात निकाय राज्य परिषद द्वारा प्राधिकृत हैं वह पर्यवेक्षित उद्यमों के शीर्ष कार्यपालकों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करता है और कानूनी प्रक्रिया से उनके निष्पादन का मूल्यांकन करता है। एस ए एस ए सी पर्यवेक्षित उद्यमों से मार्गदर्शी सिद्धांतों और नीतियों का पालन करने के लिए कहने हेतु उत्तरदायी है और वह उद्यमों की सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के मौलिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है तथा कानून के अनुसार स्थानीय सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन कार्य में निर्देश देती है तथा उनका पर्यवेक्षण करती है। ऐसे एस ए सी, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के प्रबंधकों की परिलब्धियों और मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के प्रबंधकों की नियुक्ति भी करती है तथा पुरस्कार एवं दंड के संबंध में निर्णय भी देती है। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों (एस ओ ई) के प्रबंधकों का कैरियर एस ए एस ए सी पर निर्भर करता है। यह परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि एस ए एस ए सी स्पष्ट रूप से सरकारी प्राधिकार में निहित हैं। एस ओ ई के बोर्डों का गठन भी एस ओ ई के जीओसी द्वारा उच्च स्तरीय नियंत्रण दर्शाता है। कई निदेशक बोर्डों और पर्यवेक्षक बोर्डों के सदस्य पिछली सरकार और/अथवा पार्टी कार्यों में नियंत्रण रखते हैं अथवा रखते थे और यह कि उनका चयन एस ए एस ए सी जैसे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सशक्त रूप से प्रभावित होता है।

**घ. कार्यक्रम के तहत लाभ :** अप्रदत्त लाभांश में नियमों के अभिप्राय के भीतर निधियों का सीधा अंतरण है। ये वित्तीय अंशदान सरकार द्वारा सीआईसीसी और एस ए एस ए सी सहित इन लेन-देनों में शामिल सरकारी निकायों के माध्यम से दिया जाते थे।

**ड. सब्सिडी कार्यक्रम का स्वरूप एवं क्या सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट है :** ये सब्सिडी अधिनियम और नियमों के तहत विशिष्ट हैं क्योंकि वे कुछ सीमित संख्या में चुनी गई कंपनियों को दी जाती थीं जिनमें सरकार भाग लेती थी। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह कार्यक्रम संबंधित उत्पाद के निर्यातक उत्पादकों के लिए समतुल्य सब्सिडी बनाता है।

**च. व्यावहारिक कार्यान्वयन (कार्यक्रम कैसे प्रचालित होता है):** अप्रदत्त लाभांश एस सी एम और नियमों के अभिप्राय में अप्रसन्नता में अनुदान के रूप में माना जाना चाहिए। चीन सरकार वह लाभांश नहीं लेती है जो निवेशकों को उनके शेयरों पर सामान्य रूप से दी जाती है। ये छद्म लाभांश एस ओ ई इस्पात उत्पादकों में सिद्धांत रूप में एस ए सी में सीधे ही शेयरधारक कंपनी के माध्यम से सरकार द्वारा दिए जाते थे।

**छ. क्या ये कार्यक्रम बराबरी वाला है:** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा बताया गया है, चीन सरकार ने उद्यमों में लाभांश लगाया जो कुछ उद्यमों को सरकारी फंड का सीधा अंतरण है और उसे छद्म रूप में अनुदान माना जा सकता है।

**ज. जांचों के परिणाम और निष्कर्ष :** चूंकि चीन सरकार एस ओ ई द्वारा लाभांश वितरण संबंधी कोई सूचना प्रदान करने में विफल रही अतः इस कार्यक्रम संबंधी ये निष्कर्ष याचिका में निहित सूचना के आधार पर तथा उसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर हैं जोकि पर्याप्त स्रोतों से समर्थित हैं। अप्रदत्त लाभांश को छद्म अनुदान अथवा इस रूप में भूले गए राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए कि चीन सरकार वह लाभांश एकत्रित नहीं करती है जो सामान्य रूप से उनके शेयरों पर निजी निवेशकों को दिया जाता है। ये छद्म अनुदान सरकार द्वारा ढलाई उत्पादकों में सीधे ही शेयरधारक कंपनी के माध्यम से दिए जाते थे। एस ए एस ए सी से संबंधित विश्लेषण यह दर्शाता है कि वह सरकारी कार्य निष्पादित करता है।

**झ. सब्सिडी राशि का परिकलन:** बराबर वाली सब्सिडी की राशि प्राप्तकर्ताओं को दिए गए लाभ के संदर्भ में परिकलित की जाती है जो जांच अवधि के दौरान मौजूद पाई जाती है। प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ अप्रदत्त लाभांश की राशि के रूप में मानी जाती है। इस लाभ के मूल्यांकन के लिए सूचना के अभाव में प्राधिकारी इस योजना के तहत दिए गए लाभ की मात्रा

का पता नहीं लगा पाया। पूर्णतः उत्तरदायी निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से प्राधिकारी यह पाते हैं कि सरकार उत्तरदायी निर्यातक कंपनी में शेयरधारक नहीं है और इसीलिए उसे इस योजना से लाभ नहीं हुआ है। एकमात्र उत्तरदायी निर्यातक द्वारा दी गई सूचना यह नहीं दर्शाती है कि उन्होंने इस योजना के तहत कोई लाभ लिया है। याचिकाकर्ता तथा साथ ही इच्छुक पक्षकारों द्वारा कोई अन्य सूचना प्रदान न करने के कारण प्राधिकारी ने अन्य गैर प्रतिवादी निर्यातकों को प्राप्त लाभों की मात्रा नहीं दी है।

### **अधिमान्य ऋण**

#### **98. कार्यक्रम सं. 20 : ढलाई उद्योगों को अधिमान्य ऋण तथा ब्याज दर**

**क. कार्यक्रम के संबंध में सार :** घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया कि संबंधित उत्पाद के चीनी उत्पादकों को वायु विद्युत क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास के समर्थन तथा प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चीन सरकार की नीति के अनुसरण में सरकारी नीति के बैंकों और सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों (एस ओ सी बी) से कम ब्याज दरों पर ऋण से लाभ मिलता है। जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं और औद्योगिक नीति में उल्लेख किया गया है, नवीकरणीय क्षेत्र तथा इस्पात क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली द्वारा तरजीही वित्तीय पहलें स्वीकृत की जाती हैं। यह कार्यक्रम उद्योग के विस्तार में सहायता एवं विकास करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों से कम (सब्सिडी वाले) ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर ढलाई उत्पादकों को लाभ प्रदान करता है। चीन सरकार चीन में स्थापित कई प्रमुख बैंकों में प्रमुख शेयरधारक है और इसीलिए इसकी बैंकों में पहुंच है।

**ख. हितबद्ध पक्षकारों के विचार :** चीन सरकार ने कहा है कि यह स्पष्ट करने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि :

“चीन के वाणिज्यिक बैंकिंग कानून के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि वाणिज्यिक बैंक सुरक्षा, परिसमाप्ति और दक्षता के सिद्धांतों को अपनाएंगे। वाणिज्यिक बैंक कानून के अनुसार अपने व्यापार प्रचालनों के संबंध में अपना निर्णय लेते हैं और इसमें किसी कंपनी अथवा किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होती है।”

चीन सरकार ने सरकारी संरचना में सुधार लाने और वाणिज्यिक बैंकों की प्रबंध क्षमता के जोखिम को बढ़ाने के लिए 2003 से वाणिज्यिक बैंकों के सुधार के लिए भारी प्रयास किए हैं। पी बी ओ सी वाणिज्यिक बैंकों के ऋण व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पुनर्गठन के बाद प्रमुख एस ओ सी आर और प्राइवेट बैंक अब सरकारी तौर पर सूचीबद्ध कंपनियां हैं जो बाजार सिद्धांतों पर पूर्णतः प्रचालन कर रही हैं। किसी उद्योग विशिष्ट क्षेत्र के अनुसार तैयार की गई और लागू की गई कोई विशिष्ट उधारदाता नीति नहीं है।

उत्तरदायी चीनी ढलाई उत्पादक जेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लि0 ने कहा है कि उसने कभी भी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया और उससे लाभ नहीं उठाया।

आई डब्ल्यू टी एम ए ने कहा है कि यह कार्यक्रम केवल इस्पात उत्पादकों से संबंधित है और यह कहने के लिए याचिका में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्यक्रम सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से ढलाई उत्पादकों पर लागू है। यह आरोप लगाया गया है कि बैंकों की उधार देने की परिपाटियां, जो चीन सरकार के स्वामित्व में हैं, योगदान करती हैं। इस प्रकार ऋण के प्रावधान नियमों के अभिप्राय के अंतर्गत सरकार से निधियों के सीधे अंतरण के फलस्वरूप है। यह नोट किया जाता है कि वित्तीय योगदान वहां नहीं हो सकता जहां बैंक और यहां तक कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंक उत्पादकों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। यह दर्शाए जाने की आवश्यकता है कि सरकारी ऋण का प्रावधान वाणिज्यिक ऋण की तुलना में लाभदायक है, जिसे कंपनी बाजार से प्राप्त करेगी जैसा कि एस सी एम करार के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। चीन के भीतर अथवा चीन के बाहर ऐसी कोई बाजार तुलना नहीं की गई है जिससे यह दर्शाया जाए कि उद्यमों की उधार देने की परिपाटियों से सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा उद्यमों को लाभ दिया जाता है।

केवल यह कहने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि निजी बैंकों को चीन ने तरजीही उधार देने की परिपाटियां अपनाने के लिए सरकार द्वारा सौंपा एवं निर्देशित किया जाता है। यह तथ्य चीन से बाहर तुलनीय वाणिज्यिक ऋण की तुलना करके लाभ निर्धारित करने के भार से याचिका का बचाव नहीं करता। किसी भी स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को चीन के वाणिज्यिक बैंकिंग कानून के अनुच्छेद-4 के संदर्भ में अपने वाणिज्यिक प्रचालनों के संबंध में सरकारी नीतियों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

**ग. प्रशासक प्राधिकारी :** इस कार्यक्रम का रख रखाव चीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय सरकारी स्तरों, सी आई सी सी और एस ए एस ए सी जोकि सरकारी निकाय है, के स्तर पर किया जाता है। एन डी आर सी राज्य परिषद समन्वय सूक्ष्म आर्थिक नीति की एक एजेंसी है और वह सरकारी निवेशों का प्रबंधन कर रही है।

**घ. कार्यक्रम के तहत लाभ:** चीन में सामान्यतः सरकारी ऋण बाजार से वास्तव में प्राप्त किए जा सकने वाले ऋणों की अपेक्षा अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रदान किए जाते हैं। चीनी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप दर्शाते हैं और वे दरें नहीं बताते जोकि कार्यकारी बाजार में पाए जाते हैं।

**ड. सामान्य दर क्या है और तरजीही दर क्या है.....** कुछ सूचना जिसके संबंध में यह निष्कर्ष दिया गया है, उसका आधार बताया जाना चाहिए।

च. **कार्यक्रम की विशिष्टता:** चीन सरकार से कहा गया था कि वे इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए और सब्सिडी के प्रयोग के संबंध में पात्रता मानदंड संबंधी सूचना प्रदान करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सब्सिडी किस सीमा तक कतिपय उद्यमों को दी जानी है तथा क्या यह विशिष्ट है। चीन सरकार ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

छ. **कार्यक्रम की प्रतिकारकता :** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा बताया गया है, इस कार्यक्रम की मौजूदगी यिनफा (2003) सं. 2050 तथा यिनफा (2004) सं. 251 द्वारा स्थापित है; विदेशी निवेश उद्योगों के मार्गदर्शन के लिए सूची (2011 में संशोधित); वाणिज्यिक बैंकिंग कानून के अनुच्छेद 34 एवं 38 (2003); एन डी आर सी आदेश सं. 35-लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए नीतियां, सरकारी औद्योगिक नीतियों को पूरा करने के संबंध में वाणिज्यिक बैंक अधिनियम संबंधी कानून के निर्णय 40 तथा अनुच्छेद 24, 25, 34।

घरेलू उद्योग ने यह बात भी रखी कि चीन सरकार ने इस योजना की मौजूदगी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में सूचित की है, जैसा कि डब्ल्यू टी ओ व्यापार नीति समीक्षा रिपोर्ट डब्ल्यू टी/ टी पी आर/ एस/300 में रिकॉर्ड किया गया है; दस्तावेज डब्ल्यू टी/ टीपीआर/ एस/ 264, जुलाई, 2012; 2006; चीन के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दुत्से बैंक का अनुसंधान; चीन के बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में दुत्से बैंक अनुसंधान, 2006 से ली गई सूचना, पृष्ठ 3-4; चीन के पीपुल्स बैंक के मौद्रिक नीति विश्लेषण समूहों की 2010 की मौद्रिक रिपोर्ट तिमाही-2 से ली गई सूचना, 5 अगस्त, 2010 पृष्ठ 10; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति कार्यकारी दस्तावेज, "चीन के बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में प्रगति: क्या बैंक व्यवहार बदला है ? ", डब्ल्यू पी/06/71, मार्च, 2006 (पृष्ठ 3-4, 13, 18-20 देखें); अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि कार्यकारी दस्तावेज, "चीन में ब्याज दर उदारीकरण", डब्ल्यूपी/09/171, अगस्त, 2009, (पृष्ठ 3-4, 21-23 देखें); अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि देश की रिपोर्ट, पी आर सी: 2010 अनुच्छेद IV परामर्श, सं. 10/238, जुलाई, 2010, (पृष्ठ 22, 24 और 28-29 देखें); ओ ई सी डी 2010 चीन का आर्थिक सर्वेक्षण, फरवरी, 2010, (अध्याय-3, पृष्ठ-71, 73-81, 97 देखें); ओ ई सी डी चीन के वित्तीय क्षेत्र के सुधार, आर्थिक विभाग कार्यकारी दस्तावेज सं. 747, इको/डब्ल्यू के पी (2010) 3, 1 फरवरी, 2010, (पृष्ठ 2, 8-15, 36 देखें); इस्पात उद्योग (2009) के लिए समायोजन एवं पुनरुद्धार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत नियमों में प्रमुख उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि हेतु प्रावधान हैं। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, अन्य जांच प्राधिकारियों ने चीन के विरुद्ध अपने निष्कर्षों में इस स्कीम को भी प्रतिकारक माना है।

ज. **जांचों के परिणाम एवं निष्कर्ष :** कुल साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातक को भारी मात्रा में ऋण इस नीति अथवा उन अन्य सरकारी बैंकों द्वारा दिए जाते हैं जो सरकार के साथ उनके बहुत निकट संबंधों के कारण पब्लिक निकाय माने जाते हैं। घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए दावे के अनुसार वे 50 प्रतिशत से भी अधिक सरकार के स्वामित्व वाले हैं और इस प्रकार सरकार द्वारा नियंत्रित माने जाते हैं। ये बैंक प्रभावी रूप से सरकारी प्राधिकार का प्रयोग करते हैं क्योंकि चीनी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज दरों के संबंध में जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार सरकार द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप होता है (अर्थात् पी बी ओ सी) जबकि कुछ मामलों में कंपनियां अर्ध स्वायत्त होती हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कम से कम संभव दर पर ऋण देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में इन कंपनियों की उधार देने की परिपाटियां सीधे ही सरकार के दायित्व में आती हैं। एक बहुत बड़ा परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी है जो कि अध्ययनों और रिपोर्टों से सिद्ध होता है कि चीनी वित्तीय प्रणाली में अब भी सरकार का भारी हस्तक्षेप विद्यमान है। चीन सूचना देने में विफल रहा जिससे सरकार के साथ सरकारी बैंकों के संबंधों के बारे में एक अच्छी समझ बन पाती। इस प्रकार नीति अथवा अन्य सरकारी बैंकों द्वारा ऋण के मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय नियमों के अभिप्राय से सरकार से निधियों के सीधे अंतरण के रूप में ढलाई उत्पादकों को वित्तीय अंशदान है।

अन्य गैर-सहकारी निर्यातकों के लिए न तो चीन सरकार और न ही अलग-अलग निर्यातकों द्वारा खुद इस संबंध में सूचना दी गई कि क्या लाभ इस कार्यक्रम के तहत इन निर्यातकों को दिए गए। चीन सरकार से कहा गया कि वे उस साक्ष्य के संबंध में कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा नीति में किसी संशोधन के बारे में बताएं कि ये कार्यक्रम वर्तमान जांचों से संगत नहीं थे। चीन सरकार ने यह दोहराने के सिवाय और कोई सूचना नहीं दी कि उत्तरदायी निर्यातक ने कथित योजना से कोई लाभ नहीं लिया है।

झ. **सब्सिडी राज्य का परिकलन :** प्रतिकारक सब्सिडी की राशि प्राप्तकर्ताओं को दिए गए लाभ के संदर्भ में परिकलित की जाती है, जो जांच की अवधि के दौरान मौजूद पाई गई है। प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ बैंकों से लिए गए ऋण पर कंपनी द्वारा दी गई राशि और बाजार से प्राप्य तुलनीय वाणिज्यिक ऋण के लिए कंपनी द्वारा दी गई राशि के बीच अंतर को माना जाता है। चूंकि चीनी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप दर्शाते हैं अतः उन दरों को नहीं दर्शाते जो कार्यकारी बाजार में पाए जाते।

चीन सरकार और सहकारी निर्यातक उत्पादकों, दोनों से अनुरोध किया गया था कि वे चीनी बैंकों की उधार देने की नीतियों के संबंध में और निर्यातक उत्पादकों को दिए गए ऋणों के तरीके के संबंध में सूचना प्रदान करें। चीन सरकार तथा उत्तरदायी निर्यातक यह सूचना देने में विफल रहे, यद्यपि, उनसे ऐसा करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है। तदनुसार, इस दृष्टि से सहयोग का अभाव और कुल उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए प्राधिकारी ने यह माना कि चीन में ऋणों के लिए सामान्य ब्याज दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष है। जियाली ने अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणी में परिसंपत्तियों की बुक वेल्यू और बंधक की गई परिसंपत्तियों की प्रतिशतता को क्रमशः ऋण राशि और ब्याज की दर के रूप में विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके द्वारा अर्जित किए गए ऋणों पर \*\*\* % से \*\*\* % के बीच ब्याज की दर से यह प्रदर्शित होता है कि योजना के तहत जियाली को कोई भी लाभ नहीं मिला था। याचिकाकर्ता और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा कोई अन्य सूचना प्रदान न किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ने उत्तर न देने वाले अन्य निर्यातकों के अर्जित लाभ की मात्रा तय नहीं की।



**अधिमार्ग आयकर कार्यक्रम और कर प्रोत्साहन**

99. **कार्यक्रम सं. 25 :** एफ आई ई और उन विदेशी उद्यमों के लिए तरजीही कर नीतियां जिनकी स्थापना/स्थान चीन में हैं, और जो उत्पादन में लगे हैं अथवा घरेलू तौर पर उत्पादक उपस्करों की खरीद कर व्यापार प्रचालन कर रहे हैं।

क. **कार्यक्रम के संबंध में सार:** जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा बताया गया है, यदि ये उद्यम अपने विनिर्माण प्रचालनों को चीन निर्मित उपस्करों से उन्नत करते हैं तो चीन सरकार ऐसे एफ आई ई और विदेशी उद्यमों को अधिमार्ग आयकर नीतियों की पेशकश करती है। विशेष रूप से ऐसे एफ आई ई और विदेशी उद्यमों को, जो चीन सरकार की औद्योगिक नीतियों के समरूप प्रौद्योगिकी का उन्नयन करते हैं, वे अपने अगले वर्ष के आयकर दायित्व से उपस्करों की लागत का 40 प्रतिशत घटा सकते हैं और उन परिस्थितियों में जब आयकर मशीनरी की लागत के 40 प्रतिशत से कम हो, तो शेष लागत 5 वर्ष तक की अवधि के लिए आगे के वर्षों में घटाई जा सकती है। एक एफ आई ई की श्रेणी में रखने के लिए किसी उद्यम को एक चीनी-विदेशी इक्विटी वाला संयुक्त उद्यम, चीनी-विदेशी सहकारी संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण रूप से विदेशी स्वामित्व वाला उद्यम होना चाहिए जोकि एफ आई ई आयकर कानून के अनुच्छेद 8 के तहत चीन में स्थापित हो।

ख. **हितबद्ध पक्षकारों के विचार :** चीन सरकार ने कहा कि यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 1999 को कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम में 2008 के नए उद्यम आयकर कानून द्वारा रद्द कर दिया गया था। चूंकि ये योजना 2008 के नए उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 57 के तहत तरजीही कर व्यवहार के किसी प्रकार से संबंधित नहीं था, अतः कोई छूट अवधि प्रदान नहीं की गई थी। इस कार्यक्रम के पीछे सरकार की नीति विदेशी निवेश आकर्षित करना और प्रौद्योगिकी नवीनीकरण को सहायता देना था। किसी भी स्थिति में इस जांच में सहयोग करने वाली उत्तरदायी कंपनी को इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं मिला।

उत्तरदायी चीनी ढलाई उत्पादक झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लि0 ने कहा है कि उसने एफ आई ई के रूप में इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

आई डब्ल्यू टी एम ए ने विरोधस्वरूप कहा कि इस कार्यक्रम को 2008 के नए उद्यम आयकर कानून द्वारा रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम के शीर्षक के सिवाय उपर्युक्त कार्यक्रम के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। कानूनी व्याख्या पर जोर न देकर यह सूचना एस सी एम करार के अनुच्छेद 11.2 के संदर्भ में "पर्याप्त साक्ष्य" के रूप में मानी जा सकती है। साथ ही कार्यक्रम सं. 26 केवल एफ आई ई पर लागू होता है। यह दर्शाने के लिए याचिका में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि नियातक का उद्यम एफ आई ई है। इस कार्यक्रम के तहत कोई विशिष्टता सिद्ध नहीं की गई है।

ग. **प्रशासक प्राधिकारी :** इस कार्यक्रम का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), सरकारी कर प्रशासन (एस ए टी), वाणिज्य मंत्रालय (एम ओ एफ सी ओ एम), जो ए एस सी एम और अधिनियम एवं नियमों के अभिप्राय से एक सरकारी निकाय है। यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका संचालन सरकारी कर प्रशासन (एस ए टी) तथा उसके स्थानीय शाखा कार्यालयों अथवा ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

घ. **इस कार्यक्रम के तहत लाभ:** इस कार्यक्रम के तहत उन एफ आई ई को कर की बचत करने के रूप में विदेशी निवेश वाले उद्यमों को लाभ प्रदान किया जाता है। एफ आई ई कर कानून के तहत विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से चीन में यह एक सबसे बड़ा सामान्य प्रोत्साहन है। इस कार्यक्रम से उन एफ आई ई को लाभ दिया जाता है जो चीन निर्मित उपस्करों में निवेश करते हैं जिनकी परियोजनाएं विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक दिशानिर्देश की सूची की वी श्रेणियों में प्रतिबंधित अथवा प्रोत्साहित के रूप में वर्गीकृत हैं।

ड. **कार्यक्रम की विशिष्टता :** यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत लाभ केवल एफ आई ई तक सीमित है। चूंकि इस कार्यक्रम के तहत लाभ किसी खास प्रकृति के उद्यमों की कतिपय किस्मों तक सीमित हैं अतः यह कार्यक्रम नियमों के अभिप्राय से विशिष्ट है। चीन में अन्य कंपनियों (डी आई ई अथवा घरेलू निवेशित उद्यम होने के नाते)। इस सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, केवल उत्पादन सापेक्ष एफ आई ई सब्सिडी के लिए पात्र हैं (अर्थात् जो एफ आई ई उत्पादन सापेक्ष नहीं हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं)। दूसरी ओर, इस कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन एफ आई ई को उपलब्ध है जो उत्पादन अथवा व्यापार प्रचालनों में लगे होने के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और जो घरेलू रूप से उत्पादित उपस्करों की खरीद कर रहे हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह एफ आई ई के लिए सीमित है और यह आयातित सामानों के ऊपर घरेलू सामान के प्रयोग की ओर उन्मुख है।

च. **कार्यक्रम की प्रतिकारकता :** जैसा कि घरेलू उद्योग ने कहा है, इस कार्यक्रम की मौजूदगी आयातकरण के गैर-कर-छूट योग्य वस्तुओं की सूची; घरेलू रूप से उत्पादित उपस्करों की खरीद पर एफ आई ई के लिए आय कर क्रेडिट; कर लगाने के लिए अंतरिम उपाय दर्शाने संबंधी कर निर्धारण संबंधी सरकार का परिपत्र; विदेशी निवेश उद्योगों के मार्गदर्शन के लिए सूची और (2011 में संशोधित); आयातित उपस्करों की कर नीतियों के समायोजन संबंधी राज्य परिषद का परिपत्र [जी यू ओ एफ ए (1997) सं. 37]; प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपस्करों और मशीनरी से संबंधित आयात स्तर कर नीतियों के समायोजन के संबंध में नोटिस [कायगुयांशू (2014) सं.2] में स्थापित है।

यह भी पाया गया है कि यह योजना विश्व व्यापार संगठन में होने की सूचना है जैसा कि डब्ल्यू टी ओ दस्तावेज जी/एस सी एम/ एन/123 सी एच एन.डीओसी; जी/एससीएम/एन/155/सीएचएन.डीओसी तथा जी/एससीएम/एन 186/सीएचएन.डीओसी; जी/एससीएम/ एन/267/सीएचएन; में रिकॉर्ड किया गया है। यह योजना चीन जनवादी गणराज्य से कतिपय गेल्बनाइज्ड स्टील वायर के संबंध में अंतिम जांच परिणाम में कनाडियन प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारक भी मानी गई है।

**छ.** **जांचों के अंतिम परिणाम तथा निष्कर्ष:** इस कार्यक्रम में नियमों के अभिप्राय से चीन सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कुछ किस्म के व्यापार उद्यमों तक सीमित होने के नाते यह कार्यक्रम नियमों के अभिप्राय से सब्सिडी-विशिष्ट है। इस कार्यक्रम में प्रतिकारक सब्सिडी है। जांच के दौरान बाद में बताए गए अनुसार याचिकाकर्ता ने ढलाई उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत किए हैं जो एफ आई ई की प्रकृति में आते हैं।

इस कार्यक्रम की प्रकृति के कारण (इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्रियाकलापों से यह आय (लाभ) प्राप्त होते हैं, आयकर पर सामान्य छूट), यह माना जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय अंशदान प्राप्तकर्ता उद्यम के सभी सामानों के निर्यात अथवा उत्पादन अथवा विनिर्माण के संबंध में दिया जाएगा।

चीनी ढलाई उत्पादक, यथा-हाइड्रा ग्रेने हाइड्रोलिक्स इक्विपमेंट ऐससरी (तियांनजिन) कंपनी लि० और जैक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कंपनी लिमिटेड, एनटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियांनजिन) कं. लि. और सिनोवेल विंड ग्रुप कं. लि., तियातन विंड एनर्जी (सुझोऊ) कं. लि., निंगो विंग वो हिंग मशीनरी इंडस्ट्री कं. लि., जियांगशू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि., दलियान हुआरू हैवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कं. लि. आदि इस लाभ के लिए पात्र हैं।

**ज.** **सब्सिडी की राशि का परिकलन :** प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी की राशि प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए लाभ के संदर्भ में परिकलित की गई है जो जांच अवधि के दौरान मौजूद पाई गई है। प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए लाभ को बचाए गए कुल कर की राशि के रूप में माना गया है। चूंकि लाभ कंपनी द्वारा निर्यात को ध्यान में न रखकर उपलब्ध है, अतः सी वी डी मार्जिन कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

उत्तरदायी निर्यातक ने दावा किया है कि उसे इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं हुआ है। कमी संबंधी पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2015 में उठाए गए पश्नों के उत्तर में उत्तरदायी निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि :

*"जांच अवधि के दौरान जियाली विंड को एक उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी कंपनी माना गया था। जियाली विंड पर लागू आयकर दर 15 प्रतिशत है। तथापि, जियाली विंड को निम्नलिखित कारणों से इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।*

*प्रथमतः उद्यम आयकर उस समय दिया जाना चाहिए जब उसे कोई लाभ हो। परंतु यदि कोई कंपनी घाटे में प्रचालित हो रही हो तो उसे आयकर देने की आवश्यकता नहीं होती। चीनी उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 18 (1 जनवरी, 2008 को पभावी) में यह प्रावधान है कि "किसी कर वर्ष के दौरान किसी उद्यम को हुए घाटों को आगे ले जाया जा सकता है और 5 वर्षों की अधिकतम अग्रणीत अवधि के लिए बाद के वर्षों के दौरान इन आय में से घटाया जा सकता है।"*

*द्वितीयतः, जियाली विंड को वित्तीय वर्ष 2012 में (आर एम बी \*\*\*) की राशि में भारी नुकसान हुआ है..... जबकि वित्तीय वर्ष 2013 में कुल लाभ (आरएमबी 4,661,188.33) का हुआ है। उपर्युक्त कार्यक्रम 32 के अनुसार, उसकी कर योग्य आय से अनुसंधान एवं विकास के खर्चों को घटाने के लिए आवेदन की गई कुल राशि (आर एम बी \*\*\*) है.....।*

*चूंकि जियाली विंड को कर वर्ष 2012 में घाटा हुआ है, अतः कर वर्ष 2013 में हुए लाभ को 2012 के घाटे के लिए प्रयुक्त करने की अनुमति है। उपर्युक्त कार्यक्रम 32 के अनुसार, यहां तक कि यदि स्थानीय कर निर्धारण ब्यूरो अनुसंधान एवं विकास के खर्चों को घटाने के लिए जियाली विंड के आवेदन को अनुमोदित नहीं करता तो भी इसकी कर वर्ष 2013 में कर योग्य आय नकारात्मक थी। परिणामस्वरूप जियाली विंड को 2013 में उद्यम आयकर देने की आवश्यकता नहीं थी। अतः जियाली विंड ने जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं किया।*

*जियाली विंड को दिसंबर, 2008 में जियांग प्रोविंस के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो, जियांग प्रोविंस के वित्त ब्यूरो, जियांग प्रोविंस के राज्य कर निर्धारण ब्यूरो और जियांग प्रोविंस से स्थानीय कर निर्धारण ब्यूरो द्वारा "प्रमुख उच्च प्रौद्योगिकी उद्यम" के रूप में मान्यता दी गई थी। परंतु मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कोई लाभ नहीं दिया गया।"*

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियाली इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है और इसीलिए इस योजना के तहत उन्हें लाभ नहीं दिया गया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विंड पावर उपस्कर क्षेत्र में प्रचालन करने वाले बहुत से एफ आई ई हैं जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस योजना के तहत लाभ केवल विचाराधीन उत्पाद तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कंपनी के कुल लाभों पर उपलब्ध है, जबकि एक बार कंपनी यह दावा करने लायक हो जाए कि वह कार्यक्रम के तहत लाभ लेने की हकदार है। प्राधिकारी ने लाभों की गणना जियाली विंड के तुलन पत्र के सार में उपलब्ध सूचना के आधार पर की है। चूंकि कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए उत्तर न देने वाले अन्य निर्यातकों के लिए जियाली विंड के लिए परिकलित आंकड़ों को ही अपनाया गया है। तदनुसार उत्तर न देने वाले निर्यातकों के कारोबार के 2.13 % के अनुसार सब्सिडी मार्जिन का आकलन किया गया है।

**100. कार्यक्रम सं. 28 अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां।**

**क.** **कार्यक्रम के संबंध में सार :** घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया कि यह योजना उन सभी कंपनियों को लाभ प्रदान करती है जो आर एंड डी परियोजनाएं चलाने के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इस योग्यता से अनुमति मिल जाती है कि कॉर्पोरेट आयकर अनुमोदित

परियोजनाओं के लिए वास्तविक खर्चों का 50 प्रतिशत घट जाता है। इस कार्यक्रम का अनुरक्षण चीन सरकार के स्थानीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम वहां कार्पोरेट आय में 50 प्रतिशत तक कटौती उन उद्यमों को लाभ के रूप में प्रदान करता है जहां वे कंपनियां राज्य से प्राथमिक सहायता प्राप्त कर रही हैं और उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिकीकरण की मार्गदर्शिका में सूचीबद्ध उनकी परियोजना उक्त लाभ लेने के लिए पात्र हैं। चीन सरकार उच्च एवं नए प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में लगे व्यापारिक उद्यम के रूप में कुछ कंपनियों को मान्यता देती है। इस स्कीम से उन कंपनियों को लाभ का प्रावधान है, जो अपने उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादों और नई तकनीकों की शुरुआत करते हैं। पात्र कंपनियां अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वास्तविक खर्चों का 50 प्रतिशत तक अपना कार्पोरेट आयकर कम कर सकते हैं।

**ख. हितबद्ध पक्षकारों के विचार :** चीन सरकार ने स्वीकार किया कि यह योजना अब तक लागू है और इस योजना में परिवर्तन किए जाने का कोई अनुमान नहीं है। चीन सरकार ने फिर भी कहा कि यह योजना प्रतिकारक नहीं है क्योंकि इस योजना को कनाडियन प्राधिकारी सी बी एस ए द्वारा गैर-कार्वाई योग्य माना गया है। उत्तरदायी चीनी ढलाई उत्पादक झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लि. ने लाभ के लिए आवेदन किया है परंतु जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त नहीं किया। उत्तरदायी निर्यातक ने उल्लेख किया है कि पात्रता मानदंड राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग तथा अन्य विभागों द्वारा प्रख्यापित किए गए अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए चालू प्राथमिकताओं हेतु दिशा-निर्देश (2007) तथा राज्य की प्रमुख सहायता के तहत उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निर्धारित परियोजना के अनुसंधान और विकास में लगे संस्थानों के लिए हैं। इस कार्यक्रम की पात्रता अथवा वास्तविक प्रयोग निर्यात निष्पादन, निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित आयातित सामान के घरेलू उपयोग, अथवा किसी उद्यम अथवा उद्यमों के समूह विशिष्ट अथवा किसी उद्योग अथवा उद्योगों के समूह तक आकस्मिक नहीं है।

आई डब्ल्यू टी एम ए ने कहा है कि 1 जनवरी, 2008 को रद्द कार्यक्रम भी एस सी एम करार के अनुच्छेद 8 क अनुसार गैर-कार्वाई योग्य सब्सिडी की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी निहित है। गैर-कार्वाई योग्य सब्सिडी के लिए छूटा सा प्रावधान मौजूद है तथा सी वी डी नियमावली के नियम 11 के साथ पठित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(3) में लागू है। यह कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास के संबंध में सहायता के लिए है।

**ग. प्रशासक प्राधिकारी :** इस कार्यक्रम का अनुरक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ एस टी), चीन सरकार द्वारा किया जाता है। एम ओ एस टी चीन सरकार का विभाग/निकाय है और उन कंपनियों को लाभ देने के लिए उत्तरदायी है और जो विभिन्न प्रांतों में स्थापित स्थानीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चलाते हैं। एम ओ एस टी चीन की केन्द्र सरकार का एक प्रभाग है। चीन सरकार का एक अंग होने के नाते एम ओ एस टी ए एस सी एम और अधिनियम एवं नियमावली के अभिप्राय से एक सार्वजनिक निकाय है।

**घ. कार्यक्रम के तहत लाभ :** इस कार्यक्रम से उन उद्यमों को कर की बचत के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। चीन सरकार ने बताया है कि एफ आई ई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए कर छूट के कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के बीच मौलिक अंतर है। एफ आई ई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए कर छूट कार्यक्रम से संबंधित कानूनी दस्तावेज राज्य कर निर्धारण प्रशासन हैं। इस परिपत्र के अनुच्छेद-1 के अनुसार पात्रता मानदंड यह था कि जिन विदेशी निवेश उद्यमों का शुल्क पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत (10 प्रतिशत सहित) से अधिक तक बढ़ जाए, उन्हें उसी वर्ष के लिए कर योग्य आय के लिए प्रौद्योगिकी विकास शुल्क के लिए प्रयुक्त वास्तविक राशि के 50 प्रतिशत तक की छूट जांच पर और कर निर्धारण प्राधिकारियों के अनुमोदन पर अनुमति दी गई थी।

**ड. सब्सिडी कार्यक्रम की प्रकृति तथा क्या सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट है -** इस कार्यक्रम के तहत लाभ विशिष्ट हैं क्योंकि प्रदान करने वाला प्राधिकारी प्रोत्साहित उद्यम के रूप में वर्गीकृत कतिपय उद्यमों और उद्योगों तक ही इस योजना की पहुंच सीमित करता है। यह लाभ केवल उन उद्यमों तक सीमित है जो उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यमों के रूप में निर्दिष्ट/मान्यता प्राप्त हैं और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चला रहे हैं। राज्य से नई एवं उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र वाली जो कंपनियां प्राथमिक सहायता प्राप्त कर रही हैं, उनकी अनुसंधान एवं परियोजनाओं को ही तथा जो परियोजनाएं राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग द्वारा प्रख्यापित वर्तमान विकास प्राथमिकता के तहत उच्च प्रौद्योगिकीकरण के प्रमुख क्षेत्र की मार्गदर्शिका में सूचीबद्ध हैं तथा जिन्हें चीन सरकार द्वारा उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम का स्तर प्रदान किया गया है, वे ही इस योजना के लिए पात्र हैं। चूंकि इस कार्यक्रम के तहत लाभ कतिपय किस्म के उद्यमों तक ही सीमित हैं, अतः ये कार्यक्रम नियमावली के अभिप्राय से विशिष्ट हैं।

**च. कार्यक्रम की प्रतिकारकता :** घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए अनुसार, उपर्युक्त कार्यक्रम की मौजूदगी पी आर सी के उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद-30(1) के अनुसार, पी आर सी के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियम के अनुच्छेद-95, पीआरसी की स्टेट काउंसिल के डिक्री नं. 512, 6 दिसंबर, 2007 में प्रख्यापित और प्रमुख क्षेत्रों (अधिसूचना सं. 6, 2007) की मार्गदर्शिका के अनुसार है। प्रमुख क्षेत्रों (अधिसूचना सं. 6, 2007 की मार्गदर्शिका); चीन के कर निर्धारण राज्य प्रशासन (एस ए टी) जो सुपर डिडक्शन के लिए पात्र आर एंड डी खर्चों के क्षेत्र को उल्लिखित करने वाला गुआस्वीफा (2008) सं. 116 (परिपत्र 116) द्वारा जारी, जिसके फलस्वरूप व्यवहार में उन आर एंड डी संबंधी कुछ वे खर्चे अलग किए गए जो अत्यधिक कटौती के प्रयोजन के लिए पात्र आर एंड डी खर्चों के रूप में परिपत्र 116 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए थे; 29 सितंबर, 2013 को चीन के वित्त मंत्रालय और एस ए टी ने कार्ड्सुई (2013) 70 (परिपत्र 70) जारी किया। जिसमें परिपत्र 116 में उल्लिखित आर एंड डी खर्चों की मूल श्रेणियों में वृद्धि तथा स्पष्टीकरण दिए गए। परिपत्र-70 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद हुए आर एंड डी खर्चों के लिए पूर्व तारीख से प्रभावी है। अन्य जांच प्राधिकारियों ने भी चीन के विरुद्ध अपने जांच परिणामों में इस योजना को प्रतिकारक माना है।

छ. **जांचों के अंतिम परिणाम तथा निष्कर्ष:** इस कार्यक्रम में नियमों के अभिप्राय से चीन सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कुछ किस्म के व्यापार उद्यमों तक सीमित होने के नाते यह कार्यक्रम नियमों के अभिप्राय से सब्सिडी-विशिष्ट है। इस कार्यक्रम में प्रतिकारक सब्सिडी है। चीन सरकार ने स्वीकार किया है कि कथित कार्यक्रम अभी भी मौजूद है। जिसे आई डब्ल्यू टी एम ए ने 2008 में रद्द किया हुआ गलत बताया है। चीन सरकार ने एफ आई ई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए कर छूट के साथ कथित योजना की तुलना की है और कहा है कि "सी बी एस ए ने पी आर सी के कॉरपोरेट आयकर कानून और उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियम की जांच की और फिर सहमत हुआ कि अनुसंधान एवं विकास खर्चों के लिए कर छूट विशिष्ट नहीं है। जबकि यहां प्राधिकारी "अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियों" की जांच कर रहा है। ए एस सी एम के अनुच्छेद-8 में कहा गया है कि:

*"अनुच्छेद 8- गैर कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता को अभिचिन्हित करना*

**8.2 भाग III और V के प्रावधान होते हुए निम्नलिखित आर्थिक सहायता गैर-कार्रवाई योग्य होगी:**

(क) यदि सहायता औद्योगिक अनुसंधान की लागत के 75% अथवा प्रतिस्पर्द्धा से पहले विकास कार्यकलापों की लागत के 55% से अधिक नहीं हो और बशर्ते कि इस प्रकार की सहायता केवल निम्नलिखित तक सीमित है, फर्म के साथ सविदा आधार पर फर्मों अथवा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान स्थापनाओं द्वारा किए गए अनुसंधानों के लिए सहायता:

(i) कार्मिकों की लागत (केवल अनुसंधान कार्यकलापों में नियुक्त अनुसंधानकर्ता, तकनीशियन तथा अन्य सहायक स्टाफ);

(ii) सिर्फ अनुसंधान कार्यकलापों और स्थायी रूप से प्रयोग किए जा रहे इंस्ट्रुमेंटों, उपकरण, भूमि एवं भवनों की लागत (वाणिज्यिक आधार पर निपटाए जाने की स्थिति को छोड़कर);

(iii) बोट-इन रिसर्च, तकनीकी जानकारी, पेटेंट आदि सहित केवल अनुसंधान कार्यकलाप के लिए प्रयोग की गई परामर्शी और समकक्ष सेवाओं की लागत;

(iv) अनुसंधान कार्यकलापों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुई अतिरिक्त उपरी अतिरिक्त लागत;

(v) अनुसंधान कार्यकलापों के परिणामस्वरूप सीधे खर्च हुई अन्य चालू लागतें (सामग्री आपूर्ति और इसी प्रकार की)।

(ख) क्षेत्रीय विकास 31 तथा गैर विशिष्ट (अनुच्छेद 2 के प्रयोजन के भीतर) के सामान्य ढांचे के अनुसरण में बशर्ते पात्र क्षेत्रों के भीतर किसी निर्दिष्ट सदस्य के क्षेत्र के भीतर गैर लाभ क्षेत्रों को सहायता:

(i) प्रत्येक गैर लाभ प्राप्त क्षेत्र परिभाषा करने योग्य आर्थिक और प्रशासनिक पहचान सहित निर्दिष्ट निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्र में अवश्य स्पष्ट किया जाए;

(ii) क्षेत्र को यह उल्लेख करते हुए कि क्षेत्र की कठिनाइयां अस्थायी परिस्थितियों में से अधिक उत्पन्न हुई हैं, न्यूट्रल और उद्देश्य मानदण्डों के आधार पर गैर-लाभ माना गया है, इस प्रकार के मानदण्डों को कानून, विनियम अथवा अन्य सरकारी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि जांच की जा सके;

(iii) मानदण्डों में आर्थिक विकास के मापन शामिल हैं जो निम्नलिखित कारकों में से कम से कम एक कारक पर आधारित होगा:

- प्रतिव्यक्ति आय अथवा घरेलू प्रतिव्यक्ति आय अथवा प्रतिव्यक्ति जीडीपी में से एक जो संबंधित क्षेत्र के लिए औसत के 85% से अधिक नहीं होना चाहिए;

- बेरोजगारी दर तीन वर्ष की अवधि के लिए मापे अनुसार संबंधित क्षेत्र के लिए औसत का कम से कम 110 % होनी चाहिए इस प्रकार का मापन तथापि मिश्रित होनी चाहिए और इसमें अन्य कारक शामिल होने चाहिए।

(c) कानून और/अथवा विनियमों द्वारा लगाई गई नई पर्यावरणात्मक अपेक्षाओं के लिए विद्यमान सुविधाएं 33 को अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता जिसके फलस्वरूप फर्मों के लिए अधिक कठिनाइयां और वित्तीय बोझ होगा, बशर्ते कि सहायता:

(i) एकवारगी गैर आवर्ती उपाय है; तथा

(ii) अपनाने के लागत के 20% तक सीमित है; तथा

(iii) सहायता किए गए निवेश को प्रतिस्थापित करने और प्रचालित करने की लागत को पूरा नहीं करती जो फर्मों द्वारा पूरी तरह से अवश्य वहन की जाएगी; तथा

(iv) बाधा और प्रदूषण के लिए फर्म की नियोजित कमी हेतु प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और आनुपातिक है और कोई विनिर्माण लागत जो हासिल की जा सकती है, शामिल नहीं होती; तथा

(v) उन सभी फर्मों के लिए उपलब्ध है जो नए उपक्रम और/अथवा उत्पादन प्रक्रियाएं अपना सकती हैं”

भारतीय सीवीडी नियमावली का नियम 11 उल्लेख करता है कि:

नियम 11- आर्थिक सहायता का स्वरूप। (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी आर्थिक सहायता निर्धारित करते समय यह पता लगाएगा कि जांचाधीन आर्थिक सहायता कितनी है:

(ग) जब तक कि इस प्रकार की आर्थिक सहायता वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन अथवा निर्यात में लगे व्यक्तियों की सीमित संख्या के लिए निम्नलिखित हेतु प्रदत्त की गई है

(i) विनिर्माण, उत्पादन अथवा निर्यात में लगे व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए अनुसंधान कार्यकलाप; अथवा

स्पष्टीकरण (1) खंड (ग) के उपखंड (i) के प्रयोजन से 'अनुसंधान कार्यकलापों के लिए आर्थिक सहायता' से अभिप्राय यदि सहायता औद्योगिक अनुसंधान की लागत के 75% अथवा प्रतिस्पर्द्धा से पहले विकास कार्यकलापों की लागत के 55% से अधिक नहीं हो और बशर्ते कि इस प्रकार की सहायता केवल निम्नलिखित तक सीमित है वाणिज्यिक संगठनों के साथ संविदा आधार पर वाणिज्यिक संगठनों द्वारा अथवा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान स्थापनाओं द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यकलापों के लिए सहायता से है:

(i) एकवारगी गैर आवर्ती उपाय है; तथा

(ii) अपनाने के लागत के 20% तक सीमित है; तथा

(iii) सहायता किए गए निवेश को प्रतिस्थापित करने और प्रचालित करने की लागत को पूरा नहीं करती जो फर्मों द्वारा पूरी तरह से अवश्य वहन की जाएगी; तथा

(iv) बाधा और प्रदूषण के लिए फर्म की नियोजित कमी हेतु प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और आनुपातिक है और कोई विनिर्माण लागत जो हासिल की जा सकती है, शामिल नहीं होती; तथा

(v) उन सभी फर्मों के लिए उपलब्ध है जो नए उपक्रम और/अथवा उत्पादन प्रक्रियाएं अपना सकती हैं”

प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झीजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजी का. लि. ने लाभ के लिए आवेदन किया है। यहां तक कि अन्य चाइनीज उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए हैं। अन्य प्रतिक्रिया नहीं करने वाले चाइनीज कास्टिंग उत्पादक जैसे गमेसा विंड (तिआंजिन) का. लि., एंटेक ब्रेकिंग सिस्टम (तिआंजिन) का. लि., डालिआन हुआरुई हेवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल का. लि., जेक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय संधाई का. लि., जियांगसू जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी का. लि., जियांगिन फेंगडियान फ्लेंग मैनुफैक्चर का. लि., जियांगिन हेंगुन रिंग फोरगिरिंग का. लि., किंगदाओ रिचौन प्रिकिसन मशीनरी का. लि. सतरेम चाइना लि. शंगडोंग लाइवू जिलेई विंड-पावर टैक्नोलॉजी का. लि., संधाई सिक ई एंड ए इंटरनेशनल ट्रेड का. लि., सिनोवेल विंड ग्रुप का. लि. और झुझोउ टाइम्स न्यू मेटेरियल टैक्नोलॉजी का. लि. ने भी निर्दिष्ट कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया है।

जियाली ने अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में यह कहा है कि मूल कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ जियाली विंड के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वे दो अलग अलग कंपनियां हैं और मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं है। जियाली विंड द्वारा प्रदान किए गए मूल उत्तरों का एक्जिबिट 17 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जियाली विंडकी कर योग्य आय नकारात्मक थी और यह लाभ के लिए पात्र नहीं था क्योंकि कानून में यह प्रावधान है कि उद्यम वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय से वर्तमान वर्ष में वास्तव में किए गए अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय का 50 % सीधे ही काट सकता है जैसा कि उद्यम के आर एंड डी व्यय की पूर्व कर कटौती के लिए प्रशासनिक उपाय जारी करने के संबंध में एस ए टी के नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट है। तथापि प्राधिकारी ने यह नोट

किया है कि जियाली विंड को हुई हानि और आर एंड डी व्यय की कटौती के लाभ अगले वर्षों के लिए अग्रेषित की जा सकती है। इसे देखते हुए जियाली विंड ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ अर्जित किया है।

सहयोग नहीं करने वाले अन्य सभी निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानून, विनियम अथवा नीति का कोई संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था कि ये कार्यक्रम चालू जांच से संबंधित नहीं थे। जीओसी ने निर्दिष्ट योजना से प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातकों द्वारा कोई लाभ नहीं किए जाने की बात को दोहराने के अलावा आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

**ज. आर्थिक सहायता की राशि की गणना-** कारउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता की राशि की गणना प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ जोकि पीओआई के दौरान विद्यमान पाया गया है, के अनुसार की गई है। प्राप्तकर्ताओं को इस कार्यक्रम के तहत सामान्य कर दर और कम हुए देय कर को मानते हुए लाभ प्रदत्त किया गया है। चूंकि लाभ निर्यात निष्पादन पर निर्भर नहीं है और कंपनी द्वारा विनिर्मित, उत्पादित, निर्यातित अथवा दुलाई की गई मात्रा की दृष्टि से दिया गया था। इसलिए सीवीडी मार्जिन पीओआई के दौरान सहयोग करने वाले निर्यातक उत्पादकों के कुल विक्री कारोबार की तुलना में आबंटित किया गया है।

प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने दावा किया है कि इसने कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद में वित्तीय हानि उठा रहा था। तथापि यह नोट किया गया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ अकेले विचाराधीन उत्पाद तक सीमित नहीं है। कंपनी द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होने का दावा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात कंपनी के कुल लाभ पर कार्यक्रम के तहत लाभ उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि जियाली विंड द्वारा प्रदत्त सूचना यह दर्शाती है कि उसने वर्ष 2013 में \*\*\* आरएमबी अनुसंधान एवं विकास व्यय किया था और तदनुसार जियाली के लिए लागू कर दर पर आर एंड डी का 50 प्रतिशत लाभ \*\*\* आरएमबी है। कंपनी का कारोबार \*\*\* आरएमबी मानते हुए इस याचना के लिए प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक के लिए आर्थिक सहायता मार्जिन 0.25 % निर्धारित किया गया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त संगत सूचना के अभाव में और वर्तमान जांच में प्राधिकारी के साथ चीन के किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने से प्राधिकारी यह मानते हैं कि संभवतः गैर-सहयोगी निर्यातक इस कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं और इन कार्यक्रमों की पहुंच है और इसलिए इन कार्यक्रमों के तहत वित्तीय योगदान प्राप्त किया है।

यह माना गया है कि संबद्ध वस्तुओं के इन निर्यातकों के सभी उत्पादों के संबंध में यह वित्तीय योगदान किया गया है। जीओसी ने चीन में 200 से अधिक कास्टिंग उत्पादक अभिचिन्हित किए हैं। चीन में कास्टिंग के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से कोई सूचना नहीं मिलने के कारण प्राधिकारी के अन्य उत्पादक/निर्यातकों के लिए भी 0.32% सीवीडी मार्जिन निर्धारित किया है।

**101. कार्यक्रम सं. 31 : उन कंपनियों जिन्हें उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है, के लिए अधिमानतः कर नीतियां**

क. **कार्यक्रम का सार** – घरेलू उद्योग ने निश्चयपूर्वक कहा है कि जीओसी एक कार्यक्रम चलाता है जिसमें उच्च और नई प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को अधिमानतः/रियायती आयकर की अनुमति है। जीओसी उच्च और नई प्रौद्योगिकी के उत्पादन में लगे कारोबार उद्यमों के रूप में कतिपय कंपनियों को मान्यता देती है। इन कंपनियों को 25% की सामान्य दर की तुलना में 15% की घटी दर पर आयकर का भुगतान करने की अनुमति है। संबद्ध वस्तुओं के चाइनीज उत्पादक/निर्यातक इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए हैं।

ख. **हितबद्ध पक्षों के विचार** - चीन सरकार ने स्वीकार किया है कि यह योजना अब तक लागू है और इस योजना में कोई परिवर्तन प्रत्याशित नहीं है। तथापि जीओसी ने तर्क दिया है कि यह योजना कारउंटरवेलेबल नहीं है क्योंकि यह योजना एएससीएम के प्रयोजन के भीतर विशिष्ट नहीं है। प्रतिक्रिया करने वाली चाइनीज कास्टिंग उत्पादक झिजियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजी का. लि. ने लाभ के लिए आवेदन किया है परंतु जांच की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त नहीं किया। आईडब्ल्यूटीएमए ने तर्क देते हुए यह सुझाव क्या संबद्ध उत्पाद के निर्यातक 'उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यमों' की श्रेणी में है, कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा भी कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है कि 25% की साधारण दर की तुलना में 15% की घटी हुई आयकर दर से लाभ के लिए उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यम के प्रमाण-पत्र के लिए निर्यातक उद्यम ने आवेदन किया है।

ग. **प्रशासी प्राधिकारी-** यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी) द्वारा चलाया जा रहा है। एमओएसटी चीन सरकार का एक विभाग निकाय है और विभिन्न प्रान्तों में स्थापित स्थानीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्यूरो के जरिए उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी है। एमओएसटी चीन की केंद्र सरकार के विंगों में से एक विंग है।

**चीन का एक सरकारी संगठन होने के कारण एमओएसटी एससीएम और अधिनियम तथा नियमावली के प्रायोजन के भीतर एक सरकारी निकाय है।**

- घ. **कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ** – इस कार्यक्रम को शासित करने वाला कानून जीओसी द्वारा वित्तीय योगदान को अधिदेशित करता है जिसमें चीन में पात्र उद्यमों द्वारा जीओसी को दत्त राजस्व (आयकर) पूर्वनिर्दिष्ट अथवा गैर-संग्रहण शामिल है। यह कार्यक्रम उन उद्यमों जिन्होंने उच्च और नई प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, के लिए कर बचत के रूप में उद्यमों को लाभ प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के स्वरूप के कारण (इस बात का ध्यान रखे बिना कि कार्यकलाप क्या आय (लाभ) सृजित करते हैं, आयकर पर सामान्य छूट) यह माना गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय योगदान प्राप्तकर्ता उद्यमों की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात के संबंध में किया जाएगा।
- ङ. **कार्यक्रम की विशिष्टता**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ केवल उन उद्यमों तक सीमित है जो उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यमों के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं। मान्यता दी गई है और जिन्होंने जीओसी द्वारा उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम का दर्जा दिया गया है। चूंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उद्यमों की कतिपय श्रेणियों तक सीमित है। इसलिए यह कार्यक्रम नियमावली के प्रायोजन के भीतर विशिष्ट है।
- च. **कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता** – जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपाय तथा उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम के उद्यम आयकर भुगतान से संबंधित मुद्दों पर कराधान के राज्य प्रशासन की सूचना [गुओ शुई हान [2008] सं. 985], परिपत्र जीयूओ शुई फा. सं. 2003 की 135 और सर्कुलर कशुई (2014) सं. 59 एवं 65 सहित उद्यम आयकर [16 मार्च, 2007 को प्रख्यापित सं. 63] एसएटी संबंधी पीआरसी कानून के अनुच्छेद 28 के अनुसार उक्त कार्यक्रम का अस्तित्व है। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि जीओसी ने डब्ल्यूटीओ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रिपोर्ट, डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/300; जी/एससीएम/क्यू2/सीएचएन/29 में रिकार्ड किए अनुसार डब्ल्यूटीओ ने इस योजना का अस्तित्व रिपोर्ट किया है। इसके अतिरिक्त चाइना इंडस्ट्रियल सब्सिडी स्टडी-2007 ने भी चीन में इस काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता कार्यक्रम का अस्तित्व रिपोर्ट किया है। चीन के विरुद्ध अपने विकर्ष परिणामों में अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा इस योजना को भी काउंटरवेलेबल रखा गया है। प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद जियाली ने यह प्रतिक्रिया दी है कि मूल कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ जियाली विंड के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि वे दो अलग अलग कंपनियां हैं और मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं है। जियाली द्वारा अपने मूल प्रत्युत्तर में प्रदान किए गए एक्जिजिट 19 में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कटौती की गयी राशि और छूट शून्य थी।
- छ. **जांच और निष्कर्ष के विकर्ष परिणाम** – यह कार्यक्रम केवल उन उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो इस योजना के पात्रता मानदण्डों के भीतर आते हैं। उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम का मामला प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक ने स्वयं अपनी प्रतिक्रिया में उल्लेख किया है और वेबसाइट पर भी दर्शाया है कि वे उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आते हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चीन के उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची के अनुसार 'न्यू एनर्जी एंड एफिसिएंट एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी' एचएंडटी उद्यमों के कार्यक्षेत्र के भीतर है।
- यह कार्यक्रम जीओसी द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट राजस्व के रूप में नियमावली के प्रायोजन के भीतर वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ कारोबार उद्यमों की कतिपय किस्मों तक के लिए सीमित होने के कारण इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता नियमावली के प्रायोजन के भीतर विशिष्ट है। यह कार्यक्रम काउंटरवेलेबल आर्थिक सहायता का हिस्सा है।
- सहयोग नहीं करने वाले अन्य सभी निर्यातकों के लिए जीओसी अथवा संबंधित निर्यातकों द्वारा स्वयं यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी कि क्या इन कार्यक्रमों के तहत लाभ प्रदत्त किए गए थे। जीओसी को कानून, विनियम अथवा नीति का कोई संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था कि ये कार्यक्रम चालू जांच से संबंधित नहीं थे। जीओसी ने निर्दिष्ट योजना से प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातकों द्वारा कोई लाभ नहीं किए जाने की बात को दोहराने के अलावा आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- झ. **आर्थिक सहायता राशि की गणना** - प्रतिसंतुलनकारी आर्थिक सहायता की राशि की गणना प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ जो कि जांच की अवधि के दौरान विद्यमान पाया गया था, के अनुसार की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को इस कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया लाभ, कार्यक्रम के तहत सामान्य कर दर और देय कम किए गए कर पर पर विचार करते हुए बचाए गए कुल कर की राशि माना गया है।
- उत्तर देने वाले निर्यातक ने यह दावा किया है कि उसे कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद में वित्तीय हानि उठा रहा था। तथापि यह नोट किया गया है कि जियाली विंड ने वर्ष 2013 के दौरान लाभ कमाया है और इसीलिए वह कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र है। जियाली विंड की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि लाभ की राशि \*\*\* कारोबार पर \*\*\*

आर एम वी है। देय आयकर की सामान्य दर और आयकर के वास्तविक भुगतान के बीच का अंतर कारोबार का 0.14 % बनता है जिसे इस कार्यक्रम के तहत जियाली द्वारा प्राप्त किया गया लाभ माना गया है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उपरोक्त संगत सूचना के अभाव में और वर्तमान जांच में प्राधिकारी के साथ चीन के किसी भी अन्य निर्यातक/ उत्पादक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने से प्राधिकारी यह मानते हैं कि संभवतः गैर- सहयोगी निर्यातक इन कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं और उनकी इन कार्यक्रमों तक पहुंच है और इसलिए इन कार्यक्रमों के तहत वित्तीय योगदान प्राप्त किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने अन्य उत्पादक/निर्यातकों के लिए भी 0.14 % का सी वी डी मार्जिन निर्धारित किया है।

## 102- कार्यक्रम सं 33 : विशेष उपकरणों की खरीदारी से संबंधित टैक्स क्रेडिट

(क) **कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण** - याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम उद्यमों को खरीद वर्ष में देय कॉर्पोरेट आय कर के विपरीत पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और जल की बचत तथा उत्पादन सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विशेष उपकरणों की खरीद लागत का 10% की भरपाई की अनुमति देता है। निवेश की गई राशि को 10% के शेष भाग को बाद के 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) **इच्छुक पार्टियों के विचार** - चीनी सरकार ने कहा है कि याचिका में चीनी कास्टिंग उत्पादकों को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त होने संबंधी कोई सबूत नहीं है। इसे दर्शाने वाला कोई भी सबूत उपलब्ध कराने में याचिकाकर्ता विफल रहा है। इस प्रकार, एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2, अन्य के बीच में, के अनुसार इस स्तर तक इस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है तथाकथित अनुदान के अस्तित्व, राशि और प्रकृति की विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। किसी भी घटना में, जांच में सहयोग करने वाली उत्तरदायी कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ था।

उत्तरदायी चीनी कास्टिंग निर्माता झेजियांग जियाली पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड ने यह कहा है कि उसने इस कार्यक्रम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

आईडब्ल्यूटीएमए ने यह दलील दी थी कि उद्यम के लिए पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और जल की बचत और उत्पादन सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीददारी करना, पात्रता मानदंड के लिए अपेक्षित है। हालांकि, कोई भी तथ्य यह नहीं दर्शाता है कि उद्यम ने इस तरह के उपकरणों की खरीददारी की है।

(ग) **प्रशासनिक प्राधिकरण** - वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राज्य कराधान प्रशासन (सैट), वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओम) द्वारा कार्यक्रम की देखरेख की जाती है, जो कि एससीएम तथा अधिनियम और नियमों के अर्थों के भीतर एक सार्वजनिक निकाय है। यह कार्यक्रम राज्य कराधान प्रशासन (सैट) और इसकी स्थानीय शाखा कार्यालयों या ब्यूरो द्वारा प्रशासित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

(घ) **कार्यक्रम के तहत लाभ** - यह कार्यक्रम नियमों के भीतर, जीओसी द्वारा राजस्व छोड़ देने के रूप में कर छूट प्रदान करता है।

(ङ) **कार्यक्रम की विशिष्टता**- यह कार्यक्रम उन उद्यमों के लिए विशिष्ट है; जो पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और जल की बचत और उत्पादन बचत के उपयोग के लिए उपकरणों की खरीदारी करती है।

(च) **कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता** - इस कार्यक्रम का अस्तित्व उद्यम आयकर संबंधी पी आर सी कानून के अनुच्छेद 34, राज्य परिषद द्वारा उद्यम आयकर संबंधी पी आर सी कानून के कार्यान्वयन संबंधी विनियमनों के अनुच्छेद 100 के अनुसार है। इस योजना में चीन जन. गण. में तैयार कतिपय आगेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के संबंध में अंतिम जांच परिणाम में यूरोपीय संघ द्वारा भी प्रतिसंतुलनकारी माना गया है।

(छ) **जांच परिणाम और निष्कर्ष**- यह कार्यक्रम नियमों के भीतर जीओसी द्वारा राजस्व में कर छूट प्रदान कर वित्तीय योगदान देता है। कार्यक्रम के तहत लाभ को कुछ प्रकार के व्यापार उद्यमों के लिए सीमित किए जाने के कारण यह कार्यक्रम नियमों के अर्थों के भीतर सब्सिडी विशिष्ट है। इस कार्यक्रम में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी शामिल है। जांच के दौरान बाद की प्रस्तुतियों में याचिकाकर्ता ने चीन पीआर में कास्टिंग उत्पादकों / निर्यातकों की सूची प्रस्तुत की।

इस कार्यक्रम की प्रकृति के कारण (इस आय (लाभ) को उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि की परवाह किए बगैर आयकर पर सामान्य छूट), यह माना जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता को प्राप्तकर्ता उद्यम की सभी वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण अथवा निर्यात से संबंधित बनाया जाएगा।

चीनी कास्टिंग उत्पादक जैसे गमेसा विंड (तिआनजिन) कंपनी, लिमिटेड, डालियान हुआरुई हेवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड; जियांग्सु फाव फाउंड्री कंपनी लिमिटेड; जियांग्सु जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; जियांजिन फेंगडियान फ्लेज मेनुफेक्चरर कंपनी लिमिटेड; जियांजिन हेंगरुन रिंग फोर्जिंग कंपनी लिमिटेड; क्किंगदाओ अनहुआ न्यू एनर्जी इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड; क्किंगदाओ रिचुआन प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड; सतारेम चाइना लिमिटेड; शेडोंग लाईवु जिनलेइ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड;



शंघाई सीईक ईएंडए इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड; झेजियांग जियाली विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; झुझौ टाइम्स न्यू मेटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड इस तरह के लाभ के पात्र हैं।

अन्य सभी गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए, या तो जीओसी अथवा स्वयं प्रत्येक निर्यातक द्वारा इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई कि इन कार्यक्रमों के तहत इन निर्यातकों को लाभ प्रदान किया जाता था। जीओसी को इस तथ्य के साथ कानूनों, नियमों अथवा नीति में कोई संशोधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था जो यह प्रमाणित करे कि ये कार्यक्रम मौजूदा जांच के लिए प्रासंगिक नहीं थे। जीओसी ने यह दोहराने के अलावा और कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराईया कि उत्तरदायी निर्यातक ने आरोपित स्कीम से कोई भी लाभ नहीं उठाया है।

प्राधिकरण यह ध्यान देता है कि उपर्युक्त संबंधित सूचना की अनुपस्थिति में, और चूंकि वर्तमान जांच में प्राधिकरण के साथ चीन से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है, अतः प्राधिकरण इस संभावना को मानता है कि सहयोग नहीं करने वाले निर्यातक इन कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और इसलिए इन कार्यक्रमों के तहत वित्तीय अंशदान प्राप्त हुआ है।

उत्तर देने वाले कास्टिंग उत्पादक झेजियांग जियाली पावर टेक्नोलॉजी कं. लि. ने यह कहा है कि उसने इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं लिया है। जहां तक चीन के अन्य निर्यातकों का संबंध है चूंकि प्राप्त किए गए लाभों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है इसलिए प्राधिकारी उन्हें प्राप्त लाभों की मात्रा तय करने की स्थिति नहीं है।

### **सामग्री और मशीनरी पर शुल्कों और करों से राहत**

#### **103. कार्यक्रम सं 36 : आयातित प्रौद्योगिकी और उपकरण के लिए टैरिफ और आयात वैट की छूट**

(क) कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण- कार्यक्रम अनुदान, एफआईई को लाभ पहुंचाते हैं जो कि 'प्रोत्साहित' या 'प्रतिबंधित' श्रेणियों के तहत आते हैं और या डीआईई जो कि डीआईई सूची के तहत आते हैं तथा वे जिस उपकरण का आयात करते हैं, जिसके लिए टैरिफ और / या वैट से छूट की मांग की है, को उद्यम के स्वयं के उपयोग के लिए होना चाहिए।

104. इच्छुक पक्षों के विचार- चीन सरकार ने इस योजना के प्रति यह बताते हुए प्रतिक्रिया नहीं दी कि यह योजना, कार्यक्रम 25 अर्थात् "विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) और अन्य नामित क्षेत्रों में आयातित सामग्री और उपकरण पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर (वैट) छूट" के समान ही है और उपरोक्त योजना 1 जनवरी, 2009 के बाद से समाप्त कर दी गई है। उसके बाद प्रकटीकरण के उपरांत की अवस्था में चीन सरकार ने यह कहा है कि यह कार्यक्रम, कार्यक्रम 6 के समान ही है अर्थात् विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) और अन्य नामित क्षेत्रों (एफ आई ई और डी आई ई दोनों) में आयातित सामग्री और उपकरण पर टैरिफ और मूल्य वर्धित कर (वैट) छूट" के समान है।

चीनी कास्टिंग निर्माता झेजियांग जियाली विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने जवाब देते हुए कहा कि जियाली विंड को इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

आईडब्ल्यूटीएम ने दलील दी थी कि 1 जनवरी 2008 को पीआरसी उद्यम आयकर कानून डिग्री संख्या [2007] 39 तहत पाराम्परिक अधिमान्य नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में पीआरसी राज्य परिषद द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। यह कार्यक्रम मात्र एफआईई पर ही लागू होता है। याचिका में यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि निर्यातक के उद्यम एफ आई ई हैं। इस कार्यक्रम के तहत कोई विशिष्टता स्थापित नहीं की गई है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ केवल उन एफआईई को ही दिया जाता है जो 'प्रोत्साहित' या प्रतिबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। याचिका कोई भी सबूत पेश नहीं करती कि निर्यातक एफआईई हैं। दावा किया गया है कि सेज में स्थित उद्यम होने के कारण उपकरणों को टैरिफ और आयात वैट से छूट दी गई है। सेज में स्थित उद्यम आयातित सामग्री और उपकरण पर टैरिफ और वैट में छूट के हकदार हैं जो इनका उपयोग विनिर्माण और निर्यात माल के लिए करते हैं। हालांकि, याचिका यह नहीं दिखाती है कि उनके अतिरिक्त आयात पर भी छूट प्रदान की जाती है जिसे एससीएम समझौते के फुटनोट 1 के तहत आवश्यकता के रूप में प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, फुटनोट 1 के रूप में पठित एससीएम समझौते के अनुबंध II का पैरा 1 भी इस तरह के पहले चरण के संचयी अप्रत्यक्ष करों को सब्सिडी के रूप में छूट देता है। इस तरह, सरकारी राजस्व, जो कि अन्यथा कारण है, को जब छोड़ दिया गया हो अथवा संग्रह नहीं किया गया हो तब उसे मात्र तभी वित्तीय अंशदान के रूप में माना जा सकेगा जब निर्यातित माल पर करों से छूट उनके द्वारा प्राप्त की गई सामग्री से अतिरिक्त है। प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम के लिए जांच की शुरुआत कर सीवीडी और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11 के नियम 6 का उल्लंघन किया है। याचिका में प्रस्तुत सबूतों के अभाव में इस कार्यक्रम के संबंध में जांच को एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए।

(ख) प्रशासनिक प्राधिकरण – एन डी आर सी, एस ए टी और इसकी स्थानीय कर ब्यूरो, जो कि सार्वजनिक निकाय है, के द्वारा इस कार्यक्रम की देखरेख की जाती है।

(ग) कार्यक्रम के तहत लाभ - इस कार्यक्रम को जीओसी द्वारा राजस्व छोड़ देने के रूप में सब्सिडी माना जाता है।

(घ) **कार्यक्रम की विशिष्टता** – यह कार्यक्रम विशिष्ट है चूंकि उन एफआईई और डीआईई को प्रोत्साहित करने तक सीमित है जो सूची के अंतर्गत आते हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है चूंकि यह कानून जिसके अनुसार, प्रदान करने वाला प्राधिकरण कार्य करता है, उन उद्यमों तक इसकी पहुंच को सीमित करता है जो कानून द्वारा विस्तृत रूप से परिभाषित विशिष्ट व्यवसाय श्रेणियों के तहत निवेश करते हैं और राज्य प्रोत्साहित परियोजनाओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के लिए पात्रता को सीमित करने हेतु कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं है और समाप्त करने हेतु कोई निर्णायक सबूत भी नहीं है चूंकि पात्रता स्वचालित है।

(ङ) **कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता** - घरेलू उद्योग द्वारा यथाप्रस्तुत, आयातित उपकरण संबंधी कराधान नीतियों के समायोजन के संबंध में राज्य परिषद की सूचना का अनुच्छेद 1 और 2 (जीयूओ एफए [1997] संख्या 37), वित्त मंत्रालय की घोषणा, सीमा शुल्क संबंधी सामान्य प्रशासन एवं राज्य कराधान प्रशासन [2008] संख्या 43, राज्य द्वारा विकास करने को प्रोत्साहित करने वाली घरेलू या विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में पुष्टि-पत्र के रखरखाव की चिन्ताओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में एनडीआरसी के नोटिस, संख्या 22 फरवरी 2006 की संख्या 316 2006 और या तो एफआईई अथवा घरेलू उद्यम, 2008 के लिए गैर-शुल्क-छूटयोग्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की सूची, विदेशी निवेश दिशानिर्देश (गाइडिंग) संबंधी उद्योगों के लिए सूची, वर्तमान में (2004) राज्य द्वारा समर्थित मुख्य उद्योग, उत्पाद और प्रौद्योगिकी की सूची, राज्य परिषद की विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए कराधान से गैर-छूट-प्राप्त आयात सामग्री की सूची, घरेलू निवेश परियोजनाओं के लिए कराधान से गैर-छूट-प्राप्त आयात सामग्री की सूची द्वारा इस कार्यक्रम का अस्तित्व स्थापित है।

विश्व व्यापार संगठन के दस्तावेज जी / एससीएम/ एन /123 /सीएचएन, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 में इस स्कीम का अस्तित्व होना सूचित किया गया है। चीन पीआर में सोलर ग्लास ओरिजिनेटिंग, चीन पीआर में कोटेड फाइन पेपर एंड ऑर्गेनिक कोटेड स्टील संबंधी अंतिम निष्कर्ष में यूरोपीय संघ द्वारा इस स्कीम को प्रतिसंतुलनकारी माना गया है।

(च) **जांच परिणाम और निष्कर्ष**- इस कार्यक्रम को अधिनियम और नियमों के भीतर जीओसी द्वारा राजस्व में छूट प्रदान करने के रूप में सख्ती माना जाता है जैसा कि एफआईई और अन्य पात्र घरेलू उद्यमों को वैट और / या अन्यथा देय शुल्कों के भुगतान से राहत दी जाती है यदि उन्होंने राज्य प्रोत्साहित परियोजना का प्रासंगिक एनडीआरसी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। इसलिए यह प्राप्तकर्ता कंपनियों के संबंध में एक लाभ है।

चीनी कास्टिंग उत्पादकों जैसे गमेसा विंड (तिआनजिन) कंपनी लिमिटेड, एनटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियान्जिन) कंपनी लिमिटेड, डालियान हुआरुई हेवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड; जेक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कंपनी लिमिटेड, जियांग्सु फाव फाउंड्री कंपनी लिमिटेड; जियांग्सु जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; जियांजिन फेंगडियान फ्लेज मेनुफेक्चरर कंपनी लिमिटेड; जियांजिन हेंगरुन रिंग फोर्जिंग कंपनी लिमिटेड; क्रिंगदाओ अनहुआ न्यू एनर्जी इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड; क्रिंगदाओ रिचुआन प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड; सतारेम चाइना लिमिटेड; शेडोंग लाईवु जिनलेइ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; शंघाई सीईई ईएंडए इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड; सिनोवेल विंड ग्रुप कंपनी लिमिटेड; झुझौ टाइम्स न्यू मेटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड इस तरह के लाभ के पात्र हैं। चीन सरकार के प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने योजना की प्रतिसंतुलनकारिता के निर्धारण के लिए आगे कार्यवाही नहीं की है।

### 105. कार्यक्रम संख्या 37- भूमि उपयोग शुल्क में कमी

(क) **कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण** - चीनी सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र ("एसईजेड"), उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास जोनों, निर्यात प्रसंस्करण जोनों, मुक्त बंदरगाहों, बोन्डेड जोनों, और इसी तरह के जोन जैसे विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोनों (एसईए) में सक्रिय निर्माताओं को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये विशेष आर्थिक जोन (एसईए) विशिष्ट कर पैकेज और अन्य प्रोत्साहनों से निवेश को बढ़ावा देते हैं। इन प्रोत्साहनों में साधारणतया भूमि उपयोग शुल्क, आयात और निर्यात शुल्क और बुनियादी ढांचा सेवाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कमी अथवा छूट शामिल हैं। सरकार ने भी निर्यात उन्मुख निवेश से संबंधित परियोजनाओं के लिए और कुछ उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की।

चीन में भूमि के उपयोग कर का भुगतान करने की आवश्यकता "शहरों और कस्बों पर चीन पीपुल्स गणराज्य शासी की भूमि उपयोग कर के अंतरिम विनियम" के अनुसार है। यह शहरी भूमि उपयोग कर एफआईई पर तब तक लागू नहीं हुआ था जब तक कि इसे शामिल करने के लिए हाल ही में संशोधन पारित नहीं किया गया था। संशोधन, जिसे एफआईई पर लागू किया है, को "शहरों और कस्बों पर चीन पीपुल्स गणराज्य शासी की भूमि उपयोग कर के अंतरिम विनियम के संशोधन संबंधी राज्य परिषद के निर्णय" (राज्य परिषद [2006] संख्या 483 का आदेश) के तहत किया गया था। एफआईई और डीआईई दोनों 1 जनवरी 2007 (पीओआई के प्रारंभ) से भूमि उपयोग कर का भुगतान करते हैं। 1 जनवरी 2007 से पहले, एफआईई ने एक मानार्थ भूमि उपयोग शुल्क का भुगतान किया था। एफआईई को भूमि उपयोग शुल्क का भुगतान करना एक अपवाद स्वरूप आवश्यकता थी, जिन्होंने हस्तांतरण के माध्यम से अपना भूमि उपयोग अधिकार हासिल किया था।

(ख) **इच्छुक पक्षकारों के विचार** – चीन सरकार ने कहा है कि वर्तमान में चीनी उद्यमों को हस्तांतरण या किराये पर लेने के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने के लिए भूमि हस्तांतरण शुल्क या भूमि-किराया शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

यदि बाजार के अन्य कारक ग्रामीण आर्थिक संगठन के साथ उद्यम की स्थापना से ग्रामीण सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग करते हैं, तो शेयरों की खरीद या संयुक्त आपरेशन संबंधी भूमि उपयोग अधिकार के मूल्य को दोनों पक्षों द्वारा बाजार के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण आर्थिक संगठन अपने शेयरों या संयुक्त आपरेशन के अनुसार लाभ प्राप्त करते हैं।

चीनी कार्स्टिंग उत्पादकों को इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने संबंधी कोई सबूत, याचिका में दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार, अन्यो में एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार, इस हद तक इस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपित अनुदान का अस्तित्व, राशि और प्रकृति की विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। किसी भी घटना में, इस जांच में सहयोग करने वाली कंपनी को इस कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ था।

उत्तर देने वाली चीनी कार्स्टिंग निर्माता झेजियांग जियाली विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने कहा कि जियाली विंड ने इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था।

आईडब्ल्यूटीएमए ने दलील दी कि इस कार्यक्रम संबंधी याचिका में कोई वित्तीय अंशदान नहीं दिखाया गया है। याचिका मात्र यह दर्शाती है कि कार्यक्रम मात्र एफआईई पर ही लागू होता है। याचिकाकर्ता यह दर्शाने में विफल रहा है कि याचिका के तहत नामोदित निर्यातकों पर कार्यक्रम लागू होता है। प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम के लिए जांच की शुरुआत कर सीवीडी नियम, अनुच्छेद 11.2 के नियम 6 और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में मुहैया कराए गए सबूतों के अभाव में एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम संबंधी जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

**(ग) प्रशासनिक प्राधिकरण -** एसएटी द्वारा कार्यक्रम की देखरेख की जाती है लेकिन प्रांतीय और स्थानीय भूमि उपयोग प्रबंधन प्राधिकारी भूमि के उपयोग शुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार है जो सार्वजनिक निकाय है, तथा एफआईई को अनुदान देती है, जिन्होंने हस्तांतरण द्वारा भूमि उपयोग अधिकार हासिल किया है, इस स्कीम के लिए पात्र हैं।

**(घ) कार्यक्रम के तहत लाभ -** यह पाया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित कुछ कंपनियाँ उस भूमि के लिए दीर्घावधि कम भूमि उपयोग शुल्क का भुगतान करती हैं, जहाँ उनके कारखाने स्थित हैं। चीन पीआर के वर्तमान संपदा अधिकार व्यवस्था में, भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान के माध्यम से निर्दिष्ट अवधि के लिए उपयोग का अधिकार, जो कि 40 से 70 वर्ष है, राज्य से प्राप्त किया जा सकता है। इस भूमि के उपयोग के शुल्क का निर्धारण, प्रस्तावित विकास के स्थान, प्रकार और घनत्व के आधार पर किया जाता है। भूमि पर राज्य के स्वामित्व को बनाए रखते हुए भूमि स्वामित्व और उपयोग अधिकार का यह अलगाव भूमि उपयोग अधिकार के व्यापार की अनुमति देता है।

**(ङ) कार्यक्रम की विशिष्टता -** यह स्कीम विशिष्ट है चूँकि यह एफआईई तक सीमित है। चीन के कानून के तहत, सारी भूमि राज्य स्वामित्व में है। विदेशी निवेशक विधिवत् रूप से भूमि विकास, उपयोग और व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वे भी निर्धारित उद्देश्यों और उपयोग की शर्तों के अनुसार कानून के तहत भूमि अधिकार का हस्तांतरण और पट्टा, कर सकते हैं अथवा बंधक रख सकते हैं। जब विदेशी 15 साल से अधिक की प्रचालनात्मक अवधि के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाओं में निवेश करते हैं तो, उद्यम द्वारा भूमि उपयोग अधिकार प्राप्त करने के दिन से पांच साल के लिए निर्माण भूमि को भूमि उपयोग शुल्क से छूट दे दी जाती है और अगले पांच वर्षों में आधा शुल्क संग्रह किया जाता है।

**(च) कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता -** घरेलू उद्योग द्वारा यथाप्रस्तुत, राज्य परिषद के आदेश [2006] सं 483; गुओ बान फा [1999] सं 73 का अनुच्छेद IV.5) (सीमा शुल्क दस्तावेज 18) क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि उपयोग शुल्क और तरजीही कमी तथा भूमि उपयोग शुल्क की छूट के पुनः समायोजन संबंधी उपाय, अतिरिक्त विदेशी निवेश "(गुओ बान फा [1999] सं 73) के लिए मौजूदा उपायों पर विचारों के अनुच्छेद IV.5 द्वारा इस कार्यक्रम का अस्तित्व स्थापित किया जाता है। चीन के खिलाफ अपने निष्कर्षों में अन्य जांच अधिकारियों द्वारा स्कीम को प्रतिसंतुलनकारी पाया गया है।

**(छ) जांच परिणाम और निष्कर्ष -** इस कार्यक्रम को अधिनियम और नियमों के भीतर जीओसी द्वारा राजस्व में छूट प्रदान करने के रूप में सज्जिदी माना जाता है जैसा कि एफआईई और अन्य पात्र उद्यमों को अन्यथा देय भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान से राहत दी जाती है। यदि उन्होंने राज्य प्रोत्साहित परियोजना का प्रासंगिक एनडीआरसी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। इसलिए यह प्राप्तकर्ता कंपनियों के संबंध में एक लाभ है।

चीनी कार्स्टिंग उत्पादकों जैसे गमेसा विंड (तिआनजिन) कंपनी लिमिटेड, एनटेक ब्रेकिंग सिस्टम्स (तियान्जिन) कंपनी लिमिटेड, डालियान हुआरुई हेवी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड; जेक्सप्रो इंडस्ट्री सप्लाय शंघाई कंपनी लिमिटेड, जियांग्सु फाव फाउंड्री कंपनी लिमिटेड; जियांग्सु जिक्सिन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; जियांजिन फेंगडियान फ्लेंज मेनुफेक्चरर कंपनी लिमिटेड; जियांजिन हेंगरुन रिंग फोर्जिंग कंपनी लिमिटेड; क्किंगदाओ अनहुआ न्यू एनर्जी इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड; क्किंगदाओ रिचुआन प्रेसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड;

सतारेम चाइना लिमिटेड; शेडोंग लाईवु जिनलेइ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; शंघाई सीईक ईएंडए इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड; सिनोवेल विंड ग्रुप कंपनी लिमिटेड; झुझौ टाइम्स न्यू मेटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड इस तरह के लाभ के पात्र हैं।

**(ज) सब्सिडी राशि की गणना-** प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ के मामले में बराबर उपलब्ध सब्सिडी राशि की गणना की जाती है, जिसे जांच अवधि के दौरान पाया गया। भूमि उपयोग शुल्क के भुगतान से राहत की राशि को प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ माना जाता है।

उत्तर देने वाले निर्यातक ने दावा किया था कि उसने कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि मूल कंपनी ने "आरएमबी के लिए "भूमि उपयोग कर वापसी" राशि प्राप्त की, जो कि 0.04% है।

प्राधिकरण ने यह पाया कि उपर्युक्त प्रासंगिक सूचना के अभाव में और वर्तमान जांच में चीन से किसी भी अन्य निर्यातक / उत्पादकों ने प्राधिकरण के साथ सहयोग नहीं किया है, अतः प्राधिकरण मानता है कि गैर सहयोगी निर्यातक ने कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा कर इन कार्यक्रमों तक पहुंच बनाई है और इसलिए उन्होंने इन कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की है। याचिकाकर्ता ने सबूत मुहैया कराया है कि अन्य कास्टिंग उत्पादकों में से कम से कम कुछ इस लाभ के हकदार थे। प्रकटीकरण के उपरांत जियाली विंड ने यह अनुरोध किया कि "वेलफेयर बिजनेस वेल्यू एडेड टैक्स रिफंड", "एक्सपोर्ट टैक्स रिफंड" और "अन्य कर रिफंड" का प्रयोग कार्यक्रम की गणना के लिए नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले तो वे भू उपयोग कर से संबंधित नहीं हैं, दूसरे एक्सपोर्ट टैक्स रिफंड को सब्सिडी नहीं माना जाएगा। जियाली विंड द्वारा किए गए उपरोक्त प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने गणना की समीक्षा की और जियाली विंड और अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों, दोनों के लिए सी वी डी मार्जिन 0.03 % पर निर्धारित किया है।

### **उचित बाजार मूल्य से कम पर सरकार द्वारा प्रदान सामग्री / सेवाएं**

#### **106. कार्यक्रम संख्या 40: उचित बाजार मूल्य से कम पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बिजली**

**(क) कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण [स्कीम का परिचय]** - अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की देख-रेख की जाती है, जो उद्यमों और उद्योगों के सीमित समूह, खासकर कास्टिंग उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले उद्योगों को रियायती दर प्रदान करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं। संबंधित एनडीआरसी सूचना में निम्न बिजली दर निर्धारित की जाती है और इसे स्थानीय कीमत ब्यूरो द्वारा जारी सूचना में शामिल किया जाता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जीओसी ने तरजीही दरों के माध्यम से पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम के लिए बिजली प्रदान की। बिजली की दरों को अलग अलग प्रांतों में अलग ढंग से निर्धारित किया जाता था और यह भी कि तरजीही दरों को उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक औद्योगिक नीति उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

**(ख) इच्छुक पक्षों के विचार** - चीन सरकार ने कहा है कि एनडीआरसी सीधे केंद्र सरकार स्तरीय बिजली ग्रिड और प्रांत स्तरीय बिजली ग्रिड के तहत पार-प्रांतीय, स्वायत्त क्षेत्रीय और नगर निगम के स्तर पर बिजली की कीमतों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। सीमा पार प्रांतीय बिजली ग्रिडों को चीन के स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन (एसजीसीसी) और चीन के दक्षिणी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (सीएसजी) द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता है। जीओसी को उत्पादन की मात्रा और औसत लागत के बारे में पता नहीं है। वर्तमान में, चीन में बिजली की बिक्री सरकार के मूल्य निर्धारण के अधीन है और प्रतियोगिता तंत्र को धीरे-धीरे उत्पादन तथा बिक्री दोनों पक्षों में शुरू किया गया है। उदाहरण स्वरूप, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बोली लगाने और द्विपक्षीय व्यापार को प्रायोगिक रूप शुरू किया है। बिजली उत्पादक उद्यमों और बिजली उपयोगकर्ताओं के बीच सीधी खरीद को कुछ प्रांतों में प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत दोनों पक्ष स्वेच्छा से कीमतों के बारे में बातचीत कर सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को और अधिक विकल्प मिलता है। एसजीसीसी और सीएसजी छोड़कर, बिजली उपयोगकर्ताओं और बिजली उत्पादन उद्यमों के बीच सीधे लेन-देन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रांतों में कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। दोनों पक्ष स्वैच्छिक मोल-तोल के माध्यम से मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान में, बिजली की कीमत एकीकृत नेतृत्व और विकेन्द्रीकृत जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार सरकारी कीमत विभागों द्वारा निर्धारित की जाती है। सीमा पार प्रांतीय बिजली ग्रिड, और स्वायत्त क्षेत्रों तथा नगर पालिकाओं के ग्रिड को केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रबंधित किया जाता है। प्रांतीय स्तर के तहत बिजली ग्रिडों को प्रांतीय सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। "उचित मुआवजा लागत, उचित आय का आकलन, कानून के अनुसार, कर राशि का समावेश, निष्पक्ष बोझ प्रतीति" के सिद्धांतों पर सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा टैरिफ स्तर तैयार किया जाता है। आम तौर पर, निवेशकों की प्रत्याशित आय दर बैंकों की ऋण दर से कम नहीं है। चीन में बिजली उत्पादन उद्यमों की एक बड़ी राशि है। जीओसी उनकी उत्पादन लागत की जानकारी नहीं रखता है। वर्तमान में, बिजली की कीमत को आवासीय, कृषि, सामान्य उद्योग और वाणिज्य तथा अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, समान वर्गीकरण के उपयोगकर्ता को बिजली की कीमत समान दर पर देनी होती है।

"उचित मुआवजा लागत, उचित आय का आकलन, कानून के अनुसार, कर राशि का समावेश, निष्पक्ष बोझ प्रतीति" के सिद्धांतों पर, सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा टैरिफ स्तर तैयार किया जाता है।

उत्तर देने वाली चीनी कास्टिंग निर्माता झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने कहा कि जियाली विंड ने जाँच अवधि के दौरान बाजार भाव पर आपूर्तिकर्ता से बिजली खरीदी। जियाली विंड ने इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था। प्रकटीकरण के

उपरांत जियाली ने प्राधिकारी का ध्यान बिजली की खरीद के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य की ओर आकर्षित किया। बिजली के लिए इनवायस यह दर्शाता है कि बिजली की खरीद कीमत प्राधिकारी द्वारा मानी गयी प्रति के डब्ल्यू एच \*\*\* आर एम बी की तुलना में प्रति के डब्ल्यू एच \*\*\* आर एम बी थी। दर्ज किए गए साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जियाली विंड ने बिजली की खरीद प्राधिकारी द्वारा विचार की गयी बेंचमार्क दर अनुरूप दर पर की है। इसे देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि जियाली ने योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

आईडब्ल्यूटीएमए ने दलील दी कि जीओसी ने पर्याप्त दरों की तुलना में तरजीही कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई। याचिका के अनुसार राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की एक नीति के रूप में तरजीही दर लगाता है। हालांकि चीनी परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 प्राधिकरण को सब्सिडी की पहचान करने और मापने में पद्धति का उपयोग करने की अनुमति देता है जो इस संभावना को ध्यान में रखता है कि चीन में प्रचलित बाजार दर बेंचमार्क के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। हालांकि, याचिकाकर्ता लाभ निर्धारित करने के लिए चीन के बाहर किसी भी बेंचमार्क का सुझाव देने में नाकाम रहा है।

इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मात्र कार्टिंग उद्योगों को ही तरजीही बिजली दर प्रदान की गई है। तथापि, कथित तौर पर कार्यक्रम की विशिष्टता के संबंध में याचिकाकर्ता मात्र दावा करता है कि बिजली संबंधी प्रावधान कार्यान्तर-विशिष्ट है चूंकि अधिकारी रियायती दरों के निर्धारण के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं और यह याचिकाकर्ता का विश्वास है कि कुछ क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को तरजीही दर प्रदान की जाती है। एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2.4 के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि विशिष्टता केवल सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्थापित की जा सकती है और याचिकाकर्ता की मान्यताओं के आधार पर नहीं की जा सकती है। किसी भी मामले में, यह कल्पनातीत है कि गैर विशिष्ट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के क्रम में देश भर में बिजली की दरें समान ही होनी चाहिए। प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम के लिए जांच की शुरुआत कर सीवीडी नियमों के नियम 6 तथा एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में उपलब्ध कराई गई सबूतों के अभाव में एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

**(ग) प्रशासनिक प्राधिकरण** - एनडीआरसी बिजली बाजार को विनियमित करने और चीन में मूल्य निर्धारण की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। पार-प्रांतीय और प्रांतीय ग्रिडों को दो राज्य स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ताओं : चीन के स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन और चीन के दक्षिणी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। नगर निगम के स्तर पर बिजली आपूर्तिकर्ता इन कंपनियों के सहायक हैं। कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से चीन में एक प्रतियोगिता तंत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी इस स्तर पर इसका प्रभाव नगण्य है। प्रासंगिक एनडीआरसी सूचना में कम बिजली दर निर्धारित की जाती है और स्थानीय कीमत ब्यूरो द्वारा जारी सूचना में शामिल की जाती है।

**(घ) कार्यक्रम के तहत लाभ** - इस कार्यक्रम से प्राप्त लाभ भारतीय नियमों और एएससीएम के अर्थ में वित्तीय योगदान है, जिसके तहत सरकार स्थानीय सार्वजनिक बिजली आपूर्ति कंपनी के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराती है। यह सामान्य बुनियादी सुविधाओं के अलावा अन्य वस्तु के प्रावधान के रूप में इस स्तर तक सरकारी योगदान तैयार करता है कि सरकार ने पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम पर बिजली प्रदान की है। यह स्थापित किया गया है कि यह निर्यातक साधारणतया अन्य बड़े औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए आम तौर पर लागू दर से कम दर पर बिजली पाने का हकदार था।

**(ङ) कार्यक्रम की विशिष्टता** - यह कार्यक्रम उद्यम या सेक्टर विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट दोनों है। उत्पादकों/ निर्यातकों को बिजली की व्यवस्था के रूप में सब्सिडी विशिष्ट है चूंकि एनडीआरसी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक सूची में निम्न बिजली दर निर्धारित की जाती है। यह कम दर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की एक उप श्रेणी में शामिल कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों के कुछ उद्यमों तक सीमित है। इसलिए, यह कम दर केवल नियमों और एएससीएम के भीतर इन श्रेणियों के कंपनियों तक विधि सम्मत सीमित है।

सब्सिडी भी क्षेत्र विशिष्ट है चूंकि यह एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित है और यह एक सीमित नामित भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ याचिकाकर्ता द्वारा केवल सूचीबद्ध निर्यात उत्पादक स्थित है, में लागू होता है। चीन के विशाल पश्चिमी क्षेत्रों के विकास के लिए कई नीतियों के संबंध में राज्य परिषद का परिपत्र स्पष्ट रूप से बिजली पारेषण और प्रावधान में मूल्य प्रणाली का उल्लेख निश्चित क्षेत्रों में विकास के लिए एक उपकरण के रूप में करता है।

**(च) कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता** - कार्यक्रम का अस्तित्व चीन के विशाल पश्चिमी क्षेत्रों के विकास के संबंध में विभिन्न नीतियों के संबंध में राज्य परिषद के परिपत्र से स्पष्ट है। चीन पीपुल्स रिपब्लिक में बनने वाले कुछ ऑर्गेनिक कोटेड इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ का अंतिम निष्कर्ष; चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, और ताइवान से नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील पर अमेरिका का अंतिम निष्कर्ष, चीन पीआर में सौर ग्लास ओरिजिनेटिंग पर यूरोपीय संघ का अंतिम निष्कर्ष।

**(छ) जांच परिणाम और निष्कर्ष** - प्राधिकरण ने यह पाया है कि एनडीआरसी है जो विभिन्न प्रांतों में लागू बिजली की कीमतें तय करता है। यह सत्यापित किया गया कि स्थानीय कीमत ब्यूरो महज एनडीआरसी द्वारा केंद्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय के एक कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है। इस तथ्य से इसकी भी पुष्टि होती है कि एनडीआरसी नोटिस जारी करता है जिसमें यह प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित वास्तविक कीमत निर्धारित करता है और फिर इन सूचनाओं को औपचारिक रूप से स्थानीय कीमत ब्यूरो द्वारा अपनाया और स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है। जांच से भी स्थापित होता है कि अपने 5 साल की योजना और क्षेत्रीय योजनाओं में केंद्रीय और

स्थानीय सरकारों द्वारा सेट औद्योगिक नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति सहित कुछ कारकों के अनुसार कुछ क्षेत्रों के लिए और/या प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर विभिन्न बिजली दरें लागू होती हैं।

**(ज) सब्सिडी राशि की गणना-** चीन में बिजली के सामान्य मूल्य का अनुमान याचिकाकर्ता की दर पर \*\*\* आर एम बी प्रति के डब्ल्यू एच आधार पर लगाया गया है। जियाली ने बिजली xxx आर एम बी प्रति के डब्ल्यू एच की दर से खरीदी थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जियाली ने योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। किसी अन्य सूचना के न होने पर प्राधिकारी ने इस संबंध में जियाली विंड और उत्तर न देने वाले अन्य निर्यातकों द्वारा प्राप्त की सब्सिडी, यदि कोई है, तो उसकी गणना नहीं की है।

#### 107. कार्यक्रम संख्या 43: पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम पर विभिन्न वस्तुओं का प्रावधान

**(क) कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण-** घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि चीन के कास्टिंग निर्यातक, जीओसी द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में कच्चे माल या इनपुटों और उपयोगिता वाली सामग्री के प्रावधान से लाभान्वित हो रहे हैं। खासकर याचिका इसे सबूत बनाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में इनपुट शामिल है जो कि पिग आयरन, स्टील स्क्रेप (सीआरसीए), फेरो सिलिकॉन, फेरो सिलिकॉन एमजी, कोक, इनोक्युलेंट्स, सिलिका सैंड, रेजिन, उत्प्रेरक, एलपीजी, फर्नेस अस्तर सामग्री, डीजल, लेडल लाइनिंग सामग्री, सिरेमिक ट्यूब, स्लिव्स और रिफ्रेक्टरी कोटिंग है। जीओसी द्वारा कास्टिंग उत्पादकों को विशेष रूप से पिग आयरन, स्टील स्क्रेप, और कोक सहित एसओई से निर्मित कई स्टील उत्पादनों के लिए प्रावधान प्रदान किया जा रहा है। चीन पीआर के सरकारी प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में कास्टिंग निर्माण में इस्तेमाल मुख्य इनपुट का उत्पादन और आपूर्ति की जा रही थी।

**(ख) इच्छुक पक्षों के विचार -** चीन सरकार ने कहा है कि याचिका में यह दर्शाने वाला कोई भी सबूत नहीं है कि चीनी कास्टिंग उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए हों। याचिकाकर्ता इसे दर्शाता हुए कोई भी सबूत उपलब्ध कराने में विफल रहा है। इस प्रकार, अन्यो के बीच एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2, के अनुसार, इस स्तर तक इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है कि आरोपित अनुदान के अस्तित्व, राशि और प्रकृति की विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। किसी भी घटना में, सहयोग करने वाली उत्तरदायी कम्पनी को कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

उत्तर देने वाली चीनी कास्टिंग उत्पादक झेजियांग जियाली विंड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने कहा कि जियाली विंड ने जाँच अवधि के दौरान बाजार भाव पर आपूर्तिकर्ता से विभिन्न सामग्री खरीदी। जियाली विंड ने इस कार्यक्रम से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था।

आईडब्ल्यूटीएमए ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने सामान्यतः यह दावा किया है कि चीन सरकार पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में सामान उपलब्ध कराती है। याचिकाकर्ता ने यह बैचमार्क भी उपलब्ध नहीं कराया है जिसे उन्होंने सब्सिडी की पहचान करने और आंकने में अपनाया है। इसलिए याचिका कर्ता ऐसे कार्यक्रम के अस्तित्व का दावा नहीं कर सकता है।

याचिका के अनुसार राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी) उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के नीति के रूप में तरजीही दर लगाते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया है कि यह मात्रा कास्टिंग उद्योगों के लिए ही उपलब्ध है।

प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम के लिए जांच की शुरुआत कर सीवीडी नियमों के नियम 6 तथा एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.2 और अनुच्छेद 11.3 का उल्लंघन किया है। याचिका में उपलब्ध कराए गए सबूतों के अभाव में एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

**(ग) प्रशासनिक प्राधिकरण-** सरकार द्वारा बाजार मूल्य से कम पर उपलब्ध कराई गई इनपुट सामाग्रियां (कच्चा माल) और यूटिलिटीज समान सब्सिडी तैयार करती हैं, चूंकि इस कार्यक्रम की देख-रेख चीन पीआर सरकार द्वारा की जाती है जो कि एक सार्वजनिक निकाय है। इस कार्यक्रम में वित्तीय अंशदान जुड़ा हुआ है, जो कि पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में एसओई के, सार्वजनिक निकाय होने के कारण, उसके द्वारा सामाग्रियों का प्रावधान करने से जुड़ा हुआ है।

**(घ) कार्यक्रम के तहत लाभ-** कार्यक्रम एसओई द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में इनपुट सामाग्रियों और यूटिलिटीज की व्यवस्था कर उत्पादकों को निर्धारित वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता देता है और इस तरह सब्सिडी की समान उपलब्धता स्थापित होती है।

चीनी एसओई जो स्टील अथवा लोहा अथवा कोई अन्य दुर्लभ खनिज सामाग्रियों का उत्पादन करते हैं, सार्वजनिक निकाय हैं। कास्टिंग उत्पादकों को इन एसओई द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में इनपुट अथवा कच्ची सामाग्रियां उपलब्ध कराना एक वित्तीय सहायता है और इससे समान सब्सिडी उपलब्धता स्थापित होती है। परिग्रहण संधि स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि "चीन प्रसंस्करण व्यापार के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित स्टील पर वैट का संग्रह नहीं करता है।" यही बात अन्य कच्ची सामाग्रियों जैसे कोयला, बिजली आदि के साथ भी है जहां सरकार का कीमत की संरचना पर पूरा नियंत्रण है।

इस कार्यक्रम के तहत चीन में बाजार की स्थितियों से लाभ प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम राशि में मध्यस्थ अथवा एसओई के माध्यम से जीओसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इनपुटों के द्वारा निर्यातक कास्टिंग को लाभ पहुंचाया गया है।

(ड) **कार्यक्रम की विशिष्टता** - यह कार्यक्रम विशिष्ट है, चूंकि कार्यक्रम के तहत लाभ को सीमित किया गया है क्योंकि डब्ल्यूओईजी कास्टिंग के निर्यातकों को पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम राशि में इनपुट सामाग्रियां दी जाती हैं, बाजार भाव पर नहीं।

(च) **कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनकारिता** - कार्यक्रम के अस्तित्व की स्थापना चीन और मेक्सिको से यूएस-गेल्वनाइज्ड स्टील वायर, यूएस-सर्टेन सीमलेस कार्बन और अलोए स्टील स्टैंडर्ड, चीन जनवादी गणराज्य से लाइन और प्रेशर पाइप ("सीमलेस पाइप") और चीन से यूएस-कार्बन तथा सर्टेन अलोए स्टील वायर रॉड द्वारा की जाती है।

(छ) **जांच परिणाम और निष्कर्ष**- प्राधिकरण मानता है कि निर्धारित सामाग्री के उत्पादकों को हस्तांतर की जा रही इनपुटों का प्रावधान अप्रत्यक्ष लाभ है जो इस स्तर तक निर्यातित सामाग्रियों के संबंध में प्रदान किया जाता है कि निजी मध्यस्थों के लिए प्रदान किया गया लाभ पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम में उपलब्ध कराई जा रही इनपुटों के रास्ते निर्यातकों से होते हुए प्राप्त हो। जहां निजी मध्यस्थों के माध्यम से सार्वजनिक निकाय, एसओई द्वारा कच्ची सामाग्रियों और इनपुटों के प्रावधान से वित्तीय सहायता जुड़ी हुई है, वहां उत्पाद के निर्यातक को उन इनपुटों का व्यापार करना विचाराधीन है। लाभ राशि, सामान्य दर पर अथवा पर्याप्त पारिश्रमिक पर खरीद मूल्य और पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम पर वस्तुओं के खरीद मूल्य के बीच अन्तर राशि के समान होती है। जहां जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक को पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम पर कार्यक्रम के तहत इनपुटों के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ है, अतः इसे कास्टिंग के संबंध में लाभ माना जाएगा और वित्तीय सहायता एएससीएम तथा भारतीय नियमों के अनुसार सब्सिडी की परिभाषा को पूरा करेगी।

(ज) **सब्सिडी राशि की गणना**- प्राप्तकर्ताओं को प्रदत्त लाभ के मामले में बराबर उपलब्ध सब्सिडी राशि की गणना की जाती है, जिसे जांच अवधि के दौरान पाया गया। जांच अवधि के दौरान बाजार मूल्य से भी कम में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट सामाग्रियों (कच्ची सामाग्री) की राशि को लाभ माना जाता है। नियम और एएससीएम के अनुसार इस सब्सिडी राशि (अंश) की गणना मासिक विश्व बाजार मूल्य के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सुपुर्दगी, आयात शुल्क, वैट और सब्सिडी मार्जिन की गणना के लिए चीनी अंतर्देशीय दुलाई शुल्क के आधार पर की जाती है। पिग आयरन और स्टील स्क्रैप का समान मूल भारत में निर्यात की जा रही वस्तुओं से काफी अलग हैं। प्रकटीकरण के उपरांत जियाली ने खपाए गए कच्चे माल अर्थात् पिग आयरन और स्टील स्क्रैप के वास्तविक भुगतान की वार्षिक औसत कीमत प्रदान की है। जियाली और घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त इनपुट की सामान्य दरें और घरेलू उद्योग के मानकों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने इस योजना के तहत लाभ और सी वी डी मार्जिन पर विचार किया है जो 8.12% है। किसी अन्य सूचना के न होने पर प्राधिकारी ने उत्तर न देने वाले निर्यातकों के लिए उसी सब्सिडी मार्जिन का प्रयोग किया है।

108. प्राधिकारी ने चीन के एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक और अन्य के संबंध में सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है उक्त के संबंध में स्कीमों/कार्यक्रमों की निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र.सं.	शीर्ष	कार्यक्रम सं.	स्कीमें	जिआली विंड के लिए सीआईएफ कीमत पर सब्सिडी मार्जिन का %	अन्य के लिए सीआईएफ कीमत पर सब्सिडी मार्जिन का %
1	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रोत्साहन और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र	कार्यक्रम सं. 5	एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आय कर से छूट और/या कटौती	----	----
		कार्यक्रम सं. 6	एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर टैरिफ और अन्य मूल्यवर्धित कर (वैट) से छूट	----	----
2	अनुदान	कार्यक्रम सं. 8	राज्य मुख्य प्रौद्योगिकी पुनरुद्धार परियोजना निधि	1.99	1.99
		कार्यक्रम सं. 9	स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी ओर/या प्रतिसंतुलनकारी विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति		
		कार्यक्रम सं. 10	अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान		

		कार्यक्रम सं. 11	नवोन्मेषी प्रयोगिक उद्यम अनुदान		
		कार्यक्रम सं. 12	सुपरस्टार उद्यम अनुदान		
		कार्यक्रम सं. 13	ऐसे उद्यमों के लिए पुरस्कार जिनके उत्पाद चीन के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'या चीन के प्रसिद्ध ब्रांडों' के रूप में पात्र होते हैं।		
		कार्यक्रम सं. 14	हार्ड-टेक उद्योग की उद्यम निवेश निधि		
		कार्यक्रम सं. 15	विदेशी निवेश के साथ मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु अनुदान		
		कार्यक्रम सं. 16	नवोन्मेषी लघु और मध्यम उद्यम अनुदान		
		कार्यक्रम सं. 17	निजी-स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों के लिए अनुदान		
3	इक्विटी कार्यक्रम	कार्यक्रम सं. 18	इक्विटी निवेश	----	----
		कार्यक्रम सं. 19	अप्रदत्त लाभांश	----	----
4	अधिमानी ऋण	कार्यक्रम सं. 20	कास्टिंग उद्योग के लिए अधिमानी ऋण और ब्याज दरें	----	----
5	अधिमानी आय कर कार्यक्रम और कर प्रोत्साहन	कार्यक्रम सं. 25	ऐसे एफआईई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां जो चीन में स्थापित हैं और घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद से उत्पादन और व्यवसाय प्रचालनों में शामिल हैं।	----	2.13
		कार्यक्रम सं. 28	अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्ययों की कटौती के लिए कर नीतियां	0.25	0.25
		कार्यक्रम सं. 31	उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां	0.14	0.14
		कार्यक्रम सं. 33	विशेष उपकरणों के खरीद से संबंधित कर ऋण	-	-
6	सामग्री और मशीनरी पर शुल्कों और करों से राहत	कार्यक्रम सं. 36	आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरण के लिए टैरिफ और आयात वैट से छूट	-	-
		कार्यक्रम सं. 37	भूमि प्रयोग शुल्क में कटौती	0.03	0.03
7	पर्याप्त से कम मूल्य पर निवेश सामग्रियों और सुविधाओं का प्रावधान	कार्यक्रम सं. 40	उचित बाजार मूल्य से कम पर सरकार द्वारा प्रदत्त बिजली	-	-
		कार्यक्रम सं. 43	पर्याप्त मूल्य से कम पर विभिन्न वस्तुओं का प्रावधान	8.12	8.12
		कुल		10.53	12.66
		लदान मूल्य के प्रतिशत के रूप में कुल सब्सिडी मार्जिन		11.18	13.44



**ज. क्षति और कारणात्मक संबंध****ज.1. घरेलू उद्योग के अनुरोध**

109. घरेलू उद्योग ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. यह तथ्य कि उपभोक्ता चीनी उत्पादकों द्वारा दी गई कम कीमतों के कारण उत्पाद का आयात कर रहे हैं ही सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन के आयातों के कारण हो रही है। मांग में कमी का कोई भी कारण हो वह केवल क्षति के मात्रा संबंधी हिस्से पर ही ध्यान देता है। तथापि, इससे घरेलू उद्योग पर हुए प्रतिकूल कीमत प्रभाव का समाधान नहीं हुआ है।
- ii. चीन से कम कीमत के पाटित और सब्सिडीयुक्त आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग को उसके द्वारा बेची गई मात्रा के लिए तर्कसंगत कीमत मिलती। यदि आधार वर्ष में प्रचलित मांग का स्तर आधार रूप में लिया जाए और तब लाभप्रदता निर्धारित की जाए तो विश्लेषण से पता चलेगा कि घरेलू उद्योग को तब भी लाभ, नकद प्रवाह, और निवेश पर आय जैसे मापदंडों के संबंध में नुकसान हुआ है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति कम कीमत वाले पाटित और सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई है।
- iii. घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में समग्ररूप से गिरावट आई है जबकि चीन के आयातों का बाजार हिस्सा बड़ा है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रतिकूल मात्रा प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री को ऐसी स्थिति में निर्धारित करने जबकि घरेलू उद्योग के पास आधार वर्ष के समान ही बाजार हिस्सा होता। यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्रियां उनके तत्कालीन स्तर से काफी अधिक होती। उत्पादन और बिक्री में यह घाटा भारत में कम कीमत के आयातों के कारण हुआ है।
- iv. नियोजित प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। याचिकाकर्ता भारत में और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उत्पादन करता है और अनेक उपभोक्ताओं को बिक्री करता है। संभार तंत्र के अक्षम होने या उसके अधिक समय लेने की कोई समस्या नहीं है। वास्तव में, इस उद्योग में मशीन प्रचालनों की विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उतराई काफी आम बात है और उससे लागतों या डिलिवरी समय में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- v. सीवीडी को लागू करना जनहित में होगा और उसका प्रभाव तीन अलग-अलग पक्षों- उत्पादक, उपभोक्ता और आम जनता – के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सरकार को वृहत्तर जनहित में कास्टिंग उद्योग के लिए समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा प्रदान करनी चाहिए।
- vi. स्वतः आवेदन से संबंधित प्रावधान स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं जाँच की शुरुआत कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बताए गए/भरोसा किए गए परंतु अन्यथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध साक्ष्यों पर भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार यदि याचिकाकर्ता ने अन्य जाँचकर्ता प्राधिकारियों के निर्णय का उल्लेख नहीं किया है तो भी प्राधिकारी याचिका में अन्यथा उपलब्ध साक्ष्यों का संज्ञान ले सकते हैं और जाँच की कार्यवाही कर सकते हैं। याचिका में जाँच शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, साक्ष्यों की मात्रा और गुणवत्ता जाँच की प्रगति में सुधार करती है।
- vii. वर्तमान मामले में, याचिका में अभिज्ञात 44 स्कीमों में से 36 'राज्य अर्थात् केन्द्र सरकार (एमओएफसीओएम एंड एमओसी), प्रादेशिक सरकार और कराधान के राज्य प्रशासन' द्वारा प्रशासित होती हैं और इसलिए निर्विवाद रूप से सरकारी निकाय की श्रेणी में आती है और डब्ल्यू टी ओ का निर्णय इन स्कीमों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, ऐसी 8 स्कीमों जिनमें याचिकाकर्ता ने एसओई की संबद्धता/लिप्तता की पहचान की है याचिकाकर्ता अनुरोध करता है कि केवल यह तथ्य कि डब्ल्यू टीओ ने मान है कि उन मामलों में एसओई को पर्याप्त जाँच किए बिना गलत ढंग से सरकारी निकाय माना गया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि ये निकाय वर्तमान मामले में भी सरकारी निकाय बनेंगे। इसका अर्थ केवल उचित जाँच है और याचिकाकर्ता ऐसी किसी उचित जाँच के विरुद्ध नहीं है।
- viii. इस बात को देखते हुए गुणवत्ता कोई मुद्दा नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद समस्त निर्धारित मानकों को पूरा करता है। वास्तव में, एक ग्राहक ने क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता से अपनी जरूरत के थोड़े से हिस्से को ही खरीदा और याचिकाकर्ता के कीमत कम करने पर अब याचिकाकर्ता से भारी मात्रा में खरीद को बढ़ा दिया जो सिद्ध करता है कि आर्डर नहीं देने में उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता और डिलिवरी समय कोई बाधा नहीं है। प्राधिकारी को यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी को दिए गए आर्डरों के लिए सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सका। यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई कास्टिंग को गुणवत्ता संबंधी समस्या के कारण अस्वीकार करना पड़ा।

- ix. संबद्ध देश से आयात सब्सिडीप्राप्त कीमतों पर किए गए और उनमें समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- x. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मूल्य और मात्रा, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह और बाजार हिस्से की दृष्टि से विकृति आई है।
- xi. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है। इसके अलावा, आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं।
- xii. घरेलू बाजार में काफी हिस्सा पहले की सब्सिडी प्राप्त आयातों का है और यह हिस्सा बढ़ रहा है।
- xiii. घरेलू उद्योग के पास देश में वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- xiv. घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों के बीच काफी अंतर है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने काफी बिक्री मात्राएं गवां दी हैं। इस प्रकार, भारत में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने बिक्री मात्राएं गवां दी हैं जो संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- xv. आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमतों में बुरी तरह से कटौती कर रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा है।
- xvi. लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में नुकसान सब्सिडी प्राप्त आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- xvii. संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा घटा है।
- xviii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सब्सिडीप्राप्त आयातों की मौजूदगी के कारण नुकसान हुआ है।
- xix. घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक हो गई है।
- xx. घरेलू उद्योग जाँच अवधि के दौरान काफी ऋणात्मक लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय को खो रहा है।
- xxi. संबद्ध देश से आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है। आयातों में भारी वृद्धि हुई है। कीमत कटौती काफी अधिक है। आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं कि आग और आयात होने की पूरी संभावना है। घरेलू बाजार का काफी हिस्सा पहले ही सब्सिडीप्राप्त आयातों के पास है और यह हिस्सा बढ़ रहा है।

## ज.2. जीओसी/उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितपक्षों के अनुरोध

110. जीओसी और एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक ने क्षति के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है। परंतु, आयातकों और आईडब्ल्यूटीएमए ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- i. सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति या क्षति के खतरे के अलावा, प्राधिकारी के लिए ऐसे अन्य कारकों की जाँच करना भी अपेक्षित है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ii. यह सुझाव देना गलत है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट कथित सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण आई है। 2012-13 और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट मांग में गिरावट जो सरकार द्वारा लाभों को वापस लिए जाने के कारण आई थी, का प्रत्यक्ष परिणाम था।
- iii. घटती हुई मांग की स्थिति में, जब उत्पाद पर प्रीमियम नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे उत्पाद की कीमतें निश्चित रूप से कम होंगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह दावा कि कीमतों में यह कमी आयातों के कारण हुई है पूर्णतः गलत है।
- iv. इसके अलावा, मांग में कमी के कारण संबद्ध वस्तु के उत्पादन में पिछले 4 वर्षों के दौरान भारी कमी आई है। उत्पादन में इस गिरावट के लिए आयातों को दोष नहीं दिया जा सकता है।
- v. इसी प्रकार, भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट मांग में कमी के कारण हुई है और न कि आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण।
- vi. घटती हुई मांग के साथ घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करनी पड़ी है। भारत में संबंधित उत्पाद में मंदी के रुझान के लिए आयातों को दोष नहीं दिया जा सकता है।

- vii. संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बीच कोई संबंध नहीं है। 2011-12 और 2012-13 के बीच, जब चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा में कमी आई और आयात कीमतों में भारी वृद्धि हुई तो इकाई घाटा, नकद घाटा और पीबीआईटी के अनुसार घरेलू उद्योग के घाटों में भी काफी वृद्धि हुई। इसी प्रकार 2012-13 और पीओआई के बीच जब आयातों में आयात कीमतों में गिरावट के साथ वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ था। घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई कोई भी क्षति अन्य कारकों के कारण हुई है और न कि कथित सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण।
- viii. चीन जन. गण. से आयातों के कारण याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा प्रभावित नहीं हुआ है। 2011-12 और 2012-13 की तुलना में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में पीओआई के दौरान वास्तव में सुधार हुआ है।
- ix. याचिकाकर्ता ने अद्यतन अवधि के लिए कीमत कटौती तालिका उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया कीमत कटौती विश्लेषण विश्वसनीय नहीं है।
- x. अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न कंपनियां विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस कास्टिंग की लागत में भी भारी अंतर होता है। इस प्रकार, तकनीकी अंतर पर भी प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

### अ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

111. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, और संबद्ध देश से सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण क्षति की जाँच की है।

112. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 13(1) के अनुसार:

*'13. क्षति का निर्धारण – (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह भी निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है या उसका खतरा है, या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा हुई है।'*

113. 2006 में यथा संशोधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली, 1995 का अनुबंध 1 क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है। अनुबंध के पैराग्राफ 1(1), (2) और (3) का पाठ निम्नानुसार है:

*'1. (1) नियम 13 के प्रयोजनार्थ क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगा और उसमें इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी (क) सब्सिडीप्राप्त आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव।'*

*(2) सब्सिडीप्राप्त आयातों की मात्रा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार करेंगे कि क्या सब्सिडीप्राप्त आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।*

*(3) कीमतों पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान वस्तु की तुलना में सब्सिडीप्राप्त आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों से कीमत में पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।*

114. नियमावली के अनुबंध 1 का पैरा 1 (5) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित किए जाने वाले संगत आर्थिक मापदंडों को सूचीबद्ध करता है:

*'(5) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव की जाँच करते समय उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन करेंगे जिसमें उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, उत्पादकता, निवेश पर आय, या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता की जाँच शामिल होगी और कृषि के मामले में क्या सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों पर बोझ बढ़ा है।'*

115. यह सच हो सकता है कि अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न कंपनियां विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करती हैं, परंतु इससे सब्सिडी और घरेलू उद्योग पर उसके क्षतिकारी प्रभाव के मुद्दे का समाधान नहीं होता है। प्रौद्योगिकी में अंतर उत्पाद को अलग नहीं बनाता है।

116. भारत में घरेलू उद्योग पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भण्डार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर संबंधित नियम के अनुबंधों के अनुसार विचार किया गया है।

#### **क) घरेलू उद्योग पर सब्सिडीप्राप्त आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**

##### **मांग और बाजार हिस्सा**

117. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। आधार वर्ष से वर्ष 2012-13 तक मांग में कुछ गिरावट आई थी। तथापि, पीओआई में मांग में वृद्धि हुई और वह तर्कसंगत स्तर पर रहने के लिए पर्याप्त थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का परिकलन परियोजना संकल्पना स्तर पर अनुमानित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर 2012-13 के दौरान 82.40 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर आधारित है। इसमें घरेलू उद्योग द्वारा निरंतर कम क्षमता उपयोग पर ध्यान दिया गया है। कास्टिंग को अब केवल एल एंड टी (सीएमयू) के कोयम्बटूर संयंत्र में ही बनाया जाता है। तथापि, नीचे दिए गए उत्पादन के आंकड़े समग्र रूप से कंपनी के लिए हैं:

मांग	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
घरेलू उद्योग की बिक्रियां (एलएंडटी की सीएमयू और केबीएल)	एमटी	14,122	8,079	5,133	6,888
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	7,310	7,368	3,076	3,364
संबद्ध देश – आयात	एमटी	4,486	15,117	10,430	14,245
अन्य देश-आयात	एमटी	591	1,661	502	214
कुल मांग/खपत	एमटी	26,509	32,225	19,141	24,711

पीओआई\*-अक्टू. 2012- दिस. 2013 (15 महीने)

##### **समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात मात्रा**

118. सब्सिडीप्राप्त कीमतों पर संबद्ध देश से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। सब्सिडीप्राप्त आयात आधार वर्ष से वर्ष 2011-12 में बढ़े हैं। यद्यपि आयातों में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई है तथापि पीओआई में उनमें पुनः वृद्धि हुई है। चीन और अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:-

आयात-मात्रा	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
चीन	एमटी	4,486	15,117	10,430	14,245
अन्य देश	एमटी	591	1,661	502	214
कुल आयात	एमटी	5,077	16,778	10,932	14,459

पीओआई\*-अक्टू. 2012- दिस. 2013 (15 महीने)

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में 4486 एमटी के आस-पास थे जो जाँच अवधि में बढ़कर 14,245 एमटी से अधिक हो गए। वार्षिकीकृत आंकड़े दर्शाएँ।

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों में भारत में उत्पाद के आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
आयात मात्रा					
चीन	एमटी	4,486	15,117	10,430	14,245
अन्य देश	एमटी	591	1,661	502	214
कुल आयात	एमटी	5,077	16,778	10,932	14,459
आयातों का बाजार हिस्सा-मात्रा आधार					
चीन	%	88%	90%	95%	99%
अन्य देश	%	12%	10%	5%	1%

पीओआई\*-अक्टू. 2012- दिस. 2013 (15 महीने)

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
चीन	%	17	47	54	58
अन्य देश	%	2	5	3	1
घरेलू उद्योग	%	53	25	27	28
अन्य भारतीय उत्पादक	%	28	23	16	14
भारतीय उत्पादन	एमटी	23,327	17,291	8,650	11,261
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश के आयात	%	19	87	121	126

पीओआई\*-अक्टू. 2012- दिस. 2013 (15 महीने)

122. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से सब्सिडीप्राप्त आयातों के हिस्से में क्षति अवधि में वस्तुतः वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु की मांग को अकेले पूरा कर सकता है। तथापि, याचिकाकर्ता चीन जन. गण. से सब्सिडीप्राप्त आयातों की मौजूदगी के कारण ऐसा नहीं कर सका है।

#### i. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

123. जहां तक कीमतों पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव का संबंध है प्राधिकारी, ने इस बात पर विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडीप्राप्त आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से कीमत में पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सीओपी), भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पंहच लागत के साथ की गई है।

124. कीमत कटौती का परिकलन इस अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के तुलनीय प्रकार के भारत में घरेलू बिक्री कीमत के साथ निर्यात कीमत की तुलना करके किया गया है। निवल बिक्री प्राप्ति को बाह्य भाड़े और करों की कटौती करने के बाद ज्ञात किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न उपभोक्ताओं को बेचे गए उत्पाद की लागत और कीमत में भारी अंतर को देखते हुए, कीमत कटौती को तुलनीय उत्पाद प्रकारों पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।

**i. कीमत कटौती**

125. निवल बिक्री प्राप्ति को बाहरी मालभाड़े और करों को घटाकर ज्ञात किया गया है। आयातों का पहुंच मूल्य की गणना 1 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार और संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य में लागू उपकर को शामिल करके लागू मूल सीमाशुल्क को जोड़कर की गई है। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई है और यह पाया गया है कि जॉच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती काफी अधिक रही है।

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
<b>संबद्ध देश</b>					
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./एमटी	88520	94416	115836	120662
रूझान	सूचीबद्ध	100	107	131	136
निवल बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
रूझान	सूचीबद्ध	100	114	101	97
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	%	40-50	50-60	10-20	0-10

**ii. कम कीमत पर बिक्री**

126. पी सी एन वार क्षतिरहित कीमत की गणना की गई और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री को ज्ञात करने के लिए संगत समान वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की गई। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण डीजीएडी में मानक प्रक्रिया के अनुसार पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि जॉच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.
क्षतिरहित कीमत	रूएमटी/.	***
पहुंच मूल्य (पीओआई)	रूएमटी/.	***
कम कीमत पर बिक्री	रूएमटी/.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	15-25

**iii. कीमत न्यूनीकरण/हास**

127. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या क्या सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव के कारण भारत में समान वस्तु की कीमतों हास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।

मापदंड	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
बिक्री लागत - घरेलू	रू./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	137	157	128

बिक्री कीमत - घरेलू	रू./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	101	97
पंहुच कीमत	रू./एमटी	88520	94416	115836	120662
	सूचीबद्ध	100	107	131	136

पीओआई\*-अक्टू: 2012- दिस: 2013

128. उक्त तालिका से पता चलता है कि बिक्रियों की भारित औसत लागत क्षति अवधि के दौरान लगातार बिक्री कीमत से अधिक रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीओआई में बिक्री कीमत लगभग आधार वर्ष की कीमत के समान स्तर पर ही रही है यद्यपि पीओआई में बिक्री लागत में आधार वर्ष में 100 आधार बिन्दुओं की तुलना में 128 आधार बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण कीमतें कम रही थी और घरेलू उद्योग लागतों में बढ़ोतरी के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं पाया था। सब्सिडीप्राप्त आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी ह्रासकारी प्रभाव भी डाला था।

129. इस प्रकार घरेलू उद्योग पर सब्सिडीप्राप्त आयातों का प्रभाव प्रतिकूल और काफी अधिक रहा है।

### घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

130. एएससीएम के अनुच्छेद 15.4 में इस प्रकार व्यवस्था है:

‘घरेलू उद्योग पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा जिसमें उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, उत्पादकता, निवेश पर आय, या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी या निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों की जाँच शामिल होगी और कृषि के मामले में क्या सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों पर बोझ बढ़ा है। यह सूची विस्तृत नहीं है और न ही इनमें से एक या अनेक कारकों से आवश्यक रूप से निर्णायक मार्गदर्शन मिल सकता है।’

131. नियमावली के अनुबंध 1 (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित किए जाने वाले संगत आर्थिक कारकों को सूचीबद्ध किया गया है:

‘निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर सब्सिडीप्राप्त आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन करेंगे जिसमें उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, उत्पादकता, निवेश पर आय, या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी या निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों की जाँच शामिल होगी और कृषि के मामले में क्या सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों पर बोझ बढ़ा है।’

### 1) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

132. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में क्षति अवधि के दौरान (सीएमयू इकाई) घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

आर्थिक मापदंड	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
क्षमता	एमटी	30,000	30,000	30,000	37,500
उत्पादन - पीयूसी	एमटी	11,305	7,751	4,984	7,897
उत्पादन - अन्य	एमटी	-	156	848	780
संयंत्र का उत्पादन	एमटी	11,305	7,907	5,832	8,678
क्षमता उपयोग	%	38	26	17	21

संयंत्र उपयोग	%	38	26	19	23
बिक्री मात्रा – घरेलू	एमटी	9,410	5,907	4,543	6,888
	सूचीबद्ध	100	63	48	73

पीओआई\*-अक्टू. 2012- दिस. 2013

यहां यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का परिकलन परियोजना संकल्पना स्तर पर अनुमानित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर 2012-13 के दौरान 82.40 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर आधारित है। इसमें घरेलू उद्योग द्वारा निरंतर कम क्षमता उपयोग पर ध्यान दिया गया है। कास्टिंग को अब केवल एल एंड टी (सीएमयू) के कोयम्बटूर संयंत्र में ही बनाया जाता है। तथापि, नीचे दिए गए उत्पादन के आंकड़े समग्र रूप से कंपनी के लिए हैं।

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अकेले घरेलू उद्योग के पास ही देश में उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में पूरी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। उत्पादन में यह गिरावट देश में पर्याप्त मांग के बावजूद हुई है।

134. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। चूंकि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए उत्पादन सुविधाओं का उपयोग कर रहा है इसलिए प्राधिकारी ने अन्य उत्पादों के उत्पादन को भी शामिल करके क्षमता उपयोग को निर्धारित किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक हितबद्ध पक्ष ने यह दलील दी है कि घरेलू उद्योग वांछित मात्राओं में उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति नहीं कर सकता है और वह अन्य उत्पाद का भी उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी ने मौके पर सत्यापन के समय घरेलू उद्योग के रिकार्डों की विपश्ये रूप से जाँच की है और यह पाया कि वस्तुतः याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त क्षमताएं हैं और उसे भारी अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ रहा है।

135. प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।

136. यहां मांग के परिदृश्य पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

## 2) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

137. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग (सीएमयू) की स्थिति निम्नानुसार है:

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
बिक्री लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	140	158	138
बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	104	100
लाभ/(हानि)	रू./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(5)	(159)	(79)
लाभ/(हानि)	रू./लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(3)	(77)	(46)
नकद लाभ	रू./लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	30	(21)	1
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(3)	(105)	(75)



पीओआई-अक्टू. 2012- दिस. 2013

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को 2012-13 और पीओआई के दौरान भारी वित्तीय घाटा झेलना पड़ा है। नकद लाभों में भी लाभों के समान ही प्रवृत्ति रही है। घरेलू उद्योग को 2012-13 और पीओआई के दौरान भारी नकद घाटा झेलना पड़ा है।

139. निवेश पर आय में भी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के समान ही रुझान प्रदर्शित हुआ है। घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान निवेश पर भारी ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

### 3) लाभप्रदता

140. प्रतिदिन उत्पादन के अनुसार मापी गई उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन में गिरावट के कारण विकृति आई है।

मापदंड	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
उत्पादकता प्रतिदिन	दिन/एमटी	53	38	24	20
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (सीएमयू)	एमटी/ व्यक्ति	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	49	73

पीओआई-अक्टू. 2012- दिस. 2013

### 4) मालसूचियां

141. संबद्ध वस्तु आर्डर के अनुसार निर्मित 'उत्पाद' हैं। इस प्रकार मालसूची का मापदंड क्षति के मूल्यांकन के लिए उचित मापदंड नहीं है।

### 5) रोजगार और मजदूरी

142. प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन श्रम-प्रधान है। प्रदत्त मजदूरी में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित हुई है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि देश के श्रम कानूनों को देखते हुए कर्मचारियों को काम पर रखना और हटाना अपनाया जाने वाला अंतिम विकल्प है।

मापदंड	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई*
मजदूरी (सीएमयू)	रू./लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	52	61
रोजगार (सीएमयू)	सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	105	105

पीओआई-अक्टू. 2012- दिस. 2013

### 6) वृद्धि

143. मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है।

### 7) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

144. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति को देखते हुए जहां संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण उसका कार्यनिष्पादन खराब हो रहा है, तो भारी पाये निवेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। घरेलू उद्योग के पास पहले ही काफी क्षमता मौजूद है और उसका काफी हिस्सा बेकार पड़ा है।

### 8) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

145. घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, लागत संरचना में बदलाव, संबद्ध देशों से आयात कीमतों, सब्सिडी प्राप्त आयातों के अलावा अन्य कारक जिनकी वजह से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं, आदि की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से

आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम रहा है, जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और इसलिए वह घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देशों से पाटित संबद्ध वस्तु का आयात पहुंच मूल्य है।

### 9) वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

146. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में विकृति आई है, जिसका सारांश नीचे दिया गया है:

क) संबद्ध देश से सब्सिडीप्राप्त आयातों में समग्र रूप से और भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ख) सब्सिडीप्राप्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं।

ग) सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और उसका ह्रास कर रहे हैं। कोई सहसंबंध ज्ञात नहीं हुआ है।

घ) घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मूल्य और मात्रा, लाभ, निवेशों पर आय, नकद प्रवाह और बाजार हिस्से के संबंध में विकृति आई है।

### ट. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

#### ट.1. घरेलू उद्योग के विचार

147. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- चीन के आयातों ने काफी अधिक बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसलिए, मांग में कमी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्य कारण नहीं है।
- घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति चीन जन. गण. से सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा अपनायी जा रही प्रौद्योगिकी से तुलनीय है। विनिर्माण प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। बाजार में सब्सिडीप्राप्त आयातों की उपलब्धता घरेलू उद्योग को हो रही वर्तमान क्षति का प्रमुख कारक है।

148. घरेलू उद्योग को क्षति सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण हुई है। इसके अलावा अन्य कारकों के कारण क्षति, यदि कोई हो, को याचिकाकर्ता द्वारा नीचे दिए गए व्योरे के अनुसार अलग किया गया है।

क) मांग में कमी अथवा खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन: प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान करीब 25 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार अंश में करीब 61 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बाजार अंश में करीब 154 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह पता चलता है कि मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई बड़ी क्षति के लिए प्रमुख कारक नहीं है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा:

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं रही हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ग) प्रौद्योगिकी में विकास: उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारण नहीं है।

घ) निर्यात कार्यनिष्पादन: याचिकाकर्ता के पास विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं है। फिर भी प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर विचार किया है।

ङ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन : घरेलू उद्योग की दावा की गई क्षति विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में है।

149. एक बार यह दर्शाने के बाद कि क) सब्सिडीप्राप्त आयातों से प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव पड़ा है और ख) सब्सिडीप्राप्त आयातों द्वारा हुई क्षति के प्रभाव अनुबंध। के पैराग्राफ 1(5) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दर्शाए गए हैं, तब इस निष्कर्ष का एकमात्र आधार यह है कि क्षति गैर-उत्तरदायी विश्लेषण अर्थात् उन अन्य कारकों ने क्षति पहुंचाई है, के माध्यम से सब्सिडीप्राप्त आयातों द्वारा क्षति नहीं हुई है।

150. जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दर्शाया गया है सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि क्षति उन अन्य कारकों के कारण हुई है। ऐसे मामले में एकमात्र अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति मुख्यतः संबद्ध देश से सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण हुई है।

151 निम्नलिखित मापदंड कारणात्मक संबंध सिद्ध करते हैं और यह दर्शाते हैं घरेलू उद्योग को क्षति सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण हुई है:

- i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित और विदेशी उत्पादकों की कीमतों के बीच भारी अंतर है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बिक्री मात्रात्मक क्षति हुई है। इस प्रकार भारत में पर्याप्त मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग ने बिक्री मात्राओं को गंवाया है जो संबद्ध देश से सब्सिडीप्राप्त आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- ii. आयातित उत्पाद से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमतों में कमी करने को बाध्य होना पड़ा है।
- iii. लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में कमी प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण हुई है।
- iv. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है। इसके सीधे परिणाम के रूप में भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा कम हुआ है।
- v. सब्सिडीप्राप्त आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में विकृति आई है।
- vi. घरेलू उद्योग का विकास अनेक मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक रहा है।

#### **ठ. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा**

152. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए पी सी एन वार क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के लिए यथा निर्धारित पी सी एन वार क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से निर्यातों के अनुरूपी पी सी एन वार पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

विवरण	मै. झेजियांग जिआली विंड पावर टेक्नालॉजी कंपनी लि.	असहयोगी निर्यातक
क्षतिरहित कीमत - ₹./एमटी	***	***
पहुंच मूल्य - ₹./एमटी	***	***
क्षति मार्जिन - ₹./एमटी	***	***
क्षति मार्जिन - लदान मूल्य का %	***	***
क्षति मार्जिन रेंज %	5-15	15-25

#### **ड. प्रकटन के बाद की टिप्पणियां**

153. घरेलू उद्योग, जीओसी और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

##### **घरेलू उद्योग द्वारा पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां**

- i. आर्थिक सहायता जांच संबद्ध एवं मूल कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभों के लिए बढ़ाई गई थी। मूल कंपनी द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के संबंध में सीवीडी मार्जिन में विचार और शामिल किया जाना अपेक्षित है। जियाली टैक्नोलॉजी कंपनी (मूल कंपनी) को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है और उनके द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के संबंध में उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार जियाली विंड पावर पूरा सहयोग करने में विफल रहा और प्राधिकारी बेहतर उपलब्ध सूचना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।

- ii. याचिकाकर्ता सभी निर्यातकों को अभिचिन्हित करने के लिए सांविधिक बाध्यता के अधीन नहीं है और डीए को अभी ज्ञात निर्यातकों को जांच शुरू करने की अधिसूचना की प्रति भेजनी थी, न ही व्यक्तिक निर्यातकों से सूचना प्राप्त करनी थी। यूएस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीओआई को यह सुनिश्चित करना है कि पीयूसी के सभी संबंधित निर्यातकताओं को प्रभावली भेजी गई है।
- iii. दावे के साथ यह कहते हुए कि कई योजनाएं अब लागू नहीं है अथवा कार्यक्रम को समाप्त करना जीओसी द्वारा संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों का समर्थन नहीं करता, जीओसी को गैर-सहयोगी प्रमाणित किया जाना है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कार्यक्रम का नाम बदल गया हो अथवा उसी लक्ष्य समूह को लक्षित करते हुए उन्हीं लाभों सहित पुराने कार्यक्रम को अलग नामपद्धति से प्रतिस्थापित कर दिया हो। डीआई ने पहले प्रमाणित किया है कि ऐसी और भी योजनाएं/कार्यक्रम हैं जो सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्राप्त किए जा रहे लाभ अथवा पीआर चीन में मौजूद आर्थिक सहायता योजनाओं के रूप में जीओसी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। जीओसी ने चीन सरकार अथवा प्रतिक्रिया करने वाले चाइनीज निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं/साक्ष्यों की ऑन-द-स्पॉट जांच की सहमति नहीं दी। इस प्रकार गैर-सहयोग सिद्ध करता है।
- iv. जियाली विंड ने यह कहा कि घरेलू बाजार में कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुएं और भारत को निर्यातित वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय हैं और समान वस्तु है।
- v. प्रतिक्रिया करने वाली निर्यातक चीन में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक नहीं हैं और प्राप्त लाभ एकमात्र प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातक तक प्रतिबंधित/सीमित नहीं है। आयात आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संगत अवधि के दौरान काफी निर्यातक कंपनियों द्वारा निर्यात किया जा रहा है।
- vi. जियाली विंड ने कभी भी प्राप्त विभिन्न अनुदानों और जारी किए गए प्रमाण-पत्रों और सहायक कंपनियों के साथ-साथ मूल कंपनी की वेबसाइटों पर विजिबल के संबंध में विरोधाभास की प्रतिक्रिया नहीं की है।
- vii. विभिन्न योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभों के उत्तर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातकर्ता गैर-सहयोगी रहे हैं और इससे जियाली विंड प्राधिकारी को पूरा सहयोग नहीं दे पायी।
- viii. पीयूसी विंड ऑपरेटिड इलैक्ट्रिसिटी जेनरेटर के लिए कास्टिंग जिसे विंडमिल अथवा विंड टरबाइन या मशीन नहीं के नाम से भी जाना जाता है, कच्ची, फिनिस्ड अथवा सब-असेम्बलड रूप में अथवा सब-असेम्बली के रूप में अथवा किसी उपकरण/कम्पोनेन्ट के एक भाग के रूप में विंड ऑपरेटिड इलैक्ट्रिसिटी जेनरेटर से अभिप्राय है। विंडमिल में प्रयोग होने वाली कुछ सब-असेम्बलीज में गियर बॉक्स, नेस्ले असेम्बली और हब पिच असेम्बली है। इन सब-असेम्बलीज में कास्टिंग और अन्य कम्पोनेन्ट शामिल है। उदाहरण के तौर पर नेस्ले असेम्बली में बेस फ्रेम, गियर बॉक्स शामिल है जिसमें प्लेटेड कैरियर, हाउसिंग, टार्क आर्म, हब असेम्बली जिसमें रोटार हब/हब और पिच सिस्टम शामिल है।
- ix. उपभोक्ता के पास विकल्प उपलब्ध है कि वह कोई कास्टिंग और अन्य मेटिंग पार्ट पृथक-पृथक और अपने स्थान पर असेम्बल करता है अथवा इसके स्थान पर सब-असेम्बलड उत्पाद खरीदता है। सब-असेम्बली तैयार करने में शामिल प्रचालनों में लगभग स्कू ड्राइवर टैक्रोलॉजी और प्रयासों में किए जा रहे समग्र प्रचालों के अनुपात में काफी कम है। कास्टिंग और अन्य उत्पाद पृथक-पृथक खरीदने के स्थान पर सब-असेम्बलड उत्पाद खरीदना किसी सम्भावित उपभोक्ता के लिए व्यवहार्य है।
- x. यदि विचाराधीन उत्पाद में सब-असेम्बलीज शामिल नहीं होती तो इससे कोई भी व्यापार रक्षा उपाय करने का प्रयोजन ही विफल हो जाता है और प्रस्तावित उपायों के कार्यक्षेत्र के भीतर कास्टिंग को रखने मात्र के कारण सम्पूर्ण सब-असेम्बलियों के लिए पीयूसी के कार्यक्षेत्र में नहीं बदला जा सकता। सीवीडी उपाय, यदि कोई हो, के कार्यक्षेत्र के बने रहने तक सब-असेम्बलीज को पीयूसी के कार्यक्षेत्र में मानना उचित है। इसलिए यह सब-असेम्बलीज के कास्टिंग भाग तक सीमित है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में इस कार्य क्षेत्र की पुष्टि करे।
- xi. चूंकि पीयूसी को उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अलावा सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित किया गया है। इसलिए डीए शुल्क तालिका में यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि आयातकर्ताओं द्वारा स्वीकृत की जा रही वस्तुओं के तहत सीमा शुल्क वर्गीकरण का ध्यान रखे बिना पीयूसी शुल्क लगाया जाना चाहिए। केवल शुल्क तालिका की विषयवस्तु इससे संबंधित है। पीयूसी से संबंधित पैरे में उल्लिखित कुछ भी परन्तु शुल्क तालिका में उल्लिखित नहीं, की वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते समय उपेक्षा की जा सकती है।
- xii. इसके अतिरिक्त, पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर विचार और विश्वास करता है। सीमा शुल्क प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संज्ञान में नहीं लेते। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सीमा शुल्क तालिका में ही ये सभी स्पष्टीकरण शामिल हैं।
- xiii. डीआई द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं नियमावली की शर्तों के अनुसार चीन आयातित पीयूसी के लिए समान वस्तु है। विंडमिल उत्पादकों के डिजाइन और क्षमता पर निर्भर करते हुए उत्पाद डिजाइन और मॉडल विशिष्ट है। तथापि,

घरेलू उत्पादक और निर्यातक दोनों भारत में उन्हीं विंडमिल उत्पादकों को आपूर्ति करते हैं। जियाली विंड ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा बेची गई वस्तुएं और भारत को निर्यात की गई वस्तुएं सीधे तुलनीय हैं और वास्तविक एवं तकनीकी विशेषताओं में भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की गई और स्वदेशी बाजार में बेची गई वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है।

- xiv. लार्सन और टुब्रो द्वारा याचिका दायर की गई थी। मैसर्स पटेल एलायज ने याचिका का समर्थन किया है। पीओआई में भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता बहुत बड़े अनुपात में कमांड करता है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड नियमावली 2(ख) के प्रयोजन के भीतर पात्र डीआई है और याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में बड़े अनुपात है।
- xv. वर्तमान मामले में आईडब्ल्यूटीएमए ने जांच के बाद के चरण में स्वयं को डीए के समक्ष प्रस्तुत किया है।
- xvi. अब भारत में निर्धारित कानून है कि डब्ल्यूटीओ करार सीधे डीए के लिए लागू होता है। वास्तविकता यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का मत है कि डीए डब्ल्यूटीओ प्रावधानों और उसके निर्णयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। रिलायंस के मामले में सेरामिक टाइलों से संबंधित मामले में डीए के निर्णय के साथ-साथ डब्ल्यूटीओ के उपरोक्त निर्णय को रखा गया है।
- xvii. जहां तक वर्तमान जांच के पूरा होने के लिए बचे समग्र समय पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात नई सब्सिडी को जांच में शामिल न करने का संबंध है, यह कहा जाता है कि इसे यह तथ्य कम नहीं होता कि चीन सरकार ने अहसयोग किया है और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रश्नावली में विशिष्ट सूचना मांगने के बावजूद चीन में विद्यमान इन आर्थिक सहायता योजनाओं के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- xviii. अभिज्ञात 44 योजनाओं में से 37 कार्यक्रम उन निकायों, जो राज्य की श्रेणी के भीतर आते हैं, द्वारा प्रशासित किए जाते हैं (जीओसी, चीन में प्रान्तीय, नगर निगम, स्थानीय निकाय)। याचिकाकर्ता द्वारा केवल 7 कार्यक्रम अभिचिन्हित किए गए हैं जो एसओई द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं। यह प्रमाणित करने के लिए याचिकाकर्ता ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि ये प्रशासक प्राधिकारी कानून के प्रयोजन के भीतर सार्वजनिक निकाय है।
- xix. लाभ की मात्रा के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता ने 12 नवंबर, 2015 के पत्र के तहत 22 योजनाएं वापिस ले ली हैं। ये योजनाएं उन अन्य जांच प्राधिकारियों, जो वर्तमान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से स्वीकार की गई हैं, द्वारा प्रति संतुलनकारी मानी गई हैं।
- xx. जियाली विंड और इसकी मूल कंपनी की वेबसाइट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कंपनी को विभिन्न अनुदान प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई अनुदान एकबारगी अनुदान स्वरूप की नहीं है। वास्तविकता यह है कि जियाली विंड ये अनुदान बार-बार प्राप्त कर रहा है और ये अनुदान नियमित स्वरूप के अनुदान हैं।
- xxi. डीए कृपया यह मत रखे कि निर्यातकों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि इन कार्यक्रम के तहत लाभ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल को फैलाया जाना अपेक्षित है।
- xxii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में निरपेक्ष रूप से संबद्ध देश से आर्थिक सहायता प्राप्त आयात में वृद्धि हुई है। आर्थिक सहायता प्राप्त आयात, घरेलू उद्योग की कम दाम कीमत है। आयात बाजार में डीआई की कीमतों को कम कर रहा है। उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा और मात्रा, लाभ, निवेश पर प्रतिफल, नकद प्रवाह और बाजार हिस्से की दृष्टि से डीआई का निष्पादन खराब हुआ है। वर्तमान पीओआई में आर्थिक सहायता मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों धनात्मक और पर्याप्त हैं। आर्थिक सहायतारोधी/काउंटरवेलेबल शुल्क नहीं लगाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा क्षति वहन करने की सम्भावना है।
- xxiii. एनआईपी ने याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया है। तथापि, यह देखा गया है कि डीए द्वारा आवंटन/विभाजन बदल दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि पद्धति का यह परिवर्तन अनुपयुक्त है।
- xxiv. यथामूल्य आधार पर शुल्क लगाया जा सकता है क्योंकि पीयूसी बहुत किस्म के उत्पादों में शामिल है जिनकी कीमतें काफी भिन्न-भिन्न हैं।

#### **जीओसी द्वारा पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां**

- i. वर्तमान आर्थिक सहायता रोधी जांच तुच्छ एवं निराधार मुकदमें और एएससीएम में निर्धारित कानूनी अपेक्षाओं के विरोध में शुरू की गई थी।
- ii. 'औचित्यपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध' याचिकाकर्ता को पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए याचिकाकर्ता की बाध्यता से छूट नहीं देता है। इसके विपरीत विवरण मात्र यह उल्लेख करता है कि याचिकाकर्ता ने वह सूचना उपलब्ध कराई है जो याचिका के समर्थन में उनके

- पास औचित्यपूर्ण ढंग से उपलब्ध थी। 'पर्याप्त साक्ष्य' के संबंध में मानक अपेक्षाएं सामान्य संदर्भ में पूरी नहीं की जा सकती अथवा अन्य क्षेत्राधिकार द्वारा दिए गए विकर्ष परिणामों की नकल नहीं कर सकते।
- iii. परामर्श करके, प्रश्नावली के उत्तर देकर, स्पष्ट स्पष्टीकरणों सहित साक्ष्य उपलब्ध कराकर, कमी वाले दो पत्रों का उत्तर देकर, सुनवाई करके, ऑन द स्पॉट आगे स्पष्टीकरणों से संबंधित जीओआई के साथ पत्र व्यवहार करके जीओसी ने अपनी बेहतर क्षमता से भारत सरकार के साथ सहयोग करने का प्रयास किया है।
- iv. स्पष्टीकरण विवरण में उल्लेख है कि प्रतिक्रिया करने वाले अकेले चाइनीज उत्पादक/निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/सूचना की स्पॉट जांच करने के लिए चीन का दौरा करने के लिए जीओसी ने प्राधिकारी को अनुमति नहीं दी। जीओसी ने कभी भी प्रतिक्रिया करने वाले एकमात्र चाइनीज उत्पादक/निर्यातक की स्पॉट जांच करने के लिए आपत्ति नहीं की।
- v. उपलब्ध तथ्य निर्धारण करने के लिए प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। जीओसी ने वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी को आवश्यक सूचना अपनी बेहतर क्षमता से उपलब्ध कराई है। उन कार्यक्रमों जो प्रथम दृष्ट्य मामले सिद्ध करने में याचिकाकर्ता विफल रहा है उन मामलों के संबंध में सबूत का बोझ निर्दिष्ट आर्थिक सहायता के लिए सूचना को पूरा करने हेतु जीओसी को स्विच अथवा आबंटित नहीं की जानी चाहिए।
- vi. एससीएम के अनुच्छेद 12.8 की अपेक्षा है कि अंतिम निर्धारण से पूर्व अनिवार्य तथ्यों का प्रकटीकरण अवश्य किया जाए और अपने हितों की रक्षा करने के लिए पक्षों को इस प्रकार के प्रकटीकरण हेतु पर्याप्त समय दिया जाए। जीओआई ने जीओसी को कम समय दिया और अपने हितों की रक्षा करने के लिए उत्पादक को सहयोग दिया।
- vii. जीओआई ने वित्तीय योगदान, लाभ और जीओसी की विशेषता तथा सहयोग करने वाले उत्पादक के संबंध में अनिवार्य तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्दिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में लाभों की गणना करने के लिए पद्धति सही ढंग से स्पष्ट करने में जीओआई विफल रहा।
- viii. रद्द किए गए कार्यक्रमों के संबंध में जीओसी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का ध्यान रखने में प्राधिकारी विफल रहा है। इस प्रकार की जांच डब्ल्यूटीओ कानूनों के तहत जीओआई की बाध्यताओं का उल्लंघन है।
- ix. आयातित उपकरण पर प्रशुल्क और वैट छूट के लिए कार्यक्रम सं. 6 के संबंध में आर्थिक सहायता राशि की जीओआई की गणना गलत है। प्रथमतः वैट छूट 1 जनवरी, 2009 को समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिक्रिया करने वाले चाइनीज उत्पादकों ने किसी उपकरण का आयात कभी नहीं किया है।
- x. अनुदान कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता राशि की गणना उचित नहीं है। तथापि, जीओआई ने कोई औचित्य उपलब्ध कराए बिना इन कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम पहले ही रद्द कर दिए थे तथा इन कार्यक्रमों के लिए एक पैकेज के लिए आर्थिक सहायता राशि की गणना की है।
- xi. उत्पादक की मूल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में जीओआई द्वारा पाई गई आर्थिक सहायता की राशि इन निर्दिष्ट कार्यक्रमों के लिए कुछ नहीं है और जांचाधीन उत्पाद से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में, पाए गए आर्थिक सहायता कार्यक्रम तथा गणना की गई आर्थिक सहायता की राशि के बीच कोई संबंध नहीं है।
- xii. कार्यक्रम 6 और 36 एक ही कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार द्वारा दो गिने गए हैं। कार्यक्रम संख्या 6 और 36 आयातित उपकरण पर प्रशुल्क और वैट की छूट से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता ने गलती से अपनी याचिका में निश्चयपूर्वक कहा है कि यह कार्यक्रम दो भिन्न-भिन्न कार्यक्रम हैं।
- xiii. इन आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि राज्य स्वामित्व के बैंक और राज्य स्वामित्व के उद्यम सार्वजनिक निकाय हैं।

#### **झिजियांग जियाली विंड द्वारा पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां**

- i. जियाली विंड एसईजेड अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित नहीं है और जियाली विंड ने कोई आयातित सामग्री अथवा उपकरण नहीं खरीदा है, सभी आदान और पूंजीगत उपकरण चीनी बाजार से मंगाए गए हैं। अतः जियाली विंड कार्यक्रम संख्या 6 अर्थात् एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरण पर प्रशुल्क एवं मूल्यवर्धित कर (वैट) छूट (एफआईई और डीआईई दोनों के लिए) के लिए पात्र नहीं हैं।

- ii. अनुदान के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि \*\*\* आकड़ों की दोहरी गणना की गई है। इस प्रकार कुल राशि \*\*\* सही नहीं है। आरएमबी \*\*\* की राशि में सरकारी आर्थिक सहायता कुल राशि थी जो वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखितानुसार मद 18 के जरिए मद 2 से सूचीबद्ध सभी मदों में शामिल कर ली गई है।
- iii. कार्यक्रम संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 के लिए लाभ की गणना हेतु प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि इसे कार्यक्रम 8 से 17 के एक पैकेज के लिए 5.89 प्रतिशत की गणना के स्थान पर प्रत्येक निर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए लाभ की गणना करनी चाहिए।
- iv. मूल कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ जियाली विंड के लिए लागू नहीं होंगे क्योंकि वे दो स्वतंत्र कंपनियां हैं और मूल कंपनी पीयूसी में शामिल नहीं है। मूल कंपनी द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सहायता पीयूसी से संबंधित नहीं थी। इस प्रकार यह जियाली विंड को आबंटित नहीं की जानी चाहिए।
- v. कार्टिंग उद्योग के लिए अधिमानतः ऋणों और ब्याज दरों से संबंधित कार्यक्रम 20 के संबंध में जियाली विंड ने \*\*\*%-\*\*\*% की रेंज में ब्याज दर पर विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त किया था, ऋणों से इसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
- vi. कार्टिंग उद्योग के लिए अधिमानतः ऋणों और ब्याज दरों के लिए गणना आधार गलत प्रतीत होता है। यह अनुरोध किया गया है कि \*\*\* और \*\*\* ऋण की राशि नहीं थी और \*\*\*% और \*\*\*% ऋण ब्याज दर नहीं थी। ये क्रमशः परिसंपत्तियों का लेखा मूल्य और परिसंपत्तियों का % है। पीओआई के दौरान जियाली विंड ने \*\*\*%-\*\*\*% की रेंज में ब्याज दर सहित विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त किया था, जो पूरी तरह से यह दर्शाता है कि ब्याज दरें सामान्य बाजार दरें थीं।
- vii. कार्यक्रम संख्या 28 : अनुसंधान एवं विकास व्यय (आर एंड डी) व्यय की कटौती के लिए कर नीतियों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ जियाली विंड के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि वे दो स्वतंत्र कंपनियां हैं।
- viii. कार्यक्रम संख्या 31 : कंपनियों के लिए अधिमानतः कर नीतियों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ मान्यता प्राप्त है और जियाली विंड के लिए लागू नहीं होंगे क्योंकि ये दो स्वतंत्र कंपनियां हैं और मूल कंपनी पीयूसी में शामिल नहीं है।
- ix. कार्यक्रम संख्या 36 : में प्रकटीकरण विवरण में आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरण के लिए प्रशुल्क और आयात वैट की छूट के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि जियाली विंड इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हुई है क्योंकि यह एफआईई नहीं है। तथापि, जियाली के सीवीडी मार्जिन 'लागू नहीं' के स्थान पर 1.69 निर्धारित किया गया है। स्थिति को सही किए जाने की आवश्यकता है।
- x. कार्यक्रम की गणना के लिए 'कल्याण करोबार मूल्य वर्धित कर रीफंड', 'निर्यात कर रीफंड' और 'अन्य कर रीफंड' प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ये भूमि प्रयोग कर से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निर्यात कर रीफंड को इस कारण की वजह से आर्थिक सहायता नहीं माना जाना चाहिए कि ये लाभ केवल उस सीमा तक विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात कर रीफंड इस कारण की वजह से आर्थिक सहायता नहीं माना जाना चाहिए कि मौजूदा लाभ केवल उस सीमा जो घरेलू खपत के लिए बिक्री करते समय समान उत्पादों के उत्पादन और वितरण के संबंध में है वसूली गई राशि की छूट से अधिक नहीं हो। शुल्क अथवा करों से निर्यातित उत्पाद की छूट समान उत्पाद द्वारा उस समय वहन की जानी चाहिए जिस समय घरेलू खपत के लिए भेजी गई हो अथवा राशि में इस प्रकार के शुल्क अथवा करों की छूट प्रोद्भूत से अधिक नहीं हो, डब्ल्यूटीओ प्रावधानों की शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता नहीं मानी जानी चाहिए। फिर भी जांच अवधि के दौरान निर्यात (\*\*\*%) पर वैट छूट की राशि घरेलू बाजार (\*\*\*%) में संबंधित उत्पाद पर लगाई गई वैट दर से अधिक नहीं थी, इसलिए वैट रीफंड काउंटरबेलेबल लाभ प्रदत्त नहीं करता।
- xi. कार्यक्रम संख्या 37 : भूमि प्रयोग फीस में कमी के संबंध में मूल कंपनी द्वारा प्राप्त 'भूमि प्रयोग कर रीफंड' जियाली विंड के लिए लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दो स्वतंत्र कंपनियां हैं और मूल कंपनी पीयूसी में शामिल नहीं है।
- xii. कार्यक्रम संख्या 40 : उचित बाजार मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विद्युत के संबंध में जियाली विंड ने इलेक्ट्रिसिटी सहित सभी आदानों के लिए बाजार कीमत पर भुगतान किया था और इसलिए कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। डीजीएडी द्वारा प्रयोग की गई कीमत न तो औद्योगिक प्रयोग के लिए कीमत है और न ही जियाली द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमत है।

- xiii. कार्यक्रम संख्या 43 : पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए विभिन्न वस्तुओं के प्रावधान के संबंध में जियाली विंड ने अपनी अनुपूरक प्रतिक्रिया में खपत की गई कच्ची सामग्री और प्रतिटन आरएमबी\*\*\* भुगतान की गई राशि संबंधी सूचना उपलब्ध कराई थी। भुगतान की गई वास्तविक कीमत प्राधिकारी द्वारा गणना में प्रयोग की जानी चाहिए।

**इंडियन विंड टरबाइन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूटीएमए) द्वारा पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां**

- i. प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां दायर करने के लिए प्राधिकारी द्वारा कम समय दिया गया। प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षों को सभी विश्वसनीय दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे और सुनवाई का एक ओर अवसर देना चाहिए था।
- ii. प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू करना कानून की दृष्टि से खराब है। परिकल्पना के आधार पर साक्ष्य देकर जांच शुरू करना अनुमेय नहीं है। अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों को साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
- iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विंड मिल के सभी भागों हेतु कास्टिंग शामिल करके उत्पाद के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया है जबकि प्रारंभ में पीयूसी द्वारा 'कास्टिंग फॉर विंड ऑपरेटेड इलैक्ट्रीसिटी जेनरेटरर्स' परिभाषित किया गया था।
- iv. सब-असेंबलड रूप में कास्टिंग अथवा एक सब-असेंबली के भाग के रूप में कास्टिंग अथवा उपकरण/कंपोनेंट के एक भाग के रूप में कास्टिंग जैसे उत्पाद भारत में कभी भी आयातित नहीं किए गए। परिणामस्वरूप इस प्रकार के उत्पादों की किस्मों को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।
- v. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने पीयूसी में शामिल उत्पादों की विभिन्न किस्मों के आधार पर क्षति और आकस्मिक लिंक की कोई जांच नहीं की है। उत्पाद की किस्म के आधार पर बाजार हिस्से, उत्पादन, उत्पादन क्षमता उपयोग जैसे क्षति प्राचलों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा संशोधित प्रकटीकरण विवरण जारी किया जाएगा।
- vi. पैरा 17 में प्राधिकारी ने कहा है कि "संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख अनुपात याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन का बड़ा हिस्सा है" तथापि यह इस प्रकार के दावे के लिए आधार उपलब्ध कराने में विफल रहा है।
- vii. याचिकाकर्ता ने अधिक गोपनीयता बरते जाने का उल्लेख किया है। प्राधिकारी को प्रतिक्रिया करने वालों को द्वारा विश्वसनीय दस्तावेजों उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे।
- viii. याचिका में दावा की गई आर्थिक सहायता योजना के संबंध में घरेलू उद्योग में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। घरेलू उद्योग पीओआई के दौरान प्रचालित शेष योजनाओं के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका। इस प्रकार के मामले में योजनाएं विशिष्ट नहीं हो सकती और इसलिए काउंटरवेल् नहीं की जा सकती।
- ix. कार्यक्रम संख्या 5 : एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/अथवा कमी तथा कार्यक्रम 6 : एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरण पर प्रशुल्क एवं मूल्यवर्धित कर(वैट) छूट के संबंध में प्राधिकारी ने कहा है कि घरेलू उद्योग ने उन उत्पादकों और निर्यातकों की सूची उपलब्ध कराई थी जो एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित हैं और लाभ के लिए पात्र एफआईई स्वरूप की हैं। निर्यातकों अथवा उत्पादकों की इस प्रकार की सूची प्रतिक्रिया करने वालों को कभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्राधिकारी ने इन आर्थिक सहायताओं की गणना के लिए पद्धति अथवा आधार उपलब्ध नहीं कराया है। ये कार्यक्रम गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता है और इन कार्यक्रमों के लिए जांच समाप्त कर देनी चाहिए।
- x. कार्यक्रम 8 : राज्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पुनरुद्धार परियोजना निधि के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि यह कार्यक्रम जीओसी द्वारा प्रदत्त राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान उपलब्ध कराता है। प्रथमतः प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता की गणना हेतु पद्धति अथवा आधार उपलब्ध नहीं कराया है। दूसरे प्राधिकारी इस तथ्य कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग डिग्री संख्या 59 के अनुसार 22 जनवरी, 2008 में रद्द कर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए विफल रहा है। सीवीडी शुल्क की गणना करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है और इस कार्यक्रम के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। ये कार्यक्रम गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता है और इन कार्यक्रमों के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- xi. कार्यक्रम 9 : स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी और/अथवा काउंटरवेलिंग कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राधिकारी को एससीएम के अनुच्छेद 9 के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी जानी चाहिए।



- xii. कार्यक्रम 10 : अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान के संबंध में प्रतिक्रिया करने वाले निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है और इसलिए इस कार्यक्रम के लिए कार्यवाही समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम गैर-कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता है और इन कार्यक्रमों के लिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- xiii. कार्यक्रम संख्या 11 : नवाचार प्रयोगात्मक उद्यम अनुदान के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उत्पादकों/निर्यातकों की सूची प्रतिक्रिया करने वालों को प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसलिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम अनुसंधान और विकास के संबंध में सहायता हेतु होने के कारण यह गैर-कार्रवाई योग्य है और इसलिए समाप्त की जानी चाहिए।
- xiv. कार्यक्रम 12 : सुपरस्टार उद्यम अनुदान के संबंध में इस कार्यक्रम के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदण्ड 2006-2008 की अवधि से संबंधित थे और बाद की अवधि के लिए नहीं थे। यह सुझाव देने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि यह कार्यक्रम बाद की अवधि हेतु उपलब्ध है। याचिका में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए जांच को समाप्त कर देना चाहिए।
- xv. कार्यक्रम 13 : उन उद्यमों जिनके उत्पाद चीन के 'प्रसिद्ध ट्रेडमार्क' अथवा चीन के प्रसिद्ध ब्रांड के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, के लिए पुरस्कार के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादकों/निर्यातकों की सूची प्रतिक्रिया करने वालों के साथ साझा नहीं की गई है। इसलिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए लागू है, के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाने में विफल रहा है कि निर्यातकों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए प्राधिकारी को कार्यवाहियां समाप्त कर देनी चाहिए।
- xvi. जहां तक कार्यक्रम 14 : उच्च प्रौद्योगिकी की उद्यम निवेश निधि का संबंध है याचिका द्वारा दी गई उत्पादकों/निर्यातकों की सूची उत्तरदाताओं को नहीं दी गई है और इसी लिए जांच को रद्द कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तरदाता बार-बार कहते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि यह योजना इस जांच में विचाराधीन उत्पाद पर लागू है। प्राधिकारी को इस कार्यक्रम के लिए कार्यवाही समाप्त करनी चाहिए।
- xvii. जहां तक कार्यक्रम 15: विदेशी निवेश वाले मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान का संबंध है, इस बात के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि यह योजना विदेशी निवेशकों को मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में गौगडू नगर पालिका के प्रांत के लिए उपलब्ध है। याचिका में इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्यक्रम संबद्ध उत्पाद के निर्यातकों से संबंधित है। अतः इस कार्यक्रम के लिए जांच रद्द कर देनी चाहिए।
- xviii. जहां तक कार्यक्रम 16: लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए नए अनुदान का संबंध है, प्राधिकारी को उन निर्यातकों तक अपने निष्कर्षों को प्रतिबंधित करना चाहिए जिनके नाम याचिका में दिए गए हैं। याचिकाकर्ता जांच के इतने देर के चरण में निर्यातकों अथवा उत्पादकों की कोई सूची नहीं दे सकता। साथ ही कार्यक्रम के संबंध में विशिष्टता सिद्ध नहीं है। अतः इस कार्यक्रम के लिए जांच रद्द कर देनी चाहिए।
- xix. *जहां तक कार्यक्रम 17: निजी स्वामित्व वाले निर्यात उद्यमों को अनुदान का संबंध है, साक्ष्य के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है और याचिकाकर्ता ने सामान्य रूप से कहा है कि गैर सरकारी अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाने से संबंधित नोटिसों में पात्र उद्यम की सूची है। यह कार्यक्रम यूनन प्रांत में स्थित गैर-सरकारी उद्यमों के लिए उपलब्ध है। तथापि, यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक यूनन प्रांत के हैं। अतः प्राधिकारी को चाहिए कि वे इस कार्यक्रम के लिए जांच रद्द कर दें।*
- xx. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने कार्यक्रम क्रम सं. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 के लिए सहयोगी और गैर-सहयोगी के लिए सब्सिडी की मात्रा 5.89 प्रतिशत पर परिकलित की है। प्राधिकारी ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि निर्यातकों और उत्पादकों ने इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ लिया है। साथ ही इसका कोई आधार नहीं दिया गया है कि इन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी का परिकलन किस आधार पर किया गया है। प्राधिकारी यह सिद्ध करने में विफल है कि यदि कोई सब्सिडी है तो निर्यातकों को दी गई उस सब्सिडी से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। प्राधिकारी को चाहिए कि इन कार्यक्रमों के विरुद्ध सब्सिडी को समाप्त करे।
- xxi. जहां तक कार्यक्रम 18: इक्विटी सम्मिश्रण का संबंध है, केवल याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सी आई सी सी कार्यक्रम सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। प्राधिकारी को अपने निर्धारण

- के लिए आधार प्रदान करना है। साथ ही प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बताया गया है कि उसने दिए गए कार्यक्रम के लिए सब्सिडी कैसे परिकलित की।
- xxii. जहां तक कार्यक्रम 19 अप्रदत्त लाभांश का संबंध है, प्राधिकारी ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि कार्यक्रम सार्वजनिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह कि इस कार्यक्रम के तहत निर्यातकों ने वे लाभ लिए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा मानने मात्र से प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह कार्यक्रम प्रतिकारक सब्सिडी है और यह कि यह सार्वजनिक निकाय द्वारा दी जाती है। प्राधिकारी ने ऐसा भी कोई आधार नहीं दिया है जिस पर उसने सब्सिडी की मात्रा 0.26 प्रतिशत होना परिकलित किया है।
- xxiii. जहां तक कार्यक्रम सं. 20: ढलाई उद्योग को तरजीही ऋण तथा ब्याज दरों का संबंध है, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि यह कार्यक्रम ढलाई उत्पादकों के लिए उपलब्ध है। मात्र यह कहना पर्याप्त नहीं है कि निजी बैंक भी चीन में तरजीही ऋण देने की परिपाटियों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा सौंपे गए/निर्देशित किए गए हैं। इन तथ्यों से चीन से बाहर तुलनीय वाणिज्यिक ऋण की तुलना कर इस लाभ को निर्धारित करने के भार से याचिकाकर्ता को नहीं छोड़ते। किसी भी स्थिति में चीन के वाणिज्यिक बैंकिंग कानून के अनुच्छेद-4 के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों को अपने वाणिज्यिक प्रचालनों के संबंध में सरकारी नीतियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।
- xxiv. जहां तक कार्यक्रम 25 : जहां तक चीन में स्थापनाओं अथवा स्थानों वाले विदेशी उद्यमों और एफ आई ई तथा उत्पादन अथवा व्यापार प्रचालनों में लगे उन उद्यमों, जो घरेलू रूप से उत्पादित उपस्करों की खरीद कर रहे हैं, के लिए तरजीही कर नीतियों का संबंध है, प्राधिकारी ने वह आधार नहीं बताया है जिसके आधार पर उसने सब्सिडी का परिकलन किया है। साथ ही उत्पादकों और निर्यातकों की सूची उस पर टिप्पणी करने के लिए उत्तरदाता को कभी भी नहीं दी गई। यह दर्शाने के लिए याचिका में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि निर्यातक के उद्यम एफ आई ई हैं। इस कार्यक्रम के तहत कोई विशिष्टता सिद्ध नहीं की गई है।
- xxv. जहां तक कार्यक्रम 28 : अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के खर्चों को घटाने के लिए कर नीतियों का संबंध है, प्राधिकारी ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया है जिसके आधार पर उसने कार्यक्रम के तहत लाभ का परिकलन किया है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि यह कार्यक्रम में प्रतिकारक सब्सिडी है और मौजूद है।
- xxvi. जहां तक कार्यक्रम सं. 31 : उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी की कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए तरजीही कर नीतियों का संबंध है, प्राधिकारी ने वह आधार नहीं बताया है जिस पर उसने इस कार्यक्रम के तहत लाभ परिकलित किया है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि इस कार्यक्रम में प्रतिकारक सब्सिडी है।
- xxvii. जहां तक कार्यक्रम 33 : विशेष उपस्करों की खरीद से संबंधित कर लाभ का संबंध है, प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष के लिए कोई आधार नहीं दिया है कि कार्यक्रम प्रतिकारक है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पात्रता मानदंड के लिए उद्यम को पर्यावरणी संरक्षण, ऊर्जा तथा जल बचत और उत्पादन सुरक्षा से संबंधित उपस्करों को खरीदने की अपेक्षा है। तथापि, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि उद्यम ऐसे उपस्करों की खरीद में लगा हुआ है।
- xxviii. जहां तक कार्यक्रम 36: आयातित प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के लिए शुल्क तथा आयात मूल्यवर्धित प्रशुल्क की छूट का संबंध है, यह कार्यक्रम पी आर सी उद्यम आयकर कानून डिक्री सं. (2007) 39 के तहत ग्रांटफादरिंग प्रीपरेसियल पालिसी के कार्यान्वयन के संबंध में पी आर सी स्टेट काउंसिल द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार 1 जनवरी, 2008 को रद्द कर दिया गया है। साथ ही यह कार्यक्रम केवल एफ आई ई पर लागू है। यह दर्शाने के लिए याचिका में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि निर्यातक के उद्यम एफ आई ई हैं। इस कार्यक्रम के तहत कोई विशिष्टता सिद्ध नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि निर्यातक एफ आई ई है।
- xxix. जहां तक कार्यक्रम 37: भूमि-प्रयोग-शुल्क में कमी का संबंध है, प्राधिकारी ने इसका कोई आधार नहीं बताया है जिस पर इस कार्यक्रम के तहत लाभ परिकलित किए गए हैं। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि इस कार्यक्रम में प्रतिकारक सब्सिडी है। प्राधिकारी ने यह दर्शाने के लिए कोई प्रयाप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं कि यह योजना वर्तमान निर्यातक पर लागू है। अतः प्राधिकारी को चाहिए कि वे इस कार्यक्रम की कार्यवाही रद्द करें।
- xxx. जहां तक कार्यक्रम सं. 40: सरकार द्वारा सस्ते बाजार मूल्य से कम की दर पर दी गई बिजली का संबंध है, प्राधिकारी ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया है जिस पर उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह योजना प्रतिकारक है तथा यह भी नहीं बताया कि इस कार्यक्रम के लिए सब्सिडी का परिकलन किस प्रकार किया गया है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कि केवल ढलाई उद्योगों को ही तरजीही विद्युत दरें दी गई हैं।

- xxxii. जहां तक कार्यक्रम 43: पर्याप्त आय से कम के लिए विभिन्न सामानों का प्रावधान का संबंध है, प्राधिकारी की टिप्पणी गलत है। सन्डि के परिकलन के लिए प्राधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। साथ ही यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है कि यह केवल ढलाई उद्योग के लिए उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी को चाहिए कि वे इस कार्यक्रम के लिए कार्यवाहियां रद्द करें।

#### जी ई इंडिया इंडस्ट्रियल प्रा. लि. और इनोक्स विंड लि. द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां :

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अनिवार्य तथ्यों, विशेषकर जो आकस्मिक संपर्क से संबंधित हैं, उन तथ्यों को पर्याप्त रूप से प्रकट करने में विफल रहे। प्राधिकारी को उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देते हुए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए नया प्रकटन विवरण जारी करना ही चाहिए।
- ii. प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि उत्पाद क्षेत्र में सहायक असेंबलियां तथा घटक शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद को उत्पाद क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति और परिभाषा देते हुए परिभाषित किया जाना चाहिए तथा उसमें हटाए गए उत्पादों और विभिन्न सहायक असेंबलियों तथा शामिल घटकों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे।
- iii. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि ढलाई की विभिन्न किस्मों के भिन्न-भिन्न अंतिम अनुप्रयोग हैं तथा अलग-अलग लागतें/कीमतें हैं। परंतु साथ ही वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि ऐसे अंतर होने से ढलाई, विभिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं मानी जा सकती। पी सी एन सिद्धांत लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवलतुलनीय वस्तुओं की तुलना की जाए। यह उदाहरण विचाराधीन क्षेत्र के तहत अस्पष्ट और अनौचित्यपूर्ण उत्पाद हो जाता है।
- iv. याचिकाकर्ता के सामान वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीयता के अभाव में विचाराधीन आयातित उत्पाद के समान नहीं हैं।
- v. प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को बताए जा रहे किसी पी सी एन सिद्धांत का पहला उदाहरण होना प्रतीत होता है। पी सी एन सिद्धांत के संबंध में टिप्पणियां अथवा सुझाव आमंत्रित करने का निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई पत्र नहीं था।
- vi. प्राधिकारी ने भारित औसत तुलना की है परंतु वह पी सी एन सिद्धांत का प्रयोग किए बिना कीमत प्रभाव की तुलना की है। ऐसा विसंगत हानिकारक विश्लेषण औचित्यपूर्ण नहीं है।
- vii. प्राधिकारी की टिप्पणी कि उपभोक्ता की लागत में मुश्किल से 0.1 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिकारक उपाय का प्रभाव है, गलत है। संभारिकीय अदक्षताएं, यथा मंहंगी आपूर्ति श्रृंखला का मॉडल, घरेलू उद्योग से खरीद की लागत पर भारी प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक तकनीकी विशेषताओं से युक्त उत्पाद को तैयार करने में याचिकाकर्ता की असमर्थता एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण आयातक को संबद्ध वस्तुओं का आयात करना पड़ा।
- viii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और संबद्ध सामानों के आयात में कमी के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। वर्ष 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान, जिसमें आयात में कमी आई थी, विचाराधीन उत्पादों के आयात के लिए मांग में भी कमी आई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 की अवधि से जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की बिक्री और संबद्ध देश की बिक्री में वृद्धि हुई जिससे सिद्ध हुआ कि घरेलू उद्योग और संबद्ध देश के बीच मांग और बाजार हिस्से के सह-संबंध का अभाव है।
- ix. संबद्ध देश से आयात का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी को ध्यान में न रखते हुए बढ़ा है। अतः घरेलू उद्योग के सामने आई क्षति आयातों में वृद्धि के कारण नहीं मानी जा सकती।
- x. कीमत प्रभाव परिकलन अनुपयुक्त है क्योंकि यह पी सी एन के आधार पर नहीं है परंतु भारित औसत आधार पर है। साथ ही कम कीमत पर बिक्री पिछले वर्ष के आंकड़ों के संबंध में विश्लेषित नहीं की गई है जिसके बिना क्षति की अवधि में कीमत प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
- xi. लाभदायकता और आयातों में कमी के बीच सह संबंध नहीं है। प्राधिकारी द्वारा किये गए निर्धारण में यह नहीं दर्शाया गया है कि लाभदायकता और आयातों के बीच आकस्मिक संपर्क क्या है।
- xii. परिकलित एन आई पी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पी सी एन पर आधारित रखे जाने की आवश्यकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह भी चाहिए कि वे एन आई पी से संबंधित अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करें ताकि आयातक अपने हितों की रक्षा कर सकें।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

154. चीन सरकार, घरेलू उद्योग और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों की जांच की गई और प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराग्राफों में उसका समाधान किया गया। क्षति से संबंधित प्रकटन पश्चात टिप्पणियों को यथा तथ्यतः इस निष्कर्षमें प्राधिकारी द्वारा आयोजित क्षति विश्लेषण से दूर कर दिया गया है। चीन

सरकार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई अन्य विशिष्ट प्रकटन पश्चात टिप्पणियां संगत मानी गई हैं, उनकी जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में उनका समाधान किया गया है :

- i. जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है कि सब्सिडी विरोधी जांच फर्जी और न पाए गए मुकदमों के आधार पर तथा ए एस सी एम में निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं के विपरीत शुरू की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच नियंत्रित संबद्ध वस्तुओं का सब्सिडीकरण, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा उपर्युक्त सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच के आकस्मिक संबंध दर्शाते हुए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर शुरू की गई थी।
- ii. इस पर सहमति है कि याचिकाकर्ता को उपर्युक्त रूप से उपलब्ध साक्ष्य से पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दायित्व से छूट नहीं मिलती, परंतु याचिकाकर्ता की संगत साक्ष्यों तक पहुंच के अभाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता। चीन सरकार तथा उस मामले के लिए उत्तरदाता नियंत्रित पूरे साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी बात रख सकते थे और प्राधिकारी को उसी स्थान पर सही स्थिति सुनिश्चित करने और सिद्ध करने के संबंध में सूचना/साक्ष्यों का सत्यापन करने में समर्थ बना सकते थे।
- iii. प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान चीन सरकार दी गई सूचना/साक्ष्यों के स्थल पर ही सत्यापन किए जाने के लिए चीन सरकार की सहमति और सुविधा प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रयास किए गए थे। चीन सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक के स्थल पर ही सत्यापन के लिए चीन जाने की आवश्यक अनुमति प्रदान करें। परंतु चीन सरकार से सहमति/अनुमति प्राप्त न होने के कारण स्थल पर ही सत्यापन नहीं किए जा सके। चीन सरकार के लिए यह बेहतर होता कि यदि वे अपनी सूचना/साक्ष्यों के स्थल पर ही सत्यापन के लिए सहमति देते तो विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में सच्चाई सामने आ सकती थी।
- iv. जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है, कि उपलब्ध तथ्यों का निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब हितबद्ध पक्षकार पूरी तरह से सहयोग नहीं करते तो सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करना ही प्राधिकारियों के लिए जांच करते समय विश्व भर में स्वीकार्य विकल्प होता है। जहां तक उन कार्यक्रमों का संबंध है, जहां याचिकाकर्ता पर्याप्त साक्ष्य/स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, प्राधिकारी ने ऐसे कार्यक्रमों की प्रतिकारकता स्थापित करने के लिए जांच आगे नहीं बढ़ाई।
- v. जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है, कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणी करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय नहीं दिया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे प्रयोजनों के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नियमों में निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, इस जांच को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणी करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को काफी समय दिया गया था। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना के अगोपनीय रूपांतर सरकारी फाइल में प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।
- vi. जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है कि भारत सरकार ने विभिन्न कथित कार्यक्रमों के संबंध में लाभों का परिकलन करने के लिए सिद्धांत प्रकट नहीं किए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक और हर योजना/कार्यक्रम के परिकलन के लिए सिद्धांत प्रकटन विवरण तथा इस अंतिम निष्कर्ष में स्पष्ट कर दिए गए हैं।
- vii. जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है, कि इन आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि सरकार के स्वामित्व वाले बैंक और सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम सरकारी निकाय हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ए एस सी एम के अनुच्छेद-1 के संदर्भ में, "सार्वजनिक निकाय" शब्द का अभिप्राय उस किसी कंपनी से है जिसमें सरकारी प्राधिकार हों, जो सरकारी प्राधिकारों का प्रयोग करती हो अथवा जिसमें सरकारी प्राधिकार निहित हों। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, जैसे सरकार के स्वामित्व वाले बैंक और सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम भी सरकारी निकाय हैं क्योंकि इन कंपनियों में उनके कार्यों के निष्पादन के समय सरकारी प्राधिकार निहित होते हैं।
- viii. जहां तक इस विरोध का संबंध है कि प्राधिकारी को कार्यक्रम 8 से 17 के पैकेज के लिए 5.89 प्रतिशत लाभ परिकलित करने के बजाए प्रत्येक कथित कार्यक्रम के लिए लाभ परिकलित करने चाहिए, यह नोट किया जाता है कि जियाली की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए व्यौरों में उनके द्वारा प्राप्त योजनावार सब्सिडियां नहीं दर्शायी गयी हैं। इस दृष्टि से प्राधिकारीने समग्र रूप से कार्यक्रम 8 से 17 के लिए जियाली को हुए लाभ की गणना की है।
- ix. जहां तक इस विरोधका संबंध है, कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने शुरुआत में विंड मिल के सभी भागों के लिए ढलाई को शामिल करते हुए उत्पाद के क्षेत्र को बढ़ाया है जबकि शुरुआत में "विंड प्रचालित विद्युत उत्पादकों के लिए ढलाई" को एक

विचाराधीन उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया था, प्राधिकारी यह बताते हैं कि वायु प्रचालित विद्युत उत्पादक तथा विंड मिल एक ही हैं। "विंड प्रचालित विद्युत उत्पादक (डब्ल्यू ओ ई जी)" एक "विंड मिल" है तथा इसी लिए "विंड प्रचालित विद्युत उत्पादक" का अभिप्राय "विंड मिल" अथवा "विंड टरबाइन" के लिए ढलाई से है।

- x. जहां तक इस विरोध का संबंध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादों में शामिल विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आधार पर क्षति तथा आकस्मिक संबंध की कोई जांच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोई विचाराधीन उत्पाद नहीं है, परंतु विचाराधीन उत्पादों के विभिन्न हिस्से हैं। अतः विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक भाग के लिए क्षति विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए पी सी एन तैयार की, क्षति मार्जिन निर्धारित किया और तदनुसार क्षति विश्लेषण किया।
- xi. जहां तक इस बात का संबंध है, कि परिकलित एन आई पी पीसीएन के आधार पर होने की आवश्यकता है और प्राधिकारी को एन आई पी से संबंधित अनिवार्य तथ्य भी प्रकट करने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान दिशानिर्देशों और डी जी ए डी में जारी परिपाटी के संदर्भ में पी सी एन वार एनआईपी संगणित की गई है। एन आई पी वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और घरेलू उद्योग के लिए एक गोपनीय सूचना होने के नाते उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता।
- xii. जहां तक घरेलू उद्योग की इस बात का संबंध है कि एन आई पी की गणना में आवंटन/अनुपात का आधार प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है और सिद्धांत में यह परिवर्तन अनपयुक्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि खर्चों के आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- xiii. जहां तक इस विरोध का संबंध है कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार आवश्यक तकनीकी विशिष्टियों के साथ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में घरेलू उद्योग विफल रहा है और उनकी संभारिकीय अक्षमताएं चीन गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि करने के लिए वास्तविक कारण हैं, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई बात से नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग से अपनी आवश्यकताओं का केवल एक छोटा सा भाग केवल एक उपभोक्ता ने खरीदा और घरेलू उद्योग द्वारा कीमतें घटाए जाने के बाद घरेलू उद्योग से अपनी खरीद काफी मात्रा में बढ़ाई। इससे सिद्ध होता है कि संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को आदेश देने के लिए उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान पर कीमत का प्रमुख प्रभाव पड़ता है।
- xiv. जहां तक इस विरोध का संबंध है कि पैतृक कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ जियाली विंड पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वे दो स्वतंत्र कंपनियां हैं और विचाराधीन उत्पाद में पैतृक कंपनी शामिल नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 ज़ेजियांग जियाली टेक्नोलॉजी कं. लि., वर्तमान जांच में उत्तरदाता कंपनी की पैतृक कंपनी, का अपना कोई कार्य व्यापार नहीं है तथा अपने सभी कार्य अनुसंधान एवं विकास सेवाओं सहित संबद्ध वस्तुओं और अन्य सामानों के उत्पादन तथा बिक्री में शामिल अपनी 5 सहायक कंपनियों के माध्यम से करती है। तथापि, प्राधिकारी मै0 ज़ेजियांग जियाली टेक्नोलॉजी कंपनी लि. की वैबसाइट सूचना से नोट करते हैं कि इस कंपनी ने निष्पादन संबंधी अनेक पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं तथा अनुदान आदि भी प्राप्त किए हैं। चूंकि स्पष्ट रूप से पैतृक कंपनी का अपना कोई कार्य व्यापार नहीं है, अतः इसके द्वारा प्राप्त किए गए सभी पुरस्कार, प्रमाण पत्र, अनुदान आदि स्पष्ट रूप से इसकी सहायक कंपनियों के निष्पादन के निमित्त हैं। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैतृक कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ/सब्सिडी उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होगी।
- xv. जहां तक इस विरोध का संबंध है, कि "कल्याणकारी कार्य मूल्यवर्धितकर वापसी", "निर्यात कर की वापसी" और "अन्य कर की वापसी" इस कार्यक्रम के परिकलन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे भूमि प्रयोग कर से संबंधित नहीं हैं, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में परिकलनों के लिए पुनः कार्य किया है।
- xvi. जहां तक इस विरोध का संबंध है कि कार्यक्रम सं. 37: भूमि उपयोग शुल्क में कमी, पैतृक कंपनी द्वारा प्राप्त "भूमि उपयोग कर वापसी" जियाली विंड पर लागू नहीं होंगे क्योंकि वे दो स्वतंत्र कंपनियां हैं और पैतृक कंपनी विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पैतृक कंपनी का अपना कोई कार्य व्यापार नहीं है, और पैतृक कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किए गए हैं। पैतृक कंपनी द्वारा दिए गए विवरण के अभाव में प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत पैतृक कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कुल लाभों को पैतृक कंपनी के कारोबार में आवंटित किया है जिसमें उत्तरदाता निर्यातक कंपनी सहित इसकी सभी सहायक कंपनियों का कारोबार शामिल है।

**द. निष्कर्ष:**

155. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि इस जाँच परिणाम में दर्ज हैं, की जाँच करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

क. संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सब्सिडीप्राप्त मूल्य पर किया गया है, और इस प्रकार पाटन हुआ है।

ख. विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडीकरण के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. यह वास्तविक क्षति संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण हुई है।

**ण. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे**

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगाने का उद्देश्य आम तौर पर सब्सिडीकरण की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगाने से संबद्ध वस्तु की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि प्रतिसंतुलनकारी उपायों से भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी विशेष रूप से तब जबकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को उस राशि तक सीमित किया गया है जो सब्सिडीप्राप्त संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत प्रतिसंतुलनकारी उपायों को लागू करने से सब्सिडीकरण द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करना दूर किया जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक पसंद की उपलब्धता को बनाये रखने में मदद मिलेगी।

**सिफारिशें**

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना चीन जन. गण. की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और सब्सिडीकरण, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडीकरण, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन तथा ऐसे सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि सब्सिडी एवं क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी नीचे दिए गए ढंग और तरीके से चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

159. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन इनमें से जो भी कम हो के बार प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 8 में यथा उल्लिखित आयातों के पंधुच मूल्य के प्रतिशत के रूप में निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की सिफारिश की जाती है।

**शुल्क तालिका**

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	पहुंच मूल्य के % रूप में शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 84 और 85 में 84834000, 85030090, 85030010	वायु प्रचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए कास्टिंग्स, चाहे मशीन्ड हों अथवा नहीं, अपरिष्कृत, तैयार या उप-संयोजित रूप में, या उप संयोजन के भार के रूप में या किसी उपकरण/संघटक के भाग के रूप में, विंड प्रचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए लक्षित	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै. झेजियांग जिआली विंड पावर टेक्नालॉजी कंपनी लि.	मै. झेजियांग जिआली विंड पावर टेक्नालॉजी कंपनी लि.	8.78
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	कोई	13.44
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	कोई देश	कोई	कोई	13.44
4	-वही-	-वही-	कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	कोई	13.44

160. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की गणना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9क के 9 तथा अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

161. केन्द्र सरकार द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना पर आधारित आदेश के विरुद्ध खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, 27th November, 2015

**Final Findings**

**Subject: Anti-subsidy/Countervailing Duty investigation concerning imports of Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators, originating in or exported from China PR.**

**17/6/2013-DGAD:-** Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules);

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

2. Whereas, M/s Larsen & Toubro Limited (hereinafter also referred to as the petitioner) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the Rules), for initiation of Anti-subsidy/Countervailing Duty investigation concerning imports of “Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators”, (hereinafter also referred to as the subject goods or Castings), originating in or exported from China PR. Vide the above petition, the petitioner alleged subsidization of imports of the product under consideration and consequent injury to the domestic industry and requested for levy of anti-subsidy/countervailing duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. And Whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, issued a public notice vide Notification No. 17/6/2013-DGAD dated 29th May, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the sub Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
4. Abbreviations/terminology used in the present determination are explained herein below:

Sl. No.	Abbreviations/terminology	Meaning
1	Authority	Designated Authority
2	Petitioner/domestic industry	M/s Larsen & Toubro Limited.
3	GOI	Govt. of India
4	MNRE	Ministry of New & Renewable Energy
5	GOC	Govt. of China
	Sole Responding exporter	M/s Zhejiang Jiali Wind Power Technology Company Limited
6	CVD	Anti subsidy/Countervailing duty
8	ASCM/Agreement	Agreement On Subsidies And Countervailing Measures



9	Act	Customs Tariff Act, 1975
10	Rules	Customs Tariff (Identification, Assessment And Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles And For Determination of Injury) Rules, 1995

**B. PROCEDURE**

5. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
- i. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of the anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (7) of Rules supra.
  - ii. The Authority invited the Govt. of China for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement. The consultation was held on 5th May, 2014 in New Delhi, which was attended by the following representatives of the Govt. of China (hereinafter also referred to as the GOC):
    - i. Jha Xinjiang, Second Secretary, Embassy of China, Delhi.
    - ii. Yang Xiuquing, Third Secretary, Embassy of China, Delhi.
    - iii. Gu Yuan, First Secretary, MOFCOM, China PR.
    - iv. Luo Xin, dy. Commissioner.
    - v. Gu Yu, First Secretary, MOFCOM, China PR.
    - vi. Wang Hejun, Commercial Counselor.
    - vii. Xu Yan Guang, Dy. Director, MOFCOM
    - viii. Wang Xihui, Commercial Counselor.
  - iii. During the consultations and subsequently vide their note verbal dated 26th May, 2014, the GOC claimed that the evidence in the petition was incomplete in certain critical respects, the alleged subsidy schemes/programmes have already been rescinded and the Designated Authority should not consider the petition for initiating the investigation. Vide the aforesaid note verbal, GOC made the following post consultation submissions:
    - a. The petition is not properly documented.
    - b. Most of the alleged programs in the petition are mere assertions without supportive evidence.
    - c. In order to make an anti-subsidy complaint, the petitioner has simply copied the contents of findings of other WTO member countries such as USA, EU, Canada, Australia etc, without justifying how such outdated information relevant to other products and situations could be relevant for the present petition.
    - d. Benefits conferred on some other industries cannot be obtained by industries involved in the product under consideration of the present petition.
    - e. The rescinded programs alleged by the petitioner should be rejected.
    - f. Scope of the product under consideration (PUC) is too broad and unclear.
    - g. If the PUC is defined in such broad manner, then the Indian producers of all the like articles should be covered in the scope of domestic industry.
    - h. Further, given the physical differences and diversity of usages among various product categories within the scope of PUC, the petitioner has to make clear distinction among different categories of products and conduct analysis on competition, price effect, as well as injury and causal link separately.
    - i. The petition suffers from utmost confidentiality. Certain critical information concerning import data, costing etc are missing in the petition. Lack of transparency may impair the rights of the other interested parties to rebut the allegations of the petitioner.
    - j. Imposition of countervailing measures against the imports of product under consideration from China will impair the competitiveness of the Indian power plant sector, the development of private sector and the welfare of Indian people at large.
  - iv. The Authority notes that the Government of China PR did not provide any substantiated evidence in support of their claims made during the pre-initiation consultations. Consequently, the Authority went ahead with the initiation of the investigation with the prima facie evidence of countervailable subsidized

imports of product under consideration from China PR and injury caused to the domestic industry due to such imports. The Authority considered the petition filed by the petitioner and the contentions of the GOC and held that it was appropriate to initiate and conduct countervailing duty investigations in order to determine whether the producers/exporters of the product under consideration were benefited from countervailable subsidies and, whether such subsidized imports were causing injury to the domestic industry and if so, whether it is appropriate to recommend imposition of countervailing duty measures (hereinafter referred to as "CVD" or "subsidy duty") on imports of the product under consideration from China PR and if so, to determine the quantum of CVD that should be imposed on the imports of the product under consideration.

- v. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th May, 2014 to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users in India, other Indian producers of subject goods and the domestic industry as per the addresses made available by the petitioner and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- vi. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of China PR in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.
- vii. The Embassy of China PR in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 7(2) of the Rules with a request to advise the producers/exporters from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassy of China PR along with the names and addresses of the known producers/ exporters from China PR.
- viii. The Authority sent a questionnaire to the GOC in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the GOC. The GOC filed a questionnaire response, which has been taken into account to the extent the same is relevant and could be adopted for the present purposes.
- ix. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
  - a) Wenzhou Kaicheng Foundry Co. Ltd., Beijing
  - b) Jiangsu Wenhui Steel Engineering Co. Ltd., Jiangsu
  - c) Shaanxi Quinchuan Machinery Import and Export Co Ltd., Shaanxi
  - d) Dingzhaou Dongfang Foundry Co. Ltd., Hebei
  - e) Beijing Beiyong Foundry Co. Ltd., Beijing.
  - f) Zhejiang Jiali Wind Power Technology Company Limited, Hangzhou
- x. Although GOC identified more than 200 producers of castings in China in their response, only one producer/exporter from China i.e. M/s Zhejiang Jiali Wind Power Technology Company Limited filed the questionnaire response. Neither there is any response from other Chinese producers/exporters directly, nor has GOC provided any information with regard to these producers in China.
- xi. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - a) M/s Chiranjeevi Wind Energy Ltd.
  - b) M/s Gamesa Wind Turbine Pvt. Ltd.
  - c) M/s GE India Industrial Pvt. Ltd.
  - d) M/s Global Wind Power Ltd.
  - e) M/s Inox Wind Ltd.
  - f) M/s Leitwind Shriram Manufacturing Ltd.
  - g) M/s Pioneer Wincon Pvt. Ltd.
  - h) M/s Regen Powertech Pvt. Ltd.
  - i) M/s RRB Energy Ltd.
  - j) M/s Shriram EPCI Ltd.
  - k) M/s Siva Wind Turbine India Pvt. Ltd.

- l) M/s Southern Wind Farms Ltd.
  - m) M/s Wind World (India) Ltd.
  - n) M/s Suzlon Energy Ltd.
  - o) Indian Wind Turbine Manufacturers Association
- xii. The following importers filed importers questionnaire response in the prescribed format:
- i. M/s Pioneer Wincon Pvt Ltd
  - ii. M/s Inox Wind Ltd.
  - iii. M/s GE India Industrial Pvt. Ltd.
- xiii. Submissions were also made by the interested parties post initiation and during the course of the investigation, which have been examined and addressed in the present final finding to the extent considered relevant by the Authority.
- xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The said information was received from the DGCI&S. The Authority has relied upon DGCI&S data in this finding.
- xvi. The Non-injurious Price has been worked out based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and consistent practices in the DGAD.
- xvii. Verification of the information provided by the petitioner, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon by the Authority.
- xviii. The Authority requested the Govt. of China to notify its willingness or otherwise to conduct on-the-spot verification of the responses/evidences submitted by the Government of China and the responding Chinese exporter. However, on the spot verification of the information/data/evidences furnished and claims made by the Govt of China as well as the only respondent Chinese producer/exporter could not be carried out as despite best persuasion Govt of China neither consented for their verification nor provided the necessary permission to the Authority to visit China to conduct on the spot verification. Resultantly, due to such non-cooperation, the Authority relied upon the best available information as per the Rules.
- xix. The questionnaire response filed by the GOC and M/s Jiali Wind, the lone respondent Chinese producer/exporter were examined in detail. It was considered necessary and appropriate to seek further information/clarifications on various submissions and information filed by these interested parties. Further, it was considered appropriate to provide further opportunity to the GOC and the responding exporter to rectify deficiencies in the questionnaire responses. The GOC and respondent exporter responded to the supplementary questionnaires issued by the Authority. It was however noted that GOC and responding exporter did not provide all such information as was requested by the authority. Moreover, the veracity and correctness of the information/data furnished by the GOC as well as Jiali Wind could not be established by the Authority through on the spot verification due to non-cooperation by GOC. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated as confidential.
- xx. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
- xxi. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is from 1st October, 2012 to 31st December, 2013 (15 Months annualized). The injury investigation period has however been considered as the period from 1st April 2009 to the end of the POI, i.e., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.

- xxii. In accordance with the Rules, the Authority provided opportunity to all the known interested parties to present their views orally in hearings held on 22nd July, 2015 and 14th August, 2015. The parties, which presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of the views expressed orally followed by rejoinder submission.
- xxiii. In accordance with Rule 18 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 17th November, 2015 and comments received thereon, along with the submissions made by the interested parties during the course of the investigation, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.
- xxiv. \*\*\* in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxv. The Central Government in the Department of Revenue, Ministry of Finance extended the time limit for completion of the investigation and issue of the final findings up to 28th November, 2015 vide their Office Memorandum No. 354/84/2015--TRU dated 15th May, 2015.
- xxvi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs 58.05.

### **C. Level of cooperation by Government of China**

6. The Authority notes that despite adequate opportunities provided to the Government of China (GOC), through the deficiency letters and otherwise, to provide detailed information concerning the various alleged subsidy schemes, the benefits provided to the Chinese producers/exporters under the same and the countervailability of the same vis-à-vis the Subsidy Agreement, the GOC neither provided the complete information, nor consented for the on the spot verification offered by the Authority. The GOC did not permit the Authority to visit China to conduct on the spot verification of the data/information furnished by the sole Chinese respondent producer/exporter. Had the GOC cooperated and allowed on the spot verification of their information/documents/records and that of the sole respondent Chinese producer/exporter, the Authority would have been in a better position to establish whether the alleged programs exist, whether the SOEs involved in the alleged programs are public bodies and whether the alleged programs are countervailable under the law. Since GOC did not extend the required cooperation, the Authority had to look for and rely upon other best available information.

### **D. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

#### **D.1. Submissions made by the Domestic Industry**

7. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:
  - i. The Product under Consideration (PUC) in the present investigation is “Castings for wind-operated electricity generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators”. Castings for wind-operated electricity generators are also known as “windmill” or “wind turbine”.
  - ii. A Windmill requires a number of casting parts, including the—
    - a) Hub, Rotohub, Rotor Nabe,
    - b) Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation,
    - c) Bearing Housing, Bearing Support,
    - d) Hollow Shaft,
    - e) Main Axle, Rotor Shaft, Main Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin,
    - f) Lateral Suspender,
    - g) Pitch Stop, Stator,
    - h) Generator castings, Part of Generators, Rotor,
    - i) Torque Arm support, Gear Box.
  - iii. The product scope includes only wind turbine casting within the scope of the PUC. Casting if imported in raw/unfinished/semi finished or if imported as a part of sub-assembly equipments are within the scope of PUC. In case of sub-assembly, petitioner has not sought anti subsidy duty on entire sub-assembly. Petitioner has sought CVD on casting portion of the sub-assembly.
  - iv. The basic function of a casting is in a wind turbine, to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity.

- v. Although the product under consideration is classified under Customs sub-heading No. 8503 under the Customs Tariff Act, they are also being imported under other tariff heads viz; 84834000, 85030090, 85030010 in Chapter 84 and 85. However, customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.
- vi. There is no difference in subject goods produced by the petitioner and exported from the subject country. Subject goods produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject country are like article in accordance to the Rules.
- vii. “Wind operated electricity generators (WOEG)” is a “wind mill” and therefore casting for “wind operated electricity generators” implies casting for “wind mill” or “Wind Turbine”. The central government in various notifications is using the term for wind mill as WOEG.
- viii. The sole responding exporter, Jiali Wind submitted that the goods sold by the company in home market and exported to India are directly comparable. Jiali Wind submitted that there is no difference between the goods sold in home market and exported to other countries including India in physical and technical characteristics.

## **D.2. Submissions made by GOC**

- 8. Post initiation, no submission has been made by the Government of China with regard to the product under consideration.

## **D.3. Submissions made by producers/exporters/ importers/ other interested parties**

- 9. Following are the submissions made by the producers/exporters/ importers/ other interested parties with regard to the product under consideration:
  - i. The product under consideration is too broad and defined wrongly. It needs to be simplified and defined clearly without any ambiguity. Castings by definition mean a single object made using a mould. There can never be a casting in a sub-assembled form.
  - ii. The product under consideration, as defined by authority in the initiation notification, is restricted to only castings for wind operated electricity generators. Thus, any other casting, which is not used in wind-electricity generators are outside the purview of subject investigation.
  - iii. The products that are not castings and the product types that were not even imported into India or produced by the domestic industry should be excluded from the purview of this investigation.
  - iv. It is not necessary that benefits conferred on sub-assembled parts will be included in the final product. Unless it is proved that the subsidy enjoyed by the castings manufacturer have been passed on to the other products, such downstream products should not be included in a CVD investigation. Therefore, Authority should exclude Castings in sub-assembled form, Castings as a part of sub-assembly or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators from the scope of the present investigation.

## **D.4. Examination by the Authority**

- 10. The meaning and scope of the product under consideration was defined by the Authority in the initiation notification as follows:

“5. The product under consideration in the present investigation is “Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators”. A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc. The basic function of a casting is in a wind turbine, to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity.

6. The product under consideration is classified under Customs sub-heading No. 8503 under the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration does not have dedicated customs classification. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

11. Following are the observations made by the Authority in regard to the product under consideration:

- i. The product under consideration (PUC) in the present investigation, as defined in the initiation notification, is “Castings for wind-operated electricity generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators”. The product under consideration has also been collectively referred to as castings for wind operated electricity generators (WOEG).
- ii. The basic function of a casting is in a wind turbine, to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like tower, blades, etc. which leads to the generation of electricity.
- iii. The product under consideration is a casting for a wind-operated electricity generator (WOEG) which is popularly known as windmill. A windmill is a mill that converts the wind energy into mechanical energy by means of rotating blades, which in turn moves the turbine to generate electricity. A windmill comprises of various casting and non-casting parts such as fan or blades made of fibre glass, tower made of steel structure etc.
- iv. A windmill requires a number of casting parts including Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc.
- v. Although the product under consideration is classified under Customs sub-heading No. 8503 under Chapter 85 of Customs Tariff Act, 1975, as reported by the domestic industry and reflected in the relied upon imports data obtained from DGCI&S, the PUC is being imported under various other heads as well. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation. It has been contended by the opposite interested parties that the scope of the product under consideration is too wide. It has also been contended that the scope of the product under consideration refers only to castings in a generator used in a windmill. The Authority notes that there are at least three terminologies in vogue in this regard - (a) windmill; (b) wind turbine; and (c) wind-operated electricity generators. All these nomenclatures are one and the same meant for generating electricity from the kinetic power of the wind. For example, the Customs authorities have issued Notification No. 21/2014- Customs dated 11th July 2014 which refers to “Parts and raw materials required for use in manufacturing the Wind Operated Electricity Generators”. This further proves that when it refers to “Wind Operated Electricity Generators”, it actually refers to wind mill. The Authority thus notes that windmill, wind turbine and WOEG refer to the same product and castings for WOEG are nothing but castings for windmill or castings for wind turbine.
- vi. The Authority notes that the basic production process involved in the production of the product under consideration is production of raw casting. Once raw casting has been made, it undergoes multiple machining operations. These machining operations can be performed either by the producers themselves or by stand alone parties specializing in machining operations (in China or in India) or by the end consumers themselves. Further, a large number of castings are collectively used in a windmill. Some of these castings are assembled along with other products to prepare a sub-assembly. Eventually, a windmill comprises of a number of these sub-assemblies. Therefore, the eventual consumer has a choice of buying the product under consideration at any stage of its production process and even as a part of a sub-assembly.
- vii. Some of the sub-assemblies used in a windmill include Gear Box, Nacelle assembly and Hub pitch assembly. These sub-assemblies comprise of castings and other components. For example, Nacelle assembly consists of base frame, Gear Box consists of Planet Carrier, Housings, Torque arm and Hub assembly consist of Rotor hub/Hub and a pitch system. Therefore, it is open to a consumer to either buy a casting and other mating parts separately and assemble at its own place, or, instead buy the sub-assembled product as well.
- viii. The operations involved in preparing sub-assembly are almost a screw driver technology and efforts involved are quite insignificant in proportion to overall operations carried out. Therefore, it is quite feasible for an eventual consumer to buy sub-assembled products instead of buying castings and other products separately. The Authority, therefore, notes that if the scope of the PUC does not include the sub-assemblies, it shall defeat the very purpose of imposing any trade defense measure, if any. The Authority however appreciates that the scope of the PUC cannot be extended to entirety of sub-assemblies, merely because it contains castings within the scope of the measures. The Authority therefore holds that it is appropriate to consider sub-assemblies within the scope of the product under consideration so long as the scope of the CVD measures, if any, is limited to casting portions of the sub-assemblies.

- ix. For the reasons similar to inclusion of sub-assemblies, it is appropriate to consider castings that may be imported as a part of equipment/component within the scope of the product under consideration so long as the scope of the measures is limited to casting portions of these equipments/components used for wind mills or wind turbines or wind-operated electricity generators.
- x. In view of the above, the Authority holds that the scope of the product under consideration defined in the notice of initiation is appropriate and defines the scope of the product under consideration for final determination as follows:

*"Castings for wind-operated electricity generators also known as castings for windmill or wind turbine, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators"*

#### **D.5. Like Article**

12. The WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures defines like product as:

*"[T]he term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike; in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration."*

13. Following are the observations made by the Authority in regard to the like article:

- i. The product under consideration in the present investigation is "Castings for wind-operated electricity generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators".
- ii. A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc.
- iii. Various castings parts are used in a wind mill at different places at the top of wind mills. Various parts are produced by similar production process, using similar raw materials and differ essentially in their shape, size, design, and extent of machining depending on the place where these casting parts are required to be used in eventual application. Therefore, different parts of castings fall in the same general category of castings. Casting is a very wide terminology and there are several types of castings produced for different purposes. The present investigation is however limited to casting for WOEG only. Since different types of castings are interchangeably produced and differ only in terms of shape, size, design, extent of machining, different types of castings constitute one article for the purpose of present investigations. It is, however, recognized that different types of castings are produced to meet different end application and these castings may differ significantly in terms of their associated costs and prices. It would, therefore be not appropriate to do a comparison of imported product price with the domestic industry price/NIP on the basis of weighted average of different types of castings. The Authority has therefore devised a model match criteria in order to ensure fair comparison between the domestic product and imported product as elaborated separately herein below. However, difference in costs and prices of different types of castings does not mean that each casting is a different article.
- iv. The Authority notes that the PUC can be broadly categorized into different types of castings produced for different end applications in a wind mill. For example, a Hub is one of wind turbine's heaviest components, weighing 8 to 10 tons for a 2-MW turbine. The hub is produced and designed to be rigid yet able to absorb a high level of vibration. Whereas Rotor Nave is the component which, with the help of the rotor blades, converts the energy in the wind into rotary mechanical movement. And, Base Frame is used to give base to the blades or in which the blades are fitted in. Different types of castings produced and sold in this industry are listed below along with their end application:

SN	Type of Casting	Application
1	A - Hub, Rotohub, Rotor Nabe	Connects the Three Blades and transmits the rotational Movement to the Gear Box. The hub is also connected to the pitch mechanism of the Machine.

SN	Type of Casting	Application
2	B - Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation	Sits on the tower and supports the load of Hub, Rotorshaft, Gear box, Generator, the nacelle cover and other smaller assemblies. The Framesa Yaws also is connected to the Yaw mechanism of the machine.
3	C - Bearing Housing with or without the use of Front & Rear, Bearing Support.	The Bearing Housing houses the bearings and supports the Rotor shaft which rotates on the bearing housing.
4	D - Hollow Shaft	Hollow Shaft Houses the Main Axle or the rotoshaft and in this design the shaft is stationary and the hollow shaft connects the hub to the generator.
5	E - Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft (At times can be forged)	The main Axle is attached to the main frame and bears the load of the hub, and other stationary and rotating parts
6	F - Lateral Suspender, Pitch Stop	Lateral Suspensor suspends on to a Main Frame. Pitch Stop for the Pitching Mechanism.
7	G - Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor	The Stator and rotors are part of the generator.
8	H - Torque Arm Support, rear Frame	Torque arm and supports are meant for holding the gear box in position.
9	O - Others	Not Considered Elsewhere

- v. It is noted that different types of castings differ in terms of associated cost and price and therefore the type of casting has been considered as one of the parameters for comparison purposes. Further, the product can be sold in raw form or machined form. In view of significant difference in raw and machined form of the product, this factor has been used as a parameter for fair price comparison. On the basis of the above, the Authority has devised following model match criteria in order to ensure fair comparison:

**PCN Terminology- Castings for WOEG**

Field Description	SN	Type of Casting
Product Type	Z	A - Hub, Rotohub, Rotor Nabe
		B - Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation
		C - Bearing Housing with or without the use of words Front & Rear, Bearing Support.
		D - Hollow Shaft
		E - Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft (At times can be forged)
		F - Lateral Suspender, Pitch Stop
		G - Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor
		H - Torque Arm Support, rear Frame
		O – Others
Processing	X	M= Machined C= As Cast
Capacity	Y	As per the following table



Capacity (in KW)		PCN
100	299	A
300	499	B
500	699	C
700	899	D
900	999	E
1000	1000	F
1001	1199	G
1200	1399	H
1400	1599	I
1600	1799	J
1800	1999	K
2000	2000	L
2001	2099	M
2100	2100	N
2101	2299	O
2300	2499	P
2500	2699	Q
2700	2899	R
2900	3099	S
3100	3299	T
Above 3300		Z

- vi. The petitioner claimed that the goods are produced as per requirements and specifications given by the consumer/buyer and therefore the goods supplied by the domestic industry and Chinese suppliers have to confirm to the specifications laid down by the consumers. This claim of the petitioner has not been disputed by the interested parties.
- vii. The product is primarily sold in pieces/nos. The price depends upon the design, size, weight, and processing involved in a particular casting. Two castings of the same nature like HUB of two different windmills may not be the same in terms of associated weight, design, machining and process involved. Hence, the two may differ significantly in terms of cost and price.
- viii. The sole responding Chinese exporter has admitted that the goods produced by them are comparable to the goods supplied by the domestic industry. Some of the consumers have however claimed that the goods produced by the domestic industry are different from goods imported from China primarily in terms of quality.
- ix. The Authority notes that the argument of the interested parties is with regard to quality differences perceived by one of the consumers. The Rules itself recognize a situation where the goods produced by the domestic industry may not be alike in all respect and provides that the authority shall consider in those situations another article which, although may not be alike in all respects to the product under consideration, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.

- x. The interested parties disputing the acceptability of the goods produced by the domestic industry have not provided evidence to establish that the goods produced by the domestic industry cannot be considered as a product which, although may not be alike in all respects to the product under consideration, has characteristics closely resembling those of the product under consideration. The authority also notes that there are significant contrary submissions by the domestic industry and interested parties with regard to acceptability of the goods produced and supplied by the domestic industry. The domestic industry has contended that it has produced and supplied goods to several consumers, including to the interested parties disputing the quality of the domestic industry product, in India and overseas for past several years and there is no instance where the goods produced by the domestic industry have been rejected. The domestic industry has also stated that the consumer has raised the quality issue whereas the real issue is the low priced imports accessible to the consumer. The domestic industry has also contended that the fact that one of the consumers has significantly switched over to the domestic industry product from imports further establishes that the domestic industry product is in fact substitutable with the imported product.
- xi. The Authority notes that the domestic industry is producing and selling the product under consideration for past several years both in India and abroad and there is no evidence of failure of the goods produced by the domestic industry. After careful consideration of the submissions made by various interested parties, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the goods imported from China in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Some of the consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. Further, goods supplied by the domestic industry and imported from China serve the same general purpose and perform the same function.
- xii. In view of the above, the authority holds that subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from China in terms of the Rules.
- xiii. The product is design and model specific depending upon the design and capacity of the wind mill producers. However, both the domestic producers and exporters supply to the same wind mill producers in India.

## **E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

### **E.1. Submissions made by the Domestic industry**

14. The submissions made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. The present petition has been filed by Larsen & Toubro Limited whose production constitutes more than 50% of Indian production. M/s Patel Alloys Steels Pvt. Limited has supported the petition.
  - ii. Petitioner is eligible producer of the subject goods in India. Production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production. The petitioner, therefore, constitutes domestic industry and satisfies the requirement of standing under the Rules.

### **E.2. Submissions by GOC**

15. No relevant submission has been made by the GOC with regard to scope of domestic industry and standing.

### **E.3. Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

16. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. There is no supporting letter enclosed with the petition from Patel Alloys.
  - ii. It is mentioned in the petition that there are number of other producers in India. However neither exact number nor an estimate of their numbers has been provided.
  - iii. Petitioner has filed two sets of data – one in the original petition and other in the updated petition. In the original petition filed by the Petitioner, it has estimated the production of other producers to be 2500MT for the period October 2012 to September 2013. However, in the revised annexure filed by the Petitioner for the updated and enlarged period – October 2012 to December 2013, the production has actually witnessed a sharp decline, instead of increasing further. It is incomprehensible as to how production for a larger period, which includes the period covered in the original petition, can be lower.

**E.4. Examination by the Authority**

17. Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules defines domestic industry as under:-

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".*

18. The Authority notes that the petition has been filed by Larsen & Toubro Limited. Subsequently, a copy of support letter by M/s Patel Alloys has been submitted along with information concerning capacity, production and sales. The production by the petitioner constitutes a major proportion in the Indian production of the subject goods. Petitioner has neither imported the product under consideration from the subject country during the POI nor is related to either importers or exporters of subject goods from the subject country. The Authority, therefore, notes that the petitioner has standing to file the present petition and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

**F. CONFIDENTIALITY****F.1. Views of the Domestic industry**

19. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petitioner has claimed only such information as confidential, confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
- ii. The petitioner has provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
- iii. The response has been submitted by GOC and one of the exporters of the subject country. Non-confidential version of the questionnaire responses filed by them is grossly inadequate. Even information that is publicly available (such as names of the raw material etc) has not been disclosed. Out of the identified 44 schemes, the GOC has responded to only 3 schemes and the exporter has responded only 2 schemes.
- iv. Exporter has not even provided indexed information.

**F.2. Submissions by GOC/producers/exporters/importers/other interested parties**

20. The submissions made by the GOC/producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. Excessive confidentiality has been claimed by the petitioner. Petition is incomplete and does not meet the 'adequacy and accuracy' standards as supporting evidence.
- ii. The petitioner has not provided soft copy of the import statistics in MS-Excel format, evidence in respect of existence of each subsidy program, evidence of subsidy program being applicable to the product concerned, evidence of subsidy program being applicable to this particular industry and evidence of other domestic producer and source of their production quantity.
- iii. In terms of Rule 7(7) of CVD Rules, Designated Authority is mandated to make available the evidence presented by one interested party to other interested parties. In the petition filed by the Petitioner Domestic Industry, lot of information has not been shared by the Petitioner.
- iv. Rule 6(2) of CVD Rules requires the application to be supported by evidence of, inter-alia, subsidy and if possible, its amount. Petitioner has nowhere provided any information whatsoever with respect to amount of subsidy.
- v. In addition, certain benchmark would have been used by the Petitioner for each subsidy program to arrive at the level of subsidization. However, there is no information with respect to such benchmark used.

**F.3. Examination by the Authority**

21. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of the Rules, 1995 provides as follows:-

*8. Confidential informations. ( 1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a*

*confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.* Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

22. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
23. As regards the submission of the opposite interested parties that the petitioner has not provided soft copy of the import statistics, the Authority notes that the public version of the transaction wise imports statistics submitted by the domestic industry from DGCI&S has been made available in the public file. However, it is not mandated that either the domestic industry or the Authority should make available the soft copy of the relied upon imports statistics in the public file. The Authority initiated the present investigation after examining and satisfying prima facie the countervailability of the alleged subsidy programmes being provided by the GOC to the producers/exporters of the subject goods in China.

#### **G. Miscellaneous Submissions**

##### **G.1. Miscellaneous Submissions made by the Domestic Industry**

24. The miscellaneous submissions made by the domestic industry and considered relevant by the Authority are as follows:
  - i. GOC's contention that the petition suffers from inadequacy and inaccuracy of the information to justify initiation of investigation is baseless. The petition contains the evidence in the form of decision of other investigating authorities demonstrating that the schemes brought out by the petitioner were indeed found countervailable by the other investigating authorities. It is thus not a case that the petitioner merely made allegation about existence of some schemes and provide no evidence to establish countervailability of these schemes. Further, evidences provided by the petitioner during the course of the investigations establish the existence and countervailability of these schemes.
  - ii. Petition contains sufficient evidences to justify initiation of investigation. It cannot be expected that all evidences required for making a determination shall be made available to the Authority at the stage of initiation itself. It is well established WTO jurisprudence that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses.
  - iii. The various schemes identified by the petitioner can be categorized into – (a) country wide programs, (b) sector specific programs, (c) region specific program. It is well known fact that casting producers in China are entitled for various incentives/subsidies identified by the petitioner. In fact, the evidences provided by the petitioner clearly establish that casting producers have been benefitted from these countervailable subsidies.
  - iv. The responding exporter has not fully co-operated – (a) all entities involved in production and sale of the PUC have not cooperated with the Authority; (b) the exporter has restricted information only for POI in respect of various kinds of scheme, whereas the information should be provided over useful life of the assets for those schemes where benefit goes over the life of the assets; (c) the exporter has withheld vital information from the Authority.
  - v. The annual report as well as the website of the exporter clearly shows that the company has received subsidies. However, the exporter has nowhere made references to these schemes in the questionnaire response.
  - vi. GOC has willfully restricted its response only to a few schemes and has not replied to all the schemes identified by the petitioner. Further, while stating that certain programs have been rescinded, GOC has

provided no evidence establishing the same, nor GOC has stated that there were no residual benefits in these programs; nor GOC has even stated that no other program have not been introduced while rescinding these. A number of programs by GOC conferred benefits which shall continue even if the program is withdrawn (popularly known as "residual benefits" under subsidies). Further, GOC has withdrawn few programs and brought some other programs. Above all, even when GOC stated that these programs have been withdrawn in 2008, other investigating authorities have held existence of these programs and conferment of countervailable subsidies in these programs by other investigating authorities.

- vii. Petitioner has identified a large number of programs which are China wide and are applicable to all industry. Therefore, to such extent, it is not necessary to establish availment of benefits by each and every producer of casting in China. As regards existence of financial contribution and benefits conferred, the petition specifically provides the relevant information.
- viii. There is no basis for the statement that reference to other jurisdiction's findings is unsubstantiated assertion. Majority of the program are product neutral and therefore the mere fact that these schemes pertain to different products is immaterial.
- ix. The statement in the application that evidence is not available should be read as reference to "independent evidences". Petition contained sufficient evidences. Further, the GOC has been provided opportunity for consultation prior to initiation and therefore GOC had sufficient opportunity to establish that the scheme identified by the petitioner were not applicable to the producers of the PUC in the present case.
- x. Reference to Appellate Body (AB) finding (WT/DS 379/AB/R dated 25.3.2011) is entirely immaterial as regards contents of the application. The AB finding is with regard to determination which arose in a situation where the quality and quantity of evidence did not improve at all during the course of the investigation. The relevant AB order may be perused, which clearly demonstrates that authority in that case made no effort to ascertain whether the factual position remained the same in the present period as compared to previous determination made by the US DOC.
- xi. The WTO AB held that there may be material changes in the factual positions between previous and present determination. However, in the instant case, there has been significant improvement in the quality and quantity of evidences that was available in the application and now available to the Designated Authority for determination. Petitioner has now provided ample evidence to demonstrate that the factual position with regard to these schemes has remained the same. Further, GOC or the responding exporter has not provided evidence to show that the factual position has materially changed (barring the argument that some schemes were rescinded in 2008, an argument which is incorrect and has been found so by other authorities).
- xii. GOC has not established absence of residual benefit in these programs. Further, the other investigating authorities continue to countervail these programs despite the claim that these have been rescinded.
- xiii. No reasonable burden of proof is being imposed on the exporting country or the exporters in the present case. Firstly, if the scheme has been withdrawn, there should be a notification and it should not be difficult at all for GOC to provide a copy of the same. Secondly, barring one exporter, no exporter has cooperated with the Authority. Therefore, question of imposing unreasonable burden on an exporter does not arise at all. As far as cooperating exporter is concerned, no instance has been pointed out with regard to unreasonable burden imposed by the Authority. Evidently, the GOC has simply referred to the decision of the investigating authorities without establishing how the same applies to the facts of the present case.
- xiv. Information and evidence is required to be co-related with PUC only if the program is specific to the PUC. If the program is not specific to the PUC, question of providing information or evidences relating to PUC will not be critical. For example, if "Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)" program provides benefit to the FIEs established in the SEZ zone excluding Pudong area, it is not necessary to provide information and evidence that a producer of PUC located in SEZ areas have in fact availed the benefit. It would be reasonable to proceed on the basis of an assumption that a company entitled for the benefits if it is located in any of the SEZ other than Pudong area and would have availed the benefit available under the program. It is for the exporter to establish that despite eligibility, it has not availed the benefit.
- xv. There is only one Chinese company who has responded in the present investigation. The information collected by the petitioner shows existence of almost 50 exporters of product concerned in China. The questionnaire response filed by GOC may be perused where one of the questions concerns names and addresses of various producers of the PUC in China. The information provided by the GOC may be

co-related, which shall show that despite existence of a large number of producers in China, only one producer has responded to the Authority. Further, information and evidences provided by the petitioner in the petition and thereafter so far during the course of the investigation clearly establishes that the producer of the PUC in fact has availed subsidies.

- xvi. The contention of GOC that power to investigate the subsidy is not unlimited and any information or evidence required beyond the legal requirement would be a contrary to the spirit and letter of the WTO laws is irrelevant. No information beyond the legal requirement is being demanded and therefore statement is without basis.
- xvii. The importers of castings for Wind Operated Electricity Generators (WOEG) are currently importing Castings from China at subsidized prices, whereas similar goods are being produced/can be produced by domestic industry. Casting industry is very important for development of energy industry in the Country. Unfairly low priced imports have caused and are causing significant injury to the casting industry in India.
- xviii. The subject goods originating in China have been benefited from actionable subsidies provided by various levels of the Government of China. These schemes have been held to be countervailable by the other anti dumping authorities of Canada, Europe, Australia and USA.
- xix. Belated participation by parties should not be permitted. Indian Wind Turbine Manufacturers Association attended the oral hearing though without having filed even a single page of information. Participation by the association is one year and 20 days after the deadline for response.
- xx. The response filed by the GOC has been grossly deficient. Further, GOC has responded only in respect of the responding exporter and no information has been provided in respect of rest of the exporters in China.

## **G.2. Miscellaneous Submissions by GOC**

25. The miscellaneous submissions made by the Government of China PR and considered relevant by the Authority are as follows:
  - i. The petition contains insufficient evidence. In accordance with Article 11.2 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), an application under paragraph 1 shall include sufficient evidence of the existence of (a) a subsidy and, if possible, its amount, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement, and (c) a causal link between subsidized imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this provision in the ASCM.
  - ii. As per the clarifications by the Panel on China – Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel (US), evidence of the existence of a subsidy requires evidence of the existence of a financial contribution and a benefit and the evidence of the nature of the subsidy includes evidence regarding whether the subsidy is specific.
  - iii. The petition has alleged 7 major categories of subsidies containing in total 44 subsidy programmes. But, it failed to identify which specific subsidy programs is related to the product under investigation and whether these programs existed and financial benefit conferred in the sector within which the exporting producers fall. The petition simply collected or pasted findings made by other jurisdictions involving other industrial products to present an unsubstantiated assertion, assuming all those 44 subsidy programs existed to have a financial contribution and a benefit.
  - iv. Simple reference to other findings is not allowed. In US – Definitive Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, the Appellate body states that findings of other investigations do not suffice as a reasoned and adequate explanation. This is especially so considering every single investigation is different from others in factual issues such as products involved, period concerned and entities targeted. The present petition is merely a grouping of different findings reached by other WTO members investigating different products of different sectors of industry, without identifying specifically the subsidies relevant for the subject merchandise.
  - v. Certain subsidy programs have been rescinded and thus confer no benefit. Sufficient evidence in support of rescinding of certain programs has been furnished along with questionnaire response which should be enough to terminate the investigation in respect of these rescinded programs.
  - vi. The investigating authority should not place unreasonable burden of proof on the exporters. The exporters ought to be accorded with rights to submit information and evidence to disprove or rebut any allegations made by an industry of importing country.

- vii. The investigating authority is in a neutral position to collect and analyze all the submitted or collected information and evidence. A hearing can also be organized to further hear views and comments. Thus any information or evidence that is not necessary or bears no direct relevance to the investigated product shall not be requested, because this action may overly burden an exporter.
- viii. Development of energy industry, especially green energy, is one of the key economic agenda for Govt of India. Imposition of countervailing measures may not be conducive for the growth of this sector in the country.

### G.3. Miscellaneous Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

26. The miscellaneous submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petition is deficient since it is not supported by any evidence. Moreover, it does not also exclude the subsidy programs rescinded in the exporting country. Petitioners have failed to provide evidence to show that the subject goods coming to India are subsidized and are countervailable. Accordingly, the entire investigation needs to be terminated.
- ii. List of 44 schemes given in the petition has not been duly substantiated by the petitioner. The submission of the Petitioner in this regard is grossly inadequate and should not be considered.
- iii. The initiation of the present anti subsidy investigation is inconsistent with the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures "SCM Agreement" on account of procedural and substantive issues.
- iv. New subsidy allegations cannot be included in the present investigation. Even if a new subsidy allegation is accepted by the Authority, no investigation shall be initiated against those new subsidies at this belated stage.
- v. As per Article 1 subparagraph 2 of the ASCM agreement a subsidy is countervailable as per Part III or V of the agreement and states that:

*A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2.*

Therefore only if a subsidy is specific, it will be countervailable. It is necessary for the Domestic Industry to prove that the benefit is availed by the producers of the product under consideration.

- vi. Rule 18 of CVD Rules states that authority shall disclose the essential facts under consideration and permit the interested parties to defend their interests. Therefore, it is mandatory under the Indian law to hold another hearing after disclosure of essential facts so that the interested parties can make their views known and defend their interests adequately.
- vii. Vendor selection process for the product under consideration is quite lengthy and the vendor is selected after a validation process that takes several months. Resultantly, it is not at all easy to change vendors easily once they are chosen. It is totally incorrect to suggest that buyers choose imports over domestic product based on price factors alone. Designated Authority needs to consider this aspect as well while examining demand-supply trends.
- viii. Also, at page 8 of the petition filed by Petitioner, it has been stated that two castings of the same nature may not be same in terms of associated weight, design, machining and process involved. Thus, in terms of the above submissions, it is possible that the Chinese made casting of same size may still have substantially different weight compared to Indian like article. As a result, unit of measurement in terms of Kgs or MTs may not correctly aid in examination of injury to the domestic industry.
- ix. IWTMA is an interested party in the present investigation as per the Rules and his rights cannot be taken away on ground of procedural requirements. Merely because IWTMA has not made any submissions until the oral hearing does not take away its right to present itself during the oral hearing and provide necessary information for the purposes of the present investigation. When Authority itself has extended time for completing the investigation and has conducted oral hearing during such extended period, in such a case, the rights of interested parties cannot be curtailed on the ground that investigations are time-bound.
- x. Domestic Industry has only provided line by line sorted import statistics for the POI and the injury analysis period. Domestic Industry should have provided the raw data and methodology adopted for sorting the data. Authority has also not provided the transaction wise relied upon data. Since

there is no set tariff classification for the product under consideration, unless transaction wise import statistics are examined, correct level of imports cannot be ascertained.

- xi. The casting for wind operated electricity generator is non-conventional, non-polluting and renewable source of energy. Castings are used in wind turbines to be used in wind mills along some other non casting parts which generate electricity using wind energy. If the duty is imposed on the castings it will be against the policy of government to promote renewable and non-conventional source of electricity. Therefore, the present investigation should be terminated and no duty should be imposed on casting for wind operated electricity generator.
- xii. Energy generation is the high priority for the country today for achieving greater energy production India's total energy consumption has been rising over the years and is met mostly by conventional energy sources such as coal, oil, and natural gas. Ever increasing consumption of energy not only increases our total expenditure on energy but also increases our share of greenhouse gas emissions. Imposition of countervailing duty will be against public interest.

#### **G.4. Views Expressed by the Ministry of New & Non-renewable Energy (MNRE)**

27. The following are the views expressed by MNRE:

- i. MNRE guideline allows installation of only type tested and type certified wind turbine as per IEC and GL systems certification schemes from internationally accredited testing and certifying agencies or National Institute of Wind Energy. Wind turbine components must comply with the required standards laid down by the above testing and certifying scheme.
- ii. The total demand of casting components of WOEG will be 7,00,000 MT by 2022 as against the local manufacturing capacity of 90,000 tonne/annum from L&T and Patel Alloys only.
- iii. MNRE has set an ambitious target of 60 GW capacity installation by 2022. Accordingly, the demand for the casting components would increase manifold. However, domestic manufacturing sector should not suffer due to unfair trade practices and a level playing field is required to be provided to them.
- iv. Domestic manufacturing companies have the capacity to meet the required demand, but quality of the products needs to be ensured.

#### **G.5. Examination by the Authority**

28. In the notice of initiation of the present investigation, Authority had stated that the following prima facie actionable subsidy programs are proposed to be investigated:

Sl.No	Heads	Program No.	Schemes
1.	Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas-	Program No. 1	Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area).
		Program No. 2	Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
		Program No. 3	Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
		Program No. 4	Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
		Program No. 5	Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
		Program No. 6	Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas



Sl.No	Heads	Program No.	Schemes
		Program No. 7	Preferential Tax for Casing and Forging System
2	Grants	Program No. 8	The State Key Technology Renovation Projects Fund
		Program No. 9	Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments
		Program No. 10	Research & Development (R&D) Assistance Grant
		Program No. 11	Innovative Experimental Enterprise Grant
		Program No. 12	Superstar Enterprise Grant
		Program No. 13	Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"
		Program No. 14	Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry
		Program No. 15	Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment
		Program No. 16	Innovative Small and Medium Enterprise Grants
		Program No. 17	Grants to Privately-Owned Export Enterprises
3	Equity Programs	Program No. 18	Equity infusions
		Program No. 19	Unpaid dividends
4	Preferential Loans	Program No. 20	Preferential loans and interest rates to the casting industry
5	Preferential Income Tax Programs & Tax Incentives	Program No. 21	Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years
		Program No. 22	Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
		Program No. 23	Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive
		Program No. 24	Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
		Program No. 25	Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments
		Program No. 26	Preferential Tax Policies for Domestic Enterprises Purchasing Domestically Produced Equipments for Technology Upgrading Purpose

Sl.No	Heads	Program No.	Schemes
		Program No. 27	Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
		Program No. 28	Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
		Program No. 29	Tax concessions for Central and Western Regions
		Program No. 30	Income tax credit for the purchase of domestically manufactured production equipment
		Program No. 31	Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
		Program No. 32	Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials')
		Program No. 33	Tax credit concerning the purchase of special equipment
		Program No. 34	Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
		Program No. 35	Dividend exemption between qualified resident enterprises
6	Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery	Program No. 36	Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment
		Program No. 37	Reduction in Land Use Fees
7	Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value	Program No. 38	Input Materials Hot Rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
		Program No. 39	Hot rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
		Program No. 40	Electricity provided by Government at less than Fair Market Value
		Program No. 41	Land for Less Than Adequate Remuneration to Companies Located in Industrial or Other Special Economic Zones
		Program No. 42	Program consisting of provision of water for less than adequate remuneration
		Program No. 43	Provision of various goods for less than adequate remuneration
		Program No. 44	Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration
		Program No. 45 (Added in later submission)	Input Materials (raw material) & Utilities provided by Government at less than Market value

29. As regards the argument of the opposite interested parties that the petition is deficient and devoid of evidences and therefore the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the petitioner has provided the information that was reasonably available to them to support the petition and the investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence furnished by the domestic industry showing existence of countervailable subsidies, injury and causal link to justify initiation of the investigation in accordance with the ASCM and Indian Act and the Rules. The Authority notes in this regard that the petition need not have

evidence at the stage of initiation of the investigation as is required for making a final determination. The Authority is required to merely satisfy itself that there is sufficient prima facie evidence to justify an initiation. The Authority has called additional information wherever required and verified the information furnished by the domestic industry.

30. As regards the contention that the Petitioner itself had stated in the petition that evidence was not available, the Authority notes that even though the petition's write up part stated that evidence was not available, the petition indeed included evidence in respect of each of the schemes. Even for these schemes where the petitioner had stated that the evidence was not available, Petitioner had provided evidence in the form of determination of other investigating authorities. While the authority appreciates that the determinations made by other investigating authorities may not be a sufficient basis to make a determination, the same at the least constitutes sufficient evidence to justify initiation of investigations. The petition contained sufficient prima facie evidence to show that these alleged schemes have been held countervailable by various other Authorities.
31. It is, thus, noted that even at places where the petitioner has stated that the relevant evidence has not been enclosed, in fact, the petition contains evidences in the form of findings of other investigating authorities. The Authority notes that at the stage of initiation, the Authority may not have evidence linked to individual producers/exporters of the PUC, particularly in a situation where there is no publically available information in China. None of the interested parties have shown existence of publically available information/evidence while contending that the petitioner has not provided relevant information. The Authority also notes that the evidences brought out by the petitioner in the petition shows that the CVD margins determined by some of the investigating authorities were as high as 10.54% for loans provided and 9.71% for preferential tax exemption for R&D and for preferential tax policies for FIEs cumulatively in respect of various programs and where eligibility is contingent upon export performance the margin is high up to 5.3%. The Authority notes in this regard that the de-minimis limits under the rules is mere 1% for developed countries and 2% for developing countries and therefore these schemes alone justified initiation of investigation.
32. The Authority notes that while contending that several schemes are no longer in force, the GOC has not provided any documentary evidence to show that the scheme is no longer in force. The Authority considers that if a program was introduced by the GOC at some point in time and was withdrawn subsequently, the GOC should have in its possession relevant documents showing introduction of the program and withdrawal of the same. It is, however, noted that while contending that some of the alleged schemes are no longer in force, the GOC has not provided either the documents relating to introduction of the program or documents relating to withdrawal of the program. The Authority, therefore, holds that the contention of the GOC with regard to withdrawal of the programs is unsupported with relevant documentary evidences. Since the GOC did not consent for on the spot verification of their data/information including claims made by them during the course of this investigation, the veracity of their contention that many erstwhile subsidy programmes have been rescinded cannot be accepted. Moreover, other investigating authorities have found these schemes to be in existence and countervailable in their findings.
33. The Authority further notes that vide notifications No. G/SCM/N/220/CHN, G/SCM/N/253/CHN and G/SCM/N/284/CHN dated 30 October 2015, the GOC has notified to the WTO several schemes/programmes under the SCM Agreement, covering most of the schemes/programmes which are under challenge in the present investigation.
34. As regards examination of the accuracy and adequacy of the evidence and satisfaction of the Authority with regard to sufficiency of evidence to justify initiation, the Authority notes that the petitioner provided evidences in the form of decisions of other investigating authorities where alleged programs were countervailed. Further, petitioner provided other relevant evidences in support of their claim. The Authority notes in this regard that EC in the matter of "imposing a countervailing duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China" made final determination regarding some schemes solely based on determination made by US Decision Memorandum in the matter of Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe. Under these circumstances, the Authority considers that at the stage of initiation, it is only a question of accuracy and adequacy of the evidences and prima facie satisfaction of the Authority. The authority holds that it is not appropriate to contend that there was no evidence for 19 programs in the application. The Authority also notes the decision of the WTO in the matter of Guatemala Anti-Dumping Investigation Regarding Portland Cement from Mexico (WT/DS60/R) wherein it was held that it is not necessary that the Authority restricts itself to the evidences brought by the petitioner in their petition. The Authority can consider evidence otherwise available in the petition, even if not relied upon by the petitioner.
35. With regard to the contention that subject merchandise is related to "green industry" and any countervailing measure against their imports may adversely affect growth of this sector, the Authority notes that as demonstrated by the domestic industry the costs on account of castings forms hardly 3-4% of the total project cost. Therefore, as argued by the domestic industry, the impact of the countervailing measures, if any, even at 100% level, may imply hardly 0.1% increase in costs to a consumer. This claim of the domestic industry has

not been refuted by the opposing interested parties. In any case, the Authority notes that the purpose of anti-subsidy duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the subsidization of goods so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of CVD measures would not restrict imports from China in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. Imposition of CVD measures would remove the unfair advantage gained by imports, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

36. As regards New Subsidy Allegations, the Authority notes that while the petitioner initially requested extension of investigation to include these new subsidies, the petitioner subsequently modified its contention and submitted that the evidence brought out by the petitioner with regard to existence of other subsidy schemes should be considered to hold that the GOC has not disclosed all the schemes which are in vogue in China and where the casting producers have benefitted from countervailable subsidies. The Authority notes in this regard that extension of investigation to these schemes now identified by the petitioner shall not be appropriate considering the overall time left for completion of the present investigations. Extension of investigation to these new subsidy schemes identified by the petitioner implies calling relevant information from interested parties and thereafter conducting elaborate investigations about these schemes as well. Thus, the Authority considers it appropriate not to extend the investigation to cover these new schemes brought out by the petitioner on record of the investigation. It is, however, noted that the GOC has not provided any information with regard to these subsidy schemes prevalent in China inspite of specifically seeking this information in the questionnaire issued by the authority. The Authority considers it appropriate not to extend investigations to these schemes at this stage considering the time left for completion of the investigation.
37. As regards the argument that injury to the domestic industry is because of declining demand and withdrawal of Accelerated Depreciation scheme, Generation Based Incentive, the Authority notes that while demand for the PUC declined over the injury period, it is seen that market share of domestic producer as a whole declined from 14,122 MT to 6,888 MT over the injury period. Thus, while the domestic industry was already suffering because of declining demand, the subsidized imports took away increasing share from the declining market of the domestic producers.
38. Some of the interested parties have contended that Authority should hold another hearing after issuance of disclosure of essential facts. The interested parties have compared the legal provision in anti dumping and anti subsidy law and have contended that presence of "permit the interested parties to defend their interest" phrase under anti subsidy law and absence of same under anti dumping law implies that the Authority should provide an opportunity for oral hearing to the interested parties after disclosure of essential facts. The issue was examined in detail by the Authority. It is noted in this regard that anti dumping rules provides as follows with regard to issuance of disclosure statement:-

**Indian Antidumping Rules: "16. Disclosure of information. -** *The designated authority shall, before giving its final findings, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for its decision."*

**WTO Agreement provision: "6.9** *The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests."*

**The ASCM Provision: "12.8** *The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested Members and interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests."*

39. Opportunity for oral hearing has been provided under Rule 7 of the CVD Rule which is extracted below:
 

*"7 The designated authority may allow an (6) interested country or an interested party or its representative to present information relevant to the investigation orally also, but such oral information shall be taken into consideration only when it is subsequently reproduced in writing."*
40. From the above, the Authority notes that a plain reading of the rule that the Authority is required to disclose essential facts of the investigation to the interested parties. In fact, the Agreement also makes it evident that the Authority is required to disclose the essential facts so as to enable them to defend their interests. This does not put any obligation on the Authority to allow the interested party to submit their comments orally after the issuance of the disclosure statement. The Authority in any case will provide opportunities for the interested parties to provide their comments after issue of disclosure statement and address those comments to the extent considered relevant in the Final Findings. It has been contended that the Authority should not place unreasonable burden of proof on the interested parties. The Authority, however, holds that the statement is

without justification. The Authority has not sought any information or evidence which can be construed as unreasonable burden. If some subsidy programs were prevalent in China, it should not be difficult either for the exporter or for the GOC to provide relevant information about introduction or withdrawal of these programs. If a large number of programs are being maintained in China and if these large numbers of programs are being administered by different authorities in China, it is in fact an ominous task for petitioner to provide all these information to the authority. The Authority also notes the contentions of the petitioner in this regard that lot of information with regard to these schemes are not publically available in China.

41. The Authority notes the contention of GOC that the power to investigate the subsidy is not unlimited and any information or evidence required beyond the legal requirement would be a contrary to the spirit and letter of the WTO laws. The Authority notes that no unlimited powers have been used by the Authority. The Authority has merely sought information with regard to existence of certain programs. In fact, barring two programs out of 44 programs, it is not even the contention of the GOC that these programs identified by the petitioner were never in existence in China. Only for two schemes, the GOC made submissions that there was no such program in vogue in China. Even for these two programs, the petitioner domestic industry contended that they used an incorrect name and otherwise a program conferring the benefits identified by the petitioner does exist in China. Further, the Authority merely sought information with regard to nature of program, details of administering authority, relevant legal statute, eligibility criteria, evidence regarding the commencement or the termination of the schemes, etc. Authority considers that the information sought by the Authority in any case is not excessive. It is noted in this regard that all investigating authorities seeks similar information in CVD investigation. The contention of GOC therefore that unlimited power has been exercised by the Authority is without basis. It is noted in this regard that while contending that certain programs were no longer in force, the GOC chose not to provide a copy of the document introducing the program and withdrawing the program.
42. As regards treatment of SOE as a public body, Authority notes that the petitioner has initially identified 44 programs, out of which, 37 programs are administered by those Bodies who fall within the category of state (GOC, Provincial, Municipal Corporation, local bodies in China). Only 7 programs were identified by the petitioner, which are being administered by SOE. The actual status of these SOEs could have been established, had the Chinese authority consented for on the spot verification.
43. As regards disclosure of information in the petition, the Authority examined the contention of the interested parties in detail and holds as follows:
  - a. As regards soft copy, the Authority notes that the request is beyond the prescribed proforma. The application proforma does not oblige an applicant to provide information in soft copy in the NCV version of the application.
  - b. As regards lack of evidence in respect of existence of each subsidy program, the Authority notes that the petitioner provided evidence to the reasonable extent and the petition contains information with regard to decision of other investigating authorities where these programs were considered countervailable.
  - c. With regard to evidence of subsidy program being applicable to the product concerned, the Authority notes that out of 44 programs identified in the application, 42 programs were such where the alleged benefits are not linked to the product. The benefit is linked either to the type of the business enterprise or the location where business enterprise was located or the program is contingent upon export. If a program is contingent upon exports, it follows that benefit under the program is available to all the exporters regardless of whether they are manufacturing PUC or other products. In fact, the present investigation is justified by identification of a number of programs which were contingent upon exports and where significant CVD margins were established by other investigating authorities.
  - d. A copy of the support letter from Patel Alloys has been provided by the said Company and was repeated in the post hearing written submissions filed by the domestic industry.
  - e. As regards production of other Indian producers, the petition contains sufficient information establishing that the production by the petitioner was beyond the limits prescribed under the Rules. In fact, it is noted that standing of the petitioner has not materially changed after initiation of investigation.
44. As regards the contention that there cannot be a presumption and it must have been proved that the subsidy enjoyed by the castings manufacturer have been passed on to the other products, one cannot include such downstream products in a CVD investigation, the Authority notes that the petitioner has not included downstream product within the scope of investigation. Petitioner has sought CVD duty on the casting portion of the downstream product that might be imported in future. As far as present period is concerned, information on record does not show any import of the product in the form of assemblies or sub-assemblies

and therefore the question of inclusion of downstream product in the present determination in any case does not arise.

45. As regards the contention that the alleged programs are related to specific geographical areas or cities, no averment that any producer was operating/ located in the geographical area, the Authority notes that GOC has provided a list of more than 200 casting producers in China showing their location. But, further details concerning status of these industries and subsidies availed by them have not been provided. Moreover, GOC did not cooperate to get their or the sole respondent exporter's data verified by the Authority.
46. Some interested parties have referred to the decisions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of SC Automotive Tyre Manufacturers Assn. Versus DA [2011 (263) E.L.T. 481 (S.C.)] and have contended that Designated Authority is bound to follow principles of natural justice and any violation of principles of natural justice by Authority will vitiate the recommendations of the Authority. The Authority holds that the principles of natural justice have been duly complied in the present determination in so far as the same are applicable and relevant. For example, despite the fact that IWTMA Association made itself known at the stage of hearing and did not provide any information upon initiation of investigation and till the stage of oral hearing, the Authority permitted the said association to make submissions orally and thereafter file written submissions. Further, all the submissions made by the Association, to the extent considered relevant, have been examined and addressed in the present final finding.
47. It has been contended that as per Rule 4- DA is required to investigate the existence, degree and effect of any subsidy in relation to the import of an article. Unless the product is defined correctly, effect of subsidy cannot be examined correctly. The Authority holds that article has been defined correctly in the present proceedings. No ambiguity in the definition of PUC has been alleged either by GOC or by the responding exporters.
48. As regards the contention of the interested parties that petitioner's reference to US case of utilities scale wind turbine is not applicable to the present case, the Authority notes that the reference of the petitioner is with regard to countervailable schemes found by the US Authorities in this product. Further, the petitioner has contended that the scope of the PUC in this case is in fact far wider than what has been considered by the petitioner in the present case.
49. As regards the contention that the determination made by other investigating authorities cannot be applied by the Authority, it is clarified that the present determination is not based on *ipso facto* application of determination made by other investigating authorities. The petitioner has referred to these decisions of other investigating authorities to merely establish existence of countervailable subsidies. The Authority has in any case made independent determination in the present case with regard to each and every scheme.
50. With regard to the argument of non application of mind by the DGAD at the time of initiation, the Authority does not agree with the contention and holds that the investigations were initiated only after sufficient prima-facie satisfaction with regard to adequacy, accuracy and sufficiency of evidence to justify initiation.

## **H. SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN**

### **H.1. Introduction**

51. Petitioner alleged that GOC is providing subsidy to its producers/exporters of the subject goods. The Petition contained reasonable prima facie evidence for several subsidy schemes included in both legislation and a number of policy documents which are the basis for the state support to the product. Upon initiation, Govt. of China and one of the producer/exporter from China has filed questionnaire response. The petitioner contended that the goods have been supplied by more than one Chinese producer and questionnaire response has been filed only by one Chinese producer. The petitioner has therefore contended that in any case, Govt. of China should be considered non cooperative to the extent of benefits that might have been availed by other Chinese producers.
52. The authority has considered information provided by the petitioner, the Govt. of China and the sole responding exporter in China with regard to countervailability of various alleged subsidy programs. The authority notes that the Govt. of China has not contended that the product under consideration was produced and exported only by one Chinese producer-exporter during the POI. Further, the authority notes that the Govt. of China has filed questionnaire response in so far as it relates to the responding exporter. The Govt. of China has not provided any information with regard to other Chinese producers-exporters despite acknowledging existence of many casting producers/exporters and schemes that might have been availed by these other producers-exporters.
53. Before proceeding to initiate the present investigation and in accordance with SCM Agreement, the authority invited the Govt. of China for consultations with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement. The consultations were held on 5th May 2014 in New Delhi, which was attended by the following representatives of the Govt. of China (hereinafter also referred to as the GOC):

- i. Jha Xinjiang, Second Secretary, Embassy of China, Delhi.
  - ii. Yang Xiuquing, Third Secretary, Embassy of China, Delhi.
  - iii. Gu Yuan, First Secretary, MOFCOM, China PR.
  - iv. Luo Xin, dy. Commissioner.
  - v. Gu Yu, First Secretary, MOFCOM, China PR.
  - vi. Wang Hejun, Commercial Counselor.
  - vii. Xu Yan Guang, Dy. Director, MOFCOM
  - viii. Wang Xihui, Commercial Counselor.
54. During the consultations and subsequently vide their note verbal dated 26th May, 2014, the GOC claimed that the evidence in the petition was incomplete in certain critical respects, that some of the alleged subsidy schemes/programmes have already been rescinded and the Designated Authority should not consider the petition for initiating the investigation. Although the GOC contended that most of the alleged subsidy schemes/programmes have either never existed or existed but rescinded, adequate documentary support in proof of their contention was never furnished. Even then, had the GOC consented for verification and allowed the Authority to conduct on the spot verification of the data/information of GOC as well as Jiali wind, the Authority could have established the facts. But, unfortunately GOC neither consented for its verification, nor allowed the only respondent Chinese producer/exporter to be verified.
55. The Authority notes that the Government of China PR did not provide any substantiated evidence in support of their claims made during the pre-initiation consultations. Consequently, the Designated Authority went ahead with the initiation of the investigation with the prima facie evidences of countervailable subsidized imports of product under consideration from China PR and injury caused to the domestic industry due to such imports. The Authority considered the petition filed by the petitioner, contentions of the GOC and held that it was appropriate to initiate and conduct countervailing duty investigations in order to determine whether the producers/exporters of the product under consideration were benefited from countervailable subsidies and, whether such subsidized imports were causing injury to the domestic industry and if so, whether it is appropriate to recommend imposition of countervailing duty measures (hereinafter also referred to as "CVD" or "anti-subsidy duty") on imports of the product under consideration from China PR and if so, to determine the quantum of CVD that should be imposed on the imports of the product under consideration.

## **H.2. Views of the Domestic industry regarding countervailable subsidies**

56. The submissions made by the domestic industry regarding the alleged countervailable subsidies provided by GOC are as follows:
- i. GOC is providing countervailable subsidy to its producers/exporters of the subject goods.
  - ii. The Petition contained prima facie evidence for several subsidy schemes included in both legislation and a number of policy documents which are the basis for the state support to the product.
  - iii. Domestic industry has identified existence of following subsidy schemes in China which are countervailable within the meaning of ASCM and Indian Rules:—

### **Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas-**

- a. Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area).
- b. Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- c. Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
- d. Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- e. Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- f. Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
- g. Preferential Tax for Casing and Forging Systems

## **A. Grants**

- a. The State Key Technology Renovation Projects Fund
- b. Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments

- c. Research & Development (R&D) Assistance Grant
- d. Innovative Experimental Enterprise Grant
- e. Superstar Enterprise Grant
- f. Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"
- g. Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry
- h. Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment
- i. Innovative Small and Medium Enterprise Grants
- j. Grants to Privately-Owned Export Enterprises

**B. Equity Programs**

- a. Equity infusions
- b. Unpaid dividends

**C. Preferential Loans**

- a. Preferential loans and interest rates to the casting industry

**D. Preferential Income Tax Programs**

- a. Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years
- b. Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
- c. Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive
- d. Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
- e. Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments
- f. Preferential Tax Policies for Domestic Enterprises Purchasing Domestically Produced Equipments for Technology Upgrading Purpose
- g. Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
- h. Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
- i. Tax concessions for Central and Western Regions
- j. Income tax credit for the purchase of domestically manufactured production equipment
- k. Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
- l. Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials')
- m. Tax credit concerning the purchase of special equipment
- n. Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
- o. Dividend exemption between qualified resident enterprises

**E. Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery**

- a. Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment
- b. Reduction in Land Use Fees

**F. Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value**

- a. Input Materials Hot Rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
- b. Hot rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
- c. Electricity provided by Government at less than Fair Market Value
- d. Land for Less Than Adequate Remuneration to Companies Located in Industrial or Other Special Economic Zones
- e. Programme consisting of provision of water for less than adequate remuneration



- f. Provision of various goods for less than adequate remuneration
  - g. Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration
  - h. Input Materials (raw material) & Utilities provided by Government at less than Market value
57. The aforesaid alleged schemes are in the nature of either revenue conferred such as grants, loans, equity infusion or revenue forgone like tax incentives. On the basis of prima facie evidence, the Authority has initiated the investigation in respect of the said alleged schemes/programs.
58. In their responses, GOC has made the following five sets of replies:
- a) No such Program exists in China- the GOC has not responded if such scheme has been used in China with an alternate name.
  - b) The scheme is no longer in force- there has been no document submitted by the GOC regarding the termination of the scheme. Even if the scheme has been terminated and is of the nature of Grant, Loan or equity, the benefit will be drawn throughout the useful life of the assets. Secondly, it impliedly proves that the scheme existed in China at some point of time. If the scheme was ever in force in last 15 years the benefit will continue throughout the useful life of the assets. However, GOC has not provided any evidence in support of withdrawal of these programs. Further, despite these claims of the GOC, these programs continue to be investigated by other investigating authorities and continue to hold countervailable subsidies in these programs. Therefore mere statement that these schemes are "no longer" in force does not mean that the investigations should not be conducted in respect of these schemes.
  - c) No evidence being provided by the petitioner- Prima facie petitioner has provided other authority findings which establish that the schemes are countervailable. Further the GOC has never mentioned that these schemes never existed in China or the producer of the product has never availed the financial contribution out of it or being benefitted out of it.
  - d) Not applicable to the PUC- the GOC has mentioned that the product is manufactured with steel scrap and pig iron and not with hot rolled steel. Though in the later submissions the petitioner has mentioned that due to the typographical error scheme was mentioned wrongly. The scheme was mainly intended to inputs provided on less than adequate remuneration. Thus, as regards access to input materials at Less than Fair Market Value is concerned, the petition inadvertently mentions "hot rolled steel". The petition makes it evident that the reference by the petitioner is to the inputs involved in production of the product under consideration, which are Pig Iron, Steel Scrap (CRCA), Ferro Silicon, Ferro Silicon Mg, Coke, Inoculants, Silica Sand, Resin, Catalyst, LPG, Furnace Lining Material, Diesel, Laddle Lining Material, Ceramic Tubes, Sleeves and Refractory Coating. Thus, reference to Hot Rolled Steel in the petition may kindly be read as reference to Pig Iron, Steel Scrap (CRCA), Ferro Silicon, Ferro Silicon Mg, Coke, Inoculants, Silica Sand, Resin, Catalyst, LPG, Furnace Lining Material, Diesel, Laddle Lining Material, Ceramic Tubes, Sleeves and Refractory Coating. The petitioner regrets reference to Hot Rolled Steel, petitioner submits that this inadvertent error was quite obvious and therefore GOC and exporter should have responded on the basis of inputs involved in production of the product under consideration.
  - e) Not as subsidy or Non actionable subsidy- The prerogative to decide the same is with the Designated Authority. Even the said schemes have been held countervailable by other authorities. Also GOC has not given any evidence to prove how the scheme is a non actionable subsidy.
59. Govt. of China or responding exporter has not disputed that these schemes were in the nature of grants. Nor Govt. of China or responding exporter has contended that the responding exporter did not avail any benefits under these grant schemes in the past. Considering that the benefits of a grant scheme flow throughout the useful life of the assets, the Authority should hold that the investigations is required to be continued in respect of these schemes. Further, the other investigating authorities have established countervailability of these grants schemes.
60. In any case, it is a well settled position that the petition may not have an exhaustive account of all the schemes and the exporter and GOC are required to truthfully provide details of "any other scheme" that was applicable to the producers and/or exporters in China.
61. The Govt. of China claimed that the responding exporter, M/s Zhejiang Jiali Wind Power Technology, Hangzhou has not availed any benefit under any of the schemes alleged to be countervailable by the petitioner. Though the sole responding exporter has applied for the following schemes:
- i. Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies.
  - ii. Dividend exemption between qualified resident enterprises.

62. Thus it shows that the above mentioned schemes do exist in China PR and are applicable to the producers/exporters of the product.
63. GOC was unable to clarify how the alleged schemes/programs have been held countervailable by the other investigating authorities in the recent years. It is not the argument of Govt. of China or the responding exporter that there is no program maintained by Govt. of China wherein a benefit in the nature of benefit stated by the petitioner exists. The argument of the Govt. of China is that the petitioner does not have the relevant documentary evidence.
64. The evidences regarding the existence and financial contribution by the GOC in respect of various schemes are not available in the public domain. It is not the argument of the Govt. of China that it has placed all such kind of information in public domain; nor is it the argument of Govt. of China that some information is publically available and the same has not been provided by the petitioner.
65. It is possible that the program is known by different names than the one specified by the petitioner. In fact, it is understood that even names of Chinese companies could be different in Chinese language and in English language. What is relevant is not the "name" per-se but the "benefit" that is being extended by Govt. of China. Mere fact that the benefit is being given in some other name and the petitioner has used some other name does not alter the legal position with regard to the countervailability of the benefit. The petitioner has given name only to link the benefit to some particular scheme notified by the Govt. of China.
66. The GOC has never refuted with documentary support any of the evidences provided by the petitioner, such as other authority findings, WTO reports, Trade policy reviews, private research reports etc submitted by the petitioner during the course of this investigation.
67. The GOC has in fact not responded to the "other Subsidies" prescribed in the questionnaire response. During the course of investigation, petitioner has found that the GOC has in fact not responded to a number of schemes prevailing in China. Questionnaire prescribes as follows:
 

*"2. For each program, even if some of them are not listed by the applicant, you should respond fully to the questions, even if Government of subject country believes that the program is not countervailable.*

*5. For each program, please reply to all the questions in Standard Question Annexure and all other annexure given in this questionnaire, as applicable, to the respective program.*

*7. The Department is also required to investigate any program discovered during the course of this investigation which may confer countervailable subsidies on the manufacture, production or exportation of the subject goods. You are therefore required to identify each program, whether or not any benefit under the program has been availed by an enterprise."*
68. The questionnaire is therefore meant to address those schemes as well which may be prevalent in China but for which petitioner has not requested investigations. The GOC cannot restrict its response to merely the schemes identified by the petitioner. The GOC is required to provide information in respect of each and every scheme available and applicable in China. It is however evident that the GOC has not disclosed existence of these schemes to the Authority.
69. The petitioner has thus brought following schemes on record existing in China and requests the Designated Authority to hold that these schemes constitutes countervailable schemes and the GOC has preferred not to respond to these schemes. The QR of GOC is incomplete to such an extent. Further, GOC has consciously not provided any information in respect of the following schemes:

#### **Grants**

- i. Export Assistance Grant
- ii. Grant -Special Fund for Fostering Stable Growth of Foreign Trade
- iii. Government of Shijiazhuang City Export Award (Hebei Province)
- iv. Grants for Listing Shares
- v. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province & Jiangsu Province
- vi. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
- vii. Municipal Government - Export Grant
- viii. Fuyang and Hangzhou City Government Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers (Anhui Province)
- ix. Fuyang City Government Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes

- x. Fuyang City Government Grants Under the Export of Sub-Contract Services Program
- xi. Provincial Government - Equipment Grant
- xii. Reimbursement of Foreign Affairs Services Expenses
- xiii. Refund from Government for Participating in Trade Fair
- xiv. Special Fund for Energy Saving Technology Reform
- xv. State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
- xvi. Subsidies Provided in the Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area

#### **Tax Programs**

- i. Two Free, Three Half Program for FIEs
- ii. Enterprise Income Tax Rate Reduction in the Tianjin Port Free Trade Zone
- iii. Tax credit concerning the purchase of special equipment
- iv. Various local tax discounts (Shandong Province, Chongqing City, Guangxi Region Zhuang, Tax privileges to develop central and western regions)
- v. VAT deduction on fixed assets in the Central region
- vi. VAT Exemptions for Central Region
- vii. VAT Rebates on Domestically Produced Equipment
- viii. VAT Rebates on FIE Purchases of Chinese-Made Equipment

#### **Export Subsidies**

- i. Export Seller's Credit
- ii. Export Buyer's Credits

#### **Preferential Loans and Lending's**

- i. Preferential Export Financing from the Export-Import Bank of China
- ii. Treasury Bond Loans or Grants
- iii. Policy Lending for Renewable Energy Industry

#### **Provision for Goods and Services**

- i. Exemptions From Administrative Charges for Companies in Industrial Zones and SEZs
- ii. Raw Materials Provided by the Government at Less than Fair Market Value

70. Petitioner has not sought extension of CVD investigation on individual subsidy schemes found by the petitioner at this stage. Petitioner has brought forward existence of these subsidies in China to establish gross deficiencies and willful withholding of information by the exporter and GOC. The questionnaire issued by the Designated Authority included information on "any other schemes" applicable to the product under consideration for which Chinese producers and GOC were obliged to respond. These companies and GOC have however preferred not to provide any such information. The evidence now provided by the petitioner clearly establishes concealment of facts and withholding of the facts.
71. The petitioner has submitted that the GOC on the one hand states that no such program is present, whereas on the other hand mentions the name and address of the government agency responsible for administrating these schemes/ programs.
72. The questionnaire response has been filed only by Zhejiang Jiali Wind Power Technology. Though the benefits received are not restricted/limited to the sole responding exporter. However, this company is not the sole producer of the product under consideration in China. The import data clearly shows that the product has been exported by number of other exporting companies during the relevant period. Therefore, the questionnaire response filed by Govt. of China should be considered incomplete/deficient, as it has considered benefits received only by the responding exporter.
73. With respect to majority of the programs regarding Grants, Preferential loans and interest rates, Income Tax Programs, Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas, the exporter mentioned that it has never applied to or benefited from any of the programs. Though it is pertinent to note that the website of the exporter shows contradiction with what has been stated by the exporter in the EQR.

74. The exporter mentioned to have applied for the “Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses” and “Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies”, though claimed that the benefits were never received by the exporter due to the losses incurred by the company.

75. Following are the brief of the alleged schemes as submitted by the domestic industry:

**I. Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas-**

- i. **Program No. 1: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)** constitutes a countervailable subsidies, as the program is maintained by Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body; the programs grant benefit to FIEs in the form of reduced income tax rate of 15%. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to FIEs located in a special economic zone (SEZ) and designated geographical region. Existence of the program is established by Article 19 of Tax Law of the People’s Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises, 1991, State Council Guo Fa No. 39 of 2007; Article 4, 28 and 36 of Enterprises Income Tax Law of the People’s Republic of China, 2008; WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006; WT/TPR/S/300.Canada final finding of Certain Galvanized Steel Wire; Canada final finding of Certain Stainless Steel Sinks. Chinese casting producers, such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd is eligible as it are located in these designated areas and are FIEs.
- ii. **Program No. 2: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones** constitutes a countervailable subsidy as the program is maintained by MOF, SAT, MOFCOM which is public body; the program grants benefit to FIEs in the form of reduced income tax rate of 15% and in old urban districts of cities up to 24% which are established in costal economic open areas and Economic and technological development zones. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to FIEs located in costal economic open areas and Economic and technological development zones. Existence of the program is established by Income Tax Law of the People’s Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law); Rules for the Implementation of the Income Tax Law of the People’s Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprise; Enterprises Income Tax Law 2008; WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006. The cities established by GOC as Coastal Economic Open Areas are Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang, Beihai. Canada final finding of Certain Galvanized Steel Wire; Canada final finding of Certain Stainless Steel Sinks. The casting producers located in coastal economic and development zone such as Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd, Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd, Sinovel Wind Group Co., Ltd. and Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd are eligible as they are the FIEs located in Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones.
- iii. **Program No. 3: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body; the programs grants benefit to FIEs in the form of reduced income tax established in SEZ region, Pudong Area of Shanghai. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to FIEs located in a specific geographical region. Existence of the program is established by Decree [1991] No. 85 of the State Council [30 June 1991], Order [1991] No. 45 of the President of the People’s Republic of China [9 April-91], State Council Circular Guo Fa No. 37 of 2000, Notification of the State Council on Carrying out the Transition Preferential Policies Concerning Enterprise Income Tax, Guo Fa No. 39 of 2007 and WT/TPR/S/300. Canada final finding of Certain Galvanized Steel Wire; Canada final finding of Certain Stainless Steel Sinks. Chinese casting producers, such as Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd. and Shanghai Zhong Zhu Import & Export Co. Ltd. are eligible as they are FIEs established in Pudong area.
- iv. **Program No. 4: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas** constitutes countervailable subsidies, as the program is maintained by State Administration of Taxation (SAT), which is a public body; the programs grants benefit to the enterprises located in these SEZ and designated area. The program is specific, as the benefit under the program is limited to certain enterprises located in specific designated area. Existence of the program is established by Article 28.2 of the Enterprises Income Tax Law of the People’s Republic of China, 2008; Article 93 of Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the People’s Republic of China by the State Council ; "Ministry of Finance, State Administration of Taxation, the State Development and Reform Commission on Comprehensive Utilization of Resources announced the Corporate Income Tax Catalogue (2008 edition) Notice" (Cai Shui [2008] No. 116) and (Cai Shui [2008] No. 117) (2008); Income Tax Law of the People’s Republic of China for

Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law); State Council Issue Circular Guofa (2014)No.14-(2014); State Council Notice 40-Article 57 of Corporate Income Tax; Decree No-63 of Chairman of China PR -2007; Decree No-516 State Council of China PR-2007; WTO-Semi-Annual Report-G/SCM/N/274/CAN-2014; WTO document WT/TPR/S/300; WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006. Canada final finding of Certain Galvanized Steel Wire; Canada final finding of Certain Stainless Steel Sinks. Chinese casting producers, such as Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd., Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd., Gamesa Wind (Tianjin) Co. Ltd., Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd., Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co., Ltd., Jiangyin Hengrun Ring Forging Co., Ltd., Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd., Qingdao Richuan Precision Machinery Co., Ltd. and Shandong Laiwu Jinlei Wind-power Technology Co. Ltd. are eligible as they are established in SEZs and Other Designated Areas.

- v. **Program No. 5: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas (for FIEs)** constitutes a countervailable subsidies, as the program is maintained by MOF, SAT, MOFCOM which is a public body, the program grants benefit to FIEs which are located in SEZs and other designated zone in form of reduced income tax. The program is specific; as the benefit under the program is limited to certain FIEs located in specific SEZ and designated area. Existence of the program is established by Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law); Article 5, Regulation on the Implementation of the Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprise; Regulations on special economic zones in Guangdong province (1980-08-26) ; Provisions of the State Council Concerning the Encouragement of Investment in Developing Hainan Island (1988-05-04); WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006. Canada final finding of Certain Galvanized Steel Wire; Canada final finding of Certain Stainless Steel Sinks. Chinese casting producers, such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd., Gexpro Industry Supply Shanghai Co., Ltd., Sinovel Wind Group Co., Ltd. and Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd are eligible as they are established in SEZs and Other Designated Areas.
- vi. **Program No. 6: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas (for FIEs)** constitutes a countervailable subsidies, as the program is maintained by MOF, SAT, MOFCOM which is a public body, grants benefit to FIEs which are located in SEZs and other designated areas which falls in the 'encouraged' or 'restricted' categories in the Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment and purchasing equipments shall be exempted from tariff and import VAT. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to certain FIEs located in specific SEZ and designated area. Existence of the program is established by Articles 1 and 2 of the Notice of the State Council Concerning the Adjustment of Taxation Policies for Imported Equipment (Guo Fa [1997] No. 37) and Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2004) (until 30 November 2007) or Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2007) (after 1 December 2007); SAT announcement No.49 of 2014; SAT announcement No.51 of 2014; WTO Semi-annual report Canada, Doc G/SCM/N274/CAN, 29th august, 2014. US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China and Canada final finding on Certain Stainless Steel sinks Chinese casting producers Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd., Sinovel Wind Group Co., Ltd. and Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. are eligible as they are located in the said SEZ and designated areas.
- vii. **Program No. 7: Preferential Tax for Casting and Forging System** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Ministry of Finance (MOF) and State Administrative of Tax (SAT), which is a public body and grants benefit to the casting producers in China PR in the form of preferential tax treatment i.e. tax saving. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to specific enterprises which are manufacturing and selling products listed in the annex to the Circular which states that they shall be eligible for refund for thirty-five per cent of the actually collected VAT. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to the enterprises that are producing such specific products such as castings which are eligible for the said benefit. The existence of the program is established by MOF Circular Cai Shui No. 96 of 2003 and Article 24, 25 and 26 of Renewable Energy Law of China. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China has also held the scheme countervailable. US final finding on Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe from PRC has also held the scheme countervailable.

## II. Grants

- viii. **Program No. 8: The State Key Technology Renovation Projects Fund** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by MOFCOM, Ministry of Commerce which is a public body, the program grants benefit to large-size- SOEs which are holding high credit rank among 512 key industries by either direct Government contribution to the enterprise or through the provision of low interest loans where the Government paid the interest payment for loans established by the enterprise. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to SOEs which are holding high credit rank among 512 key industries. Existence of the said program is Measures for the Administration of National Debt Special Fund for National Key Technology Renovation Projects; Notice concerning the Promulgation and Circulation of “Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects” and “Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects” (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 886) (the 1996 Notice); Notice of Amendments to the “Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects” and “Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects” (Guo Jing Mao Tou Zi [2000] No 822); Guojingmao Touzi No 122 of 1999; Notice Concerning the Promulgation and Circulation of “Measures for the Supervision and Administration of National Key Technological Renovation Projects (for Trial Implementation)” from the State Economics and Trade Commission (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 1038); WTO document G/SCM/Q2/CHN/28; WTO-G/SCM/Q2/CHN/42-2011. US final finding on Non Oriented Electric Steel from China. ; EU final finding of Certain Organic Coated steel ;Canada final finding certain galvanized steel wire; Canada- Certain Stainless Steel Sinks. Chinese casting producers such as Jiali Wind Power and Ningbo Ginlong Technologies Co. is eligible as they are SOEs.
- ix. **Program No. 9: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Ministry of Commerce and provisional authorities which is public body, grants benefit to Companies involved in the anti-dumping investigations and working in compliance with the instructions of the Ministry of Commerce and provincial authorities are eligible up to 40% legal fee reduction once they have participated in ADD investigations. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to respective enterprises which are involved in the ADD or CVD investigations. Existence of the said program is Rules for the Implementation of the Support Policy for the Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard investigation respondent. US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China. EU- Certain organic coated steel; Canada- certain galvanized steel wire; Canada- Certain stainless steel sinks.
- x. **Program No. 10: Research & Development (R&D) Assistance Grant** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Local & Municipal government such as Beijing Municipal Science and Technology Commission and Government of Wuxing district and the Science and Technology Bureau of Wuxing District (‘STB’), which is public body, grants benefit to accelerate the transformation of the economic development pattern and economic restructure, enhance the capacity of self-dependent innovation of the district, implementing the strategy on “innovative Urban District”, and making efforts to achieve the sound and rapid economy development. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to respective enterprises which are having R&D facilities and fall under the eligibility criteria. Existence of the said program is Implementation Measure to Support the Acquisition of Foreign Science & Technology Type Enterprises and the Employment of Foreign Science & Technology Development Team, issued by the Shenyang Economic & Technological Development Area administration; Notice of the Office of People’s Government of Wuxing District on Publishing and Issuing the Management Measures on three types of Science and Technology Expenses of Wuxing District. Canada final finding on Certain Stainless steel sinks originating in or exported from China PR and Canada- Certain Galvanized Steel Wire. Chinese casting producers such as Sinovel Wind Group Co., Ltd. and Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd.
- xi. **Program No. 11: Innovative Experimental Enterprise Grant** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Ministry of Science and Technology and its administrative office various provinces, which is a public body such as in Zhejiang Province. The benefit under the scheme is to Small and Medium sized enterprise and placed to undertake research and development activities. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to specific provinces and SMEs who fall in the eligibility criterion. Existence of the program is established by Article 10 & 11 of Law of PRC on promotion of SME, Notice of the ministry of finance and the ministry of industry and information technology on issuing the Measures on Administration of Special Funds for Development of SME’s (No. 96 (2012) of ministry of finance), Ministry of industry and information technology, Ministry of science and technology, Ministry of commerce on the issuance of special funds interim

measures for SMEs development (Cai Qi (2014) No. 38), Ministry of Finance on the issuance of "Interim Measures on Management of special funds for SMEs development (Cai Jian [2015] No. 458). Chinese casting producers, such as Jiali Wind Power and Ningbo Ginlong Technologies Co. Ltd are some of the exporters in Zhejiang Province eligible for such grant. Ref: US final finding on Alloy and Carbon Steel Wire Rod.

- xii. **Program No. 12: Superstar Enterprise Grant** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Government of China PR through provincial authority which is a public body. Eligible enterprise must have 'output scale' which should fall in the eligibility of the grant. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to specific enterprises which have the required output sale. Existence of the said program is Measures for Assessment and Encouragement of Superstar Enterprises and Excellent Enterprises, Notice of Huzhou Government Office Concerning Announcement of Criteria for Superstar Enterprises, Excellent Enterprises and Backbone Enterprise. Chinese casting produces Jiangsu FAW Foundry co. Ltd.; Deqing Jufeng Machinery Manufacturing Co., Ltd. and Jiali Wind Power are some of the exporters eligible for such grant.
- xiii. **Program No. 13: Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC at National, Provincial, and Local Government levels which is a public body. Eligible enterprises are specific to the key enterprises whose products qualify for the title of 'China Worldwide famous Brand' is eligible for the said benefit. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to Enterprises whose products qualify for the title of 'China Worldwide famous Brand' and/or 'famous trademark (China famous Trademark). Existence of the program Order No. 124-Measures for the Administration of Chinese famous –brand products- Dec 2009, Measures for the Administration of Chinese famous –brand products- Dec 2006, Trade policy review-WT/TPR/S/300, WTO Report G/SCM/Q2/CHN/42.US final finding on Non Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden, and Taiwan ; US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China and EU final finding on Solar Glass Originating in China PR. Chinese casting producers Jiali Wind Power, Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co. Ltd. and Jiangsu Jixin wind energy technology co. ltd. are some of the exporters eligible for such grant.
- xiv. **Program No. 14: Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by NDRC and National, Provincial/Municipal Authorities in GOC which is public body. Eligible enterprises are venture capital must be recorded with the relevant local counterpart of NDRC, the said investment companies must be recognized as high-tech enterprises and be small- to medium-sized, are benefited. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to Enterprises with 'high-tech programs' located in the High-Tech Zone or the High-Tech Park present in city or provinces like Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing. Existence of the program by Circular of Chongqing People's Government Office in Temporary Administration Measures-2005; WTO document- G/SCM/N/267/CAN and Web research-Venture capital investment in China market regulatory overview-2013. Canada final finding on Certain Stainless Steel Sinks from PRC, Canada final finding on Galvanized Steel and Aluminium Extracts. Australia final finding on Galvanized Steel and Aluminium Zinc Coated Steel. Chinese casting producer Gamesa Wind (Tianjin) Co, Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd., Gexpro Industry Supply Shanghai Co.,Ltd., Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd., Satarem China Ltd., Shanghai SIIC E&A International Trade Co. Ltd., Sinovel Wind Group Co., Ltd. who are located in Beijing, Shanghai, Tianjin, and Chongqing.
- xv. **Program No. 15: Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Local commerce authority of provinces which is a public body. The program grants benefit to FIEs located in provinces such as Guangzhou. The program is specific to FIEs which are located in Guangzhou. Existence of this program is established by "Notice of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government about Issuing the Provisions of Guangzhou Municipality on Encouraging Foreign Investors to Set up Headquarters and Regional Headquarters (No. 34 [2006])" which was later replaced with "Guangzhou Municipal People's Government to speed up the implementation of the views forwarded to notice the development of headquarters economy (Sui [2010] 2)" and Provision of Guangzhou Municipality on Encouraging Foreign Investors to Set Up Headquarters and Regional Headquarters. Chinese casting producers, such as Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd is a FIE, located in Guangzhou Municipality.
- xvi. **Program No. 16: Innovative Small and Medium Enterprise Grants** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Government of China at National, Provincial, and Local Government levels such as government of Guangdong province is responsible for the administration and

management of this program, which is a public body, the programs grants benefit to SMEs in start-up capital for small firms recognized by R&D for key projects. The program is specific as it is limited to SMEs. Existence of this program is established by Article 12,13,36 of Law of PRC on promotion of SME; Measures for Administration of International Market Developing Funds of Small and Medium Sized Enterprises; Detailed rules for the implementation of the measures for administration of international market developing funds for small and medium sized enterprises, (July 1, 2001); Circular cooperation issuing the measures for the administration of international market developing funds of small and medium sized enterprises (2010); Foreign trade development funds and management approach, Cai Qi (2014); Notice of the ministry of finance and the ministry of industry and information technology on issuing the "Measures on Administration of Special Funds for Development of SME's (No. 96 (2012) of ministry of finance)"; Ministry of industry and information technology, Ministry of science and technology, Ministry of commerce on the issuance of special funds interim measures for SMEs development (Cai Qi (2014) No. 38) & Ministry of Finance on the issuance of "Interim Measures on Management of special funds for SMEs development (Cai Jian [2015] No. 458. Chinese casting producers Jiali Wind Power Technology Co., Ltd, is eligible for such grant.

- xvii. **Program No. 17: Grants to Privately-Owned Export Enterprises** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Yunnan Provincial government which is public body, the programs grants benefit to Non-SOEs located in Yunnan Province. The program is specific as it is limited to Non-SOEs located in specific province. Existence of this program is established by notices concerning accelerating the growth of the non-state-owned economy lists the enterprises eligible.

### III. Equity Programs

- xviii. **Program No. 18: Equity infusions** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Government of China at National, Provincial, and Local Government levels, CICC and SASAC which is public body, grants benefit to companies where government was the main shareholder without acquiring additional shareholder rights. EU final finding on Certain Organic Coated Steel products originating in the People's Republic of China also holds the scheme countervailable. The program is specific as it is limited to limited number of selected entities in which the government participated.
- xix. **Program No. 19: Unpaid dividends** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Government of China at National, Provincial, and Local Government levels, which is public body, grants benefit to limited number of selected entities in which the government participated and thus specific. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China has also held the scheme countervailable.

### IV. Preferential Loans

- xx. **Program No. 20: Preferential loans and interest rates to the casting industry** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Government of China at National, Provincial, and Local Government levels, CICC and SASAC which is public body, grants benefit to Casting producers by providing loan on low (subsidized) interest rates from state-owned commercial banks and government banks to support and develop the expansion of the industry. The GOC is a major shareholder in many of the major banks established in China and therefore it has access to banks. The program is specific as it is limited to limited number of selected entities in which the government participated. Existence of this program is established by YinFa [2003] No.250 and YinFa [2004] No 251; the annual reports of Chinese banks; Catalogue for the guidance of foreign investment industries (amended in 2011); Article 34 and 38 of The Commercial banking law [2003]; NDRC Order No.35- Policies for the development of Iron and Steel Industry, decision 40 and Article 24, 25, 34 of the Law on Commercial Banks act with respect to the fulfillment of the government industrial policies; 2006 Deutsche Bank Research on China's banking sector; Document WT/TPR/S/230 p. 79, April 2010; Document WT/TPR/S/264 p. 122, July 2012; Information retrieved from the 2006 Deutsch Bank Research on China's banking sector, pages 3-4; Information retrieved from the China Monetary Report Quarter Two, 2010 of the Monetary Policy Analysis Group of the People's Bank of China, dated 5 August 2010, page 10; IMF Working Paper, "Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?", WP/06/71, March 2006, (see pages 3-4, 13, 18-20); IMF Working Paper, "Interest Rate Liberalization in China", WP/09/171, August 2009, (see pages 3-4, 21-23); IMF Country Report, PRC: 2010 Article IV Consultation, No 10/238, July 2010, (see pages 22, 24 and 28-29); OECD 2010 Economic Survey of China, February 2010, (see Chapter 3, pages 71, 73-81, 97); OECD China's Financial Sector Reforms, Economic Department Working Paper No. 747, ECO/WKP (2010) 3, 1 February 2010, (see pages 2, 8-15, 36); Detailed rules for implementing the adjustment and revitalization program for the steel industry [2009] provides for "increasing the financial support for key backbone enterprises". EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China has also held the scheme countervailable.



V. **Preferential Income Tax Programs**

- xxi. **Program No. 21: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by MOF, MOFCOM, SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to FIEs which begins to make a profit, they may receive a full exemption from income tax in the first and second years and a 50% reduction in income tax in the third, fourth, and fifth years. General exemption on income tax regardless of what activities generate this income (profit), it is considered that a financial contribution under this program would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise. The program is specific as it is limited to FIEs which are making profits. Existence of this program is established by Article 8 of the FIE Income Tax Law, Decree [1991] No. 85 of the State Council [30 June 1991], Order [1991] No. 45 of the President of the People's Republic of China [9 April-91], State Council Circular Guo Fa No. 37 of 2000 and Notification of the State Council on Carrying out the Transition Preferential Policies Concerning Enterprise Income Tax, Guo Fa No. 39 of 2007; WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006; Enterprise Income Tax Law 2008. Canada final finding on Certain Stainless Steel Sinks Originating in or exported from China PR. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China has also held the scheme countervailable. Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. and Sinovel Wind Group Co., Ltd. are eligible for such benefit.
- xxii. **Program No. 22: Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by MOF, MOFCOM, SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to Export-oriented enterprises invested in and operated by foreign businesses for which in any year the output value of all export products amounts to 70% or more of the output value of the products of the enterprise for that year may pay enterprise income tax at the tax rate specified in the Tax Law are reduced by one half. The program is specific as it is limited to FIEs where the exports constitute 70 percent of the company's sales. Existence of this program is established by Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies- Cai Shui [2009] No.69; China Enterprise Income Tax; SAT Circular Guo Shui Fa No. 1 of 2003; Circular 115-Oct 2009; SAT Circular Guo Shui Fa No. 139 of 1995; Circular Caishui (2014)No.59 & 65; China's Industrial Subsidies Study (2007); WT/TPR/S/300; G/SCM/N/123/CHN; G/SCM/Q2/CHN/25; G/SCM/Q2/CHN/29; G/SCM/N274/CAN; G/SCM/Q2/CHN/48; G/SCM/N/155/CHN; G/SCM/N/186/CHN; G/SCM/N/235/CAN-2012- Certain Thermoelectric coolers and warmers from China PR; US-Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod; US-Initiation Check list in Sodium Nitrate China PR; Certain oil country tubular goods from China PR; Certain seamless casing from China PR; EU-Certain organic steel products-2013; EU-Coated fine paper-2011. US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China. Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. and Sinovel Wind Group Co., Ltd. are eligible for such benefit.
- xxiii. **Program No. 23: Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by MOF, MOFCOM, SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to enterprises with foreign investment which are technology-intensive and knowledge-intensive and whose major products are enlisted in the "Catalogue of High and New Technology Products of China" promulgated by Ministry of Science & Technology and the sales revenue of these products of that year accounts for over 50% of the total annual sales revenue of the enterprise, may be imposed a reduced enterprises income tax rate of 15%. The program is specific as it is limited to FIEs recognized as "high" or "new" technology enterprises or established in "high" or "new" technology industrial development zones. Existence of this program is established by SAT Circular Guo Shui Fa No. 139 of 1995, SAT Circular Guo Shui Fa No. 135 of 2003; G/SCM/N/123/CHN; G/SCM/Q2/CHN/25; G/SCM/N/267/CAN. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China. Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. and Sinovel Wind Group Co., Ltd. are eligible for such benefit.
- xxiv. **Program No. 24: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to enterprises with foreign investment to encourage enterprises to undertake R&D activities. The program is specific as it is limited to FIEs undertaking R&D activities. Existence of this program is established by Notice concerning the Promulgation and Circulation of The income tax offset under this program for FIEs is provided for in the Circular of the State Administration of Taxation on the

Issues Related with the Offset Taxable Income on Technology Development Fee with Foreign Investment Enterprises (Guo Shui Fa [1999] No. 173) (the FIE R&D Tax Offset); The income tax offset under this program for all enterprises is provided for in the Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on the Preferential Policies for Enterprise Income Tax on Technical; Innovation Enterprises (Cai Shui Zi [2006] No. 8) (the Enterprise R&D Tax Offset); Circular on Measures for tax refund and exemption granted to Foreign Invested research and development Centers; Decree 63 of Chairman of People Republic of China –Article 30, 95 of Enterprise income tax; WT/TRS/300; G/SCM/Q2/CHN/49-OCT-2013; G/SCM/N/267/CAN- Semiannual Report; G/SCM/N/123/CHN; G/SCM/Q2/CHN/25. EU final finding on Coated Fine Paper (2011); US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod. Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. and Sinovel Wind Group Co., Ltd. are eligible for such benefit.

- xxv. **Program No. 25: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to FIEs that invest in Chinese-made equipment and whose projects are classified in either the Encouraged or Restricted B categories of the Catalogue of Industrial Guidance for Foreign Investment. The program is specific as it is limited to FIEs and it is contingent on the use of domestic over imported goods. Existence of this program is established by Catalogue of Non-Duty-Exemptible Articles of Importation (2012 Adjusted); Income Tax Credits for FIEs on Purchases of Domestically Produced Equipment; Circular of the State Administration of Taxation Concerning Transmitting the Interim Measure for the Administration of Tax; Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011); Circular of the State Council on Adjustment of Tax Policies of Imported Equipment (GuoFa [1997] No. 37); Notice regarding the adjustment of import-level tax policies related to key technological equipment and machinery (Caiguanshui [2014] No. 2); G/SCM/N/123CHN.doc; G/SCM/N/155/CHN.doc & G/SCM/N186/CHN.doc; G/SCM/N/267/CAN-Canada- Certain Galvanized steel wire from China PR. Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. and Sinovel Wind Group Co., Ltd. are eligible for such benefit.
- xxvi. **Program No. 26: Preferential Tax Policies for Domestic Enterprises Purchasing Domestically Produced Equipments for Technology Upgrading Purpose** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by MOF, SAT which is public body, grants benefit to Domestic enterprises are provided preferential tax treatment to purchase domestically produced equipment for technology upgrading projects. The program is specific as it is limited to Domestic enterprises that purchase domestic equipment for domestically produced equipment is eligible for the sad program and incentives through this program. Existence of this program is established by Section 771(5) of Tariff Act, 1930, MOF Circular Cai Shui No.290 of 1999; G/SCM/N/123/CHN; G/SCM/Q2/CHN/25; US Boltless Steel Shelving. Chinese casting Producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co, Ltd.; Dalian Huarui Heavy Industry International co. Ltd.; Jiangsu Faw Foundry Co. Ltd.; Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd.; Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co., Ltd.; Jiangyin Hengrun Ring Forging Co., Ltd.; Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd.; Qingdao Richuan Precision Machinery Co., Ltd.; Satarem China Limited.; Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd.; Shanghai Siic E&A International Trade Co. Ltd.; Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd.; Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd. are eligible for such benefit.
- xxvii. **Program No. 27: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to foreign investors in an FIE have been able to receive a 40% (if profits are re-invested) or 100% (if profits are re-invested in an export-orientated or technologically advanced enterprise) refund on the income tax that was paid on the re-invested amounts. A benefit to the investor is conferred in the amount of the tax refund. The program is specific as it is limited to encourage foreign investors to reinvestment in enterprises in China. Existence of this program is established by Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies- Cai Shui [2009] No.69; Catalogue-Circular of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policies-2015; Article 10 of the Foreign Invested Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax law 1991 (the FIE Income Tax Law); Article 80 of Implementing Rules of the Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law (the FIE Tax Regulations); G/SCM/N/235/CAN-2012-Ceratin Thermoelectric coolers and warmers from China PR; Certain oil country tubular goods from China PR; Certain seamless casing from China PR; US-Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod; US-Initiation Check list in Sodium Nitrate

China PR; Circular of the State Administration of Taxation on Some Issues Concerning Tax Reimbursement for Re-investment Made by Foreign Investors of Enterprise with Foreign Investment (Guo Shui Fa [1993] No 9). Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd.; Sinovel Wind Group Co., Ltd.; Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd are eligible for such benefit.

xxviii.

**Program No. 28: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses-** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Local Science and Technology Bureau, the programs grant benefits to enterprises upto 50 % reduction in corporate income, where the said companies receiving Primary Support from the State and their projects listed in guide of high tech industrialization, are eligible for the said benefit. Existence of the program, Article 30(1) of the Corporate Income Tax Law, Article 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC, The guide to Key Fields (Notification n.6, 2007); China's State Administration of Taxation (SAT) issued Guoshuifa [2008] No. 116 (Circular 116) outlining the scope of R&D expenses eligible for Super Deduction, which, in practice, resulted in excluding some R&D related expenses that were not explicitly outlined in Circular 116 as qualified R&D expenses for Super Deduction purposes; On 29 September 2013, China's Ministry of Finance and the SAT released Caishui [2013] 70 (Circular 70), providing additions and clarifications to the original categories of R&D expenses outlined in Circular 116. Circular 70 is effective retroactively for R&D expenses incurred on or after 1 January 2013. US final finding on Non Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden and Taiwan Chinese casting producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co. Ltd., Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd., Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Jiangsu Faw Foundry Co. Ltd., Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd., Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co. Ltd. Jiangyin Hengrun Ring Forging Co. Ltd., Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd., Qingdao Richuan Precision Machinery Co. Ltd., Satarem China Ltd., Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd., Shanghai Siic E&A International Trade Co. Ltd., Sinovel Wind Group Co. Ltd. and Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd.

xxix.

**Program No. 29: Tax concessions for Central and Western Regions** constitutes countervailable subsidies, as the program is maintained by GOC at Provincial Level which is a public body; the programs grants benefit to enterprises in the form of reduced income tax established in Central and Western Regions. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to enterprises located in a specific geographical region. Existence of the program is established by Notice on Favourable Tax Policies for Western Region Development (issued by the Ministry of Finance, General Tax Bureau and General Customs Office, effective from 1 January 2001); Circular on the Issues Concerning Related Tax Policies for the In-depth Implementation of the West Development Strategy (Cai Shui [2011] No. 58); Announcement on Enterprise Income Tax Policies Issues Concerning the Further Implementation of the Western China Development Strategy (February 6th, 2013); Announcement No. 14 [2015] of the State Administration of Taxation- Announcement on Issues concerning Enterprise Income Tax in Implementing the "Catalogue of Industries Encouraged to Develop in the Western Region (2015-03-10); 12th five year plan aims western region development; National Development and Reform Commission ("NDRC") announced on 20 February that the State Council has formally approved The Western Development Plan during the 12th Five-Year Plan period; Midwest industrial catalogue for foreign investment (2013 Amendment), 2013 No.1 order; Foreign investment guidelines for central and western regions issued (effective from June 10, 2013); Announcement of the state administration of taxation on issues concerning enterprise income tax related with enhancing the western region development strategy (announcement no.12); Circular of the state council concerning several policies on carrying out the development of china's vast western region GuoFa (2000) no. 33. Central region consists of Henan, Hubei, and Hunan provinces and western region consist of Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, and Xinjiang. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China. Chinese casting producers Shi Jia Zhuang Danzhuo Trade Co. Ltd. Zhuzhou Jiabang Photoelectric Material Co., Ltd. and Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd are located in this designated region.

xxx.

**Program No. 30: Income tax credit for the purchase of domestically manufactured production equipment** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by SAT and Local Taxation Bureaus of the GOC, which is a public body; the programs grant benefits to the enterprises in the form a tax benefit (i.e. a tax credit) accrued in a certain year may actually be used in a different tax year. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to the enterprises using Equipment under Encouraged Category and Restricted B Category. Existence of the program is established by Provisional measures on enterprise income tax credit for investment in domestically produced equipment for technology renovation projects of 1 July 1999 and the Notice of the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy of the Investments of an Enterprise in Purchasing Home-made Equipment, No. 52

[2008] of the State Administration of Taxation, effective 1 January 2008. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China.

- xxxii. **Program No. 31: Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Ministry of Science & Technology (MOST), which is a public body, the programs grants benefit to the enterprises in the form of tax savings to those enterprises who have applied for the certificate of high and new technology. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to those enterprises who are having high and new technology enterprise status or who applied for the same. Existence of the said program, Article 28 of the PRC Law on Enterprise Income Tax (No. 63 promulgated on 16 March 2007) SAT Circular Guo Shui Fa No. 135 of 2003; Circular Caishui (2014)No.59 & 65; WT/TPR/S/300; G/SCM/Q2/CHN/29; China's Industrial Subsidies Study- 2007; EU-Certain organic steel products-2013; Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China . Chinese casting producers are Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd., etc.
- xxxiii. **Program No. 32: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials')** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC and State Council which is a public body, the programs grants benefit to the enterprises in form of tax savings. The program is specific, which is limited only to those enterprises whose companies manufacturing products listed in the same catalogue in a way to that meets relevant national and industrial standards by using primary raw material which are listed out in the GOC catalogue. Existence of the said program Article 28, & 33 of the PRC Law on Enterprise Income Tax, Article 99 of Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the State Council; EU-Coated fine paper-2011. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China; US final finding on Non Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden, and Taiwan.
- xxxiiii. **Program No. 33: Tax credit concerning the purchase of special equipment** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC and State Council which is a public body, the programs grants benefit to the enterprises in form of reduction of income tax and thereby tax saving. The program is specific; to those enterprises that purchase equipments for the use of environmental protection, energy and water saving and production saving. Existence of the said program is Article 34 of the PRC Law on Enterprise Income Tax, Article 100 of Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the State Council EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China.
- xxxiv. **Program No. 34: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC, MOF Ministry of Finance and State Administration of Taxation (SAT), the program grants benefit in the form of tax savings generated for eligible companies by the deduction of accelerated depreciation and amortization expenses linked to the purchase of fixed assets. The program is specific, since it is limited to enterprises located in a designated geographical area, i.e. the Northeast Region, (including Liaoning, Jilin, and Heilongjiang Provinces, and Dalian Municipality). Existence of the said program is Enterprise Income Tax For Revitalization of Companies of the Old Industrial Base In The Northeast (Caishui, No 153, 20 September 2004), Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of taxation on the Assets Depreciation and the Implementation Calibre of Amortization Policy in the Northeast Old Industrial Base (Caishui, No 17, 2 February 2005). EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China Chinese casting producers are Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd., etc.
- xxxv. **Program No. 35: Dividend exemption between qualified resident enterprises** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC, which is a public body, the program grants benefit by the tax exemption on dividends, bonuses and other equity investments for Chinese resident enterprises. The program is specific as it is limited to enterprises resident in China. Existence of the said program under Article 26 of the Enterprise Income Tax Law of the PRC, Article 83 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC, Decree no. 512 of the State Council, promulgated on 6 December 2007; EU finding on Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China.

#### VI. **Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery**

- xxxvi. **Program No. 36: Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by NDRC, SAT and its local tax bureaus which is public body, grants benefit to FIE which falls in the 'encouraged' or 'restricted' categories and or DIES that fall under the DIE catalogue and they import equipment which is sought to be exempt from tariff and/or VAT which must be for the enterprise's own use. The program is specific

as it is limited to encourage FIEs or DIEs that fall under the catalogue. Existence of this program is established by Articles 1 and 2 of the Notice of the State Council Concerning the Adjustment of Taxation Policies for Imported Equipment (Guo Fa [1997] No. 37), WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006; Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment; Catalogue of Industry, Product and Technology Key Supported by the State at Present (2004); State Council's Import Goods Not Exempted from Taxation for Foreign Investment Projects Catalogue; Import Goods Not Exempted from Taxation for Domestic Investment Projects Catalogue. EU final finding on Solar Glass Originating in China PR. Chinese casting Producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co. Ltd.; Antec Braking Systems (Tianjin) Co. Ltd.; Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd.; Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd.; Jiangsu Faw Foundry Co. Ltd.; Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd.; Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co. Ltd.; Jiangyin Hengrun Ring Forging Co. Ltd.; Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd.; Qingdao Richuan Precision Machinery Co. Ltd.; Satarem China Ltd.; Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd.; Shanghai Siic E&A International Trade Co. Ltd.; Sinovel Wind Group Co. Ltd.; Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd. are eligible for such benefit.

- xxxvii. **Program No. 37: Reduction in Land Use Fees** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by SAT but the provincial and local land use management authorities were responsible for the collection of the land use fees, which is public body, grants benefit to FIEs who acquired land use rights by transfer are eligible for this scheme. The scheme is specific as it is limited for the FIEs. Existence of this program is established Order of the State Council [2006] No 483; Article IV.5 of Guo Ban Fa [1999] No 73) (Customs Document 18) Measures on readjusting land use fees and preferential reduction and exemption of land use fees in Shenzhen special economic zone. Canada final finding on Certain Stainless Steel Sinks Originating in or exported from China PR; EU final finding on Certain Organic coated Steel Products originating in the People's Republic of China; US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China; US final finding on Non Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden, and Taiwan; EU final finding on Solar Glass originating in China PR.

VII. **Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value**

- xxxviii. **Program No. 38: Input Materials Hot Rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value &**

- xxxix. **Program No. 39: Hot rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value**

The Program No. 38 & 39 have been included in the petition filed due to typographical error. Petitioner is well aware that the hot rolled steel is not used in the manufacturing of castings as a raw material.

- xl. **Program No. 40: Electricity provided by Government at less than Fair Market Value** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by NDRC and trans-provincial and provincial grids are operated by two state-owned suppliers i.e. State Grid Corporation of China and China Southern Power Grid Corporation, which are public bodies, grant benefits to the enterprises in providing electricity for less than adequate remuneration to the enterprises at a rate lower than the rate generally applicable to other large industrial users in China PR and limited to designated geographical areas where the exporting producers are located. There is discretion to administer the discounted rates to a limited group of preferred enterprises and industries, specifically, priority industries such as the casting industry. The lower electricity rate is set out in the relevant NDRC Notice and incorporated in the Notice issued by the local Price Bureau. Existence of the said program is established by and thereby countervailed by EU final finding on Certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China; US final finding on Non Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden, and Taiwan; EU final finding on Solar Glass originating in China PR.

- xli. **Program No. 41: Land for Less Than Adequate Remuneration to Companies Located in Industrial or Other Special Economic Zones** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Ministry of Land and Resources, Government of China through SOEs which maintains this program which is a public body, grants benefits to enterprises by the Chinese government at a discounted rate, or for free. The land-use policies are administered on a specific basis, specifically; local Chinese governments provide access to discounted land only for certain high-tech enterprises are specific in nature. Existence of the said program is established by Article 2 of the Land Administration Law and countervailed by EU final finding on Certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China; US final finding Non Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden, and Taiwan; US final finding on Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China; Canada final finding on Certain Stainless steel sinks originating in or exported from China PR.

- xlii. **Program No. 42: Program consisting of provision of water for less than adequate remuneration** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by NDRC, the Ministry of Water Resources and the Ministry of Environment, which is a public body, grants benefits to exporters wherein they pay less than the normal supply of water in form of revenue forgone especially applicable to the "sewage treatment fee". It provided water for less than adequate remuneration. Exporter has not paid the full price for water supply normally applicable to the category of users to which it belongs, as the "sewage treatment fee" component of the water price has not been paid. Existence of the said program is established and countervailed by US final finding of Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China.
- xliii. **Program No. 43: Provision of various goods for less than adequate remuneration** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC, which is a public body, grants benefits to the SOEs in form of less than adequate remuneration in the form of direct transfer of fund as the raw materials produced by the casting producers are the raw materials produced inputs involved in production of the PUC are Pig Iron, Steel Scrap (CRCA), Ferro Silicon, Ferro Silicon Mg, Coke, Inoculants, Silica Sand, Resin, Catalyst, LPG, Furnace Lining Material, Diesel, Laddle Lining Material, Ceramic Tubes, Sleeves and Refractory Coating and supplied by the government authorities of China PR. Existence of the program is maintained and countervailed by US-Galvanized Steel Wire from China and Mexico; US-Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe ("Seamless Pipe") from the People's Republic of China and US- Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China.
- xliv. **Program No. 44: Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration** constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by GOC through SOEs, which is a public body, the program grants benefit i.e. direct transfer of funds for purchase of goods for selected enterprises. The said program is specific as it is limited to certain eligible enterprises which are selected by the authorities. EU final finding on Certain Organic Coated Steel Products originating in the People's Republic of China and Canada final finding on Certain Galvanized Steel Wire Originating In or From China PR.
- xliv. **Program No. 45: Input Materials (raw material) and utilities provided by Government at Less than Market: Value** Input Materials (raw material) and Utilities provided by Government at Less than Market Value constitutes a countervailable subsidies, as the program is maintained by Government of China PR), which is a public body; the program grants financial contribution in the form of provision of Input Materials (raw material) and Utilities at less than adequate remuneration by SOEs to casting producers and thus constitutes a countervailable subsidy. The program is specific, as the benefit under the program is limited to the casting exporters and is given input materials (raw material) and utilities at less than adequate remuneration and not at the market price. The inputs involved in production of the PUC are Pig Iron, Steel Scrap (CRCA), Ferro Silicon, Ferro Silicon Mg, Coke, Inoculants, Silica Sand, Resin, Catalyst, LPG, Furnace Lining Material, Diesel, Laddle Lining Material, Ceramic Tubes, Sleeves and Refractory Coating. Existence of the program is established by US-Galvanized Steel Wire from China and Mexico; US-Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe ("Seamless Pipe") from the People's Republic of China and US- Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China.

### **H.3. Submissions by GOC/producers/exporters/importers/other interested parties**

76. With regard to the alleged subsidy schemes, the opposite interested parties have contended as follows:

- i. In the present investigation, the Authority has initiated CVD investigation in respect of 44 subsidy programs on the basis of allegations made by the Petitioner. Although claimed by the petitioner, Authority should not consider any new subsidy program at this belated stage. Without prejudice, if Authority does consider any new subsidy allegation, in such a circumstance, a separate investigation has to be initiated
- ii. In the petition filed by the Petitioner, 5 exporters from China PR have been named. However, the petition nowhere alleges, which all program schemes out of 44 schemes listed are applicable to which exporters. None of schemes listed pertain to the geographical region or the specific industries to which the named exporters belong. In absence of same, the alleged programs cannot be countervailed.
- iii. Further, investigations for each of the 44 subsidy programs need to be terminated as each of the subsidies are not countervailable in terms of CVD Rules and SCM Agreement. Moreover, following illustrative discrepancies/problems exist in the subsidy programs alleged by the petitioner:

- a. Subsidy program rescinded in the exporting country.
  - b. No allegation at all with respect to (a) financial contribution (b) benefit being conferred and (c) specificity.
  - c. No information except the name of the program.
  - d. Express admission that no evidence available with respect to subsidy program alleged.
  - e. No evidence other than certain findings of Canadian, Australian, US and EU authorities have been given with regard to the alleged programs. Even in these cases, none of those findings related to the product concerned or any of the known producers or exporters listed in the petition. In respect of programs related to certain specific geographical areas or cities, there was no averment in the petition that any producer of the product concerned was operating or located in the relevant geographical area or city.
  - f. No averment with regard to why State Owned Enterprises be treated as public bodies
- iv. All the evidence presented in the form of findings from other countries (assuming without admitting, that they may be treated as evidences) did not deal with the findings of Appellate Body decision in DS 379 and DS 436 that required an investigating authority to first establish that the entity concerned possessed governmental authority to perform governmental functions and not merely trading or other commercial functions. All the findings quoted by the petitioner had treated the State Owned Enterprises (SOEs) as public bodies merely for the reason that they were state owned. Accordingly, none of the findings of other governments quoted in the petition or in the subsequent letters were in line with the decisions of the Appellate Body.
- v. Petitioner has made mere allegations regarding the subsidies in question, with unsubstantiated claims on specificity and benefit. There is a difference between establishing that a program exists (with appropriate information on legislation and administering authority) and establishing that the program is an actionable or prohibited subsidy. While the Petitioner has filed information regarding a few of the alleged programs, there is no actual substantiation of why India as a WTO member is justified in levying duties to countervail these programs. The petitioner has to give evidence in support of allegations of subsidies brought by them.
77. With regard to the alleged subsidy schemes, the Govt of China have contended as follows:
- a) The Govt. of China claimed that the following alleged schemes do not exist:
    - I. Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value
      - i. Electricity provided by Government at less than Fair Market Value
      - ii. Land for Less Than Adequate Remuneration to Companies Located in Industrial or Other Special Economic Zones
      - iii. Programme consisting of provision of water for less than adequate remuneration
    - II. Preferential Loans
      - i. Preferential loans and interest rates to the casting industry
  - b) The Govt. of China claimed that the following alleged schemes do not apply for the castings producer/exporter as the main raw material for production of the products under investigation is not hot rolled steel and cold- rolled steel but the steel scrap.
    - I. Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value:
      - i. Input Materials Hot Rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
      - ii. Hot rolled Steel provided by Government at Less than Fair Market Value.
  - c) The Govt. of China claimed that the following alleged schemes are "no longer" in force.
    - I. Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas:

- i. Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area).
- ii. Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- iii. Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
- iv. Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- v. Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- vi. Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
- vii. Preferential Tax for Casting and Forging Systems

## II. Grants

- i. The State Key Technology Renovation Projects Fund
- ii. Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"

## III. Preferential Income Tax Programs

- i. Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years
- ii. Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
- iii. Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive
- iv. Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
- v. Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments
- vi. Preferential Tax Policies for Domestic Enterprises Purchasing Domestically Produced Equipments for Technology Upgrading Purpose
- vii. Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

## IV. Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery

- i. Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment

## V. Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value

- i. Income tax credit for the purchase of domestically manufactured production equipment
- d) The Govt. of China claimed that the application does not contain sufficient evidence of the actual existence of the alleged subsidy for the following schemes:

### I. Grants

- i. Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments
- ii. Research & Development (R&D) Assistance Grant
- iii. Innovative Experimental Enterprise Grant
- iv. Superstar Enterprise Grant
- v. Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry
- vi. Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment
- vii. Innovative Small and Medium Enterprise Grants
- viii. Grants to Privately-Owned Export Enterprises

## II. Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery

- i. Reduction in Land Use Fees

## III. Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value



- i. Tax concessions for Central and Western Regions
- ii. Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials')
- iii. Tax credit concerning the purchase of special equipment
- iv. Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
- v. Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration

#### IV. Equity Programs

- i. Equity infusions
- ii. Unpaid dividends

#### V. Preferential Loans

- i. Preferential loans and interest rates to the casting industry
- e) The Govt. of China claimed that the following alleged scheme is in force where the benefit is not related to the exports or any imports of any inputs, of the product concerned, that needs key support from the state in order avail tax benefit:
  - i. Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies
- f) The Govt. of China claimed that the following alleged scheme is not a subsidy but an exemption in order to avoid double taxation with no benefits conferred:
  - i. Dividend exemption between qualified resident enterprises.
- g) New Subsidy Allegations (NSA) cannot be included as allegations have been made belatedly. NSA should have to be made within a reasonable period of time (2 months after the initiation). And even if Authority has to consider NSA, a separate investigation has to be initiated against and prior consultations have to be held with exporting country.
- h) The only responding exporter, Zhejiang Jiali Wind Power Technology, Hangzhou, has claimed that the exporter company has never applied for, used, or benefitted from these programs. Also, Jiali is neither a foreign invested enterprise nor located in SEZs or other designated areas. In the production of subject good, the exporter company has never used Hot rolled Steel as input material. The company has purchased electricity, water, land and various goods during the investigation period and did not receive any benefit from this program.
- i) The only cooperating exporter / producer has stated that they have applied for "Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses" and "Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies", and obtained approval from the local taxation bureau. These programs have not been terminated. However, the nature of this program is reduced income tax rate but such benefit can only be enjoyed when the enterprise has a profit. The Exporter Company, due to huge losses in fiscal year 2012, did not receive any benefits out of the above mentioned schemes. Also the said tax concessions are neither linked directly or indirectly for acquisition of fixed assets or capital goods.
- j) The exporter, Zhejiang Jiali Wind Power Technology, Hangzhou, has claimed that it is a privately owned limited liability company. Thus, they have not received any benefit out of the equity programs i.e. Equity infusions and unpaid dividends.
- k) 5 exporters have been named by the petitioner, though nowhere the petitioner alleges, which all program are applicable to which exporter. None of schemes listed pertain to the geographical region or the specific industries to which the named exporters belong.
- l) The interested parties have raised concerns regarding the sufficiency of the petition's allegations of subsidy. The petition fails to meet the legal standards and requirements. The petition contains insufficient evidence. IWTMA has stated that in order for a program to be it has to be satisfied whether the program qualifies as a 'subsidy' in terms of Article 1 of ASCM.
- m) GOC has mentioned that Chinese exporting producer cooperated, in which detailed information and evidence are provided hoping that the authority will take into account the opinions and facts submitted.
- n) Petitioner should include sufficient evidence of the existence of (a) a subsidy and, if possible, its amount, (b) injury and (c) a causal link. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient.

- o) Petitioner has failed to identify which specific programs are related to the PUC and whether there existed a financial contribution and a benefit conferred in the sector.
- p) Investigations for each of the 44 programs need to be terminated as the same are not countervailable. There are discrepancies/problems exist in the subsidy programs alleged such as:
  - a. Subsidy program rescinded in the exporting country
  - b. No allegation at all with respect to (a) financial contribution (b) benefit being conferred and (c) specificity
  - c. No information except the name of the program
  - d. Express admission that no evidence available with respect to subsidy program alleged
  - e. No evidence other than certain findings of Canadian, Australian, US and EU authorities has been given with regard to the alleged programs.
    - i. None of those findings related to PUC or any of the known producers or exporters listed in the petition.
    - ii. Programs related to specific geographical areas or cities, no averment that any producer was operating/ located in the geographical area.
    - iii. No averment with regard to why SOEs be treated as public bodies
- q) The petitioner could not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy namely: (i) financial contribution by a government or public body; (ii) benefit; and (iii) specificity. If one or more of the above three pre-requisites are not fulfilled, in such a case the investigation for such a program ends.
- r) The GOI should justify: (i) whether it assessed the adequacy and accuracy of evidence concerning subsidization provided by the petitioner; and (ii) the basis on which it considers that the petition contains adequate and accurate information with respect to each subsidy scheme as regards the exporting producers of the product concerned such that the petition could be considered as providing objectively sufficient factual basis for the initiation of the investigation as required by Article 11.3 of the SGM Agreement.
- s) All the information and evidence must be closely related to the specific PUC. No direct relevance to the PUC shall not be requested, it may be tantamount to overly burdens that an exporter may not be able to fulfill. Specifically, all the subsidy related information and evidence must be related to (1) the subject merchandise; (2) cooperating companies.
- t) By virtue of the state or a SOE administering the program, the public body requirement is satisfied- is an incomplete and inaccurate position. Mere state ownership in an entity does not render such an entity a public body for the purposes of Article 1.1 of the ASCM or Section 9(1) of the Customs Tariff Act. Other factors with regards to the legal, organizational or financial structure of the entity must be analyzed in detail.
- u) Petitioner has not dealt with AB decision in DS 379 and DS 436. The petitioner should first establish that the entity concerned possessed governmental authority to perform governmental functions and not merely trading or other commercial functions. All the findings had treated the (SOEs) as public bodies merely for the reason that they were state owned. None of the findings quoted were in line with the decisions of the AB.
- v) Lot of information has not been shared by the Petitioner as per Rule 7(7). Petition is incomplete and does not meet the 'adequacy and accuracy' standards as supporting evidence-
  - a. Evidence in respect of existence of each subsidy program
  - b. Evidence of subsidy program being applicable to the product concerned
  - c. Evidence of subsidy program being applicable to this particular industry
  - d. Evidence of other domestic producer and source of their production quantity
- w) In the petition, total of 18 programs numbered as program have been alleged as providing some form of exemption or preferential rate of income tax. It is inconceivable that a particular enterprise would be benefitted from preferential rate of tax for all the 18 programs at the same time. Even assuming that such program results in (i) financial contribution (ii) conferment of benefit and (iii) and is also specific, the benefit can only be countervailed with respect to one of the programs or policies and not for all the programs.

- x) In the petition, total of 7 programs numbered as program 14 to 18, 37 and 42 have been alleged as providing subsidy to the enterprises located in that regions. Even assuming that such program results in (i) financial contribution (ii) conferment of benefit and (iii) and is also specific, the benefit Can only be countervailed with respect to one of the programs or policies and not for all the programs. However, it is inconceivable that a particular enterprise would be benefitted from the different subsidies as it cannot be situated in all such different provinces. In any case, as per Article 8 of the SCM agreement, these programs comprise of subsidy for aid to disadvantaged regions.
- y) Authority has violated the Rule 6 of CVD Rules, Article 11.2 and Article 3 of SCM agreement by initiating the investigation for the alleged Programs because either the program has rescinded in 2008 or is non actionable within the meaning of ASCM. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

#### H.4. Examination by the Authority

78. The various contentions raised by the interested parties concerning alleged subsidy schemes and considered relevant by the Authority, are examined and addressed as follows:

- i. As regards New Subsidy Allegations, the Authority notes that while the petitioner initially requested extension of investigation to include these new subsidies, the petitioner subsequently modified its contention and submitted that the evidence brought out by the petitioner with regard to existence of other subsidy schemes should be considered to hold that the GOC has not disclosed all the schemes which are in vogue in China and where the casting producers have benefitted from countervailable subsidies. The Authority notes that extension of investigation to the additional schemes subsequently identified by the petitioner may not be appropriate keeping in view the time available for completion of the present investigations. Consider changing the language It is, however, noted that the GOC has not provided any information with regard to the additional alleged subsidy schemes prevalent in China even though the questionnaire issued by the authority specifically sought information with regard to any other schemes prevalent in China.
- ii. As regards the contention that petitioner did not correlate the subsidy programmes with the identified 5 exporters from China PR in terms of the geographical region or the specific industries to which the named exporters belong, the Authority notes that the petitioner furnished evidences what is reasonably available to them during the course of the investigation. But, while furnishing a list of more than 200 casting producers in China, the GOC could have provided the said information as well. Moreover, had the GOC cooperated and permitted the Authority for conducting on the spot verification of the data/information of Government bodies as well as the only respondent Chinese producer/exporter, the Authority would have been in a better position to examine and address the claims/evidences made by the domestic industry in this regard.
- iii. As regards the contention that in terms of the findings of Appellate Body decision in DS 379 and DS 436 an investigating authority has to first establish that the entity concerned possessed governmental authority to perform governmental functions and not merely trading or other commercial functions to be termed as public body, the Authority notes that GOC has neither proved with documentary proof that the agencies involved in the alleged subsidies are not public body nor cooperated and allowed verification by the Authority. The Authority notes that the petitioner has initially identified 44 programs, out of which, 37 programs are administered by those Bodies falling within the category of state (GOC, Provincial, Municipal Corporation, local bodies in China). Only 7 programs were identified by the petitioner, which are being administered by SOE. As far as these programs are concerned, the Authority notes that the petitioner provided sufficient evidence to establish that these administering authorities constituted public bodies within the meaning of the law. Therefore, basing on the information furnished by the domestic industry and relying upon the information as available in the public domain, the Authority holds that all the agencies involved in the alleged subsidies in the present investigation have possessed governmental authority to perform governmental functions and therefore are public bodies.
- iv. As regards the contention that the Petitioner has made mere unsubstantiated allegations regarding the subsidies in question, with unsubstantiated claims on specificity and benefit, the Authority notes that the petitioner has provided information in respect of specificity and benefit, that was reasonably available to them, in support of their case during the course of the investigation showing existence of countervailable subsidies. If the GOC had otherwise to prove, then they could have cooperated to allow the Authority to go for on the spot verification of their data as well as the data of the sole respondent Chinese exporter.
- v. The Authority notes that while contending that several schemes are no longer in force, the GOC has not provided any documentary evidence to show that the scheme is no longer in force. The

Authority considers that if a program was introduced by the GOC at some point in time and was withdrawn subsequently, the GOC should have in its possession relevant documents showing introduction of the program and withdrawal of the same. It is, however, noted that while contending that some of the alleged schemes are no longer in force, the GOC has not provided either the documents relating to introduction of the program or documents relating to withdrawal of the program. The Authority, therefore, holds that the contention of the GOC with regard to withdrawal of the programs is unsupported with relevant documentary evidences. Moreover, it may so happen that the name of the program might have been changed or a new program with a different nomenclature might have replaced the old program with the same benefits targeting the same target group. Had the GOC cooperated and allowed the Authority to verify the data/information of the Government as well as the sole Chinese respondent producer/exporter, the truth could have emanated to a great extent. But, since the GOC did not consent for on the spot verification of their data/information including claims made by them during the course of this investigation, the veracity of their contention that many erstwhile subsidy programmes have been resinded cannot be accepted. Moreover, other investigating authorities have found these schemes to be in existence and countervailable in their findings.

79. The domestic industry, vide their letter dated 10th November, 2015, submitted a statement showing consolidated reference to the evidences provided by them earlier during the course of this investigation along with copy of the evidences (hard and soft copy). The Authority has made available the said letter along with the enclosures in the public file for inspection by the interested parties. The subsidy margin has been calculated by the domestic industry as below for the respective schemes as mentioned against each:

Sl. No.	Scheme	Jiali	Others
1	Grants under the following schemes (Program 8 to 17)	5.89%	5.89%
2	The State Key Technology Renovation Projects Fund		
3	Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments		
4	Research & Development (R&D) Assistance Grant		
5	Innovative Experimental Enterprise Grant		
6	Superstar Enterprise Grant		
7	Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"		
8	Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry		
9	Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment		
10	Innovative Small and Medium Enterprise Grants		
11	Grants to Privately-Owned Export Enterprises		
12	Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas (Program 5)	0.00%	0.25%
13	Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas (Program-6)	2.17%	2.17%
14	Equity Programs		
15	Equity Infusion (Program 18)	5.18%	5.18%
16	Unpaid Dividend (Program 19)	0.26%	0.26%
17	Preferential loans and interest rates to the casting industry (Program 20)	0.59%	2.46%
18	Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments (Program 25)	0.76%	0.76%
19	Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses (Program 28)	0.32%	0.32%

20	Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies (Program 31)	1.56%	1.74%
21	Tax credit concerning the purchase of special equipment (Program 33)	0.19%	0.19%
22	Relief from Duties and Taxes on land use fee	1.69%	1.69%
23	Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment (Program 36)		
24	Reduction in Land Use Fees (Program 37)		
25	Raw Materials-Electricity (Program 40)	2.17%	2.17%
26	Provision of various goods for less than adequate remuneration (Program 43)		
A	Raw Materials-Pig Iron	0.32%	0.32%
B	Raw Materials-CRCA Scrap	7.62%	7.62%
	Total CVD margin	28.71%	31.00%

80. Further, the domestic industry, vide their letter dated 12th November, 2015 (copy made available in public file), submitted two statements i.e. Statement A – list of schemes for which the investigations may be terminated and Statement B - schemes for which the investigations is required to be continued. They further informed that for the programs listed below in Statement-A, the petitioner does not have any further evidence with regard to the quantum of benefits which is in addition to the benefits that have been identified by the petitioner in the schemes listed in Statement-B below and requested the Authority to terminate the investigations in respect of the programs listed in Statement-A below.

**Statement-A** - Schemes for which the investigations to be Withdrawn

SN	Heads	Program No.	Schemes
1.	Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas-	Program No. 1	Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area).
		Program No. 2	Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
		Program No. 3	Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
		Program No. 4	Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
		Program No. 7	Preferential Tax for Casting and Forging System
2.	Preferential Income Tax Programs & Tax Incentives	Program No. 21	Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years
		Program No. 22	Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
		Program No. 23	Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive
		Program No. 24	Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs

		Program No. 26	Preferential Tax Policies for Domestic Enterprises Purchasing Domestically Produced Equipments for Technology Upgrading Purpose
		Program No. 27	Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
		Program No. 29	Tax concessions for Central and Western Regions
		Program No. 30	Income tax credit for the purchase of domestically manufactured production equipment
		Program No. 32	Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials') (For FIE's)
		Program No. 34	Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
		Program No. 35	Dividend exemption between qualified resident enterprises
3.	Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value	Program No. 38	Input Materials Hot Rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
		Program No. 39	Hot rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value
		Program No. 41	Land for Less Than Adequate Remuneration to Companies Located in Industrial or Other Special Economic Zones
		Program No. 42	Program consisting of provision of water for less than adequate remuneration
		Program No. 44	Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration
		Program No. 45	Input Materials (raw material) & Utilities provided by Government at less than Market value

**Statement-B** - Schemes for which the investigations to be continued

S. N.	Heads	Program No.	Schemes
1.	Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas	Program No. 5	Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
		Program No. 6	Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
2.	Grants	Program No. 8	The State Key Technology Renovation Projects Fund
		Program No. 9	Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments
		Program No. 10	Research & Development (R&D) Assistance Grant

		Program No. 11	Innovative Experimental Enterprise Grant
		Program No. 12	Superstar Enterprise Grant
		Program No. 13	Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"
		Program No. 14	Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry
		Program No. 15	Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment
		Program No. 16	Innovative Small and Medium Enterprise Grants
		Program No. 17	Grants to Privately-Owned Export Enterprises
3.	Equity Programs	Program No. 18	Equity infusions
		Program No. 19	Unpaid dividends
4.	Preferential Loans	Program No. 20	Preferential loans and interest rates to the casting industry
5.	Preferential Income Tax Programs & Tax Incentives	Program No. 25	Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments
		Program No. 28	Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
		Program No. 31	Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
		Program No. 33	Tax credit concerning the purchase of special equipment
5.	Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery	Program No. 36	Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment
		Program No. 37	Reduction in Land Use Fees
		Program No. 40	Electricity provided by Government at less than Fair Market Value
		Program No. 43	Provision of various goods for less than adequate remuneration

81. In view of the above submissions by the domestic industry and request to withdraw the investigations in respect of the schemes/programs listed in Statement-A above, the Authority does not examine the schemes listed in Statement-A above further and restricts itself to the examination of countervailability of only the schemes/programs listed in the Statement-B above and quantifies the subsidization/injury to the domestic industry.

#### **Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas**

82. **Program No. 5: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas (for FIEs)**
- (a) **Brief about the program** – The domestic industry has alleged that the program grants benefit to the FIEs, which are located in SEZs and other designated zones in the form of reduced income tax. Where the local income tax paid by the FIEs on the income of their establishments or places set up in China to engage in

production or business operations shall be computed on taxable income at the rate of 25%; local income tax shall be computed on the taxable income at the rate of 3%. The eligible foreign invested enterprises fulfilling the criteria will be entitled for paying local income tax at zero rate which is otherwise due to the GOC at the rate of 3%.

- (b) **Views of Interested Parties-** The Govt. of China stated that the program was rescinded when the new Corporate Income Tax Law came into effect on 1 January 2008. They contended that there was no grace period granted for this program. Subsequently at the post disclosure stage, the GOC, by drawing attention of the authority to the Law of the People's Republic of China on Enterprise Income Tax (Adopted at the Fifth Session of the Tenth National People's Congress on March 16, 2007) has reiterated that the scheme /program has been rescinded with effect from 1-1-2008.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has not received any benefit out of this program as it is neither a FIE nor located in SEZs.

IWTMA has contended that the Program was rescinded on 1st January 2008 as per the circular of the State Council on adjusting Tax Policies on import Equipment (GUOFA-I 997) No.37. The program was available for the Hainan Island province of the State Council for encouragement to investments. This program is for the assistance to disadvantaged region within the territory of the exporting country. Therefore the program will fall under the category of Non-actionable subsidy as per Article 8 of the SCM agreement. In view of the above position, investigation for this program should be terminated as per Article 11.9 of the ASCM agreement.

- (c) **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules.
- (d) **Benefit under the program -** The program grants benefit to the foreign invested enterprises in the form of tax savings to those FIEs who are located in a SEZ or other designated areas. The Govt. of China claimed that the alleged schemes have been rescinded in 2008 and the responding exporter has not availed the benefit out of the scheme. However, the domestic industry has claimed that the alleged scheme is still in existence in China and has been held countervailable by other authorities such as US and Canada.
- (e) **Specificity of the Program-** The program is both enterprise specific and region specific; as the benefit under the program is limited only to FIEs located in SEZ and designated areas. Since the benefit under the program is limited to certain types of the enterprises of a particular nature as well as to the designated zones such as Hainan Island, Guangdong Province, the program is specific within the meaning of the Rules.
- (f) **Countervailability of the Program –** As submitted by the domestic industry, existence of the program is established by Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises (the Tax Law); Article 5 & 9, Regulation on the Implementation of the Income Tax Law of the People 's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprise; Regulations on special economic zones in Guangdong province (1980-08-26) ; Provisions of the State Council Concerning the Encouragement of Investment in Developing Hainan Island (1988-05-04);

As submitted by the domestic industry, GOC has also reported existence of this scheme in the WTO as recorded in the WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006. The scheme has also been held countervailable by Canadian Authority in the final finding of Certain Galvanized Steel Wire against PRC and Certain Stainless Steel Sinks from PRC.

- (g) **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises situated in particular region, thus the program is specific within the meaning of the Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of the investigation, the petitioner has submitted the list of casting producers/exporters in China such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd, Gexpro Industry Supply Shanghai Co., Ltd., Sinovel Wind Group Co., Ltd. and Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd which are established in SEZs and Other Designated Areas and are in the nature of FIEs eligible for the benefit. In view of the GOC's post disclosure submission, the authority has not proceeded further to determine the countervailability of the scheme.

### 83. **Program No. 6: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas (For both FIEs & DIEs)**

- a. **Brief about the program –** The domestic industry alleged that the program grants benefit to enterprises which are located in SEZs and other designated areas and fall in the 'encouraged' or 'restricted' categories



in the “Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment and purchasing equipments”. Such enterprises shall be exempted from tariff and import VAT. This program provides an exemption from VAT and import tariffs in favor of both FIEs and domestic enterprises for imports of capital equipment used in their production.

- (h) **Views of Interested Parties-** GOC has mentioned in its response that The program applies to both certain foreign investment projects and certain domestic investment projects and may result in the exemption of the qualifying enterprises from paying import tariff and VAT on the purchase of imported equipment for self-use as long as the equipment does not fall in the categories listed in the Catalogue on Non-duty-exemptible Article of Importation for Foreign Investment Project and the Catalogue on Non-duty-exemptible Article of Importation for Domestic Investment Project. The program was established on 29 December 1997, pursuant to the Circular of the State Council on Adjusting Tax Policies on Imported Equipment (GUOFA (1997) No.37). The policy objective is to encourage foreign investment and the introduction of advanced foreign technology equipment and industrial technology upgrades. On 25 December 2008, the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation issued an Announcement on Relevant Issues Concerning the Corresponding Adjustment of Certain Preferential Policies for Import Duties The said Announcement (No. 43 [2008]) states that, as of 1 January 2009, with respect to self-use equipment imported by domestic investment projects and foreign investment projects, equipment imported with foreign government loans and international financial institutions’ loans, non-evaluated imported equipment provided by foreign processing traders, and technologies and matching pieces and spare parts imported with the above-mentioned equipment according to contracts, and which are encouraged by the state in the above-referenced Circular of the State Council (GUOFA(1997)No.37), the imposition of the import value-added tax shall resume, but import duties shall continue to be exempted within the originally prescribed scope. Subsequently at the post disclosure stage, the GOC, by drawing attention of the Authority to the Notice of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation on the Adjustment of Certain Preferential Import Duty has reiterated that the collection of the import value-added tax shall be resumed while the exemptions of tariffs shall remain applicable.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has not received any benefit out of this program as it is not located in SEZ.

IWTMA has contended that the benefit under this program is provided only to FIEs which fall under encouraged or restricted categories. It seems that the program also allows for exemption or remission of prior stage cumulative indirect taxes levied on inputs that are consumed in the production of final product. The Petition does not provide any evidence to show that the exporters are FIEs. It is claimed that equipment are exempted from tariff and import VAT for enterprises situated in SEZ. Enterprises situated in SEZ are entitled to tariff and VAT exemptions on imported materials and equipment which are used to manufacture and export goods. However, the petition does not show that the exemption which is granted is in excess of those which have been accrued as required under footnote 1 of SCM Agreement. Further, para 1 to Annex II to SCM Agreement read with footnote 1 also exempts such prior stage cumulative indirect taxes as a subsidy. That is, government revenue, which is otherwise due when foregone or not collected, can be treated as financial contribution only when the exemption from the taxes on the exported goods is in excess to those on which it has accrued. Therefore the evidence provided by the petitioner is not sufficient and adequate.

- b. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules. The authorities in charge such as the NDRC and Local Development and Reform Administration confirm whether the investment project is in line with the requirements/criteria or not.
- c. **Benefit under the program -** The program grants benefit to the enterprises in the form of revenue forgone to those FIEs or DIEs which are located in a SEZ or other designated areas and fall within the ‘encouraged’ or ‘restricted’ categories.
- d. **Specificity of the Program-** As contended by the domestic industry, the program is specific, as the benefit under the program is limited only to such FIEs and DIEs which are located in specific SEZ and designated areas and listed under ‘encouraged’ or ‘restricted’ categories. As claimed by the domestic industry, the GOC has formulated the eligibility criteria to this program based on “domestic investment project” and “foreign investment project” and the type of equipment being imported.
- e. **Countervailability of the Program –** As submitted by the domestic industry, existence of the program is established by Articles 1 and 2 of the Notice of the State Council Concerning the Adjustment of Taxation Policies for Imported Equipment (Guo Fa [1997] No. 37) and Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2004) (until 30 November 2007) or Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (2007) (after 1 December 2007); SAT announcement No.49 of 2014; SAT announcement No.51 of 2014.

As further submitted by the domestic industry, in the WTO Semi-annual report of Canada, the alleged scheme has been reported in G/SCM/N274/CAN, 29th august, 2014. The scheme has also been held countervailable by other authorities in their findings against China.

- f. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises situated in particular region, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the coasting producer/ exporter which are located in SEZs either FIE or Domestic enterprises are eligible for such benefit. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of the investigation, the petitioner has submitted the list of casting producers/exporters in China such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd, Gexpro Industry Supply Shanghai Co., Ltd., Sinovel Wind Group Co., Ltd. and Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd which are established in SEZs and Other Designated Areas and are in the nature of FIEs eligible for the benefit. In view of the GOC's post disclosure submission, the authority has proceeded with calculation of the benefits availed by the exporters under the scheme in respect of exemption of tariffs on imported equipments.
- g. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients which is found to exist during the POI. The benefit conferred on the recipients is considered to be the amount of tariff and VAT saved, considering the normal tariff rate and the reduced tariff rate payable under the program. Since the benefit is available regardless of exports by the company, the CVD margin has been determined considering the total sales made by the company. The responding exporter M/s Jiali Wind claimed that it has not benefited under the program as it is not located in SEZ.

It is noted that this subsidy is available to the eligible enterprises irrespective of the products they produce. Benefit under the program is available on import tariffs exemption on the imports of the capital equipment used in their production. The benefit under the program is available on the total sales of the company, once the company is able to claim that it is entitled to benefit under the program. The petitioner has not provided any relevant details regarding the exemption of tariff availed by the exporters of the subject goods. In the absence of the relevant information either from the petitioners or from the interested parties, the Authority has not quantified the countervailability of the program.

### **Grants**

84. Vide their letter dated 12th November, 2015, the domestic industry has requested for continuation of the investigation in respect of the following grant related programs only:

Grants	Program No. 8	The State Key Technology Renovation Projects Fund
	Program No. 9	Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments
	Program No. 10	Research & Development (R&D) Assistance Grant
	Program No. 11	Innovative Experimental Enterprise Grant
	Program No. 12	Superstar Enterprise Grant
	Program No. 13	Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"
	Program No. 14	Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry
	Program No. 15	Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment
	Program No. 16	Innovative Small and Medium Enterprise Grants
	Program No. 17	Grants to Privately-Owned Export Enterprises

85. **Program No. 8: The State Key Technology Renovation Projects Fund**

- a. **Brief about the program -** The domestic industry has alleged that the program grants benefit to large-size SOEs. These enterprises are holding high credit rank among 512 key industries. These enterprises are either getting direct Government contribution to the enterprise or through the provision of low interest loans where the Government paid the interest payment for loans established by the enterprise. The program

is specific; as the benefit under the program is limited only to SOEs which are holding high credit rank among 512 key industries.

- (i) **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that program was rescinded on February 22, 2008. There was no replacement and grace period granted for this program. So there is no casting producers/exporters can apply or receive benefits from this program during the period of investigation. According to the petition, the basic law of this program is Notice Concerning the Promulgation and Circulation of “Measures for (the Administration of National Key Technological Renovation Projects” and “Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects”( GUOJINGMAOTOUZI [1999] 886) and Notice Concerning the Promulgation and Circulation of “Measure for Supervision and Administration of National key Technological Renovation Projects (for Trail Implementation)” (GUOJINGMAOTOUZI (1999)1038). As claimed by the GOC, both these regulations were rescinded vide Order of NDRC No. 59. They further claimed that the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program. Subsequently at the post disclosure stage, the GOC, by drawing attention of the authority to the National Development and Reform Commission Decree No. 59 has reiterated that the program has been rescinded.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program. They further claimed that the grants received by the parent company are not part of the present investigation.

IWTMA contended that the Program has been rescinded on 22nd January 2008 as per the National Development and Reform Commission Decree No.59. No evidence is provided to show that the exporter’s enterprises applied for the funds and that the exporter enterprises are large-sized state owned enterprise with capable leadership, sound administration and high credit ranking among 512 key enterprise, 120 pilot enterprise group and the Leading enterprise in industries. Therefore the investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM Agreement.

- b. **Administering Authority-** The program is maintained by Ministry of Finance (MOF), and Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules. The program is a national program, administered by the ministry of commerce and its local authorities, its local Branch Offices or Bureaus.
- c. **Benefit under the program** – As submitted by the domestic industry, this program sought to provide financial support by the GOC to eligible enterprises enlisted in 512 Key enterprises to promote technological renovation in key industries, enterprises and products; facilitation of technology upgradation; improvement of product structure; improvement of quality; increase of supply; expansion of domestic demand; continuous and healthy development of the State economy. The program constitutes a subsidy as it provides financial contributions in the form of grants or direct transfer of fund for the acquisition of fixed assets, which confers a benefit to the recipient. Since the subsidy is linked to fixed assets and is allocated over time, it is concluded that even if the grant is received by the exporter between 1998 till 2013, the benefit will continue into the POI.
- d. **Specificity of the Program** - This subsidy is specific as the support is limited to certain large-sized state-owned enterprises and state-holding enterprises among 512 key enterprises and 120 pilot enterprise groups. In so far as the project focuses on companies located in specifically designated geographical regions of the old industrial base in north- east, central and west areas, it is also specific within the meaning of Rules.
- e. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, existence of the said program is Measures for the Administration of National Debt Special Fund for National Key Technology Renovation Projects; Notice concerning the Promulgation and Circulation of “Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects” and “Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects” (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 886) (the 1996 Notice); Guojingmao Touzi No 122 of 1999; Notice Concerning the Promulgation and Circulation of “Measures for the Supervision and Administration of National Key Technological Renovation Projects (for Trail Implementation)” from the State Economics and Trade Commission (Guo Jing Mao Tou Zi [1999] No 1038); Notice of Amendments to the “Measures for the Administration of National Key Technological Renovation Projects” and “Measures for the Administration of Treasury-bond Special Fund for National Key Technological Renovation Projects” (Guo Jing Mao Tou Zi [2000] No 822) The domestic industry further submitted that the existence of this scheme has been reported in the WTO, as recorded in the WTO document G/SCM/Q2/CHN/28; WTO-G/SCM/Q2/CHN/42-2011. The scheme has also been held countervailable by other investigating authorities in their findings against China.

- f. **Findings of the investigations & conclusion-** In the course of the investigation, the domestic industry has pointed out that GOC has mentioned in its response to European Commission in the matter of CVD investigation of imports of Organic Coated Steel from China PR, that this program has been terminated in 2003. Where as in the response made in the present investigation the GOC has mentioned that the scheme rescinded in 2008.

The program provides a financial contribution in the form of revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. The domestic industry further claimed during the course of the investigation that there are a few Chinese industries whose website information shows that they have received such grants. The domestic industry also claimed that the sole responding exporter is eligible and has received grants under this program.

- g. The Authority notes that only SOEs are eligible to receive grants under this scheme. Since Jiali is not a SOE, the Authority holds that it is not eligible to get grant under the Scheme. The Authority notes that Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co. Ltd., Liaoning, Dalian is one of the SOEs eligible to receive grant under this scheme For all other non-responding exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were availed by these exporters under these programs. In view of the GOC's post disclosure submission, the authority has not proceeded further to determine the countervailability of the scheme.

**86. Program No. 9: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments.**

- a. **Brief about the program -** The petitioner alleges that this program grants benefit to companies involved in the anti-dumping investigations and working in observance with the instructions of the Ministry of Commerce (MOFCOM) are eligible up to 40% legal fee reduction once they have participated in ADD/CVD investigations. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to respective enterprises which are involved in the ADD or CVD investigations. Under this program the local financial bureau refunds the 40% of the legal fees for a company's participation in anti-dumping proceeding.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that there has never been any anti-dumping or any other trade remedy measure investigation on the subject product by India in respect of subject product. Petitioner has also not shown that the exporters were ever involved in antidumping investigations and availed the benefits provided under the Program. No specificity has been established by the petitioner for the given program. No evidence provided in support of the program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Finance (MOF), and Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body within the meaning of ASCM and the Rules. The program is a national program, administered by the ministry of commerce and its local authorities, its local financial Branch Offices or Bureaus.
- d. **Benefit under the program -** This programme constitutes a subsidy as it provides financial contribution in the form of a grant or direct transfer of funds in order to cover legal fees in anti-dumping or countervailing duty investigation proceedings and confers a benefit within the meaning of Rules.
- e. **Specificity of the Program-** This subsidy is specific under Rules because it is restricted to certain enterprises that are subject to foreign anti-dumping proceedings.
- f. **Countervailability of the Program -** Existence of the said program is the Rules for the Implementation of the Support Policy for the Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard investigation.

The scheme has also been held countervailable by other investigating authorities in their findings against China.

- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises and the subsidy is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidences that these programs were not relevant to current investigations. The GOC, however, did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme. The Authority notes that the only responding exporter has stated that it has not availed any benefit under the scheme and their audited accounts also do not show that they have availed the benefit. Further, the domestic industry has also not provided any evidence to the effect that the benefit under the scheme has been availed by Jiali or any other producer/exporter of the subject goods. The Authority has, therefore, not quantified the benefit conferred by GOC under this scheme to other non responding exporters.

#### 87. Program No. 10: Research & Development (R&D) Assistance Grant

- a. **Brief about the program -** The domestic industry alleged that this programs grants benefits to the eligible enterprises in order to accelerate the transformation of the economic development pattern and economic restructure, enhance the capacity of self-dependent innovation, implementing the strategy on “Innovative Urban District”, and making efforts to achieve the sound and rapid economy development. The program is specific; as the benefit under the program is limited only to respective enterprises which are having R&D facilities and fall under the eligibility criteria. Government of Beijing and Wuxing district and the Science and Technology Bureau of Beijing and Wuxing District are jointly responsible for the administration of this program. It is considered that the program is administered in several regions by different GOC regional bodies.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated by the petitioner. Nevertheless, it is noted that the cooperated exporting producer is not located in the Wuxi city. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that this program will fall under the category of Non- actionable subsidy as per Article 8 of the SCM agreement as it consists of subsidy for research & development. The similar provision for non-actionable subsidy is present and in force in Section 9(3) of Customs Tariff Act read with Rule 11 of CVD Rules. Further, the program is in respect of entities registered and operating in Jingzhou New District. Petitioner has not provided any evidence whatsoever to suggest that the exporters of subject product are based in Jingzhou New District. Therefore the program is a non-actionable subsidy and investigation for this program should be terminated as per Article 11.9 of the SCM Agreement and Rule 11 of CVD Rules.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Science & Technology (MOST) and its Local & Municipal government such as Beijing Municipal Science and Technology Commission and Government of Wuxing district and the Science and Technology Bureau of Wuxing District (‘STB’), which are public bodies within the meaning of ASCM and the Act & the Rules. The program is a national program, administered by the Ministry of Science & Technology (MOST), local & municipal governments and local Branch Offices or Bureaus.
- d. **Benefit under the program -** Grants provided under this program are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. Due to the nature of the grant it is considered that a financial contribution would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise.
- e. **Specificity of the Program-** Only enterprises that undertake science and **technology** research are eligible for the subsidy. As the criteria or conditions providing access to the subsidy favours particular enterprises over other enterprises in China, the program is considered to be specific.

- f. **Countervailability of the Program-** As submitted by the domestic industry, the existence of the said program is evidenced by “Implementation Measure to Support the Acquisition of Foreign Science & Technology Type Enterprises and the Employment of Foreign Science & Technology Development Team, issued by the Shenyang Economic & Technological Development Area administration”; “Notice of the Office of People’s Government of Wuxing District on Publishing and Issuing the Management Measures on three types of Science and Technology Expenses of Wuxing District”. The scheme has also been held countervailable by other investigating authorities in their findings against China.
- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial **contribution** in the form of revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producers/exporters from the subject country which are eligible for the benefit of this scheme. Sinovent Wind Group Co., Ltd. and Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd are some of the Chinese casting producers which may have benefited out of this scheme. Had the GOC cooperated and permitted on the spot verification, this aspect could have been ascertained by the Authority.

Since Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. does not fulfil the eligibility criteria, no benefit has accrued to them under the scheme. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

#### 88. **Program No. 11: Innovative Experimental Enterprise Grant**

- a. **Brief about the program -** The domestic industry alleged that this program provides benefit to the Small and Medium sized enterprises. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to specific SMEs who fall in the eligibility criteria.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grant. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that the petition itself states the eligibility criteria for availing benefit under this program is that the entity should undertake Research & Development activities. Resultantly, this program will fall under the category of non-actionable subsidy as per Article 8 of the SCM agreement as this consists of subsidy for research & development. The similar provision for non-actionable subsidy is present and in force in Rule 11 of CVD Rules. This program is for the assistance with respect to research and development. Further, the program is in respect of entities registered and operating in Zhejiang province. Petitioner has not provided any evidence whatsoever to suggest that the exporters of subject product are based in Zhejiang province. Therefore the program is a non-actionable subsidy and investigation for this program should be terminated as per Article 11.9 of the ASCM Agreement.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Science & Technology (MOST) and its administrative office various provinces, which is a public body such as administrative office of Science and Technology Bureau of Zhejiang Province, which is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules. The program is a national program, administered by the Ministry of Science & Technology (MOST) and its administrative offices in various provinces.
- d. **Benefit under the program -** Grants provided under this program are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. Due to the nature of the grant, it is considered that a financial contribution would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise which falls in the category of SME and undertakes research and development activity for innovation.
- e. **Specificity of the Program-** Only enterprises that small and medium enterprise and undertake innovative research are eligible for the subsidy. As the criteria or conditions providing access to the subsidy favours particular enterprises over other enterprises in China, the program is considered to be specific. The domestic industry has mentioned that Ningbo Ginlong Technologies Co. Ltd., Ningbo Saivs Machinery Co. Ltd., Zhejiang Jiali Wind

Power Technology Co. Ltd., are situated in Zhejiang Province, who are eligible to avail benefits under the scheme. While Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd., has stated that it has not availed the benefit under the scheme, the other companies have not filed any response. Specificity needs too be revisited

- f. **Countervailability of the Program-** As submitted by the domestic industry, the existence of the program is established by Article 10 & 11 of Law of PRC on promotion of SME, Notice of the Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Information Technology on issuing the Measures on Administration of Special Funds for Development of SME's (No. 96 (2012) of ministry of finance), Ministry of Science and Technology, Ministry of Commerce on the issuance of special funds interim measures for SME's development (Cai Qi (2014) No. 38), Ministry of Finance on the issuance of "Interim Measures on Management of special funds for SMEs development (Cai Jian [2015] No. 458). Work Implementation Scheme of Zhejiang Province on Setting up Innovative Enterprises. Administered by the administrative office of Science and Technology Bureau of Zhejiang province. The scheme has also been held countervailable by other investigating authorities in their findings against China.

**Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds as revenue conferred by the GOC within the meaning of the ASCM and Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producer/ exporters. Chinese casting producers, such as Jiali Wind Power and Ningbo Ginlong Technologies Co. Ltd are some of the exporters in Zhejiang Province eligible for such grant.

The Authority notes that the Jiali being non-SME does not fulfill the criteria for benefit under the scheme. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

#### 89. Program No. 12: Superstar Enterprise Grant

- a. **Brief about the program -** The domestic industry alleged that the eligible enterprise having 'output scale' is entitled for this grant. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to specific enterprises which have the required output sale. Provincial Authority granted this award based on the total value of its sales. The company which meets the relevant sales threshold for the year receives this award in the next year.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer his question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. Nevertheless, it is noted that the cooperated exporting producer is not located in the Huzhou city. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that the eligibility criteria prescribed with respect to this program relates to period 2006-2008 and not for subsequent period. No information has been provided to suggest that this program is available for subsequent period. The program is maintained by Huzhou Economic committee. No evidence is provided to show that the grants are provided directly by the government or public body as per Article 1(1)(i) of the SCM agreement. Therefore the program cannot be termed as providing financial contribution. This subsidy Program is available only to enterprise located in Huzhou city and no evidence is provided that the exporters are located in Huzhou city. The investigation for this program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Government of China PR through provincial authority which is a public body. Such as this program is administrated by the Huzhou Economic Committee.
- d. **Benefit under the program -** Grants provided under this program are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. Due to the nature of the grant it is considered that a financial contribution would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise.
- e. **Specificity of the Program-** We further determine that the grant provided under this program is limited as a matter of law to certain enterprises; i.e., enterprises that exceed certain sales values during a year. Hence, the subsidy is specific.

- f. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, the existence of the said program is Measures for Assessment and Encouragement of Superstar Enterprises and Excellent Enterprises, Notice of Huzhou Government Office Concerning Announcement of Criteria for Superstar Enterprises, Excellent Enterprises and Backbone Enterprise. The scheme has also been held countervailable by other authorities in their findings against China.

**Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds as revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. Chinese casting produces Jiangsu FAW Foundry co. Ltd.; Deqing Jufeng Machinery Manufacturing Co. Ltd., etc are some of the exporters eligible for such grant. The Authority notes that Jiali has not availed any benefit under the scheme. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

**90. Program No. 13: Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"**

- a. **Brief about the program** – The domestic industry alleged that this scheme provides grants to companies in order to boost exporting brands and increase the market share of famous brands. The eligible enterprises are specifically chosen on the basis of the key enterprises whose products qualify for the title of 'China Worldwide famous Brand' and are bestowed with the said benefit. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to Enterprises whose products qualify for the title of 'China Worldwide famous Brand' and/or 'famous trademark (China famous Trademark).
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that China Famous Brands are merely historical honours, which have not been used since the year 2008. So there is no casting producers/exporters can apply or receive benefits from this program during POI. In addition, the amounts granted under this program when it existed were always very small and were not related to fixed assets. Therefore any grants received before the year 2008 were expensed in the year that these were received implying that no benefit can possibly have been existed in or extended to the IP of the current investigation. Nevertheless, it is noted that the cooperated exporting producer is not located in the Guangdong and Shandong Province. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that the petition itself states that the evidence is not available with respect to which products qualified for the program. Also, there is no evidence that any of the exporters of subject goods qualified for the program. This program is available only to enterprise located in Guangdong province and no evidence is provided that the exporters are located in Guangdong province. No direct transfer of funds by government of China has been established by the petitioner and therefore does not qualify to be subsidy. No specificity has been established in the petition in respect to this program. The Authority has violated the Rule 6 of CVD rules, Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by GOC at National, Provincial, and Local Government levels which are public bodies. For example, Government of Guangdong province is responsible for the administration and management of this program.
- d. **Benefit under the program** - This programme sought to provide financial support in the form of direct transfer of fund to eligible enterprises. This scheme is to boost exporting brands and increase the market share of famous brands.
- e. **Specificity of the Program-** This subsidy scheme is specific within the meaning of Rules as access to it is limited to certain enterprises i.e. exporting famous brand enterprises. There is no such legal or administrative information on the eligibility criteria, though the eligibility is totally based on the well known aspect of the product being exported.
- f. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, the existence of the program Order No. 124-Measures for the Administration of Chinese famous –brand products- Dec 2009, Measures for the Administration of Chinese famous –brand products- Dec 2006, Decision Concerning Commending and/ or Awarding to Enterprises of Guangdong Province Whose Products Qualify for the Title of 'China Worldwide Famous Brand', 'China Famous Brand', or 'China Well-Known Brand'. Notice of Shandong Province concerning the special award Fund Budget in 2008 for the Development of Self Exporting Brand [Lucaiqizhi (2008) No. 75]. As further submitted by the domestic industry, the



program has been reported in the Trade policy review-WT/TPR/S/300, WTO Report G/SCM/Q2/CHN/42. The program has also been held countervailable by other authorities in their findings against China.

- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds as revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producer/ exporter which have been bestowed with the famous brand award from the GOC. Chinese casting producers such as Jiali Wind Power and Ningbo Ginlong Technologies Co. are eligible for such grants as reported on their websites.

The Authority notes that Jiali has not availed any benefit under the scheme. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information. .

#### 91. Program No. 14: Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry

- a. **Brief about the program -** The domestic industry alleged that the program grants the direct transfer of the fund to the eligible enterprises which have venture capital and have recorded the information with the relevant local counterpart of NDRC. The said venture investment companies must be recognised as high-tech enterprises and be small to medium sized, are benefited. The program is specific, as the benefit under the program is limited only to Enterprises with 'high-tech programs' located in the High-Tech Zone or the High-Tech Park present in city or provinces like Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that there is no evidence provided in the petition with respect to direct transfer of funds by Government. Also, there is no evidence that the program qualified to be a subsidy as per Article 1(1)(i) of SCM Agreement. This program is available only to enterprise located in New Northern District and no evidence has been provided that the exporters of the subject goods are located in New Northern District. No specificity is established in the petition for this program. The Authority has violated the Rule 6 of CVD Rules, Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by NDRC and National, Provincial/Municipal Authorities in GOC which are public bodies.
- d. **Benefit under the program -** The grants provided under these programs are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. Due to the nature of each grant, it is considered that a financial contribution under each program would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise (including Casting). This financial contribution is considered to confer a benefit to recipient manufacturers of casting due to receipt of funds from the GOC.
- e. **Specificity of the Program -** the venture investment grant is provided to the specific enterprises which are in possession of; hi-tech status; and are in the nature of the short or medium type of enterprise. Also such enterprise is located in any designated high tech zones. Thus the scheme is specific within the meaning of Indian Rules.
- f. **Countervailability of the Program -** As submitted by the domestic industry, the existence of the program by Circular of Chongqing People's Government Office in Temporary Administration Measures-2005; and Web research-Venture capital investment in China market regulatory overview-2013. It is further submitted by the domestic industry that the scheme has been reported in existence in the WTO, as recorded in the WTO document G/SCM/N/267/CAN. The scheme has also held countervailable by other authorities in their findings against China.
- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of fund as revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the Authority finds that the program is specific within the

meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producer/ exporter which are eligible for the said benefit. As submitted by the domestic industry, Chinese casting producer Gamesa Wind (Tianjin) Co, Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd., Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd., Satarem China Ltd., Shanghai SIIC E&A International Trade Co. Ltd., Sinovel Wind Group Co., Ltd. who are located in Beijing, Shanghai, Tianjin, and Chongqing are eligible for the grant.

The Authority notes that Jiali has not availed any benefit under the scheme. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

**92. Program No. 15: Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment**

- a. **Brief about the program** – As submitted by the domestic industry, the program grants benefit to FIEs located in certain provinces of China such as Guangzhou. The program is specific to FIEs which are located in Guangzhou. The GOC invites the foreign enterprises to bring their head and brain to the land of China. This program is available to foreign invested enterprises whose headquarters are established in the certain designated areas. To qualify as ‘Headquarters’ the facility must control all the operations and management of any enterprises it is invested in, both in China and internationally. To qualify as ‘Regional Headquarters’, the facility must control operations and management of some or all enterprises it is invested in a certain area of China. Headquarters or Regional headquarters may be of investment companies, management companies, research and development centres, and production enterprises.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. Nevertheless, it is noted that the cooperated exporting producer is not located in the Guangzhou city. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that the petition itself states that no evidence is available with respect to this program. There is no evidence in the petition that the program pertains to exporters of the subject product. This program is available only to enterprises located in Guangzhou and no evidence is provided that the exporters of subject goods are located in Guangzhou. Therefore, the investigation for this program should be terminated as per Article 11.9 of SCM Agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Local commerce authority of provinces which is a public body. Administered by the local commerce authority of Guangzhou.
- d. **Benefit under the program** - The grants provided under these programs are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. It is considered that a financial contribution under such programs would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise. This financial contribution is considered to confer a benefit to recipient manufacturers of casting due to receipt of funds from the GOC.
- e. **Specificity of the Program** - as per the prescribed criterion the grant is limited to the enterprises which are located in specific region and are in the nature of FIEs. Furthermore, this programme is also specific within the terms of ASCM and Rules given that it is limited to certain enterprises registered in the designated geographical regions governed by the relevant provincial authorities implementing this programme.
- f. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, the existence of this program is established by “Notice of the General Office of Guangzhou Municipal People’s Government about Issuing the Provisions of Guangzhou Municipality on Encouraging Foreign Investors to Set up Headquarters and Regional Headquarters (No. 34 [2006])” which was later replaced with “Guangzhou Municipal People’s Government to speed up the implementation of the views forwarded to notice the development of headquarters economy (Sui [2010] 2)” and Provision of Guangzhou Municipality on Encouraging Foreign Investors to Set Up Headquarters and Regional Headquarters.

- g. **Findings of the investigations & conclusion.**—The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of fund as revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the Authority finds that the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. As claimed by the domestic industry, Chinese casting producers, such as Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd is a FIE, located in Guangzhou Municipality are eligible for the grant. The Authority notes that Jiali is not eligible for benefits under the scheme as it is not a FIE.

For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

### 93. Program No. 16: Innovative Small and Medium Enterprise Grants

- a. **Brief about the program** – The domestic industry alleged that the program grants benefit to SMEs in start-up capital for small firms recognized by R&D for key projects. The program is specific as it is limited to SMEs.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such Government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. Nevertheless, it is noted that the cooperated exporting producer is not located in the Guangzhou city. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that the petition itself states that the evidence is not available with respect to the program. This Program is available to units located in Guangdong province. Petitioner has not established that the exporters units of subject goods are located in Guangdong province. Specificity in respect to the program is not established. Therefore the investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Government of China at National, Provincial, and Local Government levels such as government of Guangdong province and Ningbo Zhenhai Development and Reform Bureau is responsible for the administration and management of this program, which is a public body.
- d. **Benefit under the program** - The grants provided under these programs are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. Authority considers that a financial contribution under each program would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise. This financial contribution is considered to confer a benefit to recipient manufacturers of casting due to receipt of funds from the GOC.
- e. **Specificity of the Program-** the alleged program is specific as it is limited to certain enterprises which are in the mainly small and medium scale enterprise and have R&D centers for their key projects.
- f. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, the existence of this program is established by Articles 12,13,36 of Law of PRC on promotion of SME; Measures for Administration of International Market Developing Funds of Small and Medium Sized Enterprises; Detailed rules for the implementation of the measures for administration of international market developing funds for small and medium sized enterprises, (July 1, 2001); Circular cooperation issuing the measures for the administration of international market developing funds of small and medium sized enterprises (2010); Foreign trade development funds and management approach, Cai Qi (2014); Notice of the ministry of finance and the ministry of industry and information technology on issuing the “Measures on Administration of Special Funds for Development of SME’s [No. 96 (2012) of ministry of finance]”; Ministry of industry and information technology, Ministry of science and technology, Ministry of commerce on the issuance of special funds interim measures for SMEs development [Cai Qi (2014) No. 38] & Ministry of Finance on the issuance of "Interim Measures on Management of special funds for SMEs development [Cai Jian (2015) No. 458].
- g. **Findings of the investigations & conclusion** - The program provides a financial contribution in the form of start-up capital which is direct transfer of fund as revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, the program is subsidy is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producer/ exporter which are eligible for

above mentioned grant. As claimed by the domestic industry, the Chinese casting producers such as Jiali Wind Power Technology Co., Ltd., are eligible for such grant.

The Authority notes that Jiali has not availed any benefit under the scheme. For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

#### 94. **Program No. 17: Grants to Privately-Owned Export Enterprises**

- a. **Brief about the program** – The domestic industry alleged that the programs grant benefit to Non-SOEs located in Yunnan Province. The program is specific as it is limited to Non-SOEs located in specific province. The program is to reduce the investment cost of importing technologies or equipments, and to attract foreign investment and to encourage domestic investment.
- b. **Views of Interested Parties**- The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such Government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used, or benefited from this program.

IWTMA contended that The Program is available to Non-SOEs located in Yunnan Province. However, no evidence has been provided to prove that the exporters of subject goods belong to Yunnan province. The Authority has violated the Rule 6 of CVD, Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority**- the said program constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Yunnan Provincial Government which is public body.
- d. **Benefit under the program** - The grants provided under these programs are financial contributions by the GOC, which involve a direct transfer of funds by GOC to the recipient enterprises in China. In light of the limited information available, it is considered that a financial contribution under each program would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise (including Casting). This financial contribution is considered to confer a benefit to recipient manufacturers of casting due to receipt of funds from the GOC.
- e. **Specificity of the Program** - the said grant is specific as it is limited to certain enterprises which are privately owned and are trading focus (export oriented) companies.
- f. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, the existence of this program is established by Notices concerning accelerating the growth of the non-state-owned economy which lists eligible the enterprises.
- g. **Findings of the investigations & conclusion.**—The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of fund as revenue conferred by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, thus the program is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producer/ exporter which are eligible for the above mentioned grant.

The Authority notes that Jiali has not availed any benefit under the scheme as it is not situated in Yunnan province. No information about the existence of any casting manufacturing company has been provided by either the domestic industry or the Government of China or any other interested parties. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information.

#### **Calculation of Subsidy Margin for Grants**

95. In respect of the above examined grants at Sl Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, the amount of subsidy is required to be calculated on the basis of benefit received by the company concerned. The responding exporter claimed that it has not received any benefit from the government. However, the website of the company clearly states that the company was bestowed with grants and awards in the form of “Research & Development (R&D) Assistance Grant”, “Famous Brand Award”, “Excellent innovative enterprise” and “Standard innovative enterprise” certificate. The sole responding company was asked to clarify the contradiction in the website and the response

filed by them. However, Jiali chose to reiterate its position and offered no comments on the certificate shown on the website. Moreover, the GOC did not permit the Authority to conduct on the spot verification of their information as well as that of the respondent exporter. In the deficiency letter issued by the Authority to the responding exporter, regarding the financial benefits received by the company, the company replied as follows:

*“Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd. and Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd. are different entities, Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd. is the parent company of Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd., and it is not involved in production, sales or procurement of raw materials of the product under consideration.*

*Functions of Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd. is investment in Jiali Wind. Jiali Wind operates its business and makes decision independently and the parent company does not exercise any control on Jiali Wind's business operations.*

*We would like to bring the Honorable Designated Authority's attention that the above honors are rewarded to the parent company Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd., which is not subject to this investigation”.*

*(a) Jiali Wind was recognized as “Key high-tech enterprise” in December 2008 by Science and Technology Bureau of Zhejiang Province, the Finance Bureau of Zhejiang Province, State Taxation Bureau of Zhejiang Province and Local Taxation Bureau of Zhejiang Province; no benefit was given to it for getting the recognition.*

*(b) Famous Brand was recognized to Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd. on the product of petroleum special pump, petroleum chemical equipment; no benefit was given to it for getting the recognition.*

*(c) Jiali Wind was recognized as excellent innovative enterprise of Zhejiang Province in September 2008, by Zhejiang Science and Technology Association and Zhejiang Science Press; no benefit was given to it for getting the recognition.*

*(d) Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd. was recognized as “standard innovative enterprise “in December 2012 by the Quality and Technical Bureau of Zhejiang Province; no benefit was given to it for getting the recognition.*

*(e) Zhejiang Jiali Technology Co. Ltd. was recognized as “Zhejiang Province Innovative Pilot Enterprise” in November 2008 by the following government entities: Science and Technology Bureau of Zhejiang Province, Economic and Trade Committee of Zhejiang Province, Finance Bureau of Zhejiang Province, State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Zhejiang Province, Finance Working Group Office of Government of Zhejiang Province, Quality and Technical Bureau of Zhejiang Province, Trade Union of Zhejiang Province; no benefit was given to it for getting the recognition.*

Post disclosure, Jiali Wind submitted that the figure \*\*\* has been double counted and thus the total amount of \*\*\* is not correct: The “Government subsidy” in amount of RMB \*\*\* was a total amount which has included all the items listed from item 2 through item 18 as indicated in the annual report. They further submitted that the benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC. None of the subsidy received by the parent company was related to the PUC, thus it shall not be allocated to Jiali Wind. Furthermore, as submitted by Jiali Wind, even if the Authority intends to calculate the benefits for the programs 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, it should calculate the benefit for each alleged program, instead of calculating a 5.89% for a package of programs 8 to 17.

After analyzing the annual reports of the parent company, the Authority notes that the parent company received various financial benefits in the form of grants under various heads from the government. The total amount received by the Parent company is \*\*\* RMB. Thus the benefit received by Jiali Wind allocable to the subject goods is \*\*\* RMB. Since the benefits under the various grants is not limited to a particular market and is limited to a type of enterprise, the amount of subsidies received has been divided by the total sales made by the company in all the markets. Accordingly, the quantum of subsidy for the above mentioned programmes is determined at 1.99% for Jiali.

The Authority notes that, in the absence of the above relevant information and as neither the GOC nor any of the other exporters/producers from China have fully cooperated with the Authority in the present investigations, concludes that the non-cooperating exporters meeting the eligibility criteria for these programs, have accessed these programs, and therefore received financial contributions under these programs.

The GOC identified more than 200 producers of castings in China. The Petitioner provided evidence that at least few of the other casting producers were also entitled for this benefit. In the absence of any information from other producers/exporters of castings in China, the authority has determined the CVD margin for other producers/exporters at 1.99% as has been determined for the sole responding exporter.

### **Equity Programs**

#### 96. Program 18: Equity infusions

- a. **Brief about the program** - The GOC has provided over the years substantial amounts of cash to enterprises through equity infusions. The GOC (through various state-owned entities) acquired shares in companies in which it was already the main shareholder without acquiring additional shareholder rights. GOC was requested to submit information about these programs in the original and supplementary questionnaires. But, no relevant information was provided by the GOC. These equity infusions are considered to confer a benefit to the recipient companies within the meaning of Rules. Such infusions are considered to be unusual to the investment practice of private investors. The SOE paid an overvalued price of its portion of the new share issue not in line with fair market conditions, and it used the funds raised to purchase state-owned assets and equity investments at below-market prices. The GOC paid the same price as other investors despite its shares were worth less as they had different rights and prospects than the shares sold to other shareholders.
- b. **Views of Interested Parties**- The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such Government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that Jiali Wind is a privately-owned limited liability company. Jiali Wind did not receive any benefit from this program.

IWTMA contended that there is no evidence in the petition to suggest that CICC and SASAC are public bodies and are acting on behalf of Govt. of China. This program relates to only steel producers and there is no evidence in the petition to suggest that this program is applicable, generally and especially, to casting producers. In the absence of any 'pass through' benefits being established, it cannot be said that benefit has accrued to casting producers through equity infusion. The Authority has violated Rule 6 of CVD Rules, Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering Authority**- The equity infusions concerning an SOE, where China International Capital Corporation Limited ("CICC") acted as the lead underwriter and manager of the share issuance. As claimed by the domestic industry, CICC is 51 % state-owned and it is ultimately controlled by State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC), also acted as the GOC entity controlling the SOEs. SASAC performs the responsibilities of the State as an investor and manages the state-owned assets under its supervision. SASAC, authorised by the State Council, appoints and removes the top executives of the supervised enterprises, and evaluates their performances through legal procedures. It is also responsible for urging the supervised enterprises to carry out the guiding principles and policies, has responsibility for the fundamental management of the state-owned assets of enterprises and directs and supervises the management work of local state-owned assets according to the law. SASAC is also responsible for remuneration and assessment of the SOEs' managers; furthermore, it appoints and decides on the rewards and punishments to the SOE managers. The careers of SOE managers depend on SASAC. These circumstances show that the SASAC clearly is vested with Governmental authority. The composition of the Boards of SOEs also demonstrates the high level of control by the GOC of the SOEs. Many of the members of boards of directors and boards of supervisors hold or held in the past government and/or party functions and that their selection is strongly influenced by governmental authorities such as SASAC or Communist Party of China (CCP). Therefore, these transactions were carried out by the GOC through public bodies within the meaning of Rules and the relevant WTO jurisprudence.
- d. **Benefit under the program** - Equity infusions constitute a direct transfer of funds within the meaning of Rules. These financial contributions were provided by the government through public bodies involved in these transactions, including China International Capital Corporation (CICC) and SASAC.
- e. **Specificity of the Program** - These subsidies are specific because they were provided to a limited number of selected entities in which the government participated. Therefore it can be concluded that this program constitutes a countervailable subsidy for exporting producers of the product concerned.
- f. **Whether the program is countervailable** – As submitted by the domestic industry, the GOC holds share in the enterprises and paid the same price as other investors. This amounts to direct transfer of Government funds to certain enterprises. However, the domestic industry did not provide any evidence to substantiate their claim.
- g. **Findings of the investigations & conclusion**- The Authority considers that the scheme is countervailable as the benefit is being provided to the certain enterprises in the form of equity infusions where the CICC and manages of the share issuance. As claimed by the domestic industry, CICC is 51 % state-owned and it is ultimately controlled by SASAC, which is a public body within the meaning of ASCM and Rules.
- h. **Calculation of subsidy amount**- The amount of countervailable subsidy could not be calculated in terms of the benefit conferred on the recipients, due to lack of information. The information furnished by the sole responding

exporter does not show that they had availed any benefit under the scheme. In the absence of any other information provided by the petitioner as well as other interested parties, the Authority has not quantified the benefits accrued to other non-responding exporters.

#### 97. Program 19: Unpaid dividends

- a. **Brief about the program** - According to GOC policy, state-owned enterprises do not have to pay dividends to the government as their owner even when they earn profits. As a result, SOE are able to finance massive investment through retained profits not distributed as dividends according to this program.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has responded that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers have received such government grant. The petitioner failed to provide any evidence indicating that casting producers have benefited from such grants. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that Jiali Wind is a privately-owned limited liability company. Jiali Wind did not receive any benefit from this program.

IWTMA contended that No evidence provided in the petition to show that the program is applicable to casting producers. There is no evidence in the petition to suggest that CICC and SASAC are public bodies and are acting on behalf of Govt. of China. The Authority has violated Rule 6 of CVD Rules, Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** the body known as SASAC in China is authorised by the State Council, appoints and removes the top executives of the supervised enterprises, and evaluates their performances through legal procedures. Also SASAC is responsible for urging the supervised enterprises to carry out the guiding principles and policies and has responsibility for the fundamental management of the state-owned assets of enterprises and directs and supervises the management work of local state-owned assets according to the law. SASAC is also responsible for remuneration and assessment of the SOEs' managers; furthermore, it appoints and decides on the rewards and punishments to the SOE managers. The careers of SOE managers depend on SASAC. These circumstances show that the SASAC clearly is vested with Governmental authority. The composition of the Boards of SOEs also demonstrates the high level of control by the GOC of the SOEs. Many of the members of boards of directors and boards of supervisors hold or held in the past government and/or party functions and that their selection is strongly influenced by governmental authorities such as SASAC.
- d. **Benefit under the program** - Unpaid Dividend constitutes a direct transfer of funds within the meaning of Rules. These financial contributions were provided by the government through public bodies involved in these transactions, including CICC and SASAC.
- e. **Nature of subsidy program and whether the subsidy program is specific-** These subsidies are specific under Act & Rules because they were provided to a limited number of selected entities in which the government participated. Therefore it is concluded that this program constitutes a countervailable subsidy for exporting producers of the product concerned.
- f. **Practical implementation [how the program operates]-** Unpaid dividends must be considered as a grant in disguise in the meaning of ASCM and Rules. The GOC does not collect dividends that are normally paid to private investors on their shares. These disguised grants were provided by the government through the entity directly holding the shares in the SOE steel producers, in principle SASAC.
- g. **Whether the program is countervailable** - As submitted by the domestic industry, the GOC infused dividends in the enterprises, which amounts to direct transfer of Government funds to certain enterprises and can be considered as grant in disguise.
- h. **Findings of the investigations & conclusion-** Since the GOC failed to provide any information on dividend distributions by the SOEs, the findings on this program are based on the information contained in the petition as well as the subsequent information submitted by the petitioner, as supported by adequate sources. Unpaid dividends must be considered as a disguised grant or as revenue forgone in that the GOC does not collect dividends that are normally paid to private investors on their shares. These disguised grants were provided by the government through the entity directly holding the shares in the casting producers. The analysis concerning SASAC shows that it performs Government functions.

**Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients, which is found to exist during the period of investigation. The benefit conferred on the recipients is considered to be the amount of the unpaid dividends. In the absence of information for the assessment of this benefit, the Authority could not quantify the benefit conferred under the scheme. From the information made available by the sole responding exporter, the Authority finds that the Government is not the shareholder in the

respondent exporter company and therefore not benefited under the scheme. The information furnished by the sole responding exporter does not show that they had availed any benefit under the scheme. In the absence of any other information provided by the petitioner as well as other interested parties, the Authority has not quantified the benefits accrued to other non-responding exporters.

### **Preferential Loans**

#### **98. Program No. 20: Preferential loans and interest rates to the casting industry**

- a. **Brief about the program** – The domestic industry alleged that Chinese producers of the product concerned benefit from low-interest rate loans from government policy banks and state-owned commercial banks ('SOCBs') pursuant to the GOC's policy to provide financial assistance in order to encourage and support the growth and development of the wind power sector. As illustrated in the five-year plans and industrial policy, preferential financing initiatives were granted by the banking system to the renewable sector as well as steel sector. The program grants benefit to casting producers by providing loan on low (subsidized) interest rates from state-owned commercial banks and government banks to support and develop the expansion of the industry. The GOC is a major shareholder in many of the major banks established in China and therefore it has access to banks.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China stated that there is no such program explaining that :

*"Article 4 of the "Commercial Banking Law of China" (provided as "commercial Banks shall follow the principles of safety, liquidity and efficiency. Commercial banks make their own decisions regarding their business operations in accordance with the law and without any interference from any entity or individual".*

The GOC has endeavored and put great efforts to reform commercial banks since 2003, in order to improve the governance structure and enhance the risk management capability of commercial banks. PBOC does not interfere with the loan business of commercial banks. Following the restructuring, major SOCRs as well as private banks are now publically listed companies operating solely on market principles. There is no specific lending policy designed and applied according to any specific industry sector."

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has never applied for, used or benefitted from this program.

IWTMA has contended that this program relates to only steel producers and there is no evidence in the petition to suggest that this program is applicable, generally and especially, to casting producers. It is alleged that the lending practices of banks, which are owned by Govt of China amount to contribution, as such provision of loan results in direct transfer of funds from the Govt within the meaning of the Rules. It is to be noted that financial contribution cannot arise where banks, even though Govt owned, are providing loans to producers. It is required to be shown that the Govt provision of loan is beneficial as compared to the comparable commercial loan, which the firm will obtain from the market, as per Article 14 of SCM Agreement. No such market comparison has been made either within China or outside China to demonstrate that benefit is conferred on the enterprises by the state owned banks through their lending practices.

It is not sufficient to merely state that private banks are also entrusted and directed by the Govt to follow preferential lending practices in China. Such fact does not absolve the petitioner from the burden of determining the benefit by comparing the comparable commercial loan outside China. In any case, commercial banks in terms of Article 4 of Commercial Banking Laws of China are not required to follow Govt policies with regard to their commercial operations.

- c. **Administering authority-** the program is maintained by Government of China at National, Provincial, and Local Government levels, CICC and SASAC which is public body. NDRC is an agency of the State Council coordinating macro-economic policy and managing the Government investments.
- d. **Benefit under the program** - In China generally the government loans are granted on terms more favorable than the recipient could actually obtain on the market. The loans provided by Chinese banks reflect substantial government intervention in the banking sector and do not reflect rates that would be found in a functioning market.
- e. What is the normal rate and what is the preferential rate...some information on which this finding is based must be provided.
- f. **Specificity of the Program-** The GOC was asked to provide information on the eligibility criteria for obtaining this subsidy and on the use of the subsidy, in order to determine the extent to which access to the subsidy is limited to certain enterprises and whether it is specific. The GOC provided no such information
- g. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry, the existence of this program is established by YinFa [2003] No.250 and YinFa [2004] No 251; The annual reports of Chinese banks; Catalogue for the guidance of foreign investment industries (amended in 2011); Article 34 and 38 of The Commercial banking law [2003]; NDRC Order No.35- Policies for the development of Iron and Steel Industry, decision 40 and Article 24, 25, 34 of the Law on Commercial Banks act with respect to the fulfillment of the government industrial policies;



The domestic industry further submitted that GOC has reported existence of this scheme in the WTO, as recorded in the WTO Trade Policy Review Report, WT/TPR/S/300; Document WT/TPR/S/264, July 2012; 2006 Deutsche Bank Research on China's banking sector; Information retrieved from the 2006 Deutsch Bank Research on China's banking sector, pages 3-4; Information retrieved from the China Monetary Report Quarter Two, 2010 of the Monetary Policy Analysis Group of the People's Bank of China, dated 5 August 2010, page 10; IMF Working Paper, "Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behavior Changed?", WP/06/71, March 2006, (see pages 3-4, 13, 18-20); IMF Working Paper, "Interest Rate Liberalization in China", WP/09/171, August 2009, (see pages 3-4, 21-23); IMF Country Report, PRC: 2010 Article IV Consultation, No 10/238, July 2010, (see pages 22, 24 and 28-29); OECD 2010 Economic Survey of China, February 2010, (see Chapter 3, pages 71, 73-81, 97); OECD China's Financial Sector Reforms, Economic Department Working Paper No. 747, ECO/WKP (2010) 3, 1 February 2010, (see pages 2, 8-15, 36); Detailed rules for implementing the adjustment and revitalization program for the steel industry [2009] provides for "increasing the financial support for key backbone enterprises". As claimed by the domestic industry, the scheme has also been held countervailable by the other investigating authorities in their findings against China.

- h. **Findings of the investigations & conclusion-** Furthermore, having regard to the totality of the evidence, it is considered that the vast majority of loans to the producers/exporter of the subject goods are provided by policy or other state-owned banks which are considered to be public bodies because of their close relationship to the government. As claimed by the domestic industry, they are more than 50% state-owned and are thus considered controlled by the government. These banks effectively exercise government authority since there is a clear intervention by the State (i.e. PBOC) in the way commercial banks take decisions on interest rates for loans granted to Chinese companies while in some cases companies were attributed *quasi* automatically the lowest possible rate within the limits set by the State. In these circumstances, the lending practices of these entities are directly attributable to the government. There is also a great deal of circumstantial evidence, supported by objective studies and reports, that a large amount of government intervention is still present in the Chinese financial system. Finally, China failed to provide information which would have enabled a greater understanding of the state-owned banks' relationship with government. Thus, in the case of loans provided by policy or other state-owned banks, the Authority notes that there is a financial contribution to the casting producers in the form of a direct transfer of funds from the government within the meaning of Indian Rules.

For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

- i. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients, which is found to exist during the period of investigation. The benefit conferred on the recipients is considered to be the difference between the amount that the company pays on the loan availed from banks and the amount that the company would pay for a comparable commercial loan obtainable on the market. Since the loans provided by Chinese banks reflect substantial government intervention in the banking sector and do not reflect rates that would be found in a functioning market.

Both the GOC and the cooperating exporting producers were requested to provide information on the lending policies of the Chinese banks and the way loans were attributed to the exporting producers. The GOC as well as the responding exporter failed to provide such information, although repeatedly requested to do so. Accordingly in view of this lack of cooperation and the totality of facts available, the Authority considered that the normal interest rate for Loans in China is 6% p.a. Jiali in its post disclosure comments has stated that the Authority has considered the book value of assets and the percentage of assets mortgaged/pledged as the amount of loan and the rate of interest respectively. They have further stated that the interest rates on the loans availed by them ranged from \*\*\*% to \*\*\*%, demonstrating that they were at normal market rates. In view of the above submission of Jiali, the Authority concludes that no benefits were accrued to Jiali under the scheme. In the absence of any other information provided by the petitioner as well as other interested parties, the Authority has not quantified the benefits accrued to other non-responding exporters.

#### **Preferential Income Tax Programs & Tax Incentives**

##### **99. Program No. 25: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments**

- a. **Brief about the program** – As submitted by the domestic industry, the GOC offers preferential income tax policies to FIEs and Foreign Enterprises if these enterprises upgrade their manufacturing operations with Chinese-made equipments. Specifically, FIEs and Foreign Enterprises which upgrade technology consistent with the GOC industrial policies may deduct 40 percent of the cost of equipment from their next year's income tax obligation, and in those circumstances where the income tax due is less than the 40 percent of the cost of the machinery, the

remainder of the cost may be deducted in subsequent years, for a period up to five years. To be categorized as an FIE, the enterprise must be a Chinese-Foreign equity joint venture, a Chinese-Foreign cooperative joint venture or a wholly foreign owned enterprise established in China under Article 8 of the FIE Income Tax Law.

- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China stated that the program was effectuated on 1 July 1999. This program was rescinded by the new Enterprise Income Tax Law of 2008. As this scheme did not belong to any type of preferential tax treatment under Article 57 of the new Enterprise Income Tax Law of 2008, no grace period was provided. The government's policy behind the program was to attract foreign investment and support technology renovation. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has not received any benefit out of this program as not a FIE.

IWTMA contended that the Program has been rescinded on by new Enterprise Income Tax Law of 2008. Absolutely no information has been provided with respect to the above programs except the title of the program. By no stretch of legal interpretation, such information can be considered as "sufficient evidence" in terms of Article 11.2 of SCM Agreement. Further, program No. 26 applies only to FIE's. No evidence has been presented in the petition to show that the exporter's enterprises are FIEs. No specificity has been established under this program.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules. The program is a national program, administered by the State Administration of Taxation (SAT) and its local Branch Offices or Bureaus.
- d. **Benefit under the program -** The programme grants benefit to the foreign invested enterprises in form of tax savings to those FIEs. It is one of the most common incentives in China for the purpose of attracting foreign Investment under FIE Tax Law. The program grants benefit to FIEs that invest in Chinese-made equipment and whose projects are classified in either the Encouraged or Restricted B categories of the Catalogue of Industrial Guidance for Foreign Investment.
- e. **Specificity of the Program -** The program is specific, as the benefit under the program is limited only to FIEs. Since the benefit under the program is limited to certain types of the enterprises of a particular nature, the program is specific within the meaning of the Rules. Other companies in China (being domestic invested enterprises or DIES) are not eligible for this subsidy. Further, only production-oriented FIEs are eligible for the subsidy (i.e. FIEs that are not production- oriented are not eligible for the program). Secondly the benefit under this program is only available to those FIEs, which fulfill the prescribed criterion of being engaged in Production or Business Operations and for which purchasing domestically produced equipments. The program is specific as it is limited to FIEs and it is contingent on the use of domestic over imported goods.
- f. **Countervailability of the Program -** As submitted by the domestic industry, the existence of this program is established by Catalogue of Non-Duty-Exemptible Articles of Importation (2012 Adjusted); Income Tax Credits for FIEs on Purchases of Domestically Produced Equipment; Circular of the State Administration of Taxation Concerning Transmitting the Interim Measure for the Administration of Tax; Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011); Circular of the State Council on Adjustment of Tax Policies of Imported Equipment (GuoFa [1997] No. 37); Notice regarding the adjustment of import-level tax policies related to key technological equipment and machinery (Caiguanshui [2014] No. 2);

It is also found that the scheme has been reported in existence in the WTO, as recorded in the WTO documents [G/SCM/N/123CHN.doc](#); [G/SCM/N/155/CHN.doc](#) & [G/SCM/N186/CHN.doc](#); [G/SCM/N/267/CAN](#); The scheme has also been held countervailable by Canadian Authority in the final finding on Certain Galvanized steel wire from China PR.

- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, the program is subsidy is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the casting producer/ exporter which are in the nature of FIE.

Due to the nature of this program (general exemption on income tax regardless of what activities generate this income (profit)), it is considered that a financial contribution under this program would be made in connection with the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise

Chinese casting Producers such as Hydra Grene Hydraulics Equipment Accessory (Tianjin) Co. Ltd. and Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. and Sinovel Wind Group Co., Ltd. Tiatan Wind Energy (Suzhou) CO. Ltd., Ningo Wing Wo Hing Machinery Industry Co. Ltd., Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd., Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd. etc are eligible for such benefit.

- h. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients which is found to exist during the POI. The benefit conferred on the recipients is considered to be the amount of total tax saved. Since the benefit is available regardless of exports by the company, the CVD margin has been determined considering the total sales made by the company.

The responding exporter claimed that it has not benefited under the program. In response to the questions raised in the deficiency letter dated 15th July 2015, the responding exporter mentioned that:

*“During the investigation period, Jiali Wind was recognized as a high and new technology company. The applicable income tax rate to Jiali Wind is 15%. However, Jiali Wind did not receive any benefit from this program for the reason below:*

*Firstly, the enterprise income tax must be paid when it has a profit. But if the company operates at a loss, it does not need to pay income tax. Article 18 of China’s Enterprise Income Tax Law (effective on January 1, 2008) provides “the losses incurred by an enterprise during a tax year may be carried forward and subtracted from the incomes during subsequent years for a maximum carry-forward period of 5 years.”*

*Secondly, Jiali Wind made a huge loss in an amount of [RMB \*\*\*] in the fiscal year 2012 ... while the total profit made in the fiscal year 2013 is [RMB 4,661,188.33]. According to the program 32 above, the total amount applied for the deduction of R&D expenses from its taxable income is [RMB \*\*\*]....*

*As Jiali Wind made a loss in tax year 2012, the profit made in tax year 2013 is allowed to be used for making up loss of 2012. According to the program 32 above, even if the local taxation bureau did not approve Jiali Wind’s application for deduction of R&D expenses, its taxable income in tax year 2013 is still negative. As a result, Jiali Wind did not need to pay enterprise income tax in 2013. Therefore, Jiali Wind did not receive benefit from this program during the investigation period.*

*Jiali Wind was recognized as “Key high-tech enterprise” in December 2008 by Science and Technology Bureau of Zhejiang Province, the Finance Bureau of Zhejiang Province, State Taxation Bureau of Zhejiang Province and Local Taxation Bureau of Zhejiang Province; no benefit was given to it for getting the recognition.”*

Authority notes that Jiali is not entitled to receive the benefit under the program and hence not quantified the benefits accrued to them under the scheme. However, the Authority notes that there are a large number of FIEs operating in the wind power equipment sector, who are eligible to receive benefit under the scheme. The Authority further notes that the benefit under the scheme is not limited to product under consideration alone. Benefit under the program is available on total profits of the company, once the company is able to claim that it is entitled to benefit under the program. The Authority has computed the benefits based on the information available in the extracts of the balance sheet of Jiali Wind. Since no other information is available, the figures computed for Jiali Wind has been adopted for the other Chinese non-responding exporters. Accordingly, the subsidy margin works out to 2.13% of the turnover of the non-responding exporters.

#### 100. Program No. 28: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses-

- a. **Brief about the program -** The domestic industry alleged that this scheme provides a benefit to all companies that are recognized as carrying out R&D projects. This qualification permits that the corporate income tax is decreased by 50 % of the actual expenses for approved projects. The program is maintained by Local Science and Technology Bureau of Government of China. The programs confers benefit to enterprises up to 50 % reduction in corporate income where the said companies receiving primary support from the State and their project listed in guide of high tech industrialization are eligible for the said benefit. The GOC recognises certain companies as business enterprise engaged in production of high and new technology products. This scheme provides a benefit to companies which introduce new technologies, new products or new techniques in their production. The eligible companies can decrease their corporate income tax by 50 % of the actual expenses for approved projects.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China admitted that the scheme is in force until now and no change in the scheme is anticipated. GOC however contended that the scheme is not countervailable, as the scheme has been held as non actionable by Canadian authority CBSA. The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd. has applied for the benefit but did not receive the benefit of this program during the investigation period. The responding exporter has mentioned that the eligibility criteria is to engage in the research and development of a project prescribed in the High and New Tech Fields under the Key Support of the State and the Guidelines for Current Priorities for Development in Key Sectors of Hi-Tech Industry (2007) as promulgated by the National Development and Reform Commission and other departments. The eligibility or actual use of this program is not contingent upon export performance, use of domestic over imported goods, located within designated regions, or specific to an enterprise or group of enterprises, or to any industry or group or industries.

IWTMA has contended that the Program rescinded on 1st January 2008 also falls under the category of Non-actionable subsidy as per Article 8 of the SCM agreement as this consists of subsidy for research & development. A

similar provision for non-actionable subsidy is present and in force in Section 9(3) of Customs Tariff Act read with Rule 11 of CVD Rules. This program is for the assistance with respect to research and development.

- c. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Science & Technology (MOST), Govt. of China. MOST is a Govt. of China department/body and is responsible for giving benefit to the companies that are recognized as carrying out R&D projects through the local Science and Technology Bureau established in various provinces. MOST is one of the wings of the Central Govt. of China. Being an organ of Govt. of China, MOST is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules.
- d. **Benefit under the program -** This program grants benefit in the form of tax savings to those enterprises who has invested in the R&D projects. The GOC has contended that there is fundamental difference between this program and program of Tax offset for research and development by FIEs. The legal document concerning the program Tax offset for research and development by FIEs was the State Administration of Taxation. According to Article 1 of this circular, the eligibility criterion was that foreign investment enterprises whose technology development fee increased by over 10% (including 10%) compared to the previous year, were permitted, upon examination and approval by the taxation authorities, to re-offset 50% of the amount actually used for technology development fee for the taxable income for the same year.
- e. **Nature of subsidy program and whether the subsidy program is specific-** Benefit under the program is specific as the granting authority operates, limited the access to this scheme only to certain enterprises and industries classified as encouraged. The benefit is limited only to those enterprises who are designated/recognised high and new technology enterprises and carrying out R&D projects. Only R&D projects of the companies of New and High Tech Sectors Receiving Primary Support from the State and projects listed in the Guide to Key Fields of High Tech Industrialization under the current Development Priority promulgated by the National Development and Reform Commission are eligible for the scheme., who have been conferred the status of high and new technology enterprise by the GOC. Since the benefit under the program is limited to certain types of the enterprises, the program is specific within the meaning of the Rules.
- f. **Countervailability of the Program –** As submitted by the domestic industry, the existence of the said program is as per Article 30(1) of the Enterprise Income Tax Law of the PRC (n. 63 promulgated on 16 March 2007), Art. 95 of the Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC, Decree n. 512 of the State Council of the PRC, promulgated in date on 6 December 2007 and the Guide to Key Fields (Notification n. 6, 2007). The guide to Key Fields (Notification n.6, 2007); China's State Administration of Taxation (SAT) issued Guoshuifa [2008] No. 116 (Circular 116) outlining the scope of R&D expenses eligible for Super Deduction, which, in practice, resulted in excluding some R&D related expenses that were not explicitly outlined in Circular 116 as qualified R&D expenses for Super Deduction purposes; On 29 September 2013, China's Ministry of Finance and the SAT released Caishui [2013] 70 (Circular 70), providing additions and clarifications to the original categories of R&D expenses outlined in Circular 116. Circular 70 is effective retroactively for R&D expenses incurred on or after 1 January 2013. The scheme has also been held countervailable by other investigating authorities in their findings against China.
- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, the program is subsidy is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. The government of china has admitted that the alleged program is still in existence, which is wrongly contended by the IWTMA as rescinded in 2008. The GOC has compared the alleged scheme with the Tax offset for research and development by FIEs" and stated that "The CBSA examined the Corporate Income Tax Law of the PRC and Regulation on the Implementation of Enterprise Income Tax Law, and then agreed that the tax offset for research and development expenses is not specific. Whereas the Authority is herewith examining the "Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses". Article 8 of ASCM states that:

*"Article 8- Identification of Non-Actionable Subsidies*

*8.2 Notwithstanding the provisions of Parts III and V, the following subsidies shall be non-actionable:*

*(a) assistance for research activities conducted by firms or by higher education or research establishments on a contract basis with firms if the assistance covers not more than 75 per cent of the costs of industrial research or 50 per cent of the costs of pre-competitive development activity and provided that such assistance is limited exclusively to:*

*(i) costs of personnel (researchers, technicians and other supporting staff employed exclusively in the research activity);*

*(ii) costs of instruments, equipment, land and buildings used exclusively and permanently (except when disposed of on a commercial basis) for the research activity;*

*(iii) costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the research activity, including bought-in research, technical knowledge, patents, etc.;*

- (iv) additional overhead costs incurred directly as a result of the research activity;
  - (v) other running costs (such as those of materials, supplies and the like), incurred directly as a result of the research activity.
- (b) assistance to disadvantaged regions within the territory of a Member given pursuant to a general framework of regional development 31 and non-specific (within the meaning of Article 2) within eligible regions provided that:
- (i) each disadvantaged region must be a clearly designated contiguous geographical area with a definable economic and administrative identity;
  - (ii) the region is considered as disadvantaged on the basis of neutral and objective criteria, indicating that the region's difficulties arise out of more than temporary circumstances; such criteria must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be capable of verification;
  - (iii) the criteria shall include a measurement of economic development which shall be based on at least one of the following factors:
    - one of either income per capita or household income per capita, or GDP per capita, which must not be above 85 per cent of the average for the territory concerned;
    - unemployment rate, which must be at least 110 per cent of the average for the territory concerned; as measured over a three-year period; such measurement, however, may be a composite one and may include other factors.
- (c) assistance to promote adaptation of existing facilities<sup>33</sup> to new environmental requirements imposed by law and/or regulations which result in greater constraints and financial burden on firms, provided that the assistance:
- (i) is a one-time non-recurring measure; and
  - (ii) is limited to 20 per cent of the cost of adaptation; and
  - (iii) does not cover the cost of replacing and operating the assisted investment, which must be fully borne by firms; and
  - (iv) is directly linked to and proportionate to a firm's planned reduction of nuisances and pollution, and does not cover any manufacturing cost savings which may be achieved; and
  - (v) is available to all firms which can adopt the new equipment and/or production processes."

Rule 11 of Indian CVD Rules states that:

*Rule 11- Nature of subsidy. (1) The designated authority while determining the subsidy shall ascertain as to whether the subsidy under investigation:*

*(c) it has been conferred on a limited number of persons, engaged in manufacturing, producing or exporting the article unless such a subsidy is for (i) research activities conducted by or on behalf of persons engaged in the manufacture, production or export; or*

*Explanation. (1) For the purposes of subclause (i) of clause (c) the term "subsidy for research activity" means assistance for research activities conducted by commercial organisations or by higher education or research establishments on a contract basis with the commercial organisations if the assistance covers not more than seventy five per cent of the costs of industrial research or fifty per cent of the costs of precompetitive development activity and provided that such assistance is limited exclusively to:*

- (i) costs of personnel (researchers, technicians and other supporting staff employed exclusively in the research activity);*
- (ii) costs of instruments, equipment, land and buildings used exclusively and permanently (except when disposed of on a commercial basis) for the research activity;*
- (iii) costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the research activity, including bought in research, technical knowledge, patents, etc.;*
- (iv) additional overhead costs incurred directly as a result of the research activity; and*
- (v) other running costs (such as those of materials, supplies and the like), incurred directly as a result of the research activity.*

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd. has applied for the benefit. Even other Chinese producers have benefited under the program. Other non responding Chinese casting producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co. Ltd., Antec Braking Systems (Tianjin) Co. Ltd., Dalian Huarui

Heavy Industry International Co. Ltd., Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd., Jiangsu Faw Foundry Co. Ltd., Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd., Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co. Ltd. Jiangyin Hengrun Ring Forging Co. Ltd., Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd., Qingdao Richuan Precision Machinery Co. Ltd., Satarem China Ltd., Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd., Shanghai Siic E&A International Trade Co. Ltd., Sinovel Wind Group Co. Ltd. and Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd. have also availed the benefit out of the alleged program. Jiali in their post disclosure comments have stated that the benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC. The exhibit 17 of the original response provided by Jiali Wind has clearly showed that the taxable income of Jiali Wind was negative and it was not eligible for the benefit since the law provides “the enterprise may directly deduct 50% of the research and development expenses actually incurred in the current year from the taxable income of the current year” as prescribed in the Notice of SAT on Issuing the Administrative Measures for the Pre-tax Deduction of Enterprise R&D Expenses. The authority however noted that the losses incurred by the Jiali Wind and the benefit of deduction of R&D expenses can be carried forward for the subsequent years. In view of this the benefit is accrued to the Jiali Wind under this program.

For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

- h. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients which is found to exist during the POI. The benefit conferred on the recipients is considered to be the amount of total tax saved, considering the normal tax rate and the reduced tax payable under the program. Since the benefit is not contingent upon export performance and was not granted by reference to the quantities manufactured, produced, exported or transported by the company, the CVD margin has been allocated over the total sales turnover of the cooperating exporting producers during the POI.

The responding exporter claimed that it has not benefited under the program, as it was suffering financial losses in the product under consideration. It is however noted that the benefit under the program is not limited to product under consideration alone. Benefit under the program is available on total profits of the company, once the company is able to claim that it is entitled to benefit under the program. The information provided by Jiali Wind shows that it had incurred R&D expenses of \*\*\* RMB in the year 2013 and accordingly the benefit on 50% of R&D expenses at the applicable tax rate for Jiali works out to \*\*\* RMB. Considering the turnover of the company as \*\*\* RMB, the subsidy margin for this scheme has been determined for the responding exporter as 0.25%.

The authority notes that, in the absence of the above relevant information and as none of the other exporters/producers from China have cooperated with the authority in the present investigations, Authority considers it is likely that non-cooperating exporters meet the eligibility criteria for these programs, have accessed these programs, and therefore received financial contributions under these programs.

It is considered that this financial contribution has been made in respect of all products of these exporters of the subject goods. The GOC identified above 200 producers of castings in China. Petitioner provided evidence that at least few of the other casting producers were entitled for this benefit. In the absence of any information from other producers/exporters of castings in China, the authority has determined the CVD margin for other producer/exporters also at 0.25%.

#### 101. Program No. 31: Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies

- a. **Brief about the program** – The domestic industry alleged that the GOC maintains a program wherein high and new technology companies are allowed preferential/ concessional income tax. The GOC recognises certain companies as business enterprise engaged in production of high and new technology products. These companies are allowed to pay income tax at a reduced rate of 15 % as compared to the normal rate of 25 %. The Chinese producers/exporter of the subject goods have been benefited under the program.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China admitted that the scheme is in force until now and no change in the scheme is anticipated. GOC however contended that the scheme is not countervailable, as the scheme not specific within the meaning of ASCM. The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd. has applied for the benefit but did not received the benefit of this program during the investigation period. IWTMA has contended that no information has been provided to suggest whether the exporters of subject product belonged to the category of ‘High and New Technology enterprises’. Further, no details have been provided by the petitioner that the exporter enterprise applied for certificate of high and new technology enterprise to benefit from a reduced income tax rate of 15 % as compared to ordinary rate of 25%.
- c. **Administering authority-** The program is maintained by Ministry of Science & Technology (MOST), Govt. of China. MOST is a Govt. of China department/body and is responsible for issuance of certificate of high and

new technology enterprise through the local Science and Technology Bureau established in various provinces. MOST is one of the wings of the Central Govt. of China. Being an organ of Govt. of China, MOST is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules.

- d. **Benefit under the program** - The law governing this program mandates a financial contribution by the GOC, which involves the foregoing, or non-collection, of revenue (income tax) due to the GOC by eligible enterprises in China. The programs grants benefit to the enterprises in form of tax savings to those enterprises who has applied for the certificate of high and new technology. Due to the nature of this program (general exemption on income tax regardless of what activities generate this income (profit)), it is considered that a financial contribution under this program would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise
- e. **Specificity of the Program** - Benefit under the program is limited only to those enterprises who designated/recognised as high and new technology enterprises, who have been conferred the status of high and new technology enterprise by the GOC. Since the benefit under the program is limited to certain types of the enterprises, the program is specific within the meaning of the Rules.
- f. **Countervailability of the Program** – As submitted by the domestic industry the existence of the said program is as per Article 28 of the PRC Law on Enterprise Income Tax (No. 63 promulgated on 16 March 2007) SAT along with the Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises, and the Notice of the State Administration of Taxation on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises (Guo Shui Han [2008] No. 985), Circular Guo Shui Fa No. 135 of 2003 and Circular Caishui (2014) No.59 & 65. The domestic industry further submitted that GOC has reported existence of this scheme in the WTO, as recorded in the WTO Trade Policy Review Report, WT/TPR/S/300; G/SCM/Q2/CHN/29. Further, China's Industrial Subsidies Study- 2007 has also a reported existence of this countervailable subsidy program in China. The scheme has also been held countervailable by the other investigating authorities in their findings against China. After the issuance of the disclosure statement, Jiali responded that the benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC. The exhibit 19 provided by Jiali Wind in its original response has clearly showed that the amount of Deduction and exemption was nil.
- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The program is only available to the enterprises which fall within the eligibility criteria of the scheme. The issue of High and New technology enterprise, the responding exporter itself mentions in their response as well as on the website that they fall in the category of High & New technology and they are eligible to avail the benefit incurred out of the scheme. As per the Catalogue of High and New technology products of China provided by the petitioner, "new energy and efficient energy saving technology" is within the scope of H&T enterprises.

The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, the program is subsidy is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy.

For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

- i. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients which is found to exist during the POI. The benefit conferred on the recipients is considered to be the amount of total tax saved, considering the normal tax rate and the reduced tax payable under the program.

The responding exporter claimed that it has not benefited under the program, as it was suffering financial losses in the product under consideration. It is however noted that Jiali wind has posted profit during the year 2013 and therefore eligible for the benefit under the scheme. The annual report of the Jiali wind shows the profit amounting to \*\*\* RMB on turnover of \*\*\*. The difference between the normal rate of income tax payable and the actual payment of income tax works out to 0.14% of the turnover, which has been considered as the benefit availed by the Jiali under the scheme.

The authority notes that, in the absence of the relevant information and as none of the other exporters/producers from China have cooperated with the authority in the present investigations, Authority considers that non-cooperating exporters meeting the eligibility criteria for these programs, would have accessed these programs, and therefore received financial contributions under these programs. Accordingly, the authority has determined CVD margin for other producers/ exporters also as 0.14%.

#### 102. **Program No. 33: Tax credit concerning the purchase of special equipment**

- a. **Brief about the program** - Petitioner alleged that the program allows enterprises to offset 10% of the purchase cost of special equipment used for environmental protection, energy and water saving and production safety against the corporate income tax payable in the year of purchase. The remaining part of the 10 % of the amount invested can be carried forward to the following 5 years.
- b. **Views of Interested Parties**- The Govt. of China stated that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers received benefit under this program. The petitioner failed to provide any evidence indicating that. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has not received any benefit out of this program.

IWTMA contended that the eligibility criteria requires the enterprise to purchase equipment relating to environmental protection, energy and water saving and production safety. However, no evidence has been shown the enterprise has engaged in purchase of such equipment.

- c. **Administering authority**- The program is maintained by Ministry of Finance (MOF), State Administration of Taxation (SAT), Ministry of Commerce (MOFCOM), which is a public body within the meaning of ASCM and the Act & the Rules. The program is a national program, administered by the State Administration of Taxation (SAT) and its local Branch Offices or Bureaus.
- d. **Benefit under the program** - The program provides a tax exemption in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules.
- e. **Specificity of the Program**- The program is specific; to those enterprises that purchase equipments for the use of environmental protection, energy and water saving and production saving.
- f. **Countervailability of the Program** - Existence of the said program is Article 34 of the PRC Law on Enterprise Income Tax, Article 100 of Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the State Council. The scheme has also been held countervailable by EU in the final finding on Certain Organic Coated Steel Products Originating in the People's Republic of China
- g. **Findings of the investigations & conclusion** The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of the Rules. Benefit under the program being limited to certain types of business enterprises, the program is subsidy is specific within the meaning of Rules. This programme constitutes countervailable subsidy. In later submissions during the course of investigation, the petitioner has submitted the list of casting producer/ exporters in China PR.

Due to the nature of this program (general exemption on income tax regardless of what activities generate this income (profit), it is considered that a financial contribution under this program would be made in connection to the production, manufacture or export of all goods of the recipient enterprise

Chinese casting Producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co, Ltd.; Dalian Huarui Heavy Industry International co., Ltd.; Jiangsu Faw Foundry Co., Ltd.; Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co., Ltd.; Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co., Ltd.; Jiangyin Hengrun Ring Forging Co., Ltd.; Qingdao Anhua New Energy Equipment Co., Ltd.; Qingdao Richuan Precision Machinery Co., Ltd.; Satarem China Limited.; Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd.; Shanghai Siic E&A International Trade Co., Ltd.; Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co., Ltd.; Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. are eligible for such benefit.

For all other non-cooperating exporters, no information was provided by either the GOC or the individual exporters themselves regarding whether benefits were conferred on these exporters under these programs. The GOC was asked to provide any amendments to laws, regulations or policy that evidence that these programs were not relevant to current investigations. The GOC did not provide any further information other than repeating that the responding exporter has not availed any benefit out of the alleged scheme.

The authority notes that, in the absence of the above relevant information and as none of the other exporters/producers from China have cooperated with the authority in the present investigations, Authority considers it is likely that non-cooperating exporters meet the eligibility criteria for these programs, have accessed these programs, and therefore received financial contributions under these programs.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that it has not received any benefit out of this program. As regards other Chinese exporters, since the details of benefits availed are not available, the Authority is not in a position to quantify the benefits accrued to them.



**Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery****103. Program No. 36: Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment**

- a. **Brief about the program** - The program grants benefit to FIE which falls in the 'encouraged' or 'restricted' categories and or DIES that fall under the DIE catalogue and they import equipment which is sought to be exempt from tariff and/or VAT must be for the enterprise's own use.

104. **Views of Interested Parties-** The Govt. Of China has not responded this scheme in detail stating that this scheme is same as program 25 i.e. "Tariff and Value-added tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas". And the above mentioned scheme has terminated since 1st January, 2009. Subsequently at the post disclosure stage, the GOC has stated that this programme is same as program no. 6 i.e. Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas (For both FIEs & DIES).

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that Jiali Wind did not receive any benefit from this program.

IWTMA contended that This Program has been rescinded on 1st January 2008 as per notice by the PRC State Council on the Implementation of the Grandfathering Preferential Policies under the PRC Enterprise Income Tax Law Decree No. [2007] 39. This program applies only to FIE's. No evidence has been presented in the petition to show that the exporter's enterprises are FIEs. No specificity has been established under this program. The Benefit under this program is provided only to FIEs which fall under encouraged or restricted categories. The Petition does not provided any evidence to show that the exporters are FIEs. It is claimed that equipment are exempted from tariff and import VAT for enterprise situated in SEZ. Enterprises situated in SEZ are entitled to tariff and VAT exemptions on imported materials and equipment which are used to manufacture and export goods. However, the petition does not show that the exemption is granted in excess of those which have been accrued as required under footnote 1 of SCM Agreement. Further, para 1 to Annex II to SCM Agreement read with footnote 1 also exempts such prior stage cumulative indirect taxes as a subsidy. That is, government revenue that is otherwise due when foregone or not collected can be treated as financial contribution only when the exemption from the taxes on the exported goods is in excess to those on which it has accrued. The Authority has violated Rule 6 of CVD and Article 11 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- b. **Administering authority-** The program is maintained by NDRC, SAT and its local tax bureaus which is public body.
- c. **Benefit under the program** - This program is considered a subsidy in the form of revenue forgone by the GOC.
- d. **Specificity of the Program** - The program is specific as it is limited to encourage FIEs or DIES that fall under the catalogue. The program is specific since the legislation pursuant to which the granting authority operates limits its access to enterprises that invest under specific business categories defined exhaustively by law and obtaining the Certificate of State-encouraged Projects. In addition, there are no objective criteria to limit eligibility for this program and no conclusive evidence to conclude that eligibility is automatic.
- e. **Countervailability of the Program** - As submitted by the domestic industry the existence of this program is established by Articles 1 and 2 of the Notice of the State Council Concerning the Adjustment of Taxation Policies for Imported Equipment (Guo Fa [1997] No. 37), Announcement of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation [2008] No. 43, Notice of the NDRC on the relevant issues concerning the Handling of Confirmation letter on Domestic or Foreign-funded Projects encouraged to develop by the State, No. 316 2006 of 22 February 2006 and Catalogue on Non-duty-exemptible Articles of importation for either FIEs or domestic enterprises, 2008. Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment; Catalogue of Industry, Product and Technology Key Supported by the State at Present (2004); State Council's Import Goods Not Exempted from Taxation for Foreign Investment Projects Catalogue; Import Goods Not Exempted from Taxation for Domestic Investment Projects Catalogue.

The scheme has been reported in existence in WTO document G/SCM/N/123/CHN dated 13 April 2006. The scheme has been held countervailable by EU in the final finding on Solar Glass Originating in China PR, Coated Fine Paper and Organic Coated Steel from China PR.

- f. **Findings of the investigations & conclusion-** This program is considered a subsidy in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of Act and Rules as FIEs and other eligible domestic enterprises are relieved from payment of VAT and/or tariffs otherwise due if they did not obtain the relevant NDRC certificate of State-encouraged project. It therefore confers a benefit on the recipient companies

Chinese casting Producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co. Ltd.; Antec Braking Systems (Tianjin) Co. Ltd.; Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd.; Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd.; Jiangsu Faw Foundry Co. Ltd.; Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd.; Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co. Ltd.; Jiangyin Hengrun Ring Forging Co. Ltd.; Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd.; Qingdao Richuan Precision Machinery Co. Ltd.; Satarem China Ltd.; Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd.; Shanghai Siic E&A International Trade Co. Ltd.; Sinovel Wind Group Co. Ltd.; Zhuzhou Times New Material

Technology Co. Ltd. are eligible for such benefit. In view of the GOC's post disclosure submission, the authority has not proceeded further to determine the countervailability of the scheme.

#### 105. Program No. 37: Reduction in Land Use Fees

- a. **Brief about the program** - The Chinese Government provides various financial incentives to manufacturers operating in specified Special Economic Areas ("SEA"), such as Special Economic Zones ("SEZs"), High Technology Industrial Development Zones, Export Processing Zones, free ports, bonded zones, and the like. These SEAs promote investment with unique tax packages and other incentives. The incentives generally include significant reductions or exemptions in land use fees, import and export duties, and priority treatment in obtaining basic infrastructure services. The government has also created special incentives for projects involving export-oriented investments and for certain industries.

The requirement to pay land use tax in China is pursuant to "The Interim Regulations of the People's Republic of China Governing land Use Tax on Cities and Towns". This urban land use tax was not applicable to FIEs until recent amendments were passed to include them. The amendments that extend applicability to FIEs were made under "The Decision of the State Council on Amending the Interim Regulations of the People's Republic of China Governing land Use Tax on Cities and Towns" (Order of the State Council [2006] No 483). Effectively from 1 January 2007 (the commencement of the POI) both FIEs and DIEs pay land use tax. Prior to this 1 January 2007, FIEs paid a complimentary land use fee. An exception to this requirement to pay land use fees was granted to FIEs who acquired their land use rights by means of transfer.

- b. **Views of Interested Parties**- The Govt. Of China has stated that currently, Chinese enterprises have to pay land-transferring fees or land-renting fees to acquire the use rights of State-owned land by transferring or renting. If other market subjects use rural collective-owned land by establishing an enterprise with the rural economic organization, the price of land use right to buy shares or join operation is determined by the two parties according to market principles. The rural economic organization enjoys the benefits in accordance with its shares or joint operation.

There is no evidence in the Petition demonstrating that, the Chinese casting producers received benefit under this program. Thus, pursuant to Article 11.2 among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that Jiali Wind did not receive any benefit from this program.

IWTMA contended that No financial contribution is shown in the petition for this program. The petition just provides that the program is applicable to FIEs. The petitioner has failed to show that the program is applicable to the exporters named under the petition. The Authority has violated Rule 6 of CVD Rules, Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority**- the program is maintained by SAT but the provincial and local land use management authorities were responsible for the collection of the land use fees, which is public body, grants benefit to FIEs who acquired land use rights by transfer are eligible for this scheme.
- d. **Benefit under the program** - It is found that certain companies located in Special Economic Areas pay reduced long term land use fees for land on which factories are located. In the current property rights regime in China PR, use rights for specified periods, which is 40 to 70 years, can be obtained from the state through the payment of land use fees. This land use fees are determined on the basis of the location, type and density of the proposed development. This separation of land ownership and use rights allows the trading of land use rights while maintaining state ownership of land.
- e. **Specificity of the Program** - The scheme is specific as it is limited for the FIE. Under Chinese law; all land is under state ownership. Foreign investors may lawfully obtain the rights for land development, use and business. They may also transfer and lease land rights, or put them up for mortgage in accordance with the law within the stipulated purposes and terms of the use. When foreigners invest in projects encouraged by the State for an operation term of more than 15 years, the construction land is exempt from land use fees for five years starting from the day when the enterprise obtains the use right, and the fee is collected at half price in the following five years.
- f. **Countervailability of the Program** - As submitted by the domestic industry, the existence of this program is established Order of the State Council [2006] No 483; Article IV.5 of Guo Ban Fa [1999] No 73) (Customs Document 18) Measures on readjusting land use fees and preferential reduction and exemption of land use fees in Shenzhen special economic zone. Article IV.5 of the Opinions on Current Measures to Further Encourage Foreign Investments" (Guo Ban Fa [1999] No 73). The scheme has been held countervailable by the other investigating authorities in their findings against China.

- g. **Findings of the investigations & conclusion-** This program is considered a subsidy in the form of revenue forgone by the GOC within the meaning of Act and Rules as FIEs and other eligible enterprises are relieved from payment of land use fees otherwise due. It therefore confers a benefit on the recipient companies.

Chinese casting Producers such as Gamesa Wind (Tianjin) Co. Ltd.; Antec Braking Systems (Tianjin) Co. Ltd.; Dalian Huarui Heavy Industry International Co. Ltd.; Gexpro Industry Supply Shanghai Co. Ltd.; Jiangsu Faw Foundry Co. Ltd.; Jiangsu Jixin Wind Energy Technology Co. Ltd.; Jiangyin Fengdian Flange Manufacture Co. Ltd.; Jiangyin Hengrun Ring Forging Co. Ltd.; Qingdao Anhua New Energy Equipment Co. Ltd.; Qingdao Richuan Precision Machinery Co. Ltd.; Satarem China Ltd.; Shandong Laiwu Jinlei Wind-Power Technology Co. Ltd.; Shanghai Siic E&A International Trade Co. Ltd.; Sinovel Wind Group Co. Ltd.; Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd. are eligible for such benefit.

- h. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients, which is found to exist during the period of investigation. The benefit conferred on the recipients is considered to be the amount of land use fees exempted.

The responding exporter claimed that it has not benefited under the program.

The annual report of the company shows that the Parent company has received "Land Use Tax Refund" amounting to \*\*\* RMB, which works out to 0.04%.

The authority notes that, in the absence of the above relevant information and as none of the other exporters/producers from China have cooperated with the authority in the present investigations, Authority considers it is likely that non-cooperating exporters meet the eligibility criteria for these programs, have accessed these programs, and therefore received financial contributions under these programs. Petitioner provided evidence that at least few of the other casting producers were entitled for this benefit. Post disclosure, Jiali Wind submitted that the "Welfare Business Value Added Tax Refund", "Export Tax Refund" and "Other Tax Refund" shall not be used for calculation of the program, because firstly they are not related to the land use tax, and secondly the export tax refund shall not be treated as a subsidy. In the light of the above post disclosure submissions made by Jiali Wind, the Authority reviewed the calculation and determined CVD margin for both Jiali Wind and other producers/exporters at 0.03%.

### **Goods/Services Provided by Government at Less than Fair Market Value**

#### **106. Program No. 40: Electricity provided by Government at less than Fair Market Value**

- a. **Brief about the program [Introduction of Scheme]-** The program is maintained by officials who use their discretion to administer the discounted rates to a limited group of preferred enterprises and industries, specifically, priority industries such as the casting industry. The lower electricity rate is set out in the relevant NDRC Notice and incorporated in the Notice issued by the local Price Bureau. The petitioner alleged that the GOC has provided electricity for less than adequate remuneration through preferential rates. The electricity rates were set differently in different provinces and also that preferential rates were used as an industrial policy tool to encourage enterprises.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China has stated that the NDRC is responsible for formulating the electricity prices at trans-provincial, autonomous regional and municipal levels directly under the Central Government level electricity grid and provincial level electricity grid. Trans-boundary provincial electricity grids are operated by the State Grid Corporation of China (SGCC) and China Southern Power Grid Corporation (CSG). There is no such program, so this question is not applicable. The GOC is not aware of the volume and the average cost of production. At present, the sale of electricity in China is subject to Government pricing and a competition mechanism has been gradually introduced on both the generation and sales sides. For example, the bidding and bilateral trading pilot has been introduced on the generation side. Direct purchase between power generation enterprises and power users are encouraged in some provinces, under which both parties can voluntarily negotiate prices and users have more options. Except the SGCC and CSG, there are some pilot projects within some provinces to encourage direct transactions between the electricity users and the power generation enterprises. Both parties can set the prices through voluntary price negotiations. Currently, the price of electricity is managed by the Government price departments in accordance with the principle of unified leadership and decentralized responsibility. Trans-boundary provincial electricity grids, and grids of autonomous regions and municipalities are directly managed by the Central Government. Electricity grids under the provincial level are managed by the provincial Government. Tariff levels by the competent authorities of the Government are formulated on the principles of "reasonable compensation costs, reasonable ascertainment as to the income, inclusive of the tax amount, in accordance with the law, adherence to fair burden". Normally, the anticipated yield rate of investors is no less than loan rate of banks. There is a huge amount of electricity production enterprises in China. The GOC does not hold the information of their production cost. Currently, the price of electricity is classified as resident, agriculture, general industry and commerce and others, the users in the same classification are applied the same electricity price.

Tariff levels by the competent authorities of the Government are formulated on the principles of "reasonable compensation costs, reasonable ascertainment as to the income, inclusive of the tax amount, in accordance with the law, adherence to fair a burden".

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that Jiali Wind purchased the electricity from the supplier at market price during the investigation period. Jiali Wind did not receive any benefit from this program. Post disclosure, Jiali has drawn the attention of the Authority to the evidence produced by them for the purchase of electricity. The invoice for electricity shows that the purchase price of the electricity was RMB \*\*\* per Kwh as against RMB \*\*\* per Kwh considered by the Authority. Based on the evidence on record the Authority notes that Jiali has purchased the electricity at a rate comparable with the benchmark rate considered by the Authority. In view of the above, the Authority holds that Jiali has not availed any benefit under the scheme.

IWTMA contended that it is claimed that GOC has provided electricity preferentially at less than adequate rates. As per the Petition the National Development and Reform Commission (NDRC) employs preferential rates as a policy to promote and encourage development of Industry. Though Article 15 of Chinese Accession Protocol allows the Authority to use methodology in identifying and measuring the subsidies, which take into account the possibility that prevailing market rate in China may not be appropriate for benchmark. However, petitioner has failed to suggest any benchmark, even outside China to determine the existence of benefit.

Further, no evidence has been provided to show that preferential electricity rates have been provided to casting industries only. Moreover, in relation to specificity of alleged program, the Petitioner merely claims that the provision for electricity is de-facto specific as officials use their discretion to administer the discounted rates and it is the Petitioner's belief that industries located at certain zones are provided at preferential rates. Under Article 2.4 of SCM Agreement clearly provides that specificity can be established based on positive evidence only and cannot be based on assumptions of the Petitioner. In any case, it is inconceivable that electricity rates throughout the Country should be same in order to qualify it as non-specific. Authority has violated the Rule 6 of CVD Rules and Article 11. 2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority** - The NDRC is responsible for regulating the electricity market and setting the pricing in China. The trans-provincial and provincial grids are operated by two state- owned suppliers: State Grid Corporation of China and China Southern Power Grid Corporation. The electricity suppliers at municipal level are subsidiaries of these companies. A competition mechanism is in the process of being introduced in China through a few pilot projects, but its impact is still negligible at this stage. The lower electricity rate is set out in the relevant NDRC Notice and incorporated in the Notice issued by the local Price Bureau.
- d. **Benefit under the program** - The benefit received out of this program is a financial contribution in the sense of Indian Rules and the ASCM under which the Government provided electricity through the local public electricity supply company. This constitutes a Government contribution in the form of provision of goods other than general infrastructure to the extent that the Government has provided electricity for less than adequate remuneration. It has been established that this exporter was entitled to a rate lower than the rate generally applicable to other large industrial users.
- e. **Specificity of the Program** - The program is both enterprise or sector specific and region specific. The subsidy in form of provision of electricity to the producer/exporters is specific as the lower electricity rate is set out in the relevant catalogue set by NDRC. This lower rate is limited to certain enterprises in certain specified sectors included in a sub-category of large-scale industrial users. Therefore, this lower rate is limited de jure only to companies falling into these categories in the meaning of Rules and ASCM.

The subsidy is also region specific as it is limited to a certain region and it only applies in a limited designated geographical area where the exporting producers, listed by petitioner, are located. Circular of the State Council Concerning Several Policies on Carrying out the Development of China's Vast Western Regions explicitly mentions price mechanism in electricity transmission and provision as one of the tools to achieve development of certain sectors.

- f. **Countervailability of the Program** - Existence of the program is evident by Circular of the State Council Concerning Several Policies on Carrying out the Development of China's Vast Western Regions. EU final finding on Certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China; US final finding on Non-Oriented Electric Steel From China, Germany, Japan, Korea, Sweden, and Taiwan; EU final finding on Solar Glass originating in China PR.
- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The Authority found that it is the NDRC that sets the prices of electricity applicable in the various provinces. It was verified that the local price bureau merely acts as an executive arm of the decision taken at central level by the NDRC. It is also confirmed by the fact that the NDRC issues Notices in which it sets the actual prices set for each province and then these notices are formally transposed into local notices adopted by the local price bureau and implemented at local level. The investigation also established that differential electricity rates applicable for certain sectors and/or at provincial and local level are set in accordance with certain factors, including notably the pursuit of the industrial policy goals set by the central and local Governments in their 5-year plans and in the sectoral plans.

- h. **Calculation of subsidy amount-** The normal price of electricity in China has been estimated on the basis of petitioner's rate at \*\*\* RMB per Kwh. As already explained earlier, Jiali had purchased the electricity at \*\*\* RMB per Kwh. In view of the above, the Authority concludes that Jiali has not availed any benefit under the Scheme. In the absence of any further information, the Authority has not computed the subsidy, if any, availed by Jiali Wind and other non-responding exporters in this regard.

#### 107. Program No. 43: Provision of various goods for less than adequate remuneration

- a. **Brief about the program -** The domestic industry has contended that the Chinese exporters of Casting have been benefited from the provision of raw material or inputs and utilities provided by the GOC at less than adequate remuneration. In particular the petition makes it evident that the inputs involved in production of the product under consideration, which are Pig Iron, Steel Scrap (CRCA), Ferro Silicon, Ferro Silicon Mg, Coke, Inoculants, Silica Sand, Resin, Catalyst, LPG, Furnace Lining Material, Diesel, Laddle Lining Material, Ceramic Tubes, Sleeves and Refractory Coating. In particular the provision of several steel outputs manufactured by SOEs, including pig iron, steel scrap, and coke are being provided by GOC to the casting producers. The main input used in the manufacture of Casting, was being produced and supplied by the Government authorities of China PR at less than adequate remuneration.
- b. **Views of Interested Parties-** The Govt. of China has stated that there is no evidence in the Petition demonstrating that the Chinese casting producers received benefit under this program. The petitioner failed to provide any evidence indicating that. Thus, pursuant to Article 11.2, among others, of the SCM Agreement, it is not necessary to answer this question to the extent that the existence, amount and nature of the alleged grants have not been duly substantiated. In any event, the responding company cooperated with this investigation did not benefit from this program.

The responding Chinese casting producer Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. has stated that Jiali Wind purchased various goods from suppliers at market price during the investigation period. Jiali Wind did not receive any benefit from this program.

IWTMA contended that Petitioner has generally claimed that Govt of China provides goods at less than adequate remuneration. However, no further information has been provided regarding the existence of program for each such goods. The petitioner has also not provided benchmark that they have adopted in identifying and measuring the subsidy. It cannot be assumed that the price of goods reflects inadequate remuneration. Further, no evidence has been provided in the petition in respect to program to show that casting producers benefited by this program. Therefore, petitioner cannot claim existence of such program.

As per Petition the National Development and Reform Commission (NDRC) employs preferential rates as a policy to promote and encourage development of Industry. No document provided to show that it is available to only casting Industries. Authority has violated the Rule 6 of CVD Rules and Article 11.2 and Article 11.3 of SCM agreement by initiating the investigation for this Program. The investigation for this Program should be terminated as per Article 11.9 of SCM agreement on account of lack of evidence provided in the petition.

- c. **Administering authority-** Input Materials (raw material) and Utilities provided by Government at Less than Market Value constitutes a countervailable subsidy, as the program is maintained by Government of China PR, which is a public body. This program involves a financial contribution that involves the provision of the goods by SOEs, being public bodies, at less than adequate remuneration.
- d. **Benefit under the program -** the program grants financial contribution in the form of provision of Input Materials and Utilities at less than adequate remuneration by SOEs to producers of subject goods and thus constitutes a countervailable subsidy.

Chinese SOEs that produce steel or iron or any other rare earth materials are public bodies. Providing the inputs or the raw materials in the form of less than adequate remuneration is a financial contribution by these SOEs to Casting producers constitutes a countervailable subsidy. Accession treaty clearly shows that "*China did not collect VAT on imported and domestically produced steel used as raw material for the processing trade*". Same is with the other raw materials like coal, electricity etc., where the Government is having complete control over the price structuring.

Under this program, a benefit to exported Casting is conferred by inputs being provided by the GOC through an intermediary or SOEs at an amount reflecting less than adequate remuneration, having regard to prevailing market conditions in China.

- e. **Specificity of the Program-** The program is specific, as the benefit under the program is limited as the exporters of the WOEG casting are given input materials and utilities at less than adequate remuneration and not at the market price.
- f. **Countervailability of the Program -** Existence of the program is established by US-Galvanized Steel Wire from China and Mexico; US-Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe ("Seamless Pipe") from the People's Republic of China and US- Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from China.

- g. **Findings of the investigations & conclusion-** The Authority considers that provision of inputs being transferred to the producers of the subject goods is an indirect benefit is conferred in relation to the exported goods to the extent that the benefits conferred to the private intermediaries are passed through to the exporters by way of inputs being provided at less than adequate remuneration. Where the financial contribution involves the provision of raw materials and inputs by public bodies, SOEs, through private intermediaries, do trade of those inputs to the exporters of product under consideration. The benefit amount is equal to the amount of the difference between the purchase price at the normal rate or at the adequate remuneration and the purchase price of the goods at less than adequate remuneration. Where exporters of the product under consideration during the investigation period received a financial contribution in the form of inputs under the program at less than adequate remuneration, it would therefore confer a benefit in relation to casting, and the financial contribution would meet the definition of a subsidy as per ASCM and Indian Rules.
- h. **Calculation of subsidy amount-** The amount of countervailable subsidy is calculated in terms of the benefit conferred on the recipients, which is found to exist during the investigation period. That benefit is considered to be the amount of Input Materials (raw material) provided by Government at Less than Market Value during the investigation period. In accordance with Rules and ASCM, this subsidy amount (numerator) has been calculated based on the monthly world market prices plus the international delivery charges, import duty, VAT, and Chinese inland freight charges for calculation of subsidy margin. The normal price of Pig Iron and steel scrap are much different from which the goods are being exported in India. Post disclosure, Jiali provided the yearly average prices of the raw materials consumed i.e. pig iron and steel scrap by them. Considering the difference of the average rate of the inputs used by Jiali and the domestic industry along with the norms of the domestic industry, the Authority has considered the benefit and the CVD margin under this Scheme as 8.12%. In the absence of any other information, the Authority has applied the same subsidy margin for the non-responding exporters as well.

#### **I. Determination of Subsidy Margin**

108. The Authority has determined the subsidy margin in respect of the sole respondent Chinese exporter and others concerning the above examined Schemes/programs as below:

S.N.	Heads	Program No.	Schemes	% of Subsidy Margin on CIF price For Jiali Wind	% of Subsidy Margin on CIF price For Others
1	Special Economic Zone (SEZ) Incentives and Other Designated Areas	Program No. 5	Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas	----	----
		Program No. 6	Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas	----	----
2	Grants	Program No. 8	The State Key Technology Renovation Projects Fund	1.99	1.99
		Program No. 9	Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments		
		Program No. 10	Research & Development (R&D) Assistance Grant		
		Program No. 11	Innovative Experimental Enterprise Grant		
		Program No. 12	Superstar Enterprise Grant		
		Program No. 13	Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"		

		Program No. 14	Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry		
		Program No. 15	Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment		
		Program No. 16	Innovative Small and Medium Enterprise Grants		
		Program No. 17	Grants to Privately-Owned Export Enterprises		
3	Equity Programs	Program No. 18	Equity infusions	----	----
		Program No. 19	Unpaid dividends	----	----
4	Preferential Loans	Program No. 20	Preferential loans and interest rates to the casting Industry	----	----
5	Preferential Income Tax Programs & Tax Incentives	Program No. 25	Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises which have Establishments in China and are engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments	----	2.13
		Program No. 28	Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses	0.25	0.25
		Program No. 31	Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies	0.14	0.14
		Program No. 33	Tax credit concerning the purchase of special equipment	-	-
6	Relief from Duties and Taxes on Materials and Machinery	Program No. 36	Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment	----	----
		Program No. 37	Reduction in Land Use Fees	0.03	0.03
7	Provision of input materials and utilities for less than adequate remuneration	Program No. 40	Electricity provided by Government at less than Fair Market Value	---	---
		Program No. 43	Provision of various goods for less than adequate remuneration	8.12	8.12
	Total			10.53	12.66
	Total Subsidy Margin as a % of landed value			11.18	13.44

## J. INJURY AND CAUSAL LINK

### J.1. Submissions made by the Domestic Industry

109. The Domestic Industry has submitted the following submissions regarding the injury:

- i. The fact that consumers are importing the product because of lower prices offered by the Chinese producers alone establishes that injury to the domestic industry is being caused by Chinese imports. Whatever be the cause of decline in demand, the same addresses only the volume part of the injury. This however does not address the adverse price effect suffered by the domestic industry.

- ii. In the absence of low priced dumped and subsidized imports from China, the domestic industry would have got a reasonable price for the volumes sold by the domestic industry. If the level of demand that was prevailing in base year is taken as the base and then determine the profitability, the analysis would show that the domestic industry would have still suffered deterioration in parameters such as profit, cash flow, and return on investment. This clearly establishes that injury to the domestic industry is on account of low priced dumped and subsidized imports.
- iii. The market share of the domestic industry and domestic producers as a whole declined whereas that of Chinese imports increased. This further establishes that adverse volume effect. In order to determine production and sales of the domestic industry in a situation where the domestic industry would have had the same share in demand as it had in the base year. It would be seen that the production and sales of the domestic industry would have been much higher than what these were. This loss of production and sales is because of low priced imports in India.
- iv. There is no difference in the technology employed. There is no truth in the claims of quality issues. The petitioner is producing and selling to several consumers in India and internationally. There is no question of logistics causing inefficiencies or taking additional time. In fact, in this industry, offloading of machining operations to specialized agencies is quite common phenomena and does not materially impact adversely either the costs or the delivery Schedule.
- v. Imposition of CVD shall be in public interests and the effect of same should be seen from the perspective of three different parties – the producers, the consumers and the general public. Government should provide level playing field to casting industry in the larger public interest.
- vi. The provision relating to suo moto application clearly establishes that the Designated Authority can initiate investigations on its own, which implies that the Designated Authority is entitled to consider evidences not referred/relied upon by the petitioner but otherwise available to the Authority. Thus, even if petitioner has not referred to the decision of other investigating authorities and has stated that independent evidences is not available, nothing prevents the Authority from taking cognizance of evidences otherwise available in the petition and proceed with the investigation. Petition contains sufficient evidence to initiate, the quantity and quality of evidence improves as the investigation progresses.
- vii. In the present case, out of 44 schemes identified in the petition, 36 are administered by "the state i.e. Central Government (MOFCOM & MOC), Provincial Government and State Administration of taxation" and therefore undisputedly fall in the category of public body and the WTO decision is not applicable to these schemes. Further, as regards 8 schemes where petitioner has identified association/ involvement of SOEs, petitioner submits that the mere fact that WTO has held that SOEs in those cases were incorrectly held public body without adequate examination, the same does not imply that these Bodies in the present case also shall not constitute public Bodies. It only implies proper examination and the petitioner is not against any such proper examination.
- viii. Quality is not at all a consideration given that the product produced by the petitioner confirms to all laid down standards. In fact, one of the consumers bought only a small portion of its requirement from petitioner over the injury period and increased procurement significantly from petitioner now once the petitioner reduced prices, which establishes that quality and delivery time are not the restraints for not placing orders on the consumers. No evidence has been provided to the Authority to show that the petitioner could not supply the material against orders placed on the company. No evidence has been placed on record to show that a casting supplied by the petitioner had to be discarded by consumers due to quality consideration.
- ix. Imports from the subject country are on subsidized prices and have increased in absolute terms, in relation to production and consumption in India.
- x. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values & volume, profits, return on investments, cash flow and market share.
- xi. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, the imports are depressing the domestic prices.
- xii. Significant share in the domestic market is already held by the subsidized imports and such shares are increasing.
- xiii. Domestic industry has sufficient capacity to meet current and potential demand in the Country.
- xiv. There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and Foreign Producers. Resultantly, domestic industry lost significant sales volumes. Thus, despite sufficient demand in India, the domestic industry lost sales volumes, which is a direct consequence of subsidized imports from the subject country;



- xv. Imported product is severely undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been forced to reduce the prices.
- xvi. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of subsidized imports;
- xvii. Market share of the imports from the subject country increased significantly. As a direct consequence, the market share of the Indian Producers declined.
- xviii. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has deteriorated due to presence of subsidized imports.
- xix. Growth of the domestic industry became negative in respect of a number of parameters.
- xx. The domestic industry is suffering significantly negative Profitability, cash profits and return on investment during the investigation period.
- xxi. Imports from the subject country are posing threat of material injury to the domestic industry. There is significant increase in imports. The price undercutting is significant. The imports are entering at such prices that there is strong likelihood of further importation. Significant share in the domestic market is already held by the subsidized imports and such shares are increasing.

## **J.2. Submissions by GOC/producers/exporters/importers/other interested parties**

110. The GOC and the sole responding exporter have not offered any specific comments with regard to injury. But, the importers and IWTMA have submitted as follow:

- i. Apart from existing injury or threat of injury to the domestic industry due to subsidized imports, Authority is required to examine other factors as well which caused injury to the domestic industry.
- ii. It is incorrect to suggest that decline in the performance of the domestic industry was due to alleged subsidized imports. The dip in the performance of the domestic industry during 2012-13 and POI was directly a result of fall in demand, which occurred due to withdrawal of the benefits by the Government.
- iii. In a situation of declining demand, where a premium cannot be charged for the product, prices of such products will definitely go down. Thus, the claim of the Petitioner that its reduction in prices is due to imports is totally incorrect.
- iv. Further, due to contraction in demand, production of subject goods has declined considerably during the last 4 years. Imports cannot be blamed for such decline in production.
- v. Similarly, sales of domestic industry have declined with decline in demand for subject goods in India. This clearly indicates that decline in sales of domestic industry is due to decline in demand and not competition from imports.
- vi. With declining demand, domestic industry had to resort to lowering its selling price. Imports cannot be blamed for the recessionary trend for the product concerned in India.
- vii. There is no link between subject imports and losses to the domestic industry. Between 2011-12 and 2012-13, while volume of imports from China PR showed a decline and import prices increased substantially, losses to domestic industry also increased substantially in terms of per unit loss, cash losses and PBIT. Similarly, between 2012-13 and POI, when imports volume showed increase along with decline in import prices, there was improvement in the performance of the domestic industry. Any injury suffered by the domestic industry is solely due to other factors and not alleged subsidized imports.
- viii. Imports from China PR have not affected the market share of the Petitioner. Compared to 2011-12 and 2012-13, market share of Petitioner has in fact improved during the POI.
- ix. Petitioner has not provided price undercutting table for the updated period. Thus, the price undercutting analysis provided by the petitioner is not reliable.
- x. Different companies in different countries use different technologies, as a result of which cost to produce such casting also varies significantly. Thus, technological difference has to be taken into consideration by the Authority while examining injury to the domestic industry.

## **J.3. Examination by the Authority**

111. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry and injury on account of subsidized imports from the subject country.

112. Rule 13 (1) of the Countervailing Duty Rules states:

*“13. Determination of Injury - (1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.”*

113. Annexure I to the Countervailing Duty Rules, 1995, as amended in 2006, deals with the principles governing the determination of injury. Paragraph 1(1), (2) and (3) of the Annexure read as follows:

*“1. (1) A determination of injury for purposes of rule 13 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic market for like products and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products.*

*(2) With regard to the volume of subsidized imports, the designated authority shall inter alia consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.*

*(3) With regard to the effect of the subsidized import on prices, the designated authority shall, consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of a like article in India, or whether the affect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.”*

114. Para 1(5) of the Annexure I to the Rules lists relevant economic parameters to be evaluated by the designated authority:

*“(5) The designated authority while examining the impact of the subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmes.”*

115. It may be true that different companies in different countries use different technologies, but it does not address the issue of subsidization and its injurious impact on the domestic industry. Technological difference does not make a product different.

116. For the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure I of the rules supra.

**a) Volume Effect of the subsidized imports on the Domestic Industry**

**Demand and market share**

117. For the purpose of the present investigation, Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. There was some decline in demand from the base year till the year 2012-13. However, the demand increased in the POI and substantial enough remaining at reasonable level. It may be added here that the NIP workings for domestic industry are based on the 82.40% capacity utilisation during 2012-13 based on projected financials at project conceptualization stage. This takes care of consistent low capacity utilisation by the Domestic Industry. Castings are now made only in the Coimbatore plant of L&T (CMU). However, the production figures given below are for company as a whole:

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Sales of Domestic Industry (CMU & KBL of L&T)	MT	14,122	8,079	5,133	6,888
Sales of Other Indian Producers	MT	7,310	7,368	3,076	3,364
Subject country-Imports	MT	4,486	15,117	10,430	14,245

Other Countries-Imports	MT	591	1661	502	214
Total demand/consumption	MT	26,509	32,225	19,141	24,711

POI\*- Oct' 2012- Dec' 2013 (15 Months)

#### **Import volume in absolute terms and in relation to production and consumption in India**

118. There is significant increase in imports from subject country at subsidized prices. The subsidized imports increased from the base year to the year 2011-12. Though imports declined in the year 2012-13, the same increased further in the POI. The volume of imports of the subject goods from China and other countries were as under:-

Imports – Volume	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
China	MT	4,486	15,117	10,430	14,245
Other Countries	MT	591	1,661	502	214
Total Imports	MT	5,077	16,778	10,932	14,459

POI\*- Oct' 2012- Dec' 2013 (15 Months)

119. Authority notes that imports from subject country have increased in absolute terms in POI as compared to the base year. Imports from subject country were in the region of 4,486 MT in base year which increased to more than 14,245 MT in the period of investigation. Show annualized data.

120. Authority notes that the imports from China have increased in relation to imports of the product in India, as is evident from the following table:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Import Volume					
China	MT	4,486	15,117	10,430	14,245
Other Countries	MT	591	1,661	502	214
Total Imports	MT	5,077	16,778	10,932	14,459
Market Share in Imports- Volume Basis					
China	%	88%	90%	95%	99%
Other Countries	%	12%	10%	5%	1%

POI\*- Oct' 2012- Dec' 2013 (15 Months)

121. Authority notes that the imports from China have increased in relation to production and consumption in India, as is evident from the following table:

Market Share in demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
China	%	17	47	54	58
Other countries	%	2	5	3	1
Domestic industry	%	53	25	27	28
Other Indian Producers	%	28	23	16	14
Indian Production	MT	23,327	17,291	8,650	11,261
Subject Country Imports in relation to Indian production	%	19	87	121	126

POI\*- Oct' 2012- Dec' 2013 (15 Months)

122. It is **seen** that the market share of the domestic industry has significantly declined whereas that of subsidized imports from subject country have materially increased over the injury period. The petitioner submitted that it can alone meet the demand of the subject goods in India. The petitioner, however, has not been able to do so due to the presence of subsidized imports from China PR.

**i. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

123. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.
124. Price undercutting has been worked out by comparing the export price with the domestic selling price in India of the comparable type of subject goods for the period. Further, in view of significant difference in the cost and price of the product sold to different customers, the price undercutting has been determined by considering comparable product types.

**i. Price Undercutting**

125. The net sales realization has been arrived after deducting outward freight and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty including applicable cess to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the price undercutting from the subject countries is significant during the entire injury period including POI.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
<b>Subject Country</b>					
Landed price of imports	Rs./MT	88520	94416	115836	120662
Trend	Index	100	107	131	136
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	114	101	97
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting Range	%	40-50	50-60	10-20	0-10

**ii. Price Underselling**

126. PCN wise Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the relevant like goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with standard practice in the DGAD. The analysis shows that during the POI the landed value of subject imports were below the non-injurious price of the domestic industry as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	China PR
Non-injurious price	Rs./MT	***
Landed price (POI)	Rs./MT	***
Price underselling	Rs./MT	***
Underselling	%	***
Underselling - Range	%	15-25

**iii. Price suppression/depression**

127. The Authority examined whether the effect of the subsidised imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred.

Parameter	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Cost of sales - Domestic	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	137	157	128

Selling price - Domestic	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	114	101	97
Landed Price	Rs./MT	88520	94416	115836	120662
	Index	100	107	131	136

POI\*-Oct12-Dec13

128. The table above shows that the weighted average cost of sales is consistently more than the selling price during the injury period. The Authority also notes that the selling prices in POI have remained almost at the same level as in the base year even though the cost of sales in POI has increased to 128 basis points as compared to 100 basis points in base year. This shows that the prices were suppressed on account of subsidized imports and the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to increase in costs. The subsidized imports have also had significant depression effect on the prices of the domestic industry in the market.

129. Thus, the effect of subsidized imports on the domestic industry has been adverse and significant.

#### **Economic Parameters relating to the Domestic Industry**

130. Article 15.4 of ASCM states that:

*“The examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmes. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.”*

131. Para 1(5) of the Annexure I to the Rules lists relevant economic parameters to be evaluated by the designated authority:

*“(5) The designated authority while examining the impact of the subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmes.”*

#### **1) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

132. Position of the domestic industry over the injury period (CMU Unit) with regard to Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales was as follows

Economic Parameters	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Capacity	MT	30,000	30,000	30,000	37,500
Production - PUC	MT	11,305	7,751	4,984	7,897
Production - Others	MT	-	156	848	780
Plant Production	MT	11,305	7,907	5,832	8,678
Capacity Utilization	%	38	26	17	21
Plant Utilization	%	38	26	19	23
Sales volume-Domestic	MT	9,410	5,907	4,543	6,888
	Index	100	63	48	73

POI\*-Oct 12-Dec 13

It may be added here that the NIP workings for domestic industry are based on the 82.40% capacity utilisation during 2012-13 based on projected financials at project conceptualization stage. This takes care of consistent low capacity utilisation by the Domestic Industry. Castings are now made only in the Coimbatore plant of L&T (CMU). However, the production figures given above are for company as a whole.

133. Authority notes that the domestic industry alone has sufficient capacity to meet current and potential demand of the product in the Country. The production of the product under consideration declined throughout the injury period. The decline in production is despite sufficient demand in the Country.
134. Capacity utilization of the domestic industry declined very significantly over the entire injury period. Since the petitioner is utilizing production facilities for production of the product under consideration and other products, the authority has determined capacity utilization by including production of other products also. Further, the authority notes that one of the interested parties has contended that the domestic industry cannot produce and supply the product in desired volumes and it is producing other product also. The authority specifically examined the records of the domestic industry at the time of on the spot verification and found that in fact the petitioner has sufficient capacities and was faced with significant underutilized capacities.
135. Authority finds that the sales of the domestic industry declined significantly throughout the injury period.
136. The demand scenario needs to be adequately addressed here

## 2) Profitability, return on investment and cash flows

137. Position of the domestic industry (CMU) over the injury period with regard to profits, return on investment and cash flows was as follows:

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	140	158	138
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	115	104	100
Profit/( Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	(5)	(159)	(79)
Profit/( Loss)	Rs./Lacs	***	***	***	***
	Index	100	(3)	(77)	(46)
Cash Profit	Rs./Lacs	***	***	***	***
	Index	100	30	(21)	1
ROI	%	***	***	***	***
	Index	100	(3)	(105)	(75)

POI\*-Oct 12-Dec 13

138. The Authority notes that profitability of the domestic industry deteriorated very significantly over the injury period. The domestic industry suffered significant financial losses during 2012-13 and POI. The cash profits showed the same trend as that of profits. The domestic industry has suffered significant cash losses in 2012-13 and the POI.
139. Return on investment also shows the same trend as has been witnessed in profitability of the domestic industry. The domestic industry suffered significant negative return on investment during the investigation period.

## 3) Productivity

140. Productivity measured in terms of production per day deteriorated in POI due to decline in production as compared to the base year

Parameters	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Productivity per day	Day/MT	53	38	24	20
Productivity per employee (CMU)	MT/ person	***	***	***	***
	Index	100	70	49	73

POI\*-Oct 12-Dec 13

**4) Inventories-**

141. The subject goods are “make to order” product. Thus the criterion of inventory is not the proper parameter to evaluate the injury.

**5) Employment and Wages**

142. The Authority finds that the production of subject goods is labour-intensive. The wages paid have shown normal growth. The domestic industry has stated that hiring & firing of employees is the last resort to adopt given the labour laws in the country.

Parameters	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI*
Wages (CMU)	Rs./Lacs	***	***	***	***
	Index	100	70	52	61
Employment (CMU)	Nos	***	***	***	***
	Index	100	100	105	105

POI\*-Oct 12-Dec 13

**6) Growth**

143. The growth of the domestic industry in terms of both volume and price parameters was negative.

**7) Ability to raise capital investment**

144. The Petitioner has submitted that given the state of affairs of the domestic industry where performance is deteriorating because of subsidized imports from subject country, substantial fresh investments cannot even be imagined. The domestic industry is already holding significant capacities and huge part of it is remaining idle.

**8) Factors Affecting Domestic Prices**

145. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than subsidized imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the landed value of the imports of dumped subject goods from subject countries.

**9) Conclusion on material injury**

146. The performance of the domestic industry has deteriorated over the injury period, as summarized below:

- Subsidised imports from the subject country have increased in absolute terms, in relation to production and consumption in India.
- Subsidised imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
- Subsidised imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry in the market. No correlation found
- Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values & volume, profits, return on investments, cash flow and market share.

**K. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS****K.1. Views of the Domestic industry**

147. Following are the submissions made by the Domestic Industry regarding Causal Link:

- Chinese imports have captured very significant market share. Therefore, decline in demand is not the principal cause for the injury suffered by the domestic industry.
- Material injury is being caused to domestic industry by subsidized imports from China PR. The technology adopted by domestic industry is comparable to the technology being adopted by producers of subject country. There is no significant difference in the manufacturing process. Availability of subsidized imports in the market is the principal reason for the present injury being suffered by the domestic industry.

148. Injury to the domestic industry has been caused by subsidized imports. Further, injury, if any, due to other factors has been segregated by the petitioner, as discussed in detail herein below.
- Contraction of demand or Changes in the patterns of consumption: The Authority notes that the demand for the subject goods has declined by about 25% during the POI as compared to the base year. However, the market share of the domestic industry has declined by about 61%, whereas the market share of the imports of subject goods from the subject country has gone up by about 154%. This shows that decline in demand is not the prime factor for the material injury suffered by the domestic industry. Further, the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.
  - Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
  - Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
  - Export performance: Petitioner does not have exports of the product under consideration. In any case, the Authority has considered the performance of the domestic industry in the domestic market for injury analysis.
  - Performance of other products being produced and sold by the domestic industry: Claimed injury to the domestic industry is on account of the product under consideration.
149. Once it is shown that a) there is an adverse volume and price effect from subsidized imports and b) the effects of injury caused by subsidized imports are demonstrated in terms of the parameters set out in paragraph 1(5) of Annexure I, then, the only basis on which to conclude that the injury is not caused by the subsidized imports are through non-attribution analysis, i.e., those other factors have caused the injury.
150. As demonstrated in the preceding paragraphs, listed known other factors do not establish that injury has been caused by these other factors. Such being the case, the only inescapable conclusion is that the injury to the domestic industry has been caused mainly by the subsidized imports from the subject country.
151. Following parameters establish the causal link and show that injury to the domestic industry is due to the subsidized imports-
- There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and Foreign Producers. Resultantly, domestic industry lost significant sales volumes. Thus, despite sufficient demand in India, the domestic industry lost sales volumes, which is a direct consequence of subsidized imports from the subject country;
  - Imported product is severely undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been forced to reduce the prices.
  - Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of subsidized imports;
  - Market share of the imports from the subject country increased significantly. As a direct consequence, the market share of the Indian Producers declined.
  - Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has deteriorated due to presence of subsidized imports.
  - Growth of the domestic industry became negative in respect of a number of parameters.

#### **L. Magnitude of Injury and injury margin**

152. The Authority has determined PCN wise non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The PCN wise non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the corresponding PCN wise landed value of the exports from the subject country. The weighted average injury margin thus determined is as under:-

Particulars	M/s Zhejiang Jiali Wind Power Technology Company Limited	Non-Cooperative exporters
Non-injurious price Rs/MT	***	***
Landed value - Rs/MT	***	***



Injury Margin - Rs/MT	***	***
Injury Margin - % of landed value	***	***
Injury Margin Range - %	5-15	15-25

#### M. Post Disclosure Comments

153. The following are the post disclosure comments made by the domestic industry, GOC and other interested parties:

##### Post Disclosure comments by Domestic Industry

- i. Subsidy investigations extend to benefits received by the affiliates and parent companies. Subsidies received by the parent company are required to be considered and included in CVD margins. Jiali Technology Company (the parent company) has received the subsidies and no information has been provided by them with regard to the subsidiaries received by them. Thus, Jiali Wind Power has failed to fully cooperate and the Authority is entitled to apply best available information.
- ii. Petitioner is not under statutory obligation to identify all exporters and the DA to forward a copy of initiation notification to all known exporters, nor to seek information from individual exporters. US Govt. clearly stated that the GOI is required to ensure that the questionnaire is forwarded to all concerned exporters of the PUC.
- iii. The GOC proved to be non-cooperative while contending that several schemes are no longer in force or withdrawal of the programs is unsupported with relevant documentary evidences by the GOC. It may so happen that the name of the program might have been changed or a new program with a different nomenclature might have replaced the old program with the same benefits targeting the same target group. DI has earlier provided that there are many more schemes/programs which have not been acknowledged by the GOC as subsidy schemes prevalent in China PR or being availed by the producer/ exporter of the subject goods. GOC did not consent to on-the-spot verification of the responses/ evidences submitted by the Government of China and the responding Chinese exporter, thus establishing non-cooperation.
- iv. Jiali Wind submitted that the goods sold by the company in home market and exported to India are directly comparable and are the like article.
- v. The responding exporter is not the sole producer of the subject goods in China and the benefits received are not restricted / limited to the sole responding exporter. The import data clearly shows that the product has been exported by number of other exporting companies during the relevant period.
- vi. Jiali has never responded to the contradiction regarding various grants received and the certificate issued and visible on the website of the subsidiary company as well as the parent company.
- vii. Responding exporter has been non-cooperating in providing the replies to the financial benefits received by the company against the various schemes and thereby Jiali Wind also did not extend full cooperation to the Authority.
- viii. PUC is “*Castings for wind-operated electricity generators also known as castings for windmill or wind turbine, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators*”. Some of the sub-assemblies used in a windmill include Gear Box, Nacelle assembly and Hub pitch assembly. These sub-assemblies comprise of castings and other components. For example, Nacelle assembly consists of base frame, Gear Box consists of Planet Carrier, Housings, Torque arm and Hub assembly consist of Rotor hub/Hub and a pitch system.
- ix. It is open to a consumer to either buy a casting and other mating parts separately and assemble at its own place, or, instead buy the sub-assembled product as well. The operations involved in preparing sub-assembly are almost a screw driver technology and efforts involved are quite insignificant in proportion to overall operations carried out. It is quite feasible for an eventual consumer to buy sub-assembled products instead of buying castings and other products separately.
- x. If PUC does not include the sub-assemblies, it shall defeat the very purpose of imposing any trade defense measure. It is appropriate to consider sub-assemblies within the scope of the PUC so long as the scope of the CVD measures, if any, is limited to casting portions of the sub-assemblies. It is requested that the Authority may kindly confirm this scope in the Final Findings.

- xi. Since the PUC is reported under customs classification other than the above specified, the DA may specify in duty table that the PUC should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers. Only the duty table contents are relevant in this regard. Anything mentioned in the para relating to "PUC" but not stated in duty table is likely to get ignored while issuing notification by the Ministry of Finance.
- xii. Further, the Customs authorities at the port consider and rely upon the notifications issued by the MOF. The customs authorities do not take cognizance of the final findings notifications issued by the Authority. It is, therefore, utmost important that the duty table itself includes all these clarifications.
- xiii. The subject goods produced by the DI are like article to the PUC imported from China in terms of the Rules. The product is design and model specific depending upon the design and capacity of the wind mill producers. However, both the domestic producers and exporters supply to the same wind mill producers in India. Jiali Wind submitted that the goods sold by them and exported to India are directly comparable and there is no difference between the goods sold in home market and exported to other countries including India in physical and technical characteristics.
- xiv. The petition was filed by Larsen & Toubro Limited. M/s Patel Alloys has supported the petition. The petitioner commands a major proportion in the Indian production in the POI. Larsen & Toubro Limited constitutes an eligible DI within the meaning of Rules 2(b) and the production of the petitioner constitutes a major proportion in the Indian production.
- xv. In the present case, the IWTMA has presented itself before the DA at a significantly belated stage of the investigations.
- xvi. It is now settled law in India that the WTO Agreement directly applies to the DA. In fact, the Hon'ble Supreme Court has held that the DA cannot ignore the WTO provisions and therefore WTO decisions. Reliance is placed upon above decisions of WTO as also decision of the DA in the matter concerning Ceramic Tiles.
- xvii. As regards non-extension of investigation to include the new subsidies identified by the petitioner considering the overall time left for completion of the present investigations, it is submitted that the same does not undermine the fact that the GOC has preferred non cooperation and has not provided any information with regard to these subsidy schemes prevalent in China in spite of specifically seeking this information in the questionnaire issued by the authority.
- xviii. Out of 44 schemes identified, 37 programs are administered by those Bodies falling within the category of state (GOC, Provincial, Municipal Corporation, local bodies in China). Only 7 programs were identified by the petitioner, which are being administered by SOEs. Petitioner provided sufficient evidence to establish that these administering authorities constituted public bodies within the meaning of the law.
- xix. Petitioner vide letter dated 12th Nov 2015 withdrew the 22 schemes due to non-availability of evidence for quantifying the benefits. These schemes have been held countervailable by other investigating authorities as rightly acknowledged by the DA in the present investigation.
- xx. The website of the Jiali Wind and its parent company clearly show that the company has received various grant certificates. The grants pointed out by the Petitioner are not in the nature of one time grants. In fact, Jiali Wind has been receiving these grants repeatedly and these grants are in the nature of regular grants.
- xxi. DA may kindly hold that the exporter has not established that benefits under these grants are required to be spread over the useful life of the assets.
- xxii. Subsidized imports from the subject country have increased in absolute terms, in relation to production and consumption in India. Subsidized imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. The imports are depressing the prices of the DI in the market. Performance of the DI has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values & volume, profits, return on investments, cash flow and market share. Both subsidy margin and injury margin in the current POI are positive and significant. The Domestic industry is likely to suffer injury in the event of non imposition of anti subsidy/ countervailing duty.
- xxiii. NIP has been determined on the basis of information provided by the Petitioner/domestic industry. It is however seen that the basis of allocation/apportionment has been changed by the DA. Petitioner submits that this change of methodology is inappropriate.

- xxiv. The duty may be imposed on ad-valorem basis as the PUC involves a large number of product types which is having significantly different prices.

#### **Post Disclosure Comments by GOC**

- i. The present anti-subsidy investigation was initiated on the basis of frivolous and unfounded suits and in contravention with the legal requirements prescribed in the ASCM.
- ii. The “evidence reasonable available” to the petitioner does not exempt the petitioner’s obligation to provide sufficient evidence. To the contrary, the disclosure statement merely states that: “...the petitioner has provided the information that was reasonably available to them to support the petition”. The standards and requirements with regard to “sufficient evidence” cannot be fulfilled by simple reference to or copying of findings made by other jurisdictions.
- iii. GOC has endeavored to cooperate with the GOI to the best of its abilities, by holding consultation, replying to questionnaire, providing evidence with clear clarifications, replying to two deficiency letters, attending hearing, communicating with the GOI concerning further clarifications on-the-spot.
- iv. The disclosure statement stated that “The GOC did not permit the Authority to visit China to conduct the spot verification of the data/information furnished by the sole Chinese respondent producer/exporter.” The GOC has never objected to the on spot verification of the sole Chinese respondent producer/exporter.
- v. Facts available should not be used to make a determination. GOC has provided, to its best ability, the *necessary information* to the Authority for the current investigation. With regard to those programs that the petitioner failed to establish a *prime facie* case, the burden of proof should not be switched or allocated to the GOC to complete the information for the alleged subsidies.
- vi. Article 12.8 of the ASCM requires that a disclosure of essential facts must be made before the final determination, and such disclosure should take place in *sufficient time* for the parties to defend their interest. The GOI provided insufficient time to the GOC and the cooperating producer for defending their interests.
- vii. The GOI has not disclosed the essential facts relating to financial contribution, benefit and specificity to the GOC and the cooperating producer. Further, GOI failed to adequately explain the methodology to calculate the benefits in respect of the various alleged programs.
- viii. The Authority fails to take account of the documents submitted by the GOC regarding the rescinded programs. This type of investigation is in breach of the GOI’s obligations under the WTO laws.
- ix. The GOI’s calculation of subsidy amount is wrong in respect of Program 6 i.e. for the tariff and VAT exemption on imported equipment. Firstly, the VAT exemption has expired on 1 January 2009. Moreover, the respondent Chinese producer has never imported any equipment.
- x. Calculation of subsidy amount for Grant programs is not proper. Although some of the grant programs were rescinded already, the GOI, without any justifications provided, calculated subsidy amount for a package of these grant programs.
- xi. The amount of subsidies found by the GOI on the annual report of the producer’s parent company has nothing to do with these alleged programs, bearing no relationship with the product under investigation. In other words, there is no connection between the subsidy programs found and the amount of subsidy calculated.
- xii. The program 6 and 36 are the same program which is double accounted by the GOI. Programs 6 and 36 are related to exemption of tariff and VAT on imported equipment. The petitioner mistakenly alleged in its petition that this program as two different programs.
- xiii. No evidence has been provided to support the allegations that the state owned banks and state owned enterprises are public bodies.

#### **Post Disclosure Comments by Zhejiang Jiali Wind**

- i. Jiali Wind is not located in SEZs or other designated areas and Jiali Wind has not purchased any imported material or equipment, all inputs and capital equipments were sourced from Chinese market. Therefore, Jiali wind is not eligible for the Program No. 6 i.e. Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas (For both FIEs & DIES).
- ii. As regards grants, it seems the figure \*\*\* has been double counted and thus the total amount of \*\*\* is not correct: The “government subsidy” in amount of RMB \*\*\* was a total amount which has included all the items listed from item 2 through item 18 as indicated in the annual report.

- iii. If the Authority intends to calculate the benefits for the programs 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, it should calculate the benefit for each alleged program, instead of calculating a 5.89% for a package of programs 8 to 17.
- iv. The benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC. None of the subsidy received by the parent company was related to the PUC, thus it shall not be allocated to Jiali Wind.
- v. As regards Program No. 20 concerning Preferential loans and interest rates to the casting industry, Jiali Wind obtained loan from various commercial banks with the interest rates ranging from \*\*\*%-\*\*\*%, it has not received any benefit from loans.
- vi. The calculation basis for the “Preferential loans and interest rates to the casting industry” appears to be wrong. It is submitted that \*\*\* and \*\*\* as indicated were not amount of loan, and \*\*\*% and \*\*\*% were not the loan interest rates either. They are book value of the assets and percentage of assets respectively. During the POI, Jiali Wind obtained loan from various commercial banks with the interest rates ranging from \*\*\*%-\*\*\*%, which may fully demonstrate that the interest rates were normal market rate.
- vii. As regards Program No. 28: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses, the benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies.
- viii. As regards Program No. 31: Preferential tax policies for companies that are recognised the benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC.
- ix. As regards Program No. 36: Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment, in the disclosure statement it is stated by the authority that Jiali Wind has not benefited under the program as it is not being FIE. However, CVD margin for Jiali has been determined as 1.69 instead of “not applicable”. The position needs to be rectified.
- x. The “Welfare Business Value Added Tax Refund”, “Export Tax Refund” and “Other Tax Refund” shall not be used for calculation of the program, because they are not related to the land use tax. Moreover, the export tax refund shall not be treated as a subsidy due to the reasons that a benefit exists only to the extent that the amount exempted exceeds the amount levied with respect to the production and distribution of like products when sold for domestic consumption. The exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy in terms of the WTO provisions. Nevertheless, during the investigation period, the amount of VAT exempted upon the export (\*\*\*%) was not in excess of the VAT rate levied on the product concerned in the domestic market (\*\*\*%), therefore the VAT refund does not confer a countervailable benefit.
- xi. As regards Program No. 37: Reduction in Land Use Fees, the “Land Use Tax Refund” received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC.
- xii. As regards Program No. 40: Electricity provided by Government at less than Fair Market Value, Jiali Wind had paid market price for all the inputs including the electricity and therefore has not received any benefit. The electricity price used by the DGAD is neither the price for industrial use nor the actual price paid by Jiali.
- xiii. As regards Program No. 43: Provision of various goods for less than adequate remuneration, Jiali Wind had provided the Raw Materials Consumed in its supplemental response and the actual paid price was RMB \*\*\* per ton. The actual price paid should be used for the calculation by the authority.

**Post Disclosure Comments by Indian Wind Turbine Manufacturers Association (WTMA)**

- i. Insufficient time given by the authority to file comments on the disclosure statement. Authority should provide all the relied upon documents and evidences to the interested parties and provide another opportunity of hearing.
- ii. Initiation of investigation on the basis of prima facie evidence is bad in law. Initiation of investigations to fish out evidences on assumption is not permitted. Decisions of other authorities cannot be relied upon as evidence.

- iii. The Designated Authority has enlarged the scope of the product by including casting for all parts of the Wind Mill whereas in the initiation, the “castings for wind-operated electricity generators” was defined as PUC.
- iv. Product types such as castings in sub-assembled form or castings as a part of a sub-assembly or castings as a part of equipment/ component have never imported into India. Resultantly, inclusion of such product types does not arise.
- v. Designated Authority has not conducted any examination of injury and causal link based on different type of products included in PUC. A revised Disclosure Statement may be issued by the Authority after examining the injury parameters such as market share, production, production capacity utilization, etc. based on product types.
- vi. The Authority has stated in Para 17 that “*the production by the petitioner constitute a major proportion of the subject goods*”. However, it has failed to provide the basis for such assertion.
- vii. Petitioner has claimed excessive confidentiality. Authority should provide the relied upon documents to the Respondents.
- viii. Domestic Industry did not produce any evidences in respect of subsidy schemes claimed in the petition. Domestic Industry could not produce any evidence regarding the remaining schemes operated during the POI as well. In such case, the schemes cannot be specific and therefore cannot be countervailed.
- ix. As regards Program 5: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas and Program 6: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas, the Authority has stated that the Domestic industry had provided list of producers and exporters which are established in SEZs and other Designated Areas and are in nature of FIEs eligible for the benefit. Such list of exporters or producers was never provided to the Respondents. The Authority has not provided the methodology or basis for computation of these subsidies. These programs are non-actionable subsidies and investigation for these programs should be terminated.
- x. As regards Program 8: The State Key Technology Renovation Projects Fund, the Authority has noted that the program provides financial contribution in the form of revenue conferred by the GOC. Firstly the authority has not provided the methodology or basis for computation of the subsidy for this program. Secondly the authority failed to make consideration in the fact that this program has rescinded on 22nd January 2008 as per the National Development and Reform Commission Decree No.59. No basis is provided on which the CVD duty is computed and what evidence is relied upon for this program. These programs are non-actionable subsidies and investigation for these programs should be terminated.
- xi. As regards Program 9: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments, no evidence for the program has been provided by the petitioners. Authority should terminate proceeding under Article 9 of the ASCM.
- xii. As regards Program 10: Research & Development (R&D) Assistance Grant, the responding exporters did not avail the benefit under the program and therefore the authority should terminate the proceeding for this program. Further, the program is a non- actionable subsidy and investigation for this program should be terminated.
- xiii. As regards Program No. 11: Innovative Experimental Enterprise Grant, the list of producers/exporters submitted by the petitioner was not provided by the Authority to the respondents and therefore the investigation should be terminated. Further, this program being meant for assistance with respect to research and development, this is non-actionable and therefore should be terminated.
- xiv. As regards Program 12: Superstar Enterprise Grant, The eligibility criteria prescribed with respect to this program relates to period 2006-2008 and not for subsequent period. No information has been provided to suggest that this program is available for subsequent period. The investigation for this program should be terminated on account of lack of evidence provided in the petition.
- xv. As regards Program 13: Awards to enterprises whose products qualify for “Well-Known Trademarks of China” or “Famous Brands of China”, the list of producers/exporters provided by the petitioner has not been shared with the respondents and therefore the investigation should be terminated. Moreover, the petitioner has not provided sufficient evidence to show that the scheme is applicable to product under consideration in this investigation. Further, it has failed to show that the exporter have availed the benefits under this scheme. The Authority should terminate the proceedings for this program.

- xvi. As regards Program 14: Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry, the list of producers/exporters provided by the petitioner has not been shared with the respondents and therefore the investigation should be terminated. Moreover, the Respondent repeats and reiterates that the petitioner has not provided sufficient evidence to show that the scheme is applicable to product under consideration in this investigation. The Authority should terminate the proceedings for this program.
- xvii. As regards Program 15: Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment, nothing has been provided as evidence except that the scheme is available for province of Guangzhou Municipality on encouraging foreign Investors to Set Up headquarters and regional headquarters. There is no evidence in the petition that the program pertains to exporters of the subject product. Therefore, the investigation for this program should be terminated.
- xviii. As regards Program 16: Innovative Small and Medium Enterprise Grants, the Authority should restrict its finding to the exporters whose names have been produced in the petition. The Petitioner cannot introduce any list of exporters or producers at such later stage of the investigation. Further the specificity in respect to the program is not established. Therefore, the investigation for this Program should be terminated.
- xix. As regards Program 17: Grants to Privately-Owned Export Enterprises, nothing has been provided as evidence and petitioner has simply stated that notices concerning accelerating the growth of the non-state owned economy lists the enterprise eligible. The Program is available to Non- SOEs located in Yunnan Province. However, no evidence has been provided to prove that the exporters of subject goods belong to Yunnan province. Therefore the authority should terminate the investigation for this program.
- xx. Further, the Authority has calculated the quantum of subsidy for program SI No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 for cooperating and non-cooperating at 5.89%. The Authority has not provided any evidence to show that the exporters and producers have availed the benefits under the program. Further it has not provided any basis on which it has calculated subsidy for these programs. The Authority is unable to establish that the subsidy, if any, provided to the exporters is causing injury to the domestic Industry. The authority should terminate the subsidy against these programs.
- xxi. As regards Program 18: Equity infusions, merely on the claims made by the petitioner the designated Authority cannot conclude that the program CICC is state owned enterprise. The Authority has to provide the basis of its determination. Further no methodology has been provided by the Authority how it has calculated the subsidy for the given program.
- xxii. As regards Program 19: Unpaid dividends, the Authority has not provided any evidence to show that the program is governed by the public body and that the exporters under the program have availed those benefits. Merely on the assumption by the petitioner the authority cannot conclude that the program constitute countervailable subsidy and that it is provided by the public body. The Authority has not provided any basis on which it has calculated the quantum of subsidy to be 0.26 %.
- xxiii. As regards Program No. 20, preferential loans and interest rates to the casting industry, no evidence is provided to show that this program is available to the casting producers. It is not sufficient to merely state that private banks are also entrusted and directed by the Govt to follow preferential lending practices in China. Such fact does not absolve the petitioner from the burden of determining the benefit by comparing the comparable commercial loan outside China. In any case, commercial banks in terms of Article 4 of Commercial Banking Laws of China are not required to follow Govt policies with regard to their commercial operations.
- xxiv. As regards Program 25: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments, the Authority has not provided the basis on which it has made the calculations of the subsidy. Further the list of producers and exporters were never provided to the Respondent to make comment on the same. No evidence has been presented in the petition to show that the exporter's enterprises are FIEs. No specificity has been established under this program.
- xxv. As regards Program 28: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses, the Authority has not provided any basis on which it has calculated the benefit under the program. No evidence is provided to show that the program constitute countervailable subsidy and is in existence.
- xxvi. As regards Program No. 31: Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies, the Authority has provided no basis on which it has calculated the benefit under the program. No evidence is provided to show that the program constitute countervailable subsidy.

- xxvii. As regards Program 33: Tax credit concerning the purchase of special equipment, the Authority has not provided any basis for its finding that the program is countervailable. Further it is submitted that the eligibility criteria requires the enterprise to purchase equipment relating to environmental protection, energy and water saving and production safety. However, no evidence has been shown the enterprise has engaged in purchase of such equipment.
- xxviii. As regards Program 36: Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment, this Program has been rescinded on 1st January 2008 as per notice by the PRC State Council on the Implementation of the Grandfathering Preferential Policies under the PRC Enterprise Income Tax Law Decree No. [2007] 39. Further, this program applies only to FIE's. No evidence has been presented in the petition to show that the exporter's enterprises are FIEs. No specificity has been established under this program. The Petition does not provided any evidence to show that the exporters are FIEs.
- xxix. As regards Program 37: Reduction in Land Use Fees, Authority has provided no basis on which it has calculated the benefit under the program. No evidence is provided to show that the program constitute countervailable subsidy. The Authority has not provided sufficient evidence to show that the scheme is applicable to present exporter. Therefore the Authority should terminate the proceeding for this program.
- xxx. As regards Program No. 40: Electricity provided by Government at less than Fair Market Value, the Authority has provided no basis on the basis of which it has concluded that the scheme is countervailable or how it has calculated the subsidy for this program. No evidence has been provided to show that preferential electricity rates have been provided to casting industries only.
- xxxi. As regards Program No. 43: Provision of various goods for less than adequate remuneration, the observation of the authority is incorrect. No basis for the calculation of the subsidy is provided by the Authority for this program. Further, no document has been provided to show that it is available to only casting Industries. Therefore, the Authority should terminate the proceedings for this program.

**Post Disclosure Comments by GE India Industrial Private Limited and Inox Wind Ltd**

- i. Designated Authority has failed to adequately disclose the essential facts of the investigation, especially those concerning casual link. Authority must issue a fresh disclosure statement in order to fulfill its obligations by giving sufficient time to respond to the same.
- ii. The Authority has concluded that the product scope includes sub-assemblies as well as components. The PUC needs to be defined by explaining the exact nature and definition of the product scope, the exclusions and various sub-assemblies and components covered to avoid any confusion.
- iii. Authority admits that different types of castings have different end applications and differing costs/prices. But, at the same time insists that such differences do not render the castings as different articles. The very objective of deploying a PCN methodology is to ensure that only comparable articles are compared. Such a paradoxical stance leaves an unclear and unjustified product under consideration scope.
- iv. The Petitioner's goods are not like article with the imported product under consideration due to a lack of commercial substitutability.
- v. The disclosure statement appears to be the first instance of any PCN methodology being communicated to the interested parties. There was no communication by the Designated Authority inviting comments or suggestions with regard to the PCN methodology.
- vi. Authority has conducted a weighted average comparison, but then conducted the price effect comparison without using PCN methodology. Such a haphazard injury analysis is not justified.
- vii. Authority's observation that the impact of the countervailing measures is hardly 0.1% increase in costs to a consumer is inaccurate. The logistical inefficiencies such as the costly supply chain model have a great impact on the cost of purchase from the domestic industry. Moreover, the inability of the Petitioner to produce the product with the necessary technical specifications depending on the consumer preference is the important factor due to which the Importer had to import the subject goods.
- viii. There is no correlation between the decline in market share of the domestic industry and the imports of the subject goods. During the period of 2011-12 to 2012-13 wherein there was a decline in the imports, the demand for the imports of the product under consideration also reduced. Furthermore, from the period of 2012-13 to POI the sales of the domestic industry and the subject country increased which established that there is a lack of correlation of the demand and market share between the domestic industry and the subject country.

- ix. The market share of the imports from the subject country increased irrespective of a decrease in the market share of the domestic industry. Therefore, injury faced by the domestic industry cannot be attributed to the increase in imports.
- x. The Price Effect calculation is inappropriate since it is not on the PCN basis but rather on a weighted average basis. Further, the price underselling has not been analyzed with respect to the previous year's data without which the price effect over the period of injury cannot be analyzed.
- xi. There is no correlation between the decline in profitability and the imports. The determination made by the Authority fails to show a causal link between the profitability and the imports.
- xii. The NIP calculated needs to be based on the PCN as determined by the Designated Authority. Designated Authority should also disclose the essential facts concerning NIP so as to allow the Importer to defend their interests

#### **Examination by the Authority**

154. The post-disclosure comments made by the GOC, domestic industry and other interested parties concerning the various schemes/programs have been examined and addressed by the Authority in the relevant Paras of this final finding. The post disclosure comments concerning injury are ipso facto addressed by the injury analysis conducted by the Authority in this finding. The other specific post disclosure comments made by the GOC, domestic industry and other interested parties, considered relevant, are examined and addressed by the Authority as below:

- i. As regards the comment that the present anti-subsidy investigation was initiated on the basis of frivolous and unfounded suits and in contravention with the legal requirements prescribed in the ASCM, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of adequate prima facie evidences indicating subsidization of exported subject goods, injury to the domestic industry and causal link between the said subsidization and injury to the domestic industry.
- ii. It is agreed that the evidence reasonably available to the petitioner does not exempt the petitioner's obligation to provide sufficient evidence. But, lack of accessibility of the relevant evidences to the petitioner is also not ruled out. The GOC or for that matter the respondent exporter could have substantiated their submissions by complete evidences and enabled the Authority to verify the information/evidences on the spot to ascertain and establish the correct position.
- iii. Adequate efforts were made by the Authority to obtain consent and convenience of the GOC to conduct the on the spot verification of the information/evidences furnished by the GOC during the course of the investigation. The GOC was also requested to provide the necessary permission to visit China to carry out on the spot verification of the respondent producer/exporter. But, on the spot verifications could not be carried out due to non-receipt of consent/permission from the GOC. Had GOC consented for on the spot verification, the correct position regarding many of the subsidy schemes would have emerged and enabled the Authority to properly appreciate the facts of the case.
- iv. As regards the comment that facts available should not be used to make a determination, the Authority notes that when interested parties do not cooperate to the fullest extent, then reliance upon best available facts is an acceptable alternative for the authorities worldwide while conducting investigations. As regards the programs where the petitioner failed to provide sufficient evidences/ explanation, the Authority has not gone ahead with the investigation to establish the countervailability of such programs.
- v. As regards the comment that insufficient time was provided by the authority to the interested parties for commenting on the disclosure statement, the Authority notes that the Rules do not prescribe any specific time line for such purposes. However, reasonable time was provided by the Authority to the interested parties for commenting on the disclosure statement, keeping in view the time available for completion of this investigation. Moreover, adequate opportunities were provided to the interested parties by the Authority during the course of the investigation to make submissions and the non-confidential version of the information furnished by the interested parties were made available by the Authority in the public file
- vi. As regards the comment that GOI has not disclosed the methodology to calculate the benefits in respect of the various alleged programs, the authority notes that the methodology for calculating each and every scheme/program has been explained in the disclosure statement as well as in this final finding.
- vii. As regards the comment that no evidence has been provided to support the allegations that the state owned banks and state owned enterprises are public bodies, the Authority notes that in terms



of Article 1 of ASCM, the term ‘public body’ means any entity that possesses, exercises or is vested with government authority. In this respect, the Authority notes that any State owned entity like state owned banks and state owned enterprises are also public bodies because such entities are vested with government authority while discharging their respective functions.

- viii. As regards the contention that that the Authority should calculate the benefit for each alleged program, instead of calculating a 5.89% for a package of programs 8 to 17, it is noted that the details furnished in the annual report of Jiali do not show scheme wise subsidies received by them. In view of this, the authority has computed benefits accrued to Jiali for the programs 8 to 17 as a whole.
- ix. As regards the contention that the Designated Authority has enlarged the scope of the product by including casting for all parts of the Wind Mill whereas in the initiation, the “castings for wind-operated electricity generators” was defined as PUC, the Authority reiterates that wind-operated electricity generator and Wind Mill are one and the same. “Wind operated electricity generators (WOG)” is a “wind mill” and therefore casting for “wind operated electricity generators” implies casting for “wind mill” or “Wind Turbine”.
- x. As regards the contention that Designated Authority has not conducted any examination of injury and causal link based on different type of products included in PUC, the Authority notes that there are no different types of PUC, but different parts of the PUC. Therefore, separate injury analysis for each part of PUC is not required. However, Authority devised PCN for the PUC, determined injury margin and did the injury analysis accordingly.
- xi. As regards the submission that NIP calculated needs to be based on the PCN and Authority should also disclose the essential facts concerning NIP, the Authority notes that the PCN wise NIP has been computed in terms of extant guidelines and consistent practice in the DGAD. NIP being commercially sensitive and confidential information for the domestic industry, the same cannot be disclosed to other interested parties.
- xii. As regards the submission by the domestic industry that the basis of allocation/apportionment in the computation of NIP has been changed by the Authority and this change of methodology is inappropriate, the Authority notes that no change has been made in the allocation of expenses.
- xiii. As regards the contention that inability of the domestic industry to produce the product under consideration with the necessary technical specifications as per the demand of the consumers and their logistical inefficiencies are the real reasons for increasing the imports of subject goods from China PR, the Authority notes from the submissions of the domestic industry that one of the consumers bought only a small portion of its requirement from the domestic industry over the injury period and increased its procurement significantly from the domestic industry after the reduction of prices by the domestic industry. This establishes that price is the prime factor governing the psyche of the consumers for placing orders on the domestic industry for supplying the subject goods.
- xiv. As regards the contention that the benefit received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC, the Authority notes that M/s Zhejiang Jiali Technology Co Ltd, the parent company of the respondent company in the present investigation has no business of its own and discharges all its business through its five subsidiaries involved in production and sale of the subject goods and other goods including R&D services. However, the Authority notes from the website information of M/s Zhejiang Jiali Technology Co Ltd that this company has obtained performance related several awards and certificates including grants etc. Since apparently the parent company has no business of its own, obviously all its awards, certificates, grants etc obtained by it are on account of the performance of its subsidiaries. Therefore, the Authority notes that the benefits/subsidies obtained by the parent company shall be applicable to its subsidiaries as well.
- xv. As regards the contention that the “Welfare Business Value Added Tax Refund”, “Export Tax Refund” and “Other Tax Refund” shall not be used for calculation of the program, because they are not related to the land use tax, the Authority has reworked the calculations in this final finding.
- xvi. As regards the contention that Program No. 37: Reduction in Land Use Fees, the “Land Use Tax Refund” received by the parent company shall not be applicable to Jiali Wind since they are two independent companies and the parent company is not involved in the PUC, the authority holds that parent company has no business of its own, and the benefit accrued under this programme related to the subsidiaries of the parent company. In the absence of details provided by the parent company, the Authority has allocated the total benefits received by parent company under this programme to the turnover of the parent company, which includes the turnover of all its subsidiaries including the respondent exporter.

**N. CONCLUSIONS:**

155. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized value, thus resulting in subsidization of the product.
  - The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
  - The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**O. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

156. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
157. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidised subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

**P. RECOMMENDATIONS**

158. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including the Government of China PR and adequate opportunity was given to provide positive information on the aspect of subsidization, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from China PR in the form and manner described hereunder.
159. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of countervailing duty equal to the lesser of subsidy margin and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the definitive countervailing duty as a percentage of the landed value of imports as mentioned in Col 8 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

**Duty Table**

Sl. No.	Heading / Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount as % of landed Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	84834000, 85030090, 85030010 in Chapter 84 and 85 of Customs Tariff Act	Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an	China PR	China PR	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Company Limited	Zhejiang Jiali Wind Power Technology Company Limited	8.78

		equipment/component meant for wind-operated electricity generators					
2	-do-	-do-	China PR	China PR	Any	Any	13.44
3	-do-	-do-	China PR	Any Country	Any	Any	13.44
4	-do-	-do-	Any Country	China PR	Any	Any	13.44

160. Landed value of imports for the purpose of computing the countervailing duty shall be the assessable value as determined by the customs authority under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
161. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Designated Authority